वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110 016 (भारत)

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110016

©राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (150 प्रतियाँ), 2021
(भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित)

संकाय समन्वयक : डा. संगीता अंगोम

कुलसचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), 17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा मैसर्स विबा प्रेस प्रा. लि., ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–II, नई दिल्ली–110 020, अप्रैल 2022 में 150 प्रतियां डिजाईन एवं मुद्रित।

विषय–सूची

अध्याय		
1.	विहंगावलोकन	01
2.	अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	37
3.	अनुसंधान	55
4.	पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं	81
5.	कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं	91
6.	प्रकाशन	99
7.	नीपा में सहायता अनुदान योजना	103
8.	प्रशासन और वित्त	107
अनुलग्नक		
I.	संकाय का अकादमिक योगदान	113
परिशिष्ट		
I.	प्रबंधन बोर्ड के सदस्य	217
II.	वित्त समिति के सदस्य	219
III.	अकादमिक परिषद के सदस्य	220
IV.	अध्ययन बोर्ड के सदस्य	223
V.	योजना और निरीक्षण बोर्ड के सदस्य	225
VI.	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ	227
VII.	**वार्षिक लेखा**	231
	लेखापरीक्षा रिपोर्ट	273

1

विहंगावलोकन

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL PLANNING AND

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अपने महत्वपूर्ण और व्यापक शैक्षणिक कार्यकलापों के साथ देश के शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क में विशेष स्थान रखता है।

इसकी स्थापना आरंभिक रूप से फरवरी 1962 में यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र के रूप से हुई थी। इस केंद्र का मुख्य कार्य एशिया के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये शैक्षिक योजना, प्रशासन संस्थान पर्यवेक्षण से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन तथा सदस्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। तद्नुसार 1 अप्रैल 1965 से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये एशिया क्षेत्रीय केंद्र का नाम बदलकर एशिया शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को तथा भारत सरकार के बीच दस वर्ष के समझौते के समाप्त होने के बाद, एशिया संस्थान को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और तत्पश्चात 1970 में शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की गई। पुनः इस कालेज का पुनर्गठन किया गया और 31 मई 1979 को इसका विस्तार करते हुये इसको राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया।

शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में नीपा द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुये संस्थान को वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत इसे 'मानित विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त हुआ जिसके अंतर्गत इसे डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई और पुनः नाम परिवर्तन के बाद इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) कहा जाने लगा। इसे आगे 'राष्ट्रीय संस्थान' नीपा के नाम से संबोधित किया जायेगा। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

दिनांक 30.11.2017 की अधिसूचना संख्या फा.सं. न्यूपा/प्रशासनिक/आरओ/परिपत्र/030/2017 के द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) का नाम परिवर्तन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) (मानित विश्वविद्यालय) के रूप में कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 10 नवंबर 2017 और 29 नवंबर 2017 के संप्रेषित पत्राचार सं. एफ. 5–1/2017 (सी.पी.पी.–1/डी.यू.) द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 'विश्वविद्यालय' शब्द के स्थान पर 'संस्थान' शब्द रख दिया गया है।

नीपा की दृष्टि और उद्देश्य

संस्थान का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत संस्थान शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का उद्देश्य 'ज्ञान के उन्नयन से एक मानवीय अधिगम समाज का निर्माण करना है'। इस विज़न के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान शैक्षिक नीति, उच्च स्तरीय शिक्षण के साथ योजना तथा प्रबंधन, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सेवायें प्रदान करने हेतु मिशन के रूप में कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय संस्थान के मुख्य कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी नीतियों, योजना तथा कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय तथा संघ क्षेत्रों के स्तर पर सांस्थानिक क्षमता का सुदृढ़ीकरण तथा स्कूल, समुदाय, जिला, राज्य/संघ प्रदेशों तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक त्वरित, सहभागिता और जवाबदेह शैक्षिक अभिशासन तथा प्रबंधन प्रणाली का सांस्थनीकरण।
- शैक्षिक सुधारों का अनुसमर्थन करने और शिक्षा क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की प्रभावी योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपेक्षित ज्ञान और कौशलों से सुसज्जित शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में युवा पेशेवरों सहित और शिक्षाविदों सहित विशेषीकृत मानव संसाधनों के समूह का विस्तार करना;
- शैक्षिक क्षेत्र में उभरती तथा वर्तमान चुनौतियों का सामना करने हेतु तथ्य आधारित जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा देने हेतु शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन एवं संबंधित विषयों के ज्ञान आधार में वृद्धि;
- शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार तथा बेहतर शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार, अनुसंधान परिणामों, नवाचारों तथा सर्वोत्तम व्यवहार समेत सूचना तथा ज्ञान की साझेदारी एवं पहुंच में सुधार;
- अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देते हुये शैक्षिक नीति निर्माण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन व्यवहार/तकनीक शिक्षा के सभी चरणों तथा व्यवस्था में, तथा रणनीतिक उपागम शैक्षिक योजना प्रक्रियाओं, अभिशासन तथा प्रबंधन में सुधार हेतु तथा अंतरशास्त्रीय जिज्ञासाओं में नेतृत्वकारी भूमिका जो शैक्षिक नीति–निर्माण तथा देश में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन व्यवहार का निर्माण करती है।

मुख्य कार्य

अपने उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्थान निम्नांकित मुख्य कार्यों में संलग्न है :

- शिक्षा के सभी चरणों में शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करना;
- सर्वोत्तम प्रशिक्षित शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के कैडर के गठन हेतु प्री–डाक्टरल, डॉक्टरल तथा पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों और व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों सहित अध्यापन के विकसित अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों का विकास तथा आयोजन और साथ में शैक्षिक नीतियों योजना तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु सतत् सांस्थानिक क्षमता का निर्माण करना;
- शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनुसंधान एजेंडा तथा वचनबद्धता को स्वरूप देना, क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिये आवश्यक समर्थन हेतु नये ज्ञान का सृजन तथा तथ्य आधारित नीति निर्माण और बेहतर शैक्षिक योजना और प्रबंधन व्यवहार/तकनीक का प्रयोग करना;
- केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों को उनकी शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन से संबंधित क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु तकनीकी समर्थन प्रदान करना और उन्हें शैक्षिक नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन में सुधार हेतु मदद करना;
- शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा निर्माण हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को परामर्श सेवायें प्रदान करना;
- शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान तथा नवीन ज्ञान के सृजन हेतु सूचना तथा विचारों के समाशोधन गृह के रूप में कार्य, शैक्षिक नीतियों, योजना तथा प्रशासन में विशेष रूप से, विचारों/अनुभवों के आदान–प्रदान तथा नीति–निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के बीच नीतिगत चर्चा हेतु विचार मंच प्रदान करना, प्रभावी नीतियों तथा शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन तकनीक/व्यवहार को शिक्षा क्षेत्र संबंधी चुनौतियों को सामना करने हेतु चिह्नित करना तथा शिक्षा क्षेत्र संबंधी विकास लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में सुधार हेतु संयुक्त प्रयासों/कार्यक्रमों तथा अनुसंधान अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों, निधि एवं एजेंसियों समेत राष्ट्रीय

तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के साथ नेटवर्किंग तथा सहयोग;

- शैक्षिक क्षेत्र के विकास में उभरती हुई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा विश्लेषण, शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में उभरती हुई चुनौतियों की पहचान तथा शैक्षिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त नीति निर्माण तथा कार्यक्रम हस्तक्षेप के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक क्षेत्र विकास लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रगति का मूल्यांकन।

राष्ट्रीय संस्थान के उपरोक्त कार्य राज्य तथा संघशासित प्रदेश एवं केंद्रीय स्तर पर सरकारों तथा संस्थानों के साथ निकटतम संपर्क तथा सहयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ राष्ट्रीय संस्थान कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं शिक्षा व्यवस्था की योजना तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। संस्थान का एक मुख्य पहलू जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय संस्थान का संबंध द्वि–रूप कार्य प्रणाली है। संस्थान अपने ज्ञान आधार में वृद्धि वास्तविकता क्षेत्र में अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल, कालेज, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभागों के साथ संपर्क द्वारा करता रहा है। राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय संस्थान राज्यों/संघशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण को पूर्ण करने हेतु संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण, राज्य सरकारों तथा राज्य संस्थानों के साथ निकटवर्ती संपर्क, उनकी शैक्षिक व्यवस्था का समालोचनात्मक अध्ययन, नीतियां तथा कार्यक्रम एवं उन्हें व्यावसायिक परामर्श तथा तकनीकी समर्थन हेतु प्रयासरत है। संस्थान अपने ऐसे कार्यक्रमों की शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक थिंक टैंक (प्रसार केन्द्र) बना हुआ है। संस्थान अपने अधिकांश क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और अन्तर्दृष्टि जमीनी स्तर के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं को हस्तान्तरित कर रहा है। इस प्रकार से नीपा की इस दोहरी भूमिका ने अपने अध्यापन तथा अनुसंधान के अकादमिक कार्य को व्यापक प्रामाणिकता प्रदान की है।

अकादमिक ढांचा तथा समर्थन सेवाएं

संस्थान के अकादमिक ढांचे में विभाग, केंद्र, विशेष पीठ हैं जो शिक्षा के विशिष्ट पक्षों तथा तकनीकी समर्थन एकक/समूह तथा अकादमिक समर्थन प्रणाली अपने संबंधित विषयगत क्षेत्रों से जुड़ी विकास तथा क्रियान्वयनकारी गतिविधियों के प्रति उत्तरदायी हैं। नीपा के संकाय में प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा राष्ट्रीय अध्येता सम्मिलित हैं जो शिक्षा नीति, योजना तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। प्रत्येक विभाग अंतरशास्त्रीय विषयों के आधार पर संयोजित है और वे ज्ञान, विद्वता तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रमों और अनुसंधान क्षेत्रों, सामान्यतः शिक्षा, और विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन में विशेष तौर पर संसाधन प्रदान करते हैं। प्रत्येक विभाग के पास अनुसंधान/परियोजना सहायकों तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ के रूप में संकाय सदस्य हैं। अकादमिक विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर होता है। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के निष्पादन और विकास तथा उनको प्रदान किये गये क्षेत्रों में परामर्श तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत, संस्थान के अकादमिक कार्यक्रमों का आयोजन आठ अकादमिक विभागों तथा विशेष पीठ स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक, परियोजना प्रबंधक एकक, भारत–अफ्रीका शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (आई.ए.आई.ई.पी.ए.) तथा दो केंद्रों द्वारा किया गया जिन्हें अकादमिक तथा प्रशासनिक सेवा एककों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया।

अकादमिक संगठन

विभाग

- शैक्षिक योजना
- शैक्षिक प्रशासन
- शैक्षिक वित्त
- शैक्षिक नीति
- विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा
- उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा
- शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
- शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

केन्द्र

- राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र
- उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र
- राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र (एनआरसीई)

एकक

- स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक
- अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एकक

समर्थन सेवाएं

- पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र
- कंप्यूटर केन्द्र
- प्रकाशन एकक
- परियोजना प्रबंधन एकक
- डिजीटल अभिलेखागार
- प्रशिक्षण कक्ष/हिंदी कक्ष

पीठ

- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ

अकादमिक विभाग

शैक्षिक योजना विभाग

शैक्षिक योजना विभाग (डीईपी), नीपा के मौलिक प्रभागों में से एक है जिसका मुख्य ध्येय भारत में मानव विकास की उन्नति में योगदान के साथ साक्ष्य आधारित शैक्षिक योजनाओं को बढ़ावा देना है। शैक्षिक विकास के परिणामों के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकृत योजनाओं की दिशा में बदलाव के साथ, देश में शैक्षिक योजनाओं को समझने और सुधारने हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजनाओं के आगतों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और परिणामों का अध्ययन करता है।

गरीबी को कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा पर दबाव के साथ न केवल शैक्षिक योजना का दायरा समष्टि स्तर पर रणनीतिक योजना के संस्थानीकरण को कवर करना है बल्कि विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म नियोजन और स्कूल सुधार योजना के रूप में स्थानीय स्तर की योजना तकनीकों का प्रयोग करना भी है। स्कूली शिक्षा में रणनीतिक योजना और उच्च शिक्षा में संस्थागत योजना के क्षेत्रव्यापी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शैक्षिक योजना विभाग के अन्य प्रमुख अधिदेश हैं।

शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण, इत्यादि, शैक्षिक योजना विभाग के मुख्य कार्य हैं। शिक्षा में समानता, समावेशन, शिक्षण परिणामों की गुणवत्ता, वित्तपोषण और जवाबदेही से संबंधित मुद्दों के समाधान, शिक्षा में रणनीतिक कार्यक्रम योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल का सृजन और प्रसार तथा शिक्षा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शैक्षिक योजना विभाग के प्रमुख क्षेत्र हैं।

तदनुसार, विभाग विभिन्न उप–राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को शैक्षिक योजना से संबंधित कई पाठ्यक्रमों का संचालन के अलावा संस्थान के अनुसंधान और लंबी अवधि की क्षमता विकास कार्यक्रमों में क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन, संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और व्यावसायिक सहायता और परामर्शकारी सहयोग प्रदान करता है।

अकादमिक वर्ष 2020–21 में कोरोना महामारी के कारण विभाग के कार्यकलापों पर गंभीर असर पड़ा।

शैक्षिक प्रशासन विभाग

शैक्षिक प्रशासन विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और प्रबंधन के विविध आयामों अनुसंधान, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा परामर्शकारी सेवाओं में सक्रिय रूप से बौद्धिक और अकादमिक संलग्नता है। विभाग का एक मुख्य शैक्षिक क्षेत्र सरोकार एक समृद्ध ज्ञान आधार का विकास करना और शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन के विविध आयामों पर शैक्षिक प्रशासकों तथा शोधार्थियों को एक मजबूत पेशेवर अनुसमर्थन का निर्माण करना है। अपने लक्ष्य के अनुसार शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर ठोस डाटा बेस का निर्माण किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभाग ने कई अध्ययन किये और एक बड़े पैमाने पर शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण, शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन के साथ कई दूरगामी अैर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये। कार्यशालाओं, सम्मेलनों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों और भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों भर में करीब एक हजार और तीन सौ राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक विभाग ने अपनी पहुंच बनाई। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में शैक्षिक और अकादमिक प्रशासन से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं

प्रमुख कार्यक्रम और उनके मुख्य अंश

वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना

शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए पुरस्कारों की राष्ट्रीय योजना (NSIEA) संस्थान का एक नियमित दीर्घकालिक कार्यक्रम है। कोविड–19 के प्रकोप के मद्देनजर वर्ष 2019–2020 और 2020–2021 के दौरान पुरस्कारों के विचार के लिए प्राप्त आवेदनों और नामांकनों को एक साथ जोड़कर वर्ष के अंत तक पुरस्कार समारोह के एक संयुक्त आयोजन में परिणत किया गया है। वर्तमान में 2018–2019 और 2019–2020 के लिए नामांकन के लिए कुल पात्र नामांकनों की संख्या 131 है, जिसमें 79 जिला स्तर से हैं, जबकि 52 ब्लॉक स्तर से हैं। 2018–19 के पुरस्कार के लिए, उम्मीदवारों को पात्रता चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, लेकिन बहु–स्तरीय मूल्यांकन के साथ–साथ मामलों का सत्यापन भी किया जाना है।

जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व पर अभिविन्यास सह कार्यशाला, 8–12 फरवरी, 2021

देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व के मुद्दों पर एक सप्ताह का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को गूगल मीट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की सभी प्रतिभागियों ने खूब सराहना की।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व पर कार्यशाला सह अभिविन्यास कार्यक्रम

विभाग ने 17 से 19 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व पर एक कार्यशाला सह अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। शैक्षिक प्रशासकों और अकादमिक नेताओं के सामने उच्च शिक्षा और चुनौतियों में उभरती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम को उच्च शिक्षा के संस्थागत संदर्भ में चुनौतियों का सामना करने के लिए मुद्दों और सबसे उपयुक्त रणनीतियों का पता लगाने हेतु विचार–विमर्श करने के लिए डिजाइन किया गया था। एनईपी 2020 के नीति प्रस्ताव कार्यशाला सह अभिविन्यास कार्यक्रम के वितरण के लिए प्रमुख संदर्भ बिंदु थे। लगभग 77 वरिष्ठ स्तर के अकादमिक प्रशासकों/नेताओं जैसे रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों और राज्यों और क्षेत्रों के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यशाला का प्रतिनिधित्व 19 राज्यों ने किया था। 77 प्रतिभागियों में से 28 राज्य के विश्वविद्यालयों से, नौ केंद्रीय विश्वविद्यालयों से और चार डीम्ड विश्वविद्यालय से थे।

एम.एड के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप। 22–27 फरवरी, 2021 तक आरआईई, भोपाल के छात्र

विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और आर.आई.ई.ई. भोपाल आदि जैसे संस्थानों के अनुरोध पर 2017 से एम.एड और एमए (शिक्षा) के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हर साल प्रत्येक संस्थान से 10–15 छात्र भाग लेते हैं और इंटर्नशिप पूरा करते हैं। इस साल कार्यक्रम के वितरण के तरीके में बदलाव किया गया था।

आरआईई, भोपाल से प्राप्त अनुरोध के आधार पर एम. एड छात्रों के लिए छह दिनों की ऑनलाइन इंटर्नशिप का आयोजन किया गया था। इस ऑनलाइन इंटर्नशिप में पांच छात्रों ने भाग लिया था। इंटर्नशिप के दौरान इन्हें विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। सबसे पहले, उन्हें नीपा और इसके विभिन्न विभागों/केंद्रों और उनमें से प्रत्येक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से परिचित कराया गया। इसके बाद एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताओं, सूक्ष्म नियोजन, स्कूल मानकों और मूल्यांकन, शैक्षणिक सहायता प्रणाली, वंचित समूहों की शिक्षा और स्कूल नेतृत्व जैसे कई विषयों से परिचित कराया गया।

अपने असाइनमेंट के हिस्से के रूप में, छात्रों को एस.डब्ल्यू.ओ.सी. विश्लेषण का उपयोग करके ऑनलाइन–शिक्षण–अधिगम के विश्लेषण पर एक निबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। छात्रों द्वारा इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से समझा।

शैक्षिक वित्त विभाग

इस विभाग का दोहरा उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों– राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा विश्वस्तर पर आर्थिक तथा वित्तीय पक्ष पर अनुसंधान करना तथा उसे प्रोत्साहित

करना है तथा विकासशील देशों और भारत में शिक्षा क्षेत्र की वित्तीय योजना तथा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों के क्षमता निर्माण और ज्ञान का सृजन करना है। विभाग के कार्यक्रम/गतिविधियां– अनुसंधान, अध्यापन, प्रशिक्षण तथा परामर्श हैं जो नीति, योजना तथा विकास, शिक्षा के सार्वजनिक तथा निजी वित्त पोषण, सरकारी तथा निजी संसाधनों की लामबंदी, शिक्षा के सभी स्तरों पर संसाधनों का आवंटन तथा उपयोग, प्राथमिक से उच्च, तथा संसाधन आवश्यकताओं के आकलन से जुड़े मुद्दों के इर्द–गिर्द केंद्रित हैं। अधिकांशतः शोध के क्षेत्र शिक्षा के वित्त पोषण, कार्यक्रम और नीतिगत मुद्दों से संबंधित हैं। परामर्शकारी सेवाएँ नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित हैं। अध्यापन के विषय में शिक्षा का अर्थशास्त्र और शैक्षिक वित्त पोषण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के विषय योजना तकनीक और प्रबंधन प्रणाली पर आधारित हैं।

शैक्षिक नीति विभाग

शैक्षिक नीति विभाग शैक्षिक अभिशासन और प्रबंधन में वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक नीति का अध्ययन, शैक्षिक समस्याओं का मूल्यांकन और विश्लेषण, नीति तथा व्यवहारों का मार्गदर्शन तथा परिणामों को समझने के लिए प्रतिबद्ध है। चूँकि अपने मिशन में यह प्रतिबद्ध है, शैक्षिक क्षेत्र में प्रासंगिता और गुणवत्ता, समता, पहुँच जैसे अवरोधकों के प्रति ज्ञान के वर्धन में इसलिए यह विभाग समय–समय पर विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर हितधारकों, व्यवहारकर्त्ताओं तथा भारत में शैक्षिक व्यवस्था को प्रमाणित करने वाली जननीति मुद्दों पर चर्चाएं आयोजित करता है। उपरोक्त मुद्दों के साथ शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक नीति के बीच शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन अधिगम और प्रदर्शन के बेहतर लिंकेज को स्थापित करने हेतु यह विभाग अनुसंधान पर बल देता है। अनुसंधान का उद्देश्य केवल शैक्षिक प्रतिभास की जटिलताओं को दर्शाना ही नहीं होता। बल्कि कार्रवाई के लिए संस्तुतियों प्रदान करना भी होता है। समाज में वर्तमान परिवर्तनों और शिक्षा पर इसके प्रभाव को देखते हुए, विभाग समय–समय पर हितधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए गुंज–यंत्र के रूप में कार्य करता है। विभाग योजनाकारों प्रशासकों, क्रियान्वयनकर्त्ताओं तथा विद्वानों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिससे कि वे वर्तमान ढांचे, प्रक्रियाओं और भारत में संगठित शिक्षा के सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावी और नैतिकता से कार्य कर सकें।

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग व्यापक रूप से अधिकार–आधारित और समेकित ढांचे के अंतर्गत समग्र स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक और प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष बल देता है। यह विभाग बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा के पूरे क्षेत्र को कवर करना है। इसके अलावा, विभाग के प्रमुख कार्यों में स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक, अध्यापक प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों, अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए अनुसंधान और विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है।

विभाग भारत में शैक्षिक विकास को सुधारात्मक और अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध अध्ययन करता है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिये कार्यशालाएं और क्षमता विकास के कार्यक्रम आयोजित करता है। यह विभाग स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सह–क्रियात्मक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ अनुभव और विशेष क्षमताओं को साझा करता है।

यह विभाग संस्थान का एक मुख्य और सबसे पुराना विभाग होने के नाते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), कार्यक्रमों का कार्यान्वयन (1992), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और सभी के लिए शिक्षा (स.लि.शि.) के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2007–2011 के दौरान, शैक्षिक पहुंच, पारगमन और समानता पर अनुसंधान के लिए सह–संघ के हिस्से के रूप में विभाग ने (www.create-rpc.org) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक अन्य बड़ी परियोजना जो भारत में अखिल भारतीय शिक्षा पर मध्य–दशक का आकलन जिसमें प्राथमिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर छह ईएफए लक्ष्यों में

से प्रत्येक के लिए राज्य–समीक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन कौशल, वयस्क साक्षरता और लैंगिक समानता और कई विषयगत अध्ययन पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की गई है। यह विभाग,सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा (सीएसटीई) के लिए नीतिगत सिफारिशों में भी योगदान दे रहा है।

हाल के वर्षों में, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के तत्वावधान में, विभाग ने भारत में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए दो राष्ट्रीय कार्यक्रमों 'स्कूल मानक और मूल्यांकन (शाला सिद्धि) और स्कूल नेतृत्व कार्यक्रम' को संस्थागत बनाने का समर्थन किया। इसने अवधारणा, सामग्री विकास और दोनों कार्यक्रमों को सही दृष्टिकोण से लागू करने के लिए 'राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र' और 'स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई' की स्थापना करने की सुविधा प्रदान की।

शैक्षिक परिणामों के इस युग में, शिक्षा की गुणवत्ता, प्रदर्शन में सुधार और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रभावशीलता की मांग में वृद्धि और नीतिगत विचार–विमर्श के केंद्र के रूप में जारी है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार और नींव के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता को स्वीकारते हुए, विभाग का लक्ष्य है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल प्रभावशीलता और सुधार को दीर्घकालिक लक्ष्य के सूचकांक में शामिल किया जाए। विभाग ईसीसी पर महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में भी ध्यान केंद्रित करता है और नीतिगत योजनाओं के लिए साक्ष्य–आधारित सूचनाएं प्रदान करता है।

विभाग के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रः

1. अधिकार–आधारित और शिक्षा के लिए समावेशी दृष्टिकोण

भारत सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के केंद्र बिंदु के रूप में, विभाग समावेशी संरचना में विद्यालय पूर्व और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विस्तार के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार ढांचे के अन्तर्गत शिक्षार्थियों की विविधता भी विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र के रूप में लगातार जारी है। विशेषतः विकलांग, सुविधाहीन और शहरी वंचित शिक्षार्थियों के अधिगम शोध, विकास और प्रशिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण के रूप में जारी रहेंगे।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

शिक्षा प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण समय के रूप में प्रारंभिक बचपन के महत्व को स्वीकारते हुए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, विभाग प्रारंभिक बचपन की देखभाल, पोषण और शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास और स्कूल की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही शिक्षा में योजना/प्रबंधन और गुणवत्ता के मुद्दों की खोज में लगा हुआ है। चूंकि यह क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है, इसलिए विभाग ईसीसीई क्षेत्र में कानून, शासन और गुणवत्ता द्वारा नीति और प्रथाओं का पुनरीक्षण करके अनुसंधान के दायरे का विस्तार कर रहा है।

3. स्कूल गुणवत्ता और सुधार

बदलती शिक्षा के संदर्भ में सभी बच्चों को प्रभावी और सुधारात्मक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थियों के कम प्रदर्शन का प्रमाण स्कूलों के विकास और सुधार के दृष्टिकोण को देखने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की पहल, स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है इएलिए इस ओर विभाग का ध्यान जारी है साथ ही, स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल मानक एवं मूल्यांकन ढांचा, स्कूल सुधार दिशानिर्देश निर्धारकों, स्कूलों की विकासात्मक आवश्यकताओं तथा जवाबदेही और पारदर्शिता पर विभाग का ध्यान केंद्रित रहेगा। जैसा कि विभाग सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए लगातार अकादमिक सहायता और परामर्श का प्रसार, नए ज्ञान और अवधारणाओं पर नए दृष्टिकोण के साथ कार्यक्रमों का समर्थन करेगा।

4. *शिक्षक प्रबंधन, प्रभावशीलता और विकास*

गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक शिक्षक प्रबंधन और विकास का केंद्रीयकरण माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हाल के शोध से पता चला है कि शिक्षक प्रभावशीलता छात्र अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण स्कूल–आधारित भविष्यवक्ता है। शिक्षक की गुणवत्ता को तीन व्यापक प्रारूप में रखा जा सकता है– आपूर्ति और मांग के मुद्दे; शिक्षकों की तैयारी; और व्यापक क्षमता वाले शिक्षकों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखना। उभरती हुई शिक्षक भूमिकाएँ, उनकी शैक्षणिक समझ, शिक्षण की प्रथाएँ, उनके काम के संदर्भ और शैक्षिक हितधारकों के साथ संबंध को हम शिक्षक विकास और प्रबंधन की वास्तविकताओं के बारे में जो जानते हैं उसकी सावधानीपूर्वक समझ और परीक्षा की आवश्यकता होती है। योग्य शिक्षकों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, विभाग प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षक प्रबंधन मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय स्तर के व्याख्यान और शोध अध्ययनों में लगा हुआ है। इन शोध एजेंडों को जारी रखते हुए, अनुसंधान और विकास का दायरा शिक्षक प्रभावशीलता और सुधार, प्रदर्शन, प्रबंधन और मूल्यांकन, जवाबदेही और आचार संहिता तथा शिक्षकों के सतत विकास को शामिल करेगा।

5. *शिक्षक शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन*

पिछले एक दशक के दौरान शिक्षक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम सुधार और अवधि, मानदंडों और मानकों आदि पर कानूनी सिफारिशों को लागू करने के माध्यम से अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संघर्ष कर रही है। शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक रुचि के बावजूद प्रणाली में कई कमियों को चिन्हित किया है।

शिक्षक शिक्षा विकास के नीति निर्माण और नियोजन में विभाग महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विभाग ने न केवल शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन में योगदान दिया, बल्कि विभिन्न योजना अवधियों में शिक्षक शिक्षा नीति तैयार करने का भी समर्थन किया। शिक्षक शिक्षा और राष्ट्रीय मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग (पंडित मदन मोहन मालवीय योजना) पर जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट तैयार करना विभाग और नीपा द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप हैं।

शिक्षक शिक्षा में शासन, विनियमन और गुणवत्ता आश्वासन अनुसंधान और विकास के लिए उपेक्षित क्षेत्र के रूप में जारी है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, विभाग शिक्षक शिक्षा को बदलने के लिए सही नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु अनुसंधान, विकास और राष्ट्रीय विचार–विमर्श पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

6. *स्कूल नेतृत्व*

स्कूल की गुणवत्ता में बदलाव और पुनर्संरचना के प्रबंधन और छात्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए स्कूल नेतृत्व की भूमिका भारत के नीति विमर्श में गति प्राप्त कर रही है। तदनुसार, विभाग पहले नेतृत्व विकास कार्यक्रम में मौजूदा अंतर को पकड़ने और विभिन्न राज्यों के संस्थागत रूप में स्कूल नेतृत्व पर एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। विभाग ने नेशनल कॉलेज ऑफ स्कूल लीडरशिप, नॉटिंघम के साथ सहयोग में यूकेईआरआई वित्त पोषित परियोजना में योगदान दिया और नीपा में सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप स्थापित करने के लिए विस्तारित समर्थन दिया। केंद्र के लिए परिप्रेक्ष्य योजना अलग से तैयार की गई है। विभाग अपने प्रयास को जारी रखते हुए, केन्द्र स्तर पर 'शिक्षक नेतृत्व' लाकर 'शैक्षिक नेतृत्व 'पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

7. *नागरिक संघर्ष क्षेत्रों और सुरक्षित स्कूल में शिक्षा*

सुरक्षित स्कूल को स्कूल परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपकरण के रूप में ध्यान में रखते हुए, विभाग विभिन्न हितधारकों के बीच नए सिरे से समझ पैदा करने, प्रशिक्षण सामग्री, क्षमता विकास और विचार–विमर्श को विकसित करने में लगा हुआ है।

8. प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता

विभाग साक्षरता और आजीवन अधिगम के कार्यक्रमों की नीति और योजना निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

विभाग ने इन क्षेत्रों को नीपा के मसौदा 'परिप्रेक्ष्य योजना' से दीर्घ, मध्यम और अल्पकालिक रणनीतियों के रूप में चुना है। हालांकि विभाग हमेशा ईएफए, एमडीजी और एसडीजी जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की सिफारिशों का पालन करता है, लेकिन प्रमुख कार्यक्रमों को सरकार के तात्कालिक जरूरत और परिवर्तनकारी एजेंडे के रूप में प्रस्तावित किया जाता है ताकि शिक्षा के परिणामों में सुधार और सभी शिक्षार्थियों को उनके सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

यह विभाग उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा की नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करता है। उच्चतर एवं व्यावसयिक शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ यह गुववत्ता, अभिशासन, वित्त पोषण एवं निजीकरण के मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन में संस्थागत प्रमुखों और वरिष्ठ विश्वविद्यालय और राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं संचालित करता है। विभाग उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की नीतिगत योजनाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी और पेशेवर परामर्श प्रदान करने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को लगातार अनुसंधान सहायता और नीतिगत सलाह प्रदान करता रहा है। विभाग में डब्ल्यूटीओ सेल ने अनुरोधों का विश्लेषण करने और गैट्स के तहत भारत के प्रस्तावों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाग ने उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया और उस पर चर्चा और प्रसार करने के लिए सेमिनार आयोजित किए। यह विभाग उच्चतर शिक्षा के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहयोग करता रहा है। यह विभाग विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संकायाध्यक्षों और कुलसचिवों के सम्मेलन और संगोष्ठियों के आयोजन में यू.जी.सी. का सहयोग करता रहा है। इस विभाग ने कार्य निष्पादन आधारित उच्चतर शिक्षा पर विश्व सम्मेलन आयोजित करने हेतु यूनेस्को क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन और भारतीय उच्चतर शिक्षा में कार्य निष्पादन आधारित वित्त पोषण पर योजना आयोग – विश्व बैंक प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन में भी सहयोग किया है। वार्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत यह विभाग विभिन्न श्रेणियों के कॉलेज प्राचार्यों के लिये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के विभिन्न आयामों तथा अकादमिक सुधार पर संगोष्ठियां आयोजित करने में अकादमिक समर्थन प्रदान करता है। विभाग शैक्षणिक कार्यक्रम– एम.फिल. तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों के शोधार्थियों और दो डिप्लोमा प्रोग्राम नामतः इंटरनेशनल डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (आईडेपा) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (पीजीडेपा) का अतिरिक्त शोधनिर्देशन कर रहा है। विभाग एम.फिल., पीएच.डी., आईडीईपीए और पीजीडीईपीए कार्यक्रमों के शोधार्थियों का उनके शोध प्रबंधों पर पर्यवेक्षण करता रहा है।

विभाग के सदस्य उच्च शिक्षा के कई महत्वपूर्ण और सार्थक पहलुओं पर लगातार शोध कर रहे हैं जैसे 'उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी', 'उच्च शिक्षा का वित्तपोषण', 'कॉलेजों में स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रम', 'भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाता', 'छोड़े गए युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के विकल्प और अभिनव रूप', 'विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की गतिशीलता', 'भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र', 'भारत में निजी विश्वविद्यालय', 'दक्षिण एशिया में रोजगार के लिए कौशल', 'उच्च शिक्षा में स्वायत्तता', 'बिहार और अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा का अभिशासन', 'भारतीय स्नातक कॉलेजों में पुस्तकालय सुविधाएं और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका प्रभाव', 'यूजीसी छात्रवृत्ति मूल्यांकन', 'यूजीसी यात्रा अनुदान का मूल्यांकन' और 'कोविड–19 और उच्च शिक्षा'।

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

विभाग शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्यक्रम इंडक्शन और प्रमोशन स्तर पर प्रशिक्षुओं की जरूरतों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह प्रशिक्षुओं को देश और विश्व स्तर पर चल रहे शैक्षिक सुधारों के

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और नीतियों को स्पष्ट करने में मदद करता है। इसको प्राप्त करने के लिए विभाग दो डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित करता है एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कर्मियों के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम – शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (2014 में नाम बदलकर पीजी डीईपीए) और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए) सालाना आयोजित किया जाता है। इसके अलावा विभाग 2016 से विशेष रूप से मध्य स्तर के शैक्षिक प्रशासकों के लिए एक महीने का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित करता है, अर्थात् शैक्षिक प्रशासकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईए)।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए)

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा नीपा के अनूठे कार्यक्रमों में से एक है और 1982–1983 से देश में केवल नीपा में संचालित किया गया है। 2014 तक पहले चौंतीस कार्यक्रमों को डीईपीए कहा जाता था। इसे शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडीईपीए) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के रूप में उन्नत किया गया था और मिश्रित मोड में पेश किए जाने के लिए छह महीने के स्थान पर बारह महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षिक विभागों जैसे निदेशालय, एस.सी.ई.आर.टी., सीमेट, डाईट, डी.ई.ओ., भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना, आदि से पूरे भारत के शैक्षिक प्रशासक अपने संबंधित संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीजीडीईपीए कार्यक्रम में कार्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के बाद डीईपीए प्रमाणपत्रों के साथ नौ महीने के बाद बाहर निकलने की छूट है। 2020–21 के दौरान आठ राज्यों के विभिन्न संगठनों के उन्नीस प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अब तक, लगभग 900 प्रतिभागियों की कुल संख्या को डेपा या पीजीडेपा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए)

नीपा अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए सालाना वरिष्ठ और मध्यम शैक्षिक नीति निर्माताओं, योजनाकारों और प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन (आईडीईपीए) में एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा प्रदान करता है। आईडीपीए को 1983 में यूनेस्को के साथ भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग द्वारा आयोजित एशियाई देशों के लिए उप–क्षेत्रीय बैठक की सिफारिशों की अगली कड़ी के रूप में 1985 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संस्थान ने ऐसे 36 ऐसे आईडीपीए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, प्रत्येक क्रमिक वर्ष में एक। अब तक, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्रों के 95 देशों के कुल 953 प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया है।

शैक्षिक प्रशासकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईए)

शैक्षिक प्रकाशकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईए) एक अल्पकालिक विशेष कार्यक्रम है, जिसे अधिकांश शैक्षिक अधिकारियों के काम के बोझ और लंबी अवधि के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस प्रकार देशों की सरकारों को क्षमता निर्माण की उनकी मांगों को पूरा करते हुए अपने कार्यालयों के कामकाज को प्रभावित किए बिना एक छोटी अवधि के कार्यक्रम के लिए अपने शैक्षिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने में सुविधा के लिए यह चार सप्ताह की छोटी अवधि के कार्यक्रम की पेशकश की जा रही है। आईपीईए को शैक्षिक प्रशासकों के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें भारत में लंबे समय तक रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चार सप्ताह के पैकेज्ड प्रोग्राम के लिए जो उनकी क्षमता निर्माण की तत्काल आवश्यकता को पूरा करता है और अपने गृह देशों में लौटने पर उन्हें एक बार चुनौती के साथ प्रदर्शन करने के लिए फिर से सक्रिय करता है। अब तक चार कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं और 26 देशों के कुल 75 प्रशिक्षुओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है।

अन्य गतिविधियां

इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अनुरोध कार्यक्रमों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध/

प्रायोजित कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/व्यक्तिगत संकाय सदस्यों से अकादमिक समर्थन प्राप्त करते हैं। विभाग का उद्देश्य विभिन्न क्षमता स्तरों पर प्रशिक्षित टीमों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाना है, जिसमें व्यक्तियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला स्तर की टीमों और संस्थानों की क्षमता शामिल है ताकि उन्हें शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन जो क्षमता विकास हस्तक्षेपों का एक महत्वपूर्ण घटक में सुधार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया जा सके।

मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शिक्षा विभागों और राष्ट्रीय और राज्यधजिला स्तर के संस्थानों को तकनीकी सहायता और परामर्श सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से क्षमता विकास का अनुसरण किया जाता है। विभाग आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के अलावा शिक्षा में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीतियों में अनुसंधान भी करता है।

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग शोध और क्षमता विकास संबंधित कार्य करता है और भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों की शिक्षा का आंकड़ा आधार और प्रबंधन सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए तकनीकी परामर्श देता है। यह विभाग भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) और आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के सहयोग से जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डाइस) का प्रबंधन करता है। इसके अलावा यह विभाग शैक्षिक सांख्यिकी के मुद्दों और शिक्षा के समकालीन मुद्दों पर सम्मेलन/संगोष्ठियां और शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधियों पर कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और सांख्यिकी तथा शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पर परामर्श प्रदान करता है। विभाग के संकाय सदस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली के निर्माण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। तद्नुसार स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली की दिशा में वर्ष 2012–13 से देशभर में समान आंकड़ा प्रपत्र में पहले कदम के रूप में डाइस और सेमीस का समेकित आंकड़ा संगृहित किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे 1.5 मिलियन स्कूलों से आंकड़ा एकत्र किए गए।

इस विभाग द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के विषय में एजुसेट द्वारा डाइस पर संवेदनशीलता कार्यक्रम, शैक्षिक शोध में डाइस आंकड़ों का उपयोग और स्कूल शिक्षा सांख्यिकी की एकीकृत प्रणाली आदि शामिल हैं। यह विभाग विकासशील देशों के लिए ईएमआईएस पर सुनियोजित पाठ्यक्रम के साथ–साथ पीजीडेपा के भाग के रूप में शैक्षिक योजना में मात्रात्मक विधि पर पाठ्यक्रम का अध्यापन करता है। विभाग का संकाय ईएमआईएस और स्कूली शिक्षा से संबंधित पक्षों पर भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करता है।

विशेष पीठ

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पीठ

यह पीठ स्वतंत्र भारत के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के पहले मंत्री मौलाना आज़ाद के योगदान को स्मरण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में स्थापित किया गया है। पीठ का मुख्य अनुसंधान क्षेत्र 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान मौलाना आजाद के योगदान की खोज करते हुए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास पर अध्ययन करना है। यह पीठ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष, मौलाना आजाद स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। यह पीठ मौलाना आज़ाद के दर्शन और वैश्विक विचारों व अन्य संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है।

केंद्र

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

नीपा में राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र (एनसीएसएल) का उद्देश्य स्कूलों को बदलने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ स्कूल के नेताओं को सशक्त बनाना है। अपनी स्थापना के बाद से, यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है और स्कूल नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम डिजाइन और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की है, जो केंद्र द्वारा किए गए कार्यों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। केंद्र ने वर्तमान और भावी स्कूल नेताओं के विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न प्रकार के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संचालन के लिए सामग्री, हैंडबुक और संसाधन पुस्तकें विकसित की हैं। केंद्र मुख्य रूप से चार अलग–अलग घटकों पर काम करता है। पाठ्यचर्या और सामग्री विकास, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग और संस्थान निर्माण और अनुसंधान और विकास।

अपने अस्तित्व के पिछले नौ वर्षों में, केंद्र ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम बनाया है। वर्ष 2019–2020 में, एनसीएसएल स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए विश्व के सबसे बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम 'निष्ठा'– नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट– में गहराई से लगा हुआ था। यह मा.सं.वि. मंत्रालय की मेगा पहल थी जिसका लक्ष्य देश भर में लगभग 42 लाख शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना था। एनसीएसएल ने स्कूल नेतृत्व पैकेज के विस्तृत सत्र विवरण के अलावा स्कूल प्रमुखों और सिस्टम स्तर के पदाधिकारियों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर एक मॉड्यूल तैयार किया था। एनसीएसएल फैकल्टी ने उन सभी राज्यों का दौरा किया जहां स्कूल प्रमुखों के क्षमता निर्माण के लिए उनके स्कूलों को बदलने के लिए एक मजबूत राज्य संसाधन समूह बनाने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया था। राज्यों में स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर लगभग 80 दौर का प्रशिक्षण हुआ जिसमें एनसीएसएल के शिक्षकों ने अथक रूप से भाग लिया और पाठ्यक्रम का संचालन किया। राज्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए, एनसीएसएल ने 27 राज्यों में स्कूल लीडरशिप अकादमियों (एसएलए) की स्थापना की जो केंद्र की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करती है। ये एसएलए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, दस्तावेज नेतृत्व प्रथाओं का संचालन करते हैं और विभिन्न संसाधन सामग्री को भी प्रासंगिक बनाते हैं।

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई)

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआरएचई) (http://cprhe.niepa.ac.in/) की स्थापना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) में एक स्वायत्त विशेष शैक्षणिक केंद्र के रूप में की गई थी ताकि अनुभवजन्य विश्लेषण; और भारत में उच्च शिक्षा में नीति एवं नियोजन का समर्थन और अनुसंधानों को बढ़ावा दिया जा सके। सीपीआरएचई का लक्ष्य एक ज्ञान भंडार के रूप में, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण का अत्याधुनिक केंद्र है; और भारत में उच्च शिक्षा के विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों की नीति व्याख्यानों को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा पर एक थिंक–टैंक के रूप में सेवा करना है। सीपीआरएचई का व्यापक मिशन भारत में शिक्षा के विकास के लिए तैयार की गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए आवश्यक ज्ञान के सृजन, साझा और अनुप्रयोग में योगदान देना है। केंद्र कई अंतर–संबंधित क्षेत्रों में वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर अपने प्रयासों में, उच्च शिक्षा के प्रावधान का विस्तार और सुधार; इक्विटी और समावेश सुनिश्चित करना; गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार; और शासन और प्रबंधन में सुधार को केंद्रित करेगा। साथ ही, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। सीपीआरएचई द्वारा प्रस्तावित और शुरू की गई सभी शोध गतिविधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नीपा परिप्रेक्ष्य योजना 2030 और नीपा द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन योजना के संदर्भ को ध्यान में रखा गया है।

सीपीआरएचई गतिविधियाँ 2020–21

सीपीआरएचई कार्यक्रम और गतिविधियाँ मुख्य रूप से अनुसंधान विषयों के इर्दगिर्द एकीकृत और केंद्रित हैं जिन्हें केंद्र की परिप्रेक्ष्य योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है। वर्ष 2020–21 के लिए सीपीआरएचई गतिविधियों की योजना जनवरी 2017 में तैयार करके, वि.अ. आयोग और मा.सं.वि. मंत्रालय को सौंपी गई कार्यक्रम रूपरेखा और कार्य योजना के अनुसार निम्न हैं। वर्ष 2020–21 में सीपीआरएचई गतिविधियों मौजूदा अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने, राष्ट्रीय संश्लेषण रिपोर्ट और राज्य अनुसंधान रिपोर्ट को अंतिम रूप देने, नई अनुसंधान परियोजनाओं को अंतिम रूप देने, ऑनलाइन कार्यशालाओं तथा वेबिनार के आयोजन तथा सीपीआरएचई अनुंसधान

पर आधारित विभिन्न प्रकाशनों को तैयार करने पर केंद्रित थी। वर्ष 2020–21 में केंद्र की नियमित प्रकाशन गतिविधियों में इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट (सेज और राऊटलेज द्वारा प्रकाशित), सीपीआरएचई अनुसंधान पत्र श्रृंखला, सीपीआरएचई अनुसंधान पर आधारित नीति संक्षेप और सीपीआरएचई अनुसंधान रिपोर्ट एवं सीपीआरएचई अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठयां (स्प्रिंगर नेचर, सिंगापुर, द्वारा प्रकाशित) थी। गतिविधियों का विवरण नीचे वर्णित है:

अनुसंधान

अनुभवजन्य अनुसंधान अपने संकाय सदस्यों द्वारा किए गए सीपीएचआरई की सबसे प्रमुख गतिविधि है। सीपीएचआरई ने अनुभवजन्य अध्ययनों के पहले चक्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिसमें उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेश; भारतीय उच्च शिक्षा में अध्यापन और अधिगम; भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन; भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों का वित्तपोषणः धन प्रवाह और उनका उपयोग; संस्थागत स्तर पर बाहरी और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन और उच्च शिक्षा स्नातकों की रोजगार और रोजगारशीलता का अध्ययन से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। ये बड़े पैमाने पर, बहु–संस्थागत अध्ययन भारत के 22 राज्यों में स्थित चुनिंदा संस्थानों में लागू किए गए हैं। करीब 35 शोध रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं और अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।

मा.सं.वि. मंत्रालय/वि.अ.आयोग के अनुरोध पर अनुसंधान परियोजनाएंः सीपीएचआरई अनुसंधान अध्ययनों के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुरोध पर अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन कर रहा है। जिसमें 4.8 मिलियन उम्मीदवारों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के परिणामों का विश्लेषण; पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन; भारत में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिपूर्ति और एकाग्रता का अध्ययन; 1949 में (मा.सं.वि. मंत्रालय के अनुरोध पर) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप (एनआरपी) योजना का मूल्यांकन और यूजीसी के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) पर अवधारणा नोट तैयार किया।

मा.सं.वि. मंत्रालय के अनुरोध पर, सीपीएचआरई ने भारत में निजी मानद् विश्वविद्यालयों में शुल्क नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन पूरा किया। यह परियोजना पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में लागू की गई थी। रिपोर्ट मा.सं.वि. मंत्रालय को सौंप दी गई है और अध्ययन से एक सीपीएचआरई शोध पत्र तैयार किया जा रहा है।

यूजीसी के अनुरोध पर, केंद्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग योजनाओं का बड़े पैमाने पर मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के अनुरोध पर, सीपीआरएचई वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र विविधता और सामाजिक समावेश के आयामों पर मॉड्यूल तैयार कर रहा है। मॉड्यूल मुख्य रूप से सीपीआरएचई शोध अध्ययन पर आधारित हैं, जिसका शीर्षक 'नागरिक अधिगम और लोकतांत्रिक कार्यों के लिए उच्च शिक्षाः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव का अध्ययन' है। मॉड्यूल का उद्देश्य छात्र शिक्षा, शैक्षिक एकीकरण और सामाजिक समावेश से संबंधित मुद्दों पर उच्च शिक्षा में संकाय और प्रशासकों को संवेदनशील बनाना है, जिसमें नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक जुड़ाव में उच्च शिक्षा की भूमिका शामिल है। मॉड्यूल निम्नलिखित विषयों पर विकसित किए जा रहे हैं:

मॉड्यूल 1: उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेशः अवधारणा और दृष्टिकोण

मॉड्यूल 2: उच्च शिक्षा में छात्र विविधता का वर्गीकरण

मॉड्यूल 3: परिसरों पर अकादमिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण

मॉड्यूल 4: उच्च शिक्षा में भेदभाव के रूप

मॉड्यूल 5: परिसर में सामाजिक समावेश

मॉड्यूल 6: छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

मॉड्यूल 7: छात्र विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक कार्य

मॉड्यूलों की तैयारी कार्य प्रगति पर है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं: वर्ष 2020–21 में, सीपीआरएचई ने दो अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं पर शोध रिपोर्ट भी पूरी की, और संबंधित विषयों पर वेबिनार का आयोजन किया। पूरी की गई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं:

(अ) उच्च शिक्षा में अनियत अधिगम मार्ग की योजना (आईआईईपी–यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से)। उच्च शिक्षा में अनियत अधिगम मार्ग की योजना: भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर पर एक वेबिनार 20 नवंबर 2020 को आईआईईपी–यूनेस्को के सहयोग से आयोजित किया गया था।

(ब) असमानताएं और उच्च शिक्षा: सार्वजनिक नीतियों और निजी क्षेत्र के विकास के बीच (ईएसपीआई, पेरिस के सहयोग से)। 2020 में इसे परियोजना के भाग के रूप में तैयार किया गया और शोध निर्गत तैयार कर लिए गए हैं: अनुभवजन्य अध्ययन पर आधारित 3 मोनोग्राफ और 1 शोध रिपोर्ट।

नए अनुसंधान क्षेत्र: वर्ष 2020–21 में, इसकी कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान के दूसरे दौर के लिए सीपीआरएचई अनुसंधान प्रस्तावों को निम्नलिखित विषयों पर अंतिम रूप दिया जा रहा है:

i) भारत में उच्च शिक्षा में कॉलेज की तैयारी और छात्र सफलता

ii) भाषा और असमानताएं: भारत में उच्च शिक्षा में भाषाई विविधता और छात्र सफलता का एक अध्ययन

iii) उच्च शिक्षा में नया प्रबंधकीयवाद: भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों का बदलता प्रबंधन

iv) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का वित्त पोषण: भारत में सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन

v) भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण और सीखने के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरण

vi) उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के रूप में शिक्षाविदों का व्यावसायीकरण।

प्रकाशन

अनुसंधान के अलावा, वर्ष 2020–2021 में सीपीआरएचई द्वारा चार नियमित गतिविधियाँ की गईं। इनमें सेज द्वारा प्रकाशित इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट (आईएचईआर) तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना, अनुसंधान पत्र श्रृंखला का प्रकाशन, सीपीआरएचई नीति संक्षेप तैयार करना और सीपीआरएचई अनुसंधान के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का आयोजन शामिल है।

भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट: पांच आईएचईआर पहले ही देश में उच्च शिक्षा के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों से संबंधित विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें समता, शिक्षण–शिक्षण और गुणवत्ता, उच्च शिक्षा के वित्तपोषण, और शासन और प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2020–21 में, सेज द्वारा शासन और प्रबंधन पर पांचवां आईएचईआर प्रकाशित किया गया था और उच्च शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगार पर छठे आईएचईआर को रूटलेज द्वारा प्रकाशित करने के लिए प्रेस में भेजा गया था। इसके अलावा वर्ष 2020–21 में, सीपीआरएचई ने सातवीं भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2021 की तैयारी शुरू की, जो 'भारत में निजी उच्च शिक्षा' पर केंद्रित है। रिपोर्ट को रूटलेज द्वारा प्रकाशित किए जाने की तैयारी चल रही है। सीपीआरएचई की योजना 'भारत में उच्च शिक्षा में महिलाएं' विषय पर भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2022 का अगला अंक तैयार करने की भी है।

सीपीएचआरई द्वारा आयोजित संगोष्ठियों पर आधारित प्रकाशन: इसके अलावा, सीपीआरएचई का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुत पत्रों को प्रकाशित करना भी है। उदाहरण के लिए, 2020–21 में, स्प्रिंगर नेचर द्वारा टीचिंग–लर्निंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन हायर एजुकेशन पर एक वॉल्यूम प्रकाशित किया गया है, जबकि उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचारों पर वॉल्यूम स्प्रिंगर नेचर के साथ प्रेस में है।

सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखलाः केंद्र 'सीपीआरएचई शोध पत्र' शीर्षक से एक नियमित प्रकाशन श्रृंखला निकालता है। केंद्र पहले ही श्रृंखला के तहत 14 पत्र प्रकाशित कर चुका है। वर्ष 2020–21 में, सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला उन विषयों पर प्रकाशित की गई जिनमें निजी उच्च शिक्षा में फीस और स्नातक रोजगार और रोजगार पर शामिल थे।

सीपीआरएचई नीति का संक्षिप्त विवरणः सीपीआरएचई अनुसंधान चक्र में, चयनित शोध विषयों पर नीतिगत संक्षिप्त विवरण तैयार करना संस्थागत परिवर्तन के लिए संस्थागत स्तर की निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ अनुसंधान–आधारित जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में माना जाता है। नीति के संक्षिप्त विवरण मुख्य रूप से केंद्र द्वारा पूर्ण किए गए शोध अध्ययनों और अन्य संगठनों द्वारा इसी तरह के अध्ययनों पर आधारित होते हैं। 'नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक जुड़ाव के लिए उच्च शिक्षाः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और सामाजिक समावेशन का एक अध्ययन' पर अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, सीपीआरएचई ने नीतिगत संक्षिप्त विवरण तैयार किए हैं जिनका शीर्षक हैः सीपीआरएचई नीति संक्षिप्त 1: भारत में उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की समानता; सीपीआरएचई नीति संक्षिप्त 2: भारत में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक एकीकरण प्राप्त करना; सीपीआएचई नीति संक्षिप्त 3: भारत में सामाजिक रूप से समावेशी उच्च शिक्षा परिसरों का विकास करना। इनका हिंदी में अनुवाद किया गया है और यूजीसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पॉलिसी ब्रीफ का लिंक निम्नलिखित हैः

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/8714294_CPRHE-POLICY-BRIEF-1-Diversity-and-Inclusion-in-HE.pdf

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4755136_CPRHE-POLICY-BRIEF-2-Diversity-and-Inclusion-in-HE.pdf

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/0373387_CPRHE-POLICY-BRIEF-3-Diversity-and-Inclusion-in-HE.pdf

अनुसंधान रिपोर्टः केंद्र द्वारा पूर्ण किए गए शोध अध्ययनों के आधार पर, सीपीएचआरई शोध रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सीपीएचआरई द्वारा 35 शोध रिपोर्ट तैयार की गई हैं जिसमें मा.सं.वि. मंत्रालय और यूजीसी द्वारा अनुरोध पर शोध अध्ययन के लिए रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शोध रिपोर्ट और मोनोग्राफ शामिल हैं। वर्ष 2020–21 में कुछ सिंथेसिस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और राज्य अनुसंधान रिपोर्ट को सीपीएचआरई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

सीपीआरएचई वेबिनार और ऑनलाइन बैठकेंः वर्ष 2020–21 में, सीपीआरएचई ने ऑनलाइन बैठकों सहित 7 वेबिनार का आयोजन किया। इनमें भारत में निजी उच्च शिक्षा विषय पर आईएचईआर (2021) के लेखकों के साथ दो बैठकें शामिल हैं। वर्ष 2020–21 में आईआईईपी, पेरिस और ईएसपीआई, पेरिस के साथ दोनों अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए समय–समय पर ऑन–लाइन बैठकें भी हो रही हैं, जहां सीपीएचआरई के संकाय सदस्यों ने भाग लिया है।

वेबिनार के संबंध में, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने पर एक वेबिनार यूजीसी के सहयोग से आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों को वक्ताओं के रूप में एक साथ लाया गया था। वेबिनार में 130 से अधिक प्रतिभागियों के साथ वेबिनार में व्यापक भागीदारी थी, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल थे। सीपीएचआरई द्वारा आयोजित एक और बहुत ही सफल वेबिनार फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे (जो आईआईईपी, पेरिस के सहयोग से था) पर था।

सीपीआरएचई ने 15 दिसंबर 2020 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार पर एक नीति संवाद वेबिनार का भी आयोजन किया। नीति संवाद सीपीआरएचई नीति संक्षिप्त पर आधारित था जो मुख्य रूप से छात्र विविधता और सामाजिक समावेश पर सीपीआरएचई अध्ययन से उभरने वाले अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित था।

केंद्र ने राज्य उच्च शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) के साथ नियमित परामर्श बैठकें भी आयोजित की हैं। रूसा के कार्यान्वयन में और वास्तव में राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के व्यापक विकास में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की केंद्रीय भूमिका है। वर्ष 2020–2021 में, एसएचईसी की बैठक 18 और 19 मार्च, 2021 को हुई थी। बैठक में 11

राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें राज्य परिषदों के उपाध्यक्ष, कॉलेजिएट शिक्षा निदेशालय और राज्यों में उच्च शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 2019 में आयोजित एसएचईसी पर सलाहकार बैठक की एक रिपोर्ट भी वर्ष 2020–21 में प्रकाशित की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठीः केंद्र हर साल सीपीआरएचई में खोजे जा रहे अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य विश्व स्तर पर पहचाने गए विषय पर काम कर रहे शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। सीपीआरएचई द्वारा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से छह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2020–2021 में, ''उच्च शिक्षा में विविधता, समावेश और छात्र सफलता'' पर सातवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो निर्धारित की गई थी, को कोविड यात्रा प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया था। उम्मीद है कि हम फरवरी 2022 में सेमिनार का आयोजन करने में सक्षम होंगे।

सीपीएचआरई प्रत्येक संगोष्ठी पर एक विषयगत रिपोर्ट लाता है और संगोष्ठी में प्रस्तुत चयनित पत्रों के आधार पर एक वास्तविक वाल्यूम की योजना भी बनाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में होने वाली चर्चाओं से उभरने वाली कार्यवाही और विषयों पर सात सीपीआरएचई संगोष्ठी रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं। वर्ष 2020–21 में गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन' नामक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सीपीआरएचई संगोष्ठी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

नीति समर्थन

सीपीएचआरई नियमित रूप से मा.सं.वि. मंत्रालय, यूजीसी, नीति आयोग और अन्य उच्चतर शिक्षा नीति निर्माताओं जैसे निर्णय लेने वाले निकायों को नीतिगत दस्तावेज तैयार करने और नीति स्तर की चर्चाओं में भाग लेने के माध्यम से उनके अनुरोध पर अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन करके नीति समर्थन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में, केंद्र ने टीएसआर सुब्रमण्यम समिति (शिक्षा नीति तैयार करने के लिए गठित समिति) के लिए विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से दस्तावेज तैयार किए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (कस्तूरीरंगन समिति) के लिए मसौदा समिति की चर्चा में भागीदारी और, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद की। मा.सं.वि. मंत्रालय के अनुरोध पर केंद्र ने पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक और शिक्षण पर राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), भारत में उच्च और तकनीकी संस्थानों की एकाग्रता और कम आपूर्ति पर अध्ययन और भारत में निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों में फीस का निर्धारण जैसे कई मूल्यांकन अध्ययन भी पूरे किए हैं और यूजीसी के अनुरोध पर यूजीसी कोचिंग योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया है। केंद्र ने एनईपी 2020 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए नीपा द्वारा विकसित कार्यान्वयन रणनीति दस्तावेज में योगदान दिया है। राष्ट्रीय ऋण ढांचे के विकास पर शिक्षा मंत्रालय की समिति को समर्थन देने के लिए केंद्र नीपा में सचिवालय का भी सदस्य है। केंद्र को विभिन्न नीति बैठकों में आमंत्रित और प्रतिनिधित्व किया जाता है।

अतिथि अध्येता कार्यक्रम

भारत और विदेशों से अंतरराष्ट्रीय संकाय सदस्यों और शोध विद्वानों को आकर्षित करने और उनकी मेजबानी के उद्देश्य से केंद्र ने तय शर्तों के साथ अतिथि अध्येताओं को आमंत्रित करने का प्रावधान किया है। केन्द्र के पहले विजिटिंग प्रोफेसर विलियम जी. टियरनी थे, जो विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं और वर्तमान में उच्च शिक्षा के विल्बर–कैफर प्रोफेसर और सह–निदेशक, पुलियास सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, रॉसियर स्कूल ऑफ एजुकेशन, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोफेसर हैं। वर्ष 2019–20 में, सीपीआरएचई ने प्रोफेसर विलियम जी. टियरनी की फिर से एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में मेजबानी की। सीपीआरएचई ने संकाय सदस्यों डा. हेंडरसन, इंस्टीट्यूट ऑफ वारविक और रिसर्च फेलो, सुश्री अंजलि थॉमस, इंस्टिट्यूट ऑफ वारविक, यूके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस्स) से पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के स्नातक छात्र श्री शशांक एस.आर., और सुश्री अंजलि अनिल की भी मेजबानी की। फरवरी 2020 में, सीपीआरएचई को प्रोफेसर तेबोहो मोहजा की मेजबानी करने का अवसर मिला, जो एक प्रोफेसर और कार्यक्रम निदेशक, उच्च शिक्षा, न्यूयॉर्क संस्थान से हैं। प्रोफेसर आर्थर लेविन, फुलब्राइट नेहरू प्रतिष्ठित पीठ और अध्यक्ष एमेरिटस, वुडरो विल्सन फाउंडेशन, प्रिंसटन, न्यू जर्सी,

यूएसए को वर्ष 2020–21 में सीपीआरएचई में अतिथि प्रोफेसर के रूप में शामिल होना था। हमें सूचित किया जाता है कि कोविड की स्थिति में सुधार होने पर प्रोफेसर लेविन सीपीआरएचई में शामिल हो जाएंगे।

वर्ष 2020–21 के दौरान सीपीआरएचई प्रकाशनों की सूची

सीपीआरएचई द्वारा निकाले प्रकाशनों की सूची नीचे दी गई है। इस सूची में अकादमिक पत्रिकाओं और पुस्तकों में व्यक्तिगत संकाय सदस्यों द्वारा कई प्रकाशन शामिल नहीं हैं। संकाय सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान पृष्ठ संख्या 9 से प्रारंभ होता है।

भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट

1. ***भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2021:*** भारत में निजी उच्च शिक्षा; एन.वी. वर्गीज और जिनुशा पाणिग्रही द्वारा संपादित (तैयारी जारी: रूटलेज द्वारा प्रकाशित किया जाना है)।
2. ***भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2020:*** एन.वी.वर्गीज और मोना खरे द्वारा संपादित; उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता (प्रेस में: रूटलेज द्वारा प्रकाशित किया जाएगा)।
3. ***भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2019:*** उच्च शिक्षा का शासन और प्रबंधन: एन.वी.वर्गीज और गरिमा मलिक, सेज, नई दिल्ली, 2020 द्वारा संपादित।

सीपीआरएचई द्वारा आयोजित संगोष्ठियों पर आधारित प्रकाशन:

1. उच्च शिक्षा में शिक्षण–अधिगम और नई तकनीकें; एन.वी. वर्गीज और सायंतन मंडल द्वारा संपादित। स्प्रिंगर नेचर 2020।
2. एन.वी. वर्गीज और जिनुशा पाणिग्रही द्वारा संपादित; उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचार (स्प्रिंगर नेचर, प्रेस में)

सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला

शोध पत्रों की सूची इस प्रकार है:

1. मोना खरे द्वारा स्नातक रोजगार और भारत में सतत रोजगार कौशल। सीपीएचआरई रिसर्च पेपर्स 14, नई दिल्ली, सीपीएचआरई/नीपा, 2020।
2. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क: जिणुशा पाणिग्रही द्वारा भारत में मानित विश्वविद्यालयों का एक अध्ययन। सीपीएचआरई रिसर्च पेपर 13, नई दिल्ली, सीपीएचआरई/नीपा, 2020।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी रिपोर्ट श्रृंखला

1. एन वी वर्गीज और गरिमा मलिक द्वारा ''उच्च शिक्षा में शासन और स्वायत्तता'' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर रिपोर्ट। (ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से आयोजित), सीपीएचआरई/नीपा, नई दिल्ली। 2020।

सीपीआरएचई अनुसंधान रिपोर्ट

1. चुनौतियों को अवसरों में बदलना: डॉ गरिमा मलिक और प्रोफेसर नारायणन अन्नालक्ष्मी द्वारा भारतीय उच्च शिक्षा में लचीले शिक्षण पथ, अनुसंधान रिपोर्ट, सीपीआरएचई–नीपा/आईआईईपी–यूनेस्को, पेरिस, 2020।
2. डॉ गरिमा मलिक, नई दिल्ली, सीपीआरएचई/नीपा द्वारा ''भारत में उच्च शिक्षा का शासन और प्रबंधन''। संश्लेषण रिपोर्ट। 2020।
3. ईएसपीआई इंडिया रिपोर्ट: प्रोफेसर ओडिले हेनरी, डॉ जिनुशा पाणिग्रही और डॉ निधि एस सभरवाल, ईएसपीआई, पेरिस/सीपीआरएचई–नीपा, नई दिल्ली द्वारा भारत में उच्च शिक्षा और सामाजिक असमानता। 2020।
4. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (आईईएसपी) का मोनोग्राफ, मणिपाल विश्वविद्यालय, कर्नाटक, भारत का एक मामला डॉ जिनुशा पाणिग्रही, सीपीआरई/नीपा द्वारा ईएसपीआई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए आईआरडी–सीईपीईडी को प्रस्तुत मोनोग्राफ–2020।
5. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (आईईएसपी) का मोनोग्राफ मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा, भारत का एक मामला डॉ जिणुशा पाणिग्रही, सीपीआरएचई/नीपा द्वारा। ईएसपीआई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए आईआरडी–सीईपीईडी को मोनोग्राफ प्रस्तुत किया गया। 2020।
6. निजी उच्च शिक्षा संस्थानों (आईईएसपी) का मोनोग्राफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उत्तर प्रदेश, भारत का एक मामला डॉ जिणुशा पाणिग्रही, सीपीआरएचई/नीपा द्वारा। ईएसपीआई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना 2020 के लिए

आईआरडी–सीईपीईडी को मोनोग्राफ प्रस्तुत किया गया।

सीपीआरएचई द्वारा वर्ष 2020–21 में आयोजित बैठकों एवं कार्यशालाओं की सूची

1. 14 जुलाई, 2020 को शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और अधिकारिता को आगे बढ़ाने पर वेबिनार (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से आयोजित)।
2. आईएचईआर 2021: भारत में निजी उच्च शिक्षा पर पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक 21 सितंबर, 2020 को आयोजित।
3. लचीले शिक्षण पथ पर वेबिनारः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर 20 नवंबर, 2020 (आईआईईपी–यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से आयोजित) को आयोजित किया गया।
4. भारत में उच्च शिक्षा में विविधता और समावेश पर नीति वार्ता वेबिनार 15 दिसंबर, 2020 को आयोजित किया गया था।
5. आईएचईआर 2021: भारत में निजी उच्च शिक्षा पर दूसरी सहकर्मी समीक्षा बैठक 17 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई।
6. राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक 18–19 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी।
7. सीपीएचआरई कार्यकारी समिति की बैठक 12 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र 2020–2021

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (PMMMNMTT) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसीई) की स्थापना 16 जनवरी, 2018 को की गई है। एनआरसीई, (PMMMNMTT) के तहत विशिष्ट रूप से एक ऐसा केंद्र है। इस योजना की परिकल्पना विकासशील शिक्षकों की दृष्टि से एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई है जो प्रतिस्पर्धी ज्ञान की दुनिया में अनुसंधान, नेटवर्किंग और मौजूदा संसाधनों को साझा करने के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाने और ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं।

एनआरसीई के उद्देश्य शिक्षकों के उपयोग के लिए शिक्षकों के लिए सभी संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार विकसित करना; ज्ञान संसाधनों के उपयोग के माध्यम से शिक्षकों की कार्यात्मक क्षमताओं का विकास करना; शिक्षकों की उन्नत क्षमताओं के माध्यम से छात्रों के समग्र विकास को बढ़ाना; और भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा में शिक्षकों के बीच नेटवर्किंग विकसित करना।

संसाधनों को इकट्ठा करने के साथ–साथ बनाने के अपने दृष्टिकोण में, एनआरसीई, चार घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है– विषयवार संसाधन, शिक्षण शिक्षण संसाधन, अनुसंधान संसाधन और छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण, और सलाहकार, कानूनी और साथ ही आईटी समितियों द्वारा विधिवत निर्देशित समर्थन, ने वर्ष 2020–2021 में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कोविड 19 महामारी के बावजूद, एनआरसीई ने वर्चुअल मोड के माध्यम से विषय–वार संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अपनी टियर टू और फाइनलाइजेशन कार्यशालाओं को सुचारू रूप से संचालित किया।

एनआरसीई 11.06.2020 को मूडल प्लेटफॉर्म पर अपने वेब पोर्टल का उद्घाटन करने में सक्षम था। वेबसाइट अब एक समृद्ध संसाधन भंडार के रूप में है, जिसमें जीवन विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा और प्रबंधन संसाधनों के साथ–साथ शिक्षण– सीखना और अनुसंधान जैसे दस विषयों के विषयवार संसाधनों की मेजबानी है। केंद्र ने विषयवार संकाय संवर्धन वेबिनार भी आयोजित किए, जिसमें पूरे भारत के शिक्षकों ने भाग लिया। एनआरसीई ने अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के साथ की अपनी निर्देशिका का संचालन करने के अलावा, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट संकलित की है।

एनआरसीई ने उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए क्षेत्रीय समझ को बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के विकसित नेटवर्किंग के लिए एक मंच होने के अलावा, हितधारकों के दृष्टिकोण (छात्रों) को भी सामने लाने में एक शानदार योगदान दिया है। केंद्र पूरे भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के विषयवार नेटवर्क को सक्षम करने में एक अच्छी शुरुआत करने में सक्षम रहा है। केंद्र उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अपने भंडार में अधिक विषय संसाधनों को जोड़ने के साथ–साथ अन्य विषयों में विशेषज्ञों की एक निर्देशिका विकसित करने और एनईपी, 2020 के साथ अपने उद्देश्यों को संरेखित करने की दिशा में काम करके अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहता है। उच्च शिक्षा अध्यापन और शिक्षण–अधिगम पर ध्यान दें।

एकक

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग एक अधिकार–आधारित और समावेशी ढांचे के भीतर स्कूली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सहित स्कूली शिक्षा के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। विभाग के प्रमुख कार्य हैं: स्कूल, ईसीसी, शिक्षक, शिक्षक शिक्षा के पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए। केंद्र और राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों आदि के लिए अनुसंधान और विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और परामर्श।

विभाग भारत में शिक्षा के विकास और सुधार के लिए सार्थक इनपुट का योगदान करने के लिए एक अनुभवजन्य आधार प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा क्षेत्र, ईसीसी, शिक्षक और शिक्षक शिक्षा के विविध क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करता है। विभाग सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञान, दक्षताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों में भी लगा हुआ है। सहक्रियात्मक संबंध स्थापित करने के लिएय विभाग स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुभव और विशेषज्ञता को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा, यह एक सलाहकार भूमिका निभाता है और योजनाओं और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में राज्य और केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करता है।

संस्थान का एक प्रमुख और सबसे पुराना विभाग होने के नाते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), कार्य योजना (1992), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) और सभी के लिए शिक्षा (इएफए) के निर्माण में इसके पेशेवर योगदान का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2007–2011 के दौरान, 'शैक्षणिक पहुंच, संक्रमण और इक्विटी पर अनुसंधान के लिए मंच' (www.create-rpc.org) के भाग के रूप में विभाग ने 'शैक्षिक पहुंच' के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ओर बड़ी योजना, भारत में सभी के लिए शिक्षा का मध्य दशक का मूल्यांकन पूरा किया गया एक राष्ट्रीय रिपोर्ट, कई विषयगत अध्ययन और ईसीसीई पर छह ईएफए लक्ष्यों में से प्रत्येक के लिए राज्य–समीक्षा, प्राथमिक शिक्षा, युवाओं और वयस्कों के लिए सीखने और जीवन कौशल वयस्क साक्षरता और लैंगिक समानता को तैयार किया गया है। विभाग एसएसए, आरएमएसए

और केंद्र प्रायोजित शिक्षक शिक्षा (सीएसटीई) के लिए नीतिगत सिफारिशों में भी योगदान दे रहा है।

परियोजना प्रबंधन एकक

राष्ट्रीय संस्थान में परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) की स्थापना गृह स्तर एवं प्रायोजित अनुसंधान के समर्थन और प्रबंधन के उद्देश्य से की गई थी। यह एकक शिक्षा नीति और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन (व्यक्तिगत शोध) के क्षेत्र में अध्ययन के लिए नीपा सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु नीपा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अध्ययन सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिये अनुदान सहायता योजना विभाग के सभी बाह्य वित्त–पोषित और आंतरिक अनुसंधान परियोजनाओं के उचित समन्वय के लिये प्रशासन की एक केन्द्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

यह एकक सामान्य रूप से, परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और संबंधित समर्थन सेवाएँ प्रदान करने सहित नीपा में किए गए विभिन्न परियोजनाओं के प्रबंधन के लिये प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। यह सभी मामलों में धन और घरेलू व्यय के लेखा सहित नीपा – परियोजना भर्ती और नियुक्तियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।

पीएमयू विभिन्न परियोजनाओं के लेखांकन, परियोजना स्टाफ की भर्ती, बजट के अलावा संस्थान में चल रहे और पूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित सभी कार्य की देखभाल करता है।

पीएमयू एकक में अध्यक्ष, कुलपति द्वारा चयनित किया जाता है। इसके अलावा पांच अन्य अकादमिक तथा समर्थन स्टाफ भी चयनित किये जाते हैं। समर्थन स्टाफ में परियोजना परामर्शदाता, परियोजना प्रबंधक तथा कनिष्ठ परामर्शदाता सम्मिलित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एकक

भारत की योजना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए खुद को एक पसंदीदा गंतव्य बनाने और अंततः अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने की है। देश अपने अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने का भी इच्छुक है और इसने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन (SPARC) और ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (GIAN)। कोलंबो योजना और आई टी ई सी जैसे पुराने कार्यक्रमों ने एक ठोस नींव रखी है जिस पर वर्तमान प्रयासों का निर्माण करना है। भारत में पहले से ही प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों, बहुपक्षीय निकायों और द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ शैक्षिक सहयोग गतिविधियां हैं। यह उन नेटवर्क विश्वविद्यालयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो पहले ही स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत की नेतृत्व क्षमता को तब महसूस किया जा सकता है जब यह वैश्विक पहलों की योजना और वित्तपोषण दोनों में सक्रिय रूप से संलग्न हो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अग्रणी भूमिका निभाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट सहयोग व्यवस्थाओं के संदर्भ का विश्लेषण प्रदान करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, अनुभवजन्य साक्ष्य की पीढ़ी, दस्तावेजों की तैयारी और शिक्षा मंत्रालय

को नियमित प्रतिक्रिया। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है और यह एनआईईपीए में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इकाई (यूआईसी) की स्थापना के लिए संदर्भ बनाता है।

यूआईसी के मुख्य कार्य

एकक की समग्र जिम्मेदारी शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों पर अपने अनुसंधान और प्रलेखन, सलाहकार और निगरानी भूमिका के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों को समर्थन प्रदान करना है। अधिक विशेष रूप से, एकक के निम्नलिखित कार्य हैं:

1. शिक्षा के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग में प्रवृत्तियों और पैटर्न का विश्लेषण और दस्तावेज करना।
2. शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में बैठकों में आधिकारिक भागीदारी के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेज और संक्षिप्त विवरण तैयार करने में मदद करना
3. शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की अंतर्सरकारी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ भारत की नेटवर्क गतिविधियों का समन्वय और सुदृढ़ीकरण करना।
4. शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जा सकने वाले सहयोग के कार्यक्रमों के डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी में मदद करना।
5. प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार करना।

यूआईसी में एक सलाहकार, पांच उप सलाहकार, एक कनिष्ठ परियोजना सलाहकार और एक कंप्यूटर सहायक है। सलाहकार इकाई का प्रभारी होता है और इसकी गतिविधियों का समन्वय करता है। प्रोफेसर के. रामचंद्रन यूआईसी के वरिष्ठ सलाहकार हैं। एकक का नेतृत्व नीपा के कुलपति करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ (आईसीसी) की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर, सलाहकार और उप सलाहकारों को निम्नलिखित कार्यात्मक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।

क्र. सं.	वर्टिकल का नाम	व्यापक जिम्मेदारियां
1.	अमेरिका (उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन)	जी–20, ई–9, और अमेरिका के भीतर देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/एमओयू से संबंधित कार्य/मामलों का समर्थन करना।
2.	यूरोप	यूरोपीय संघ, ओईसीडी, और यूरोप के भीतर देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/एमओयू से संबंधित कार्य/मामलों का समर्थन करना।
3.	एशिया प्रशांत (पूर्वी एशिया, दक्षिण–पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर)	एसीडी, ब्रिक्स, आसियान, आईबीएसए, और एशिया प्रशांत के देशों और एसीडी, ब्रिक्स, आसियान और आईबीएसए के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों से संबंधित कार्य/मामलों का समर्थन करना
4.	अन्य एशिया क्षेत्र (दक्षिणी एशिया, काकेशस, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया)	राष्ट्रमंडल, एससीओ, बिम्सटेक, सार्क, और एससीओ, बिम्सटेक और सार्क के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों से संबंधित कार्य/मामलों का समर्थन करना।
5.	अफ्रीका (उप–सहारा अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका)	अफ्रीकी संघ, अफ्रीका में देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों/एमओयू से संबंधित कार्य का समर्थन करता है।
6.	यूनेस्को	यूनेस्को, एएसईएम

अनुसंधानः दस्तावेजीकरण और विश्लेषण

यूआईसी ने चार व्यापक परियोजनाओं को अंजाम दिया, जिसमें एशिया प्रशांत, अफ्रीका, अन्य एशिया, यूरोप और अमेरिका सहित सभी क्षेत्रों के लिए डेटा संग्रह, प्रलेखन और विभिन्न, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और देश स्तर के शिक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण शामिल था। उन सभी को शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध के आधार पर किया गया था।

देश तथ्य पत्रक

2019–20 में शुरू की गई देश तथ्य पत्रक परियोजना जिसमें मार्च 2020 तक के डेटा शामिल हैं, को अद्यतन किया गया है और फरवरी 2021 तक जहां कहीं भी उपलब्ध है, अद्यतन जानकारी के साथ पूरा किया गया है।

देश प्रोफाइल

यह एकक विश्व के सभी क्षेत्रों से 206 देशों और क्षेत्रों के विस्तृत देश प्रोफाइल तैयार करने में भी शामिल रही है। काम कई चरणों में आयोजित किया गया है जैसे कि पहले चरण में वे देश शामिल हैं जो तीन शिक्षा मंत्रालय कार्यक्रमों – ज्ञान, एसआईआई और स्पार्क में भाग ले रहे हैं या शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन है।

प्रत्येक देश प्रोफाइल में शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित देश के साथ भारत के सहयोग के साथ–साथ देश की शिक्षा प्रणाली, नामांकन डेटा (स्कूल के साथ–साथ उच्च शिक्षा), छात्र गतिशीलता डेटा, साथ ही साथ इसके सामाजिक विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। – आर्थिक स्थिति, आदि। प्रत्येक देश की प्रोफाइल लगभग 5–10 पृष्ठ लंबी होती है। वर्तमान में, अन्य एशिया के 18 देशों और एशिया प्रशांत से 6 देशों के देश प्रोफाइल को पूरा कर लिया गया है और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

भारत और नेटवर्क विश्वविद्यालय अवधारणा

भारत नेटवर्क विश्वविद्यालय की अवधारणा के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रीय समकक्षों के साथ जुड़ रहा है, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं:

- ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय (ब्रिक्स एनयू)
- आसियान–भारत विश्वविद्यालयों का नेटवर्क
- एससीओ नेटवर्क विश्वविद्यालय
- रूस भारत नेटवर्क (आरआईएन)
- हिंद महासागर रिम विश्वविद्यालय नेटवर्क (आईओआरयूएन)

नेटवर्क यूनिवर्सिटी पर यूआईसी परियोजना इस प्रश्न पर आधारित है: ''बहुपक्षीय संगठनों में नेटवर्क विश्वविद्यालय की अवधारणाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए''। इस संदर्भ में, चार नेटवर्क विश्वविद्यालयों के संबंध में नोट्स को पूरा कर लिया गया है और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, इसके लिए एक मसौदा रूपरेखा विभिन्न नेटवर्क विश्वविद्यालयों की सारणीबद्ध रूप में तुलना करके तैयार किया गया है और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

सहयोग के लिए संभावित प्राथमिकता वाले देश–उच्च प्राथमिकता वाले देश

''प्राथमिकता वाले देशों'' पर परियोजना में कुछ ऐसे देशों की पहचान शामिल है जिन्हें राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में वृद्धि के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े हुए सहयोग को प्राप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता, मध्यम प्राथमिकता और कम प्राथमिकता दी जा सकती है और भारतीय शिक्षकों, विशेषज्ञों, विद्वानों, आदि के लिए रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। परियोजना के पहले चरण में उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र/उप–क्षेत्र से एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 13 देशों पर नोट्स शामिल थे। नोट्स का एक संशोधन बाद में इस समझ के साथ किया गया कि देशों का चयन पांच क्षेत्रों और न ही उप–क्षेत्रों के अनुसार होना चाहिए। परिणामस्वरूप कुछ और देशों को जोड़ा गया। मुख्य मानदंड किसी भी देश को देखना था जिसके साथ भारत को तत्काल शिक्षा सहयोग की आवश्यकता है। ऐसा कि शैक्षिक सहयोग न केवल शिक्षा संबंधी सहयोग बल्कि राजनयिक लाभ/सॉफ्ट पावर में भी मिलेगा। दूसरा मसौदा पूरा कर लिया गया है और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें निम्नलिखित 16 देशों के नोट्स शामिल थे:

- एशिया प्रशांत – ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और म्यांमार
- अन्य एशिया – बांग्लादेश, कजाकिस्तान और सऊदी अरब
- अफ्रीका – मिस्र, नाइजीरिया, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका
- यूरोप – यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क

अनुसंधानः समसामयिक नीति मुद्दों के साथ जुड़ाव

यूआईसी ने नीति संबंधी चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया। जबकि दो परियोजनाएं, एक एनईपी 2020 के संदर्भ में और दूसरी पल्स सर्वेक्षण के संबंध में पूरी हो चुकी हैं, दूसरी में पांच अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों (आईबीसी) के केस स्टडीज को 2020 के अंत में शुरू किया गया था और इसे 2021 में आगे बढ़ाया जा रहा है।

भारत के लिए कोविड–19 और उच्च शिक्षा चुनौतियां और अवसर

मार्च 2020 में, कोविड–19 के प्रकोप के चरम पर, यूआईसी ने दुनिया भर में उच्च शिक्षा प्रणालियों पर महामारी और आगामी लॉकडाउन के प्रभाव पर एक अध्ययन शुरू किया। शोध परियोजना का शीर्षक था ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर''। पहला मसौदा निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए पूरा किया गया थाः यूनेस्को, एएसईएम, यूरोप, एशिया प्रशांत, दक्षिण एशिया और अफ्रीका, साथ ही भारत, मई 2020 में। हालांकि, महामारी की गतिशील और तेजी से बदलती गति और इसके प्रभाव ने अध्ययन को एक कठिन प्रस्ताव बना दिया। यह निर्णय लिया गया है कि निकट भविष्य में भारत का सबक लेकर वैश्विक छात्र गतिशीलता पर कोविड–19 के प्रभाव पर एक अनुवर्ती अनुभवजन्य अध्ययन किया जाएगा जब स्थिति स्थिर हो जाती है और गहन शोध के लिए अनुकूल हो जाएगी।

एनईपी 2020ः कार्यान्वयन रणनीतियाँ–भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों का संचालन

यूआईसी ने नीपा के नेतृत्व वाली ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः कार्यान्वयन रणनीतियाँ'' में भाग लिया, जिसमें यूआईसी सहित नीपा के सभी विभागों और संकायों का योगदान था। यूआईसी वर्किंग ग्रुप का विषय ''भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों का संचालन'' था। एनईपी कोर कमेटी को प्रस्तुत किए गए वर्किंग पेपर का अंतिम मसौदा आठ खंडों के साथ 10 पृष्ठों की लंबाई का है।

वर्किंग पेपर ने भारत सरकार और उसके विभिन्न नियामक निकायों द्वारा ''दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों ... अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों (आईबीसी) की स्थापना करने हेतु सिफारिशें दीं। अन्य बातों के अलावा, इसने अपनाई जाने वाली रणनीतियों, प्रोत्साहनों की भूमिका, आदर्श नियामक वातावरण और भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों की स्थापना के लिए प्रक्रियाओं पर चर्चा की।

वर्किंग पेपर में चार यूआईसी फैकल्टी के योगदान के साथ आंतरिक परामर्श और संशोधन के कई दौर शामिल थे। वर्किंग पेपर को निम्नलिखित 4 केस स्टडीज द्वारा सूचित किया गया थाः मोनाश, दक्षिण अफ्रीका; बिट्स पिलानी–दुबई; नॉटिंघम विश्वविद्यालय मलेशिया; और ग्रामीण कैलेडोनियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बांग्लादेश।

नौ शिक्षाविदों और व्यवहारकर्ताओं (दो आईबीसी के प्रमुखों सहित) के साक्षात्कार के माध्यम से एकत्रित अंतर्दृष्टि के माध्यम से शोध को पूरक बनाया गया था।

दुबई, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और कतर में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों (आईबीसी) के केस अध्ययनः भारत के लिए पाठ

यूआईसी वर्तमान में एनईपी 2020 पर नीपा परियोजना के तत्वावधान में किए गए शोध को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैः अध्ययन में और आयाम जोड़कर कार्यान्वयन रणनीतियां। बांग्लादेश के केस स्टडी को हटा दिया गया है और दो नए केस अध्ययन जोड़े गए हैंः ''यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाः लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस का एक अध्ययन'' और ''कतर में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों की एक महत्वपूर्ण समीक्षाः भारत के लिए पाठ''। पत्र की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। सामान्य वर्गों का पहला मसौदा तैयार किया गया है। साथ ही मोनाश साउथ अफ्रीका, बिट्स पिलानी दुबई, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम मलेशिया और लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस पर केस स्टडी का पहला ड्राफ्ट पूरा हो गया है।

पल्स सर्वेक्षणः भारत में शाखा परिसरों की स्थापना के लिए संभावनाएंः 'शीर्ष 200' विश्वविद्यालयों की प्राथमिकताओं को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पल्स सर्वेक्षण

यूआईसी ने दिसंबर 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय पल्स सर्वेक्षण करके भारत में शाखा परिसरों की स्थापना के लिए संभावनाओं पर एक अध्ययन शुरू किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ रैंकिंग हेतु 'शीर्ष 200' विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रिया एकत्र करना था।

- भारत में शाखा परिसरों की स्थापना के संबंध में विदेशी विश्वविद्यालयों की वर्तमान और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना
- भारतीय पर्यावरण के संबंध में विदेशी विश्वविद्यालयों की प्रमुख चिंताओं और अपेक्षाओं की पहचान करना
- प्रारंभिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भारत को आईबीसी के लिए एक बेहतर गंतव्य बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने वाले बिंदु।

संकल्पना नोट और प्रश्नावली दिसंबर 2020 में तैयार की गई थी। ऑनलाइन सर्वेक्षण जनवरी 2021 के अंत तक पूरा हो गया था और अंतिम मसौदा रिपोर्ट को पूरा कर आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एकक

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र और डिजिटल अभिलेखागार

संस्थान एक अत्याधुनिक पुस्तकालय रखता है जिसमें शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन और संबद्ध विषयों के क्षेत्रों से संबंधित पुस्तकों और अन्य सामग्रियों का विस्तृत और समृद्ध संग्रह है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र अपने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है जैसे। सीएएस, एसडीआई, संदर्भ सेवा, वेब ओपेक, सर्कुलेशन, जेरोक्सिंग। पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने संसाधनों के बंटवारे को बढ़ावा देने के लिए विकासशील पुस्तकालय नेटवर्किंग (DELNET) का सदस्य रहा है। पुस्तकालय में वर्तमान में यूएनओ, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएलओ, यूनिसेफ, विश्व बैंक, ओईसीडी आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों के समृद्ध संग्रह के अलावा 59,208 से अधिक पुस्तकों/दस्तावेजों और 7,616 पत्रिकाओं का संग्रह है। पुस्तकालय शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, 250 पत्रिकाओं और पत्रिकाओं को भी प्राप्त करता है। पुस्तकालय ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए जेस्टोर, एलसिवियर और सेज जैसे तीन ऑनलाइन जर्नल डेटाबेस की सदस्यता भी ली है। नीपा के प्रलेखन केंद्र में लगभग 17,993 खंड हैं, जिसमें आधिकारिक रिपोर्टों, केंद्र और राज्य सरकार के प्रकाशनों, शैक्षिक सर्वेक्षणों, पंचवर्षीय योजनाओं, जनगणना रिपोर्ट और गैर प्रिंट सामग्री आदि का एक अनूठा संग्रह शामिल है। दस्तावेजीकरण केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें भी हैं। और शिक्षा पर सर्वेक्षण जो शैक्षिक अनुसंधान और नीति–निर्माण के लिए आवश्यक हैं। भारत में शिक्षा के सभी पहलुओं, क्षेत्रों और स्तरों पर संदर्भ और अनुसंधान के स्रोत के रूप में सभी दस्तावेजों को सॉफ्ट रूप में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय संस्थान में एक डिजिटल अभिलेखागार की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय संस्थान के विस्तारित चेहरे के रूप में उपयोगकर्ताओं का एक समुदाय बनाना है। उच्च स्तरीय पूर्ण स्वचालित डिजिटल स्कैनर सहित नवीनतम आईसीटी का उपयोग डिजिटल दस्तावेजों के डिजाइन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए किया जाता है। उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर, कई खोज विकल्पों के साथ, डिजिटल अकादमिक समर्थन सेवा इकाइयों की एक अंतर्निहित विशेषता है।

शिक्षा दस्तावेजों का डिजिटल अभिलेखागार 2013 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी शिक्षा दस्तावेजों को एक स्थान पर सॉफ्ट संस्करण में रखना है। डिजिटल अभिलेखागार का संग्रह पहले से ही 11,000 से अधिक है और लगातार बढ़ रहा है। दस्तावेजों को 18 श्रेणियों के तहत वर्गीकृत और केंद्रीय और राज्य और ऐसी अन्य श्रेणियों के तहत उप–विभाजित किया गया है। डिजिटल अभिलेखागार स्वतंत्रता के पश्चात से ही शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं, क्षेत्रों और स्तरों को कवर करने वाली नीति और अन्य संबंधित दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि किसी भी नीति विश्लेषक और योजनाकार, शोधकर्ता और शिक्षा में रुचि रखने वाले अन्य लोगों को संदर्भ और डेटा का उपयोग के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता न हो। डिजिटल अभिलेखागार का उद्देश्य नीपा के विस्तारित रूप में उपयोगकर्ताओं का एक समुदाय तैयार करना है।

कंप्यूटर केंद्र

कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जरुरतें पूरा करता है। यह केंद्र संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करता है। नेटवर्क संसाधन को पहुंचाने के लिए सभी संकाय और स्टाफ को नेटवर्क प्वांइट सुलभ किए गए हैं। नीपा डोमेन से सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों के व्यक्तिगत ई–मेल खाता खोले गए हैं। सभी संकाय सदस्यों को 1 जीबीपीएस की इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है। सभी स्टाफ सदस्यों को डेस्कटॉप और संकाय सदस्यों को लैपटाप आवंटित किए गए हैं। नीपा में समुचित नेटवर्क सुरक्षा का रखरखाव किया जा रहा है। केंद्र में आधुनिकतम सुविधाएं हैं, जैसे–आईबीएम–ई सिरीज सर्वर जो तीव्र अर्थनेट से जुड़ा है। वर्तमान में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं हैं–उन्नत कैट–6 केबल, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा, जिसमें उच्च कार्यनिष्पादन वाले सर्वर्स, क्लाइंट पी सी, इंटरनेट से अपलिंक और अन्य सेवाएं और अति सक्षम बहुकल्पिक यू पी एस के जरिए पर्याप्त रूप में अनवरत पावर आपूर्ति उपलब्ध है।

प्रकाशन एकक

नीपा में शिक्षा के शोध और विकास के प्रसार–प्रचार हेतु प्रकाशन कार्यक्रम है। नीपा प्रकाशन एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य संबंधित सामग्री रिपोर्टों, पुस्तकों, जर्नलों, न्यूज़लेटर, अनुसंधान आलेखों, तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रशासन से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की सूचनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं में 'जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन', 'परिप्रेक्ष्य' हिन्दी जर्नल तथा एंट्रीप न्यूज़लेटर इत्यादि। राष्ट्रीय संस्थान का प्रकाशन एकक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी पूर्ण करता है।

हिंदी कक्ष

यह कक्ष शैक्षिक योजना तथा प्रबंधन में व्यावसायिक प्रकाशनों के अनुवाद के माध्यम से अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी प्रशासन और संकाय को सहयोग देता है।

शासन और प्रबंधन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक 'मानित विश्वविद्यालय' है और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारियों में कुलाधिपति, कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, वित्त समिति और अध्ययन बोर्ड और ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें संस्थान के प्रबंधन बोर्ड द्वारा घोषित या नामित किया जा सकता है। संस्थान के कुलपति प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (पीएन–I अनुभाग) ने अपने पत्र संख्या 2–7/2016–पीएन–I दिनांक 16 जनवरी, 2020 द्वारा यूजीसी विनियम, 2019 के अनुसार नीपा के संशोधित ज्ञापन और नियमों को भेजा है। जिसमें कहा गया है कि संस्थान का सर्वोच्च शासी निकाय अब प्रबंधन बोर्ड होगा।

प्रबंधन बोर्ड: प्रबंधन बोर्ड संस्थान के नियम बनाने की शक्तियों के साथ प्रबंधन का प्रमुख अंग और संस्थान का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय होगा। प्रबंधन बोर्ड का मुख्य कार्य संस्था की बहिर्नियमावली में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है। प्रबंधन बोर्ड राष्ट्रीय संस्थान के सभी मामलों के सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। प्रबंधन बोर्ड में अध्यक्ष (पदेन) के रूप में संस्थान के कुलपति होते हैं; डीन (अकादमिक और अनुसंधान); कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद, जिन्होंने प्रोफेसर के पद पर काम किया होगा और न तो संस्थान या प्रायोजक निकाय से होंगे और न ही उनके रिश्तेदार होंगे; शिक्षा मंत्रालय (एमओई) का एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे का न हो; संस्थान के दो संकाय सदस्यः वरिष्ठता के आधार पर बारी–बारी से प्रोफेसरों और सह प्रोफेसरों में से एक–एक; और शिक्षा मंत्रालय के तीन नामांकित व्यक्ति जो प्रख्यात शिक्षाविद होंगे और प्रोफेसर के पद से नीचे के नहीं होंगे। संस्थान के कुलसचिव प्रबंधन बोर्ड के पदेन सचिव होंगे। 31 मार्च, 2021 तक प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–I में दी गई है।

वित्त समिति: वित्त समिति की मुख्य भूमिका लेखा की जांच करना और व्यय के प्रस्तावों की जांच करना है। राष्ट्रीय संस्थान के वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों को वित्त समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है और उसके बाद, प्रबंधन बोर्ड को वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्त समिति राष्ट्रीय संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर किसी दिए गए वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा तय करती है। वित्त समिति में अध्यक्ष के रूप में संस्थान के कुलपति होते हैं; डीन (अकादमिक और अनुसंधान); शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो; प्रबंधन बोर्ड के दो नामांकित व्यक्ति; जिनमें से एक बोर्ड का सदस्य और राष्ट्रीय संस्थान का वित्त अधिकारी होगा जो वित्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च, 2021 तक वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

अकादमिक परिषदः अकादमिक परिषद राष्ट्रीय संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय है। यह शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के मानकों के रखरखाव के लिए; अंतरविभागीय समन्वय, परीक्षा और परीक्षण, आदि के लिए जिम्मेदार है। अकादमिक परिषद में संस्थान के कुलपति (पदेन) के रूप में संस्थान के कुलपति होते हैं; संस्थान के डीन, (अकादमिक और अनुसंधान); राष्ट्रीय संस्थान के विभागों के प्रमुख; विभागों के प्रमुखों के अलावा अन्य विभागों के दो सह प्रोफेसर, (परस्पर वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा); परस्पर वरिष्ठता के आधार पर बारी–बारी से विभागों से दो सहायक प्रोफेसर; संस्थान की गतिविधियों से संबंधित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से तीन व्यक्ति मानित विश्वविद्यालय, कुलपति द्वारा नामित; तीन व्यक्ति जो शिक्षक नहीं हैं, उनके विशेष ज्ञान के लिए अकादमिक परिषद द्वारा सहयोजित और; कुलसचिव, अकादमिक परिषद के पदेन सचिव होंगे। 31 मार्च, 2021 तक अकादमिक परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–III में दी गई है।

अध्ययन बोर्डः राष्ट्रीय संस्थान के अध्ययन बोर्ड में संस्थान के कुलपति अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं; डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान); विभागाध्यक्ष और संकाय के सभी प्रोफेसर; परस्पर वरिष्ठता के आधार पर बारी–बारी से संकाय/विभाग के दो सह प्रोफेसर; परस्पर वरिष्ठता के आधार पर बारी–बारी से संकाय/विभाग के दो सहायक प्रोफेसर; संबंधित व्यवसाय से उनके विशेष ज्ञान के संबंध में 2 से अधिक व्यक्तियों को सहयोजित नहीं किया जाना चाहिए; परीक्षा नियंत्रक स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होगा। 31 मार्च, 2021 को अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट–IV में दी गई है।

योजना एवं निगरानी बोर्डः योजना एवं निगरानी बोर्ड संस्थान का प्रमुख योजना निकाय है और संस्थान के विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। योजना एवं निगरानी बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होते हैं। कुलसचिव इसके सचिव हैं, जिसमें सभी विभागों के सात आंतरिक सदस्य (विभागाध्यक्ष) और संस्थान के बाहर के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। 31 मार्च, 2021 को योजना और निगरानी बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट V में दी गई है।

कार्य दल और समितियाँः विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर कुलपति द्वारा विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति की सलाह देने और निगरानी करने के लिए विशेषज्ञों से युक्त परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। एक अनुसंधान अध्ययन सलाहकार बोर्ड का गठन कुलपति की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें अन्य के अलावा, सभी शैक्षणिक विभागों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं, और कुलसचिव इसके सदस्य–सचिव के रूप में होते हैं, जो योजना के तहत शैक्षिक योजना और प्रशासन में अध्ययन के लिए सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते हैं। ।

संगठनात्मक ढांचा

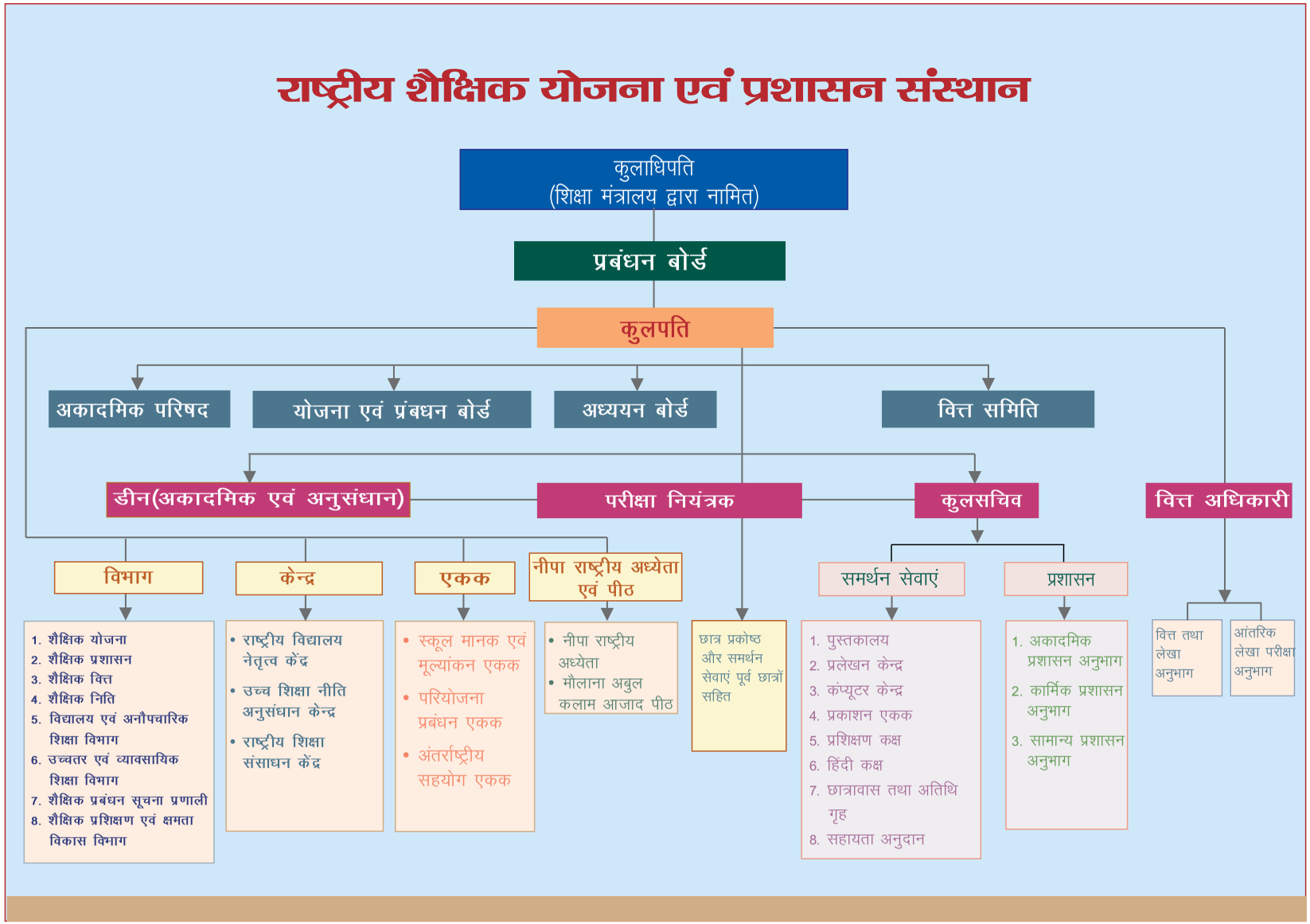
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
कुलाधिपति
(शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित)
प्रबंधन बोर्ड
कुलपति
अकादमिक परिषद
योजना एवं प्रबंधन बोर्ड
अध्ययन बोर्ड
वित्त समिति
डीन(अकादमिक एवं अनुसंधान)
परीक्षा नियंत्रक
कुलसचिव
वित्त अधिकारी
विभाग
केन्द्र
एकक
नीपा राष्ट्रीय अध्येता एवं पीठ
समर्थन सेवाएं
प्रशासन
1. शैक्षिक योजना
2. शैक्षिक प्रशासन
3. शैक्षिक वित्त
4. शैक्षिक निति
5. विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग
6. उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
7. शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
8. शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
• राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र
• उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र
• राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र
• स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक
• परियोजना प्रबंधन एकक
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एकक
• नीपा राष्ट्रीय अध्येता
• मौलाना अबुल कलाम आजाद पीठ
छात्र प्रकोष्ठ और समर्थन सेवाएं पूर्व छात्रों सहित
1. पुस्तकालय
2. प्रलेखन केन्द्र
3. कंप्यूटर केन्द्र
4. प्रकाशन एकक
5. प्रशिक्षण कक्ष
6. हिंदी कक्ष
7. छात्रावास तथा अतिथि गृह
8. सहायता अनुदान
1. अकादमिक प्रशासन अनुभाग
2. कार्मिक प्रशासन अनुभाग
3. सामान्य प्रशासन अनुभाग
वित्त तथा लेखा अनुभाग
आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग

प्रशासन और वित्त

प्रशासन और वित्तः राष्ट्रीय संस्थान के प्रशासनिक ढांचे में तीन अनुभाग–अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन और दो कक्ष–प्रशिक्षण कक्ष और एम.फिल., पीएचडी कक्ष हैं। कुलसचिव सभी अनुभागों के प्रभारी हैं। कुलसचिव नीपा परिषद, प्रबंधन बोर्ड और अकादमिक परिषद के सचिव भी हैं। कुलसचिव को प्रशासनिक कामकाज में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी और अनेक अनुभाग अधिकारी अनुसमर्थन प्रदान करते हैं।

कुलसचिव अकादमिक अनुसमर्थन सेवा एककों, जैसे–पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, एवं डिजीटल अभिलेखागार, प्रकाशन एकक और हिंदी कक्ष के कार्यकलापों के प्रति उत्तरदायी हैं। वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग के प्रभारी है। अनुभाग अधिकारी (लेखा) वित्त अधिकारी का अनुसमर्थन करता है।

स्टाफ की संख्या (2020–21)

31 मार्च, 2021 के अनुसार नीपा की कुल कर्मचारियों संख्या 167 थी।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान को कुल 3688.00 लाख रुपये का अनुदान मिला (आवर्ती और गैर–आवर्ती मद)। वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास आवर्ती मद में 302.89 लाख रुपये शेष थे। वर्ष के दौरान आंतरिक कार्यालय और छात्रावास से 66.76 लाख रुपए की राशि प्राप्ति हुई। योजना और गैर–योजना मदों में वर्ष के दौरान व्यय 3352.41 लाख रुपये था।

संस्थान के पास 1302.89 लाख रुपये शेष था और दूसरे संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों की मद में इस वर्ष 2020–21 के दौरान 220.35 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्ति हुई। प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर वर्ष के दौरान कुल 487.24 लाख रुपये खर्च किए गए। (परिशिष्ट–VII)

परिसर और भवन
आधारभूत सुविधा

संस्थान के पास एक चार–मंजिला कार्यालय, सुसज्जित स्नानघरयुक्त 60 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास और एक आवास–क्षेत्र है। इस आवास क्षेत्र में टाइप–I के 16, टाइप–II से V तक के 8–8 क्वार्टर और एक कुलपति आवास हैं।

संस्थान के पास बिंदापुर, द्वारका में टाइप–III के 25 क्वार्टर हैं।

संस्थान परिसर में सुसज्जित प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर केंद्र, अंतरराष्ट्रीय डाईनिंग हाल, जिम और क्लास रूम हैं।

संस्थान ने हाल ही में परिसर में अर्जित 2100 वर्ग मीटर के भूखंड में नया अकादमिक भवन के निर्माण के लिये अपेक्षित कदम उठाए हैं। इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लीज डीड जारी कर दिया है।

2

अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

अध्यापन और व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

एम.फिल. और पी–एच.डी.

वस्तुतः संस्थान की एम.फिल और पी.एच. डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा संस्थान विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है।

शैक्षिक प्रशासन के लिए विद्वान तैयार करना

राष्ट्रीय संस्थान एक प्रदायक संस्थान है जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जरुरत के अनुसार शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन में विशेषज्ञता से युक्त मानव संसाधनों का विकास करता है ऐसे विशेषज्ञ जो अंतरशास्त्रीय कार्यक्रमों/एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियों के पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा तैयार किये जाते हैं। वे व्यापक एवं गतिशील संदर्भों में समुचित योजनाओं और कार्यनीतियों के दिशा–निर्देशों के निर्माण या सांस्थानिक प्रबंधन की सीमित भूमिकाओं से जुड़े मामलों के समाधान करने में पूर्णतः कुशल एवं सक्षम होते हैं।

वस्तुतः संस्थान की एम.फिल. और पी–एच.डी. उपाधियाँ विशेष रूप से शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन पर केंद्रित हैं। इसके द्वारा संस्थान युवा शोधकर्त्ताओं को सशक्त और सक्षम बनाता है और शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उनकी आजीविका तैयार करता है। नीपा इसके माध्यम से शैक्षिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण का अनुसमर्थन करने हेतु विशेषज्ञ और सक्षम मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रमों का महत्व इसमें अंतर्निहित गतिशील और लचीले उपागम के

द्वारा यह शिक्षा और सामाजिक विकास के अन्य सहायक क्षेत्रों से जुड़कर नवाचारी बहुशास्त्रीय पाठ्यक्रमों का विस्तार करता है।

संस्थान द्वारा संचालित पूर्व डाक्टोरल और डाक्टोरल कार्यक्रम में शामिल हैं: (i) पूर्णकालिक एम.फिल. कार्यक्रम (ii) पूर्णकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम और (iii) अंशकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में आरंभ किए गए थे। एम.फिल. और पी–एच. डी. कार्यक्रम विभिन्न पृष्ठभूमि के शोधकर्मियों की शोध क्षमता के निर्माण के लिए डिजाइन किए गए हैं जो

शैक्षिक नीति, योजना प्रशासन तथा वित्त के संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे किए गए शोध अध्ययनों से अपेक्षा की जाती है कि ये नीति निर्माण, शिक्षा सुधार कार्यक्रमों तथा क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ–साथ ज्ञान आधार को समृद्ध करने में भारी योगदान करेंगे। एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अंतर्गत शोध के व्यापक क्षेत्रों में शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा में समता और समावेशन, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, अल्पसंख्यक शिक्षा, तुलनात्मक शिक्षा और शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण शामिल हैं।

प्रस्तुत दो वर्षीय एम.फिल. डिग्री कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष का पाठ्यक्रम कार्य (16 क्रेडिट) होते हैं। इसके बाद एक छह सप्ताह की अवधि के लिए इंटर्नशिप (4 क्रेडिट) और एक वर्ष शोध प्रबंध (16 क्रेडिट) होते हैं। सभी विद्वान जो सफलतापूर्वक पूर्वक एम.फिल. पाठ्यक्रम पूरा और निर्धारित कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करते हैं। (वर्तमान में एफ.जी.पी.ए. 5 या उससे अधिक 10 अंक) का ग्रेड पाने वाले शोधार्थी पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश और पंजीकरण प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पी–एच.डी. कार्यक्रम में दाखिला लेने की तिथि के दो वर्ष बाद ही शोधार्थी अपने शोध प्रबंध जमा करा सकते हैं।

पूर्णकालिक पी–एच.डी. कार्यक्रम में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को दाखिला की पुष्टि हेतु एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। इसके बाद वे दो वर्ष के शोध कार्य के उपरांत ही वे उपाधि हेतु अपने शोध प्रबंध जमा कर सकते हैं।

अंशकालिक पी–एच.डी. में सीधे दाखिला लेने वाले शोधार्थियों को पी–एच.डी. में दाखिला की पुष्टि से पहले एक वर्ष का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है। अंशकालिक पी–एच.डी. के शोधार्थी दाखिला की पुष्टि के कम से कम चार वर्ष बाद अपना शोध प्रबंध जमा कर सकते हैं।

तालिका 2.1

वर्ष 2020–21 में नामांकित, अध्ययनरत और अध्ययन पूर्ण करने वाले विद्वानों की सूची

	एम.फिल.	पी–एच.डी. पूर्णकालिक	पी–एच.डी. अंशकालिक	योग
वर्ष 2020–21 में नामांकन	24	17	शून्य	41
अकादमिक सत्र 2020–21 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या	39 (वर्ष 2020–21 में नामांकित विद्यार्थियों सहित)	54 (वर्ष 2007–08 से 2020–21 तक नामांकित विद्यार्थियों सहित)	14 (वर्ष 2007–08 से 2020–21 तक नामांकित विद्यार्थी)	107
वर्ष 2020–21 के दौरान छात्रवृत्ति स्नातक विद्वानों की कुल संख्या	17	06	02	25

डिप्लोमा कार्यक्रम

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम के छः घटक हैं: (i) पाठ्यक्रम तैयारी कार्य (ii) आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य (iii) परियोजना कार्य (iv) परियोजना कार्य का मूल्यांकन और अंतरिम प्रमाण पत्र विवरण और (v) उन्नत पाठ्यक्रम कार्य और (vi) अंतिम मूल्यांकन और पीजी डिप्लोमा प्रमाण–पत्र वितरण।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा)

संस्थान शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमा (डेपा) कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। वर्ष 1982–83 के आरंभ से ही यह विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष रूप से संरचित डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आरम्भ में यह कार्यक्रम पूर्व–प्रवेश पाठ्यक्रम के रूप में संरचित किया गया था। यद्यपि वर्ष 2014–15 से इस कार्यक्रम में पाठ्यक्रम को संवर्धित करके इसमें परिवर्तन किया गया है और इसके डेपा मूलभूत से पीजीडेपा (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन)– शैक्षिक योजना और प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा) में बदल दिया गया है। प्रतिभागियों के कार्य और भूमिकाओं तथा उनकी संस्थाओं जैसे एससीईआरटी/सीमेट/डाइट/डीईओ/बीईओ और राज्य सरकारों के शिक्षा निदेशालयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को संबर्धित किया गया है।

एक वर्षीय पीजीडेपा कार्यक्रम को मौजूदा डेपा में व्यापक रूपांतरण के बाद निर्मित किया गया है जो एक सघन दीर्घकालिक कार्यक्रम है जो कि देश में पेशेवर रूप से शैक्षिक प्रशासकों का संवर्ग का विकास सुनिश्चित करेगा। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) शैक्षिक योजना और प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराना।

(ii) शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर निर्णय कार्य के लिए प्रतिभागियों में योजना और प्रबंधन कौशल के विकास हेतु सक्षम बनाना।

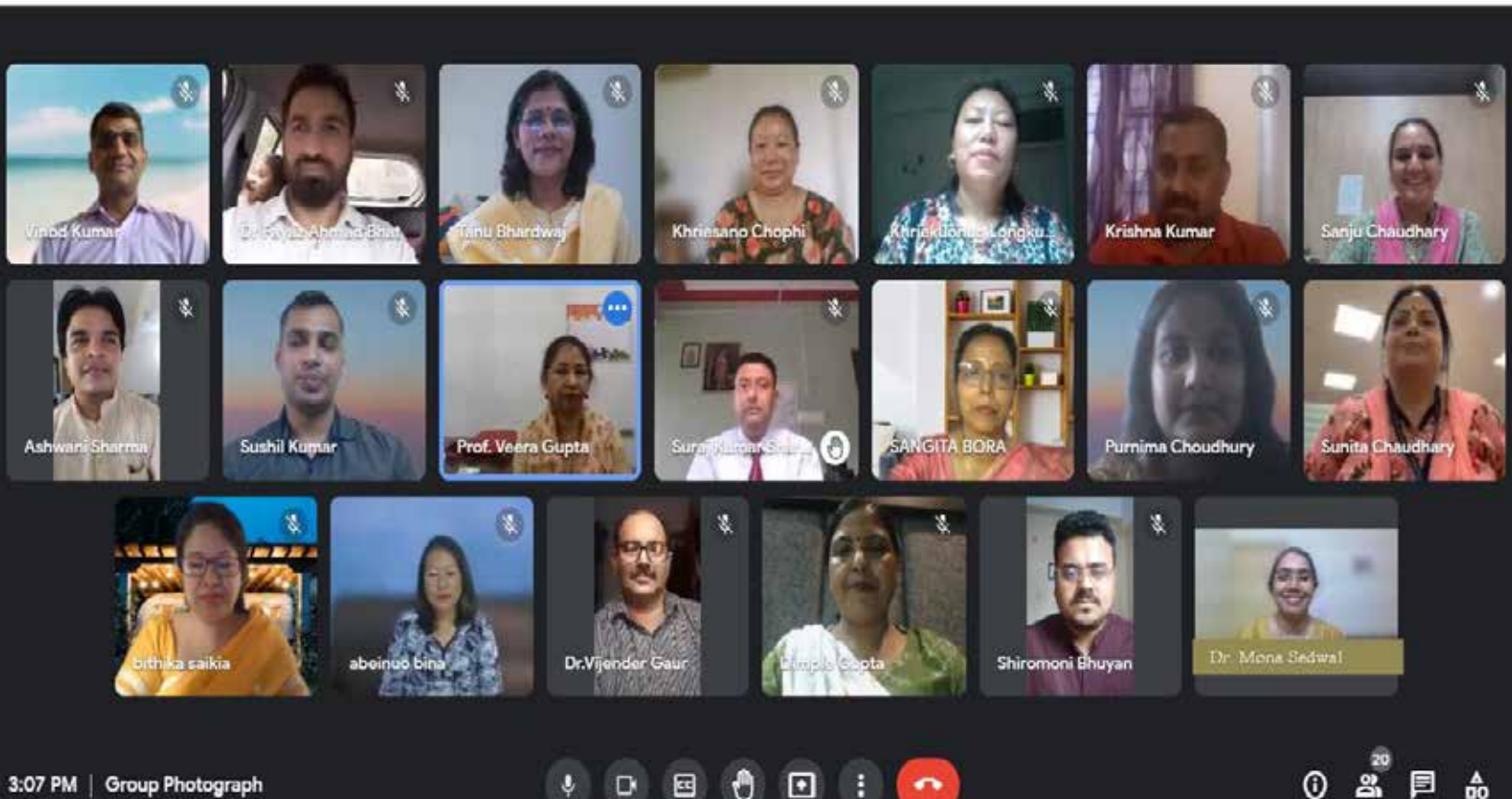

तालिका 2.2

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) राज्य/संघ क्षेत्रवार भागीदारी

राज्य/संघ क्षेत्र	छठा पी.जी.–डेपा	सातवां पी.जी.–डेपा	योग
आसाम	3	6	9
छत्तीसगढ़	1	-	1
दिल्ली	-	1	1
हरियाणा	3	4	7
हिमाचल प्रदेश	2	-	2
भारतीय नौसेना	-	2	2
जम्मू और कश्मीर	-	3	3
कर्नाटक	2	-	2
मध्य प्रदेश	1	-	1
महाराष्ट्र	2	-	2
मणिपुर	1	-	1
नागालैण्ड	-	3	3
पुदुचेरी	-	1	1
राजस्थान	-	3	3
सिक्किम	-	1	1
तमिलनाडु	1	-	1
उत्तराखंड	3	3	6
उत्तर प्रदेश	1	-	1
भारतीय वायु सेना	2	2	4
योग	**22**	**29**	**51**

(iii) प्रतिभागियों में शैक्षिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन योग्यता का विकास करना।

पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम का निरूपण करते समय मूलतः इस बात का ध्यान दिया गया था कि प्रतिभागी को इस पाठ्यक्रम के लिए नीपा में तीन माह से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े और वह अपने कार्य स्थल पर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सके। इसके अनुसार इसे 12 महीने के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में रूपातंरित किया गया है। अनेक शिक्षा विभाग इस पाठ्यक्रम हेतु अपने अधिकारियों को लंबी अवधि के लिए प्रतिनियुक्त नहीं कर सकते हैं इसलिए इस तरह से योजना बनाई गई है कि आमने–सामने और आवासीय पाठ्यक्रम कार्य हेतु प्रतिभागियों को एक खंड में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए प्रवास न करना पड़े। इसमें प्रतिभगियों के कार्यस्थल पर एक प्रारम्भिक चरण, नीपा में आमने–सामने पाठ्यक्रम कार्य, कार्यस्थल पर परियोजना कार्य, मुक्त और दूरवर्ती अधिगम प्रणाली के माध्यम से उन्नत पाठ्यक्रम का संचालन और संगोष्ठी सहित कार्यशाला शामिल है। नीपा में अंतिम मूल्यांकन और पीजीडेपा प्रमाणपत्र हेतु संगोष्ठी–सह–कार्यशाला कार्य का प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है।

छठा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम सितंबर 2019 से जुलाई 2020 के दौरान आयोजित किया गया। जिसमें 11 राज्यों/संघ प्रदेशों के 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन एवं समन्वय शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग द्वारा किया गया।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)

राष्ट्रीय संस्थान 1985 से विकासशील देशों के पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में 6 माह का अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के विद्यार्थी एशिया, अफ्रीका, मध्य एशियाई गणराज्यों, दक्षिणी अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्रों के देशों से आते हें। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं– (i) सघन पाठ्यचर्चा कार्यक्रम; (ii) अनुप्रयुक्त कार्य और (iii) लघु शोध प्रबंधन। आईडेपा की अवधि छः माह है और यह दो चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में

तीन माह का सघन पाठ्यचर्या है जो नीपा, नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। यह चरण आवासीय है और प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस चरण के दौरान परिसर में निवास करें। दूसरे चरण में प्रतिभागी को स्वदेश में ही राष्ट्रीय संस्थान के संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में क्षेत्र आधारित शोध परियोजना अध्ययन करना होता है।

आईडेपा कार्यक्रम में सिद्धान्त और व्यवहार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के साथ गहन पाठ्यचर्या शामिल है। एजेंडा के व्यापक रूप में व्याख्यान और समूह कार्य, व्यावहारिक अभ्यास, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के दौरे और शैक्षिक विकास नीति, नियोजन, प्रबंधन, प्रशासन, पर्यवेक्षण और नेतृत्व के एक चुने हुए पहलू पर एक शोध परियोजना शामिल है जिसमें क्षेत्र को अपनाना शामिल है। और अंतर–अनुशासनिक दृष्टिकोण सिद्धान्त और व्यवहार को जोड़ने के लिए लागू किए गए काम में (i) देश और विषयगत संगोष्ठी पेपर प्रस्तुतियाँ (ii) क्षेत्रों का दौरा कार्यक्रम शामिल है, जिसमें भारत में विभिन्न शैक्षिक नवाचारों की योजना और उनका प्रबंधन किया जा रहा है और (iii) एक क्षेत्र अनुसंधान परियोजना के लिए अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करना।

कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रतिभागियों के स्वदेश में ही आयोजित होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को प्रथम चरण के दौरान निर्धारित क्षेत्र कार्य आधारित शोध परियोजना पर कार्य करना पड़ता है। शोध परियोजना कार्य (तीन माह की अवधि) में पूरा करने के बाद प्रतिभागी को अपना लघुशोध प्रबंध राष्ट्रीय संस्थान को प्रस्तुत करना पड़ता है। लघु शोध प्रबंध की प्राप्ति और तदुपरांत राष्ट्रीय संस्थान के संकाय द्वारा उसके मूल्यांकन के बाद प्रतिभागी को डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाती है।

वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान ने 36वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा का दूसरा चरण पूरा किया जिसका प्रथम चरण 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया था। उसमें 14 देशों के 27 प्रतिभागी शामिल हुए। 36वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा चरण 1 मई से 31 जुलाई 2020 के दौरान आयोजित किया गया।

37वें अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का प्रथम चरण 1 फरवरी 2021 सें 30 अप्रैल 2021 तक किया जाना था। परन्तु कोविड महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा सका।

अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का संयोजन शैक्षिक प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग द्वारा आयोजित और समन्वित किया जाता है।

तालिका 2.3

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

36वां आईडेपा 2020

क्र. सं.	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	2
2.	भूटान	2
3.	कांगो	1
4.	क्यूबा	1
5.	इथियोपिया	1
6.	फ़िजी	1
7.	किर्गिज़स्तान	1
8.	मालदीप	2

क्र. सं.	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
9.	मंगोलिया	1
10.	नाइजीरिया	4
11.	दक्षिण सूडान	1
12.	तंजानिया	5
13.	जाम्बिया	4
14.	जिम्बाब्वे	1
	योग	**27**

तालिका 2.4

सभी कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी 2020–21

क्र. सं.	देश का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	2
2.	आज़रबाइजान	2
3.	भूटान	6
4.	बांग्लादेश	1
5.	कांगो	1
6.	क्यूबा	1
7.	कंबोडिया	12
8.	इथोपिया	1
9.	फ़िजी	1
10.	किर्गिज़स्तान	1
11.	इस्वाटिनी का साम्राज्य	1
12.	केन्या	3
13.	मालदीप	9
14.	मंगोलिया	1
15.	मॉरीशस	3
16.	म्यांमार	1
17.	नाइजीरिया	5
18.	नेपाल	1
19.	पेरिस	5
20.	फिलिस्तीन	1
21.	पेरू	2
22.	दक्षिण सूडान	1
23.	तंजानिया	5
24.	तुर्कमेनिस्तान	1
25.	उज़्बेकिस्तान	1
26.	यूनाइटेड किंगडम	3
27.	जाम्बिया	4
28.	जिम्बाम्बवे	1
	योग	**76**

तालिका 2.5

व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार भागीदारी 2020–21

क्र. सं.	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	151
2.	अरुणाचल प्रदेश	53
3.	असम	154
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6
5.	बिहार	162
6.	छत्तीसगढ़	77
7.	चंडीगढ़	45
8.	दिल्ली	324
9.	गोवा	18
10.	गुजरात	201
11.	हरियाणा	275
12.	हिमाचल प्रदेश	115
13.	जम्मू और कश्मीर	152
14.	झारखण्ड	72
15.	कर्नाटक	265
16.	केरल	41
17.	मध्य प्रदेश	241
18.	महाराष्ट्र	280
19.	मणिपुर	40
20.	मेघालय	39
21.	मिजोरम	52
22.	नागालैंड	61
23.	उड़ीसा	148
24.	पंजाब	159
25.	पुदुचेरी	5
26.	राजस्थान	291
27.	सिक्किम	82
28.	तेलंगाना	105
29.	तमिलनाडु	158
30.	त्रिपुरा	32
31.	उत्तराखण्ड	92
32.	उत्तर प्रदेश	291
33.	पश्चिम बंगाल	55
	योग	**4242**

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

शैक्षिक योजना और प्रशासन में सुधार हेतु सांस्थानिक क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों के शिक्षा कर्मियों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्थान (नीपा) के प्रमुख कार्यकलाप के रूप में सतत जारी है। वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय संस्थान ने शिक्षा के विभिन्न विकास क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों और शिक्षा नीति योजनाओं, प्रशासन के विविध पक्षों से जुड़े 86 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के मुख्य विषय थे : स्कूलों की योजना और प्रबंधन, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन, माध्यमिक स्तर पर स्कूल प्रावधानों का आकलन, शैक्षिक वित्त की योजना और प्रबंधन, और स्कूल नेतृत्व आदि। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी थे जिला और राज्य स्तर के शिक्षाकर्मी, शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर के अन्य अधिकारी, केंद्र, राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक संस्थानों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और अन्य प्राधिकारी, कालेज प्राचार्य और कालेजों तथा उच्च शिक्षा के वरिष्ठ प्रशासक, विश्वविद्यालय तथा समाजविज्ञान शोध संस्थानों के नवनियुक्त प्राध्यापक आदि। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान राष्ट्रीय संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गईं :

शैक्षिक प्रशासन विभाग

- शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छी प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना का कार्यान्वयन–चरण–I (निष्कर्ष चरण के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया) नीपा, नई दिल्ली, अप्रैल 2020 – मार्च 2021
- जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम, नीपा, नई दिल्ली, 8–12 फरवरी, 2021।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व, नीपा, नई दिल्ली, 17–19 फरवरी, 2021.

शैक्षिक नीति विभाग

- शिक्षा में व्यावसायिक सार्वजनिक नीति निर्माण पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ऑनलाइन मोड, 17–21 अगस्त, 2020
- राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 पर राष्ट्रीय वेबिनारः संभावनाएं, चुनौतियां और रास्ते, ऑनलाइन मोड, 19 अगस्त, 2020
- नीतिगत परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता पर राष्ट्रीय चर्चा बैठक (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए – गांधी स्मृति संस्थान, राजघाट के सहयोग से), नीपा, नई दिल्ली, अक्टूबर 01–02, 2020
- आरटीई के तहत वंचितों और कमजोरों की शिक्षा पर अभिविन्यास कार्यशालाः नीतिगत मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेप, नीपा, नई दिल्ली, फरवरी 15–17, 2021।

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

- स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियां और अवसर, नीपा, नई दिल्ली, मार्च 08–12, 2021
- लॉकडाउन और उसके पश्चात की अवधि के दौरान बच्चों के शिक्षा पर वेबिनार, 28 जून, 2020

- 'भारत में स्कूली शिक्षा में लैंगिक समता प्राप्त करना: नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में', विषय पर ऑनलाईन चर्चा बैठक, 30 दिसंबर, 2020

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

'कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा' पर वेबिनार, 24 जुलाई, 2020

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में 36वां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए) (आईटीईसी वित्त पोषित), (ऑनलाइन मोड), मार्च 31–अप्रैल 30, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए)–IV चरण, (ऑनलाइन मोड), 27 अप्रैल– 01 मई, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) – पांचवां चरण, (ऑनलाइन मोड), 04–08 मई, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) – VI चरण, (ऑनलाइन मोड), 06–10 जुलाई, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में 7वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) – I चरण (तैनाती के स्थान पर), (क्षेत्र आधारित), 01–31 अगस्त, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में 7वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) – द्वितीय चरण, (ऑनलाइन मोड), 1 सितंबर–नवंबर 30, 2020
- शिक्षा में नीति निर्माण संरचना और प्रक्रिया पर अभिविन्यास कार्यक्रम, (ऑनलाइन मोड), 21–25 सितंबर, 2020
- शैक्षिक योजना और प्रशासन में 7वां स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए)–III चरण (तैनाती के स्थान पर) (क्षेत्र आधारित), 01 दिसंबर, 2020 – 31 मार्च, 2021
- क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका और कार्यों पर नीति संवाद एससीईआरटी और एसआईईमैट, नीपा, नई दिल्ली, नवंबर 05–06, 2020
- विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा पर समावेशी शिक्षा समन्वयकों की ऑनलाइन बैठक (एसएलडी), (ऑनलाइन मोड), 03–04 दिसंबर, 2020

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व (एन.सी.एस.एल.) केंद्र

- उत्कृष्टता के लिए नेतृत्व: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 21 सितंबर – 01 अक्टूबर, 2020
- सरकारी स्कूलों में छात्र सीखने और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए नेतृत्व विकास पर क्षमता निर्माण कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 15–18 दिसंबर, 2020
- राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक, नीपा, नई दिल्ली, 01 मार्च, 2021
- स्कूल नेतृत्व पर निष्ठा ऑनलाइन मॉड्यूल: प्रारंभिक शिक्षा के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग (अंग्रेजी) – निष्ठा (अंग्रेजी) के लिए वीडियो विकास, ऑनलाइन मॉड्यूल प्लस 6 वीडियो, 28 अगस्त, 2020
- स्कूल नेतृत्व पर निष्ठा ऑनलाइन मॉड्यूल: प्रारंभिक शिक्षा के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग (हिंदी) – निष्ठा (हिंदी) के लिए वीडियो विकास, ऑनलाइन मॉड्यूल प्लस 6 वीडियो, 16 दिसंबर, 2020
- स्कूल नेतृत्व पर मॉड्यूल पर निष्ठा लाइव स्ट्रीमिंग, 28 अगस्त, 2020
- स्कूल नेतृत्व पर निष्ठा ऑनलाइन मॉड्यूल: माध्यमिक शिक्षा के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग (अंग्रेजी)

- 23 स्कूल लीडरशिप अकादमियों के साथ गूगल मीट का पहला दौर, 14–16 सितंबर, 2020
- 26 स्कूल लीडरशिप अकादमियों के साथ गूगल मीट का दूसरा दौर, दिसंबर 2020
- फरक्का बैराज परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यशाला, मुर्शिदाबाद, 11 जनवरी – 27 फरवरी, 2021
- राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक, 01 मार्च, 2021
- एनवीएस मास्टर ट्रेनर्स के लिए शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम, 22–26 फरवरी, 2021

एनसीएसएल संकाय द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण/ सत्र/ कार्यशालाएं /बैठकें /समीक्षाएं और सलाहकारी वेबिनार

- एनईपी 2020: अग्रणी स्कूल परिसर और स्थानीय शासन, 05 नवंबर, 2020
- स्कूल परिसरध्क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन, 26 सितंबर, 2020
- स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ, 22 दिसंबर, 2020
- उद्घाटन समारोह और स्कूल नेतृत्व का परिचय, उत्तर प्रदेश, 12 मई, 2020
- स्कूल नेतृत्व पर वेबिनार: स्व विकास, उत्तर प्रदेश, 14 मई, 2020
- शिक्षण और समापन का समेकन, उत्तर प्रदेश, 21 मई, 2020
- एनईपी 2020 और नेताओं का सतत व्यावसायिक विकास, 04 नवंबर, 2020
- स्कूल नेतृत्व और शिक्षक व्यावसायिक विकास पर वेबिनार, तेलंगाना, 21 मई, 2020
- एक चिंतनशील व्यवहारकर्ता पर वेबिनार: अकादमिक नेतृत्व की कला, डॉ. एच.आर. गजवानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुजरात, 28 मई, 2020
- एक नेता के रूप में समग्र विकास पर वेबिनार, डाइट छोटा मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 12 जून, 2020
- एक नेता के रूप में समग्र विकास पर वेबिनार, डाइट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 12 जून, 2020
- स्कूल नेतृत्व विकास पर वेबिनार, डाइट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, 13 जून, 2020
- आईसीटी कार्यशाला–2020 मिशन शिक्षण संवाद के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रमुखों का व्यावसायिक संघ, 10 जून, 2020
- चिंतनशील नेता बननाः स्वयं का विकास करना, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश – गाजियाबाद अध्याय, 15 जून, 2020
- माध्यमिक स्तर के लिए निष्ठा पर परिचय और प्रारंभिक चर्चा पर निष्ठा वेबिनार बैठक, 22 जून, 2020
- सीबीएसई के साथ आयोजित शैक्षणिक नेतृत्व पर ऑनलाइन प्रस्तुति सह बैठक का आयोजन और संचालन। शैक्षणिक नेतृत्व पर परियोजना के लिए आगे की राह पर चर्चा की। कुलपति, नीपा, 23 जून, 2020 के साथ एक संक्षिप्त जानकारी भी साझा की गई
- रिमोट लर्निंग और डिजिटल डिवाइडः अनुदेशन में समता के मुद्दों को संबोधित करना, डाइट, पीतमपुरा, दिल्ली, 24 जून, 2020
- 26 जून 2020 को एमफिल और पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की, विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। 24 जून, 2020

- एसएलए सिक्किम के साथ बैठक, 25 जून – 20 अगस्त, 2020
- निष्ठा मॉड्यूल को ऑनलाइन प्रारूपों में बदलने के लिए अभिविन्यास पर बैठक, 29 जून, 2020
- कोविड–19 संकट के बीच शैक्षिक नेतृत्व बाधाओं और संभावनाओं की बदलती दुनिया, सौराष्ट्र कॉलेज, 23 जुलाई, 2020
- नई शिक्षा नीतिः शिक्षक शिक्षा पर विचार, समेकित शिक्षा के लिए समष्टि संस्थान, गुजरात, 09 अगस्त, 2020
- केजीबीवी के विशेष अधिकारियों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम, 'शिक्षकों के रूप में चिंतनशील अभ्यासकर्ता' पर सत्र, समग्र शिक्षा, तेलंगाना, 26 अगस्त, 2020
- स्कूलों के प्रमुखों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, 'लीडरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस' पर सत्र, समग्र शिक्षा, वारंगल, शहरी, तेलंगाना, 19 सितंबर, 2020
- स्कूलों के प्रमुखों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, 'लीडरशिप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस' पर सत्र, समग्र शिक्षा, सिद्दीपेट, तेलंगाना, 30 सितंबर, 2020
- स्कूल परिसरों की स्थापना के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन, जवाहर नवोदय विद्यालय, 04 सितंबर, 2020
- स्कूल परिसरों की स्थापना के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन, टाटा ट्रस्ट, 11 सितंबर, 2020
- नई शिक्षा नीतिः स्कूली शिक्षा में सुधार, रवींद्र ठाकुर महाविद्यालय, त्रिपुरा, 19 सितंबर, 2020
- सीबीएसई परियोजना की अंतिम प्रस्तुति सीबीएसई के अध्यक्ष, कुलपति, नीपा और सीबीएसई परियोजना के कोर टीम के सदस्यों के सामने, 30 सितंबर, 2020
- स्कूलों का पुनर्निर्माण, दुनिया का पुनर्निर्माण (वेब श्रृंखला) – करुणा के साथ नेतृत्व, एजुकेशन टुडे सोसाइटी टुमॉरो – इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज, भारत, 16 अक्टूबर, 2020
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर वेबिनारः जम्मू–कश्मीर, एससीईआरटी जम्मू और कश्मीर के सामने चुनौतियांध्अवसर, 31 अक्टूबर, 2020
- नई शिक्षा नीतिः स्कूल शिक्षा में सुधार और स्कूल प्रमुखों की बदलती भूमिका, एससीईआरटी, त्रिपुरा, 09 नवंबर, 2020
- शिक्षक शिक्षा में यूजीसी द्वारा प्रायोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में स्कूल नेतृत्व पर सत्र पढ़ाने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित, जेएनयू, 04 दिसंबर, 2020
- समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला, डाइट, ऊना, हिमाचल प्रदेश, 28 दिसंबर, 2020.

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

- शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता महिला अधिकारिता को आगे बढ़ाने पर वेबिनार, 14 जुलाई, 2020
- आईएचईआर 2021ः भारत में निजी उच्च शिक्षा पर पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक, नीपा, नई दिल्ली, 21 सितंबर, 2020
- ''लचीले सीखने के रास्तेः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर वेबिनार (ऑनलाइन मोड), 20 नवंबर, 2020
- भारत में उच्च शिक्षा में विविधता और सामाजिक समावेशन पर नीतिगत संवाद, (ऑनलाइन मोड), 15 दिसंबर, 2020

- आईएचईआर 2021: भारत में निजी उच्च शिक्षा पर दूसरी सहकर्मी समीक्षा बैठक, नीपा, नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2020
- सीपीआरएचई कार्यकारी समिति की बैठक, नीपा, नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021
- राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक, (ऑनलाइन मोड), 18–19 मार्च, 2021

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार, जम्मू और कश्मीर पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, (ऑनलाइन मोड), 21 सितंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, असम, (ऑनलाइन मोड), 09–11 नवंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, तेलंगाना, (ऑनलाइन मोड), 12–13 नवंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, उत्तराखंड, (ऑनलाइन मोड), 25 नवंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, मेघालय, (ऑनलाइन मोड), 26–27 नवंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, राजस्थान, (ऑनलाइन मोड), 02 दिसंबर, 2020
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश, (ऑनलाइन मोड), 07 जनवरी, 2021
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, बिहार, (ऑनलाइन मोड), 12–13 जनवरी, 2021
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य आधारित स्कूल सुधार पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, झारखंड, (ऑनलाइन मोड), 21–22 जनवरी, 2021
- स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार, जम्मू और कश्मीर पर राज्य ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम, (ऑनलाइन मोड), 09 फरवरी, 2021.

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम डिजाइन करने, विकसित करने और वितरित करने के लिए संकाय विकास कार्यक्रम, नीपा, नई दिल्ली, (ऑनलाइन मोड), 22–26 जून, 2020
- ऑनलाइन शिक्षण के लिए क्षमता निर्माण पर संकाय विकास कार्यक्रम, नीपा, नई दिल्ली, (ऑनलाइन मोड), 3 –7 अगस्त, 2020
- शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोग पर संकाय विकास कार्यक्रम, नीपा, नई दिल्ली, (ऑनलाइन मोड), 23 – 27 नवंबर, 2020

राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र (एनआरसीई)

- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए रसायन विज्ञान संसाधनों को एकत्रित करने पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 18–19 जून, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए शिक्षा संसाधनों की पहचान पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 22–23 जून, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए समाजशास्त्र विषय संसाधनों के मिलान पर आभासी कार्यशाला (ऑनलाइन मोड), 25–26 जून, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए भौतिक संसाधनों के मिलान पर आभासी कार्यशाला (ऑनलाइन मोड), 18–19 अगस्त, 2020

- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए प्रबंधन संसाधनों की पहचान पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 20–21 अगस्त, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए राजनीति विज्ञान संसाधनों की पहचान पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 24–25 अगस्त, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए गणित संसाधनों की पहचान पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 06–07 अक्टूबर, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए इतिहास संसाधनों की पहचान पर आभासी कार्यशाला, (ऑनलाइन मोड), 08–09 अक्टूबर, 2020
- उच्च शिक्षा में शिक्षा शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 07 जनवरी, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए जीवन विज्ञान विषय पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), जनवरी 14, 2021
- उच्च शिक्षा में समाजशास्त्र शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 28 जनवरी, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए अर्थशास्त्र संसाधनों पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 04 फरवरी, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए रसायन विज्ञान संसाधनों पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 11 फरवरी, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए राजनीति विज्ञान विषय पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 18 फरवरी, 2021
- उच्च शिक्षा में प्रबंधन शिक्षकों पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 03 मार्च, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए भौतिकी संसाधनों पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 12 मार्च, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए इतिहास संसाधनों पर संकाय संवर्धन वेबिनार, (ऑनलाइन मोड), 18 मार्च, 2021
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए गणित संसाधनों पर संकाय संवर्धन वेबिनार (ऑनलाइन मोड), 24 मार्च, 2021

वर्ष 2020–21 के दौरान, डिप्लोमा कार्यक्रमों के अलावा, संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला सेमिनार, सम्मेलन और बैठकें आदि आयोजित कीं।

कुल 4318 प्रतिभागियों में से, 4242 (तालिका 2.5) भारतीय प्रतिभागी थे और 76 (तालिका 2.4) अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से थे।

संस्थान के स्थापना दिवस

संस्थान प्रतिवर्ष 11 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रथम स्थापना दिवस व्याख्यान 2007 में प्रो. प्रभात पटनायक उपाध्यक्ष, केरल राज्य योजना बोर्ड ने 'आल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑन हायर एजुकेशन इन द कांटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन' पर दिया गया। दूसरा व्याख्यान 2008 में 'डिजाईनिंग आर्किटेक्चर फार ए लर्निंग रिवाल्यूशन बेसड आन ए लाईफ साइकिल अप्रोच' पर प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा), यूनेस्को इकोटेक्नोलॉजी पीठ, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन ने दिया, तीसरा व्याख्यान 2009 में प्रो. आंदेबेतिल, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर तथा प्रोफेसर ऐमिरेटस, समाजशास्त्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'यूनिवर्सीटीज़ ने 'एजुकेशन, ऑटोनॉमी एंड अकाउन्टेबिलटी' विषय पर दिया। 2010 में चौथा व्याख्यान प्रो. मृणाल मिरी, अध्यक्ष, सेंटर फार द स्टडी आफ डवलपिंग सोसायटीज़ ने 'एजुकेशन, ऑटोनॉमी एंड अकाउन्टेबिलिटी' विषय पर दिया। सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान प्रो. कृष्ण कुमार, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'एजुकेशन एंड मोर्डनटी इन रूरल इंडिया' विषय पर दिया। आठवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2014 में इमेजनिंग नॉलेजः ड्रीमिंग डेमोक्रेसी' पर प्रो. शिव विश्वनाथन, प्रोफेसर, स्कूल आफ गवर्नमेन्ट एंड पब्लिक पॉलिसी, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनीवर्सीटी ने दिया। नौवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2015 में एजुकेशन एज एन इस्ट्रयूमेन्ट आफ सोशन ट्रांसफारमेशनः द रोल आफ मदरटंग विषय पर टी.के. ओमेन प्रो. एमिरेटस, जेएनयू नई दिल्ली ने दिया। दसवां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2016 में टी.एन. मदान, माननीय प्रो. इंस्टीट्यूट ऑफ इकानॉमिक ग्रोथ, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ने ''एम.आई.एन. एजूकेटेड पर्सन? रिफ्लेक्टिंग ऑन बिकमिंग एंड बीईंग'' पर दिया। 11वां स्थापना दिवस व्याख्यान अगस्त 2017 में प्रो. कुलदीप माथुर, भूतपूर्व निदेशक, नीपा तथा प्रोफेसर विधि और अभिशासन, जे.एन.यू., नई दिल्ली द्वारा ''चेंजिंग पर्सपैक्टिव्सः नियो लिबरल पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड एजुकेशन इन इंडिया'' विषय पर दिया गया। 2018 में बारहवां स्थापना दिवस व्याख्यान प्रो. मनोरंजन मोहंती, राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय (सेवानिवृत्त), माननीय प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान परिषद, नई दिल्ली द्वारा ''द पूअर बी.ए. स्टूडेन्टः क्राईसिस ऑफ अन्डरग्रेजुएट एजुकेशन इन इंडिया'' विषय पर दिया गया। अगस्त 2019 में 13वां स्थापना दिवस व्याख्यान प्रो. पंकज चन्द्रा, कुलपति, अहमदाबाद विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ने 'गर्वनिंग अकाडेमिकः विद् इन एंड विद्आऊट विषय पर दिया। चौदहवां स्थापना दिवस व्याख्यान समीक्षा वर्ष के अंतर्गत प्रो. ए. के. शिवाकुमार, विकास अर्थशास्त्री एवं नीति सलाहकार ने 'एजुकेशन एंड सोशल अर्पच्यूनिटीज़ : ब्रिजिंग द गैप' विषय पर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

वर्ष के प्रत्येक 11 नवंबर को मौलना अबुल कलाम आज़ाद की वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रहे थे। इस पावन अवसर पर नीपा प्रत्येक वर्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है। इस स्मृति श्रृंखला में प्रतिष्ठित शिक्षाविद् जैसे प्रोफेसर के.एन. पाणिकर, मुशीरूल हसन, अमिया बागची, पीटर डीसुजा, जोया हसन, कपिला वात्सायन, अपर्णा बासु, फुरकान कमर और नीरा चंडोक ने व्याख्यान दिया।

गयारहवां मौलाना आज़ाद व्याख्यान दिनांक 11 नवंबर 2020 को ऑनलाईन प्रो. ध्रूव रैना, इतिहास एवं विज्ञान तथा इतिहास दर्शनशास्त्र, जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केंद्र, स्कूल आफ सोशल साइन्सेस, जेएनयू, नई दिल्ली ने दिया। व्याख्यान का विषय था 'फ्यूचर आफ हायर एजुकेशनः थ्रू दे लैन्स आफ हिस्ट्री एंड फिलासफी', व्याख्यान की अध्यक्षता प्रो. एन.वी. वर्गीज, कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने की। इस समारोह में नीपा के छात्र, संकाय सदस्य तथा आमंत्रित अतिथियों के अलावा दिल्ली के अन्य संस्थानों के शिक्षाविद् और छात्रों ने भाग लिया।

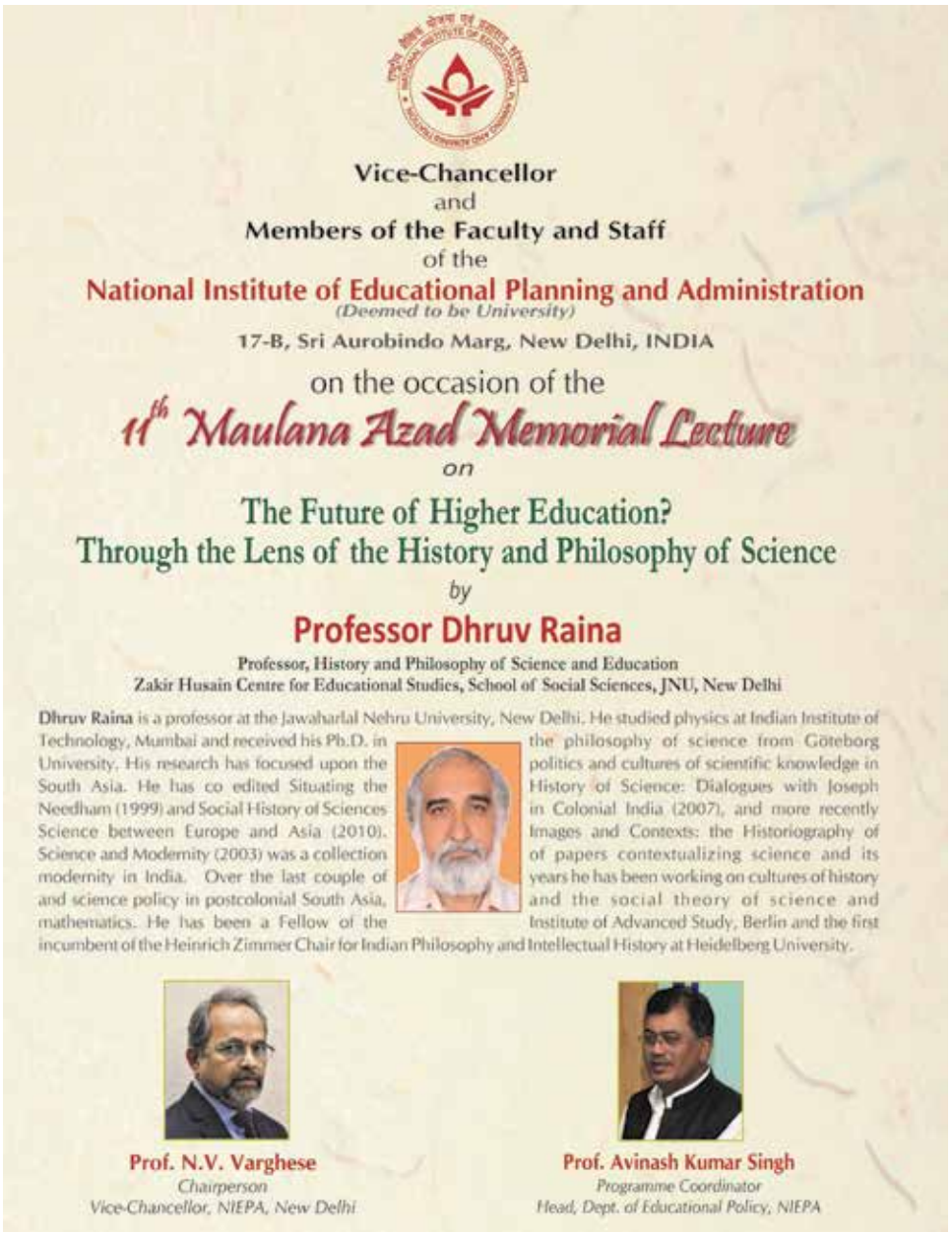

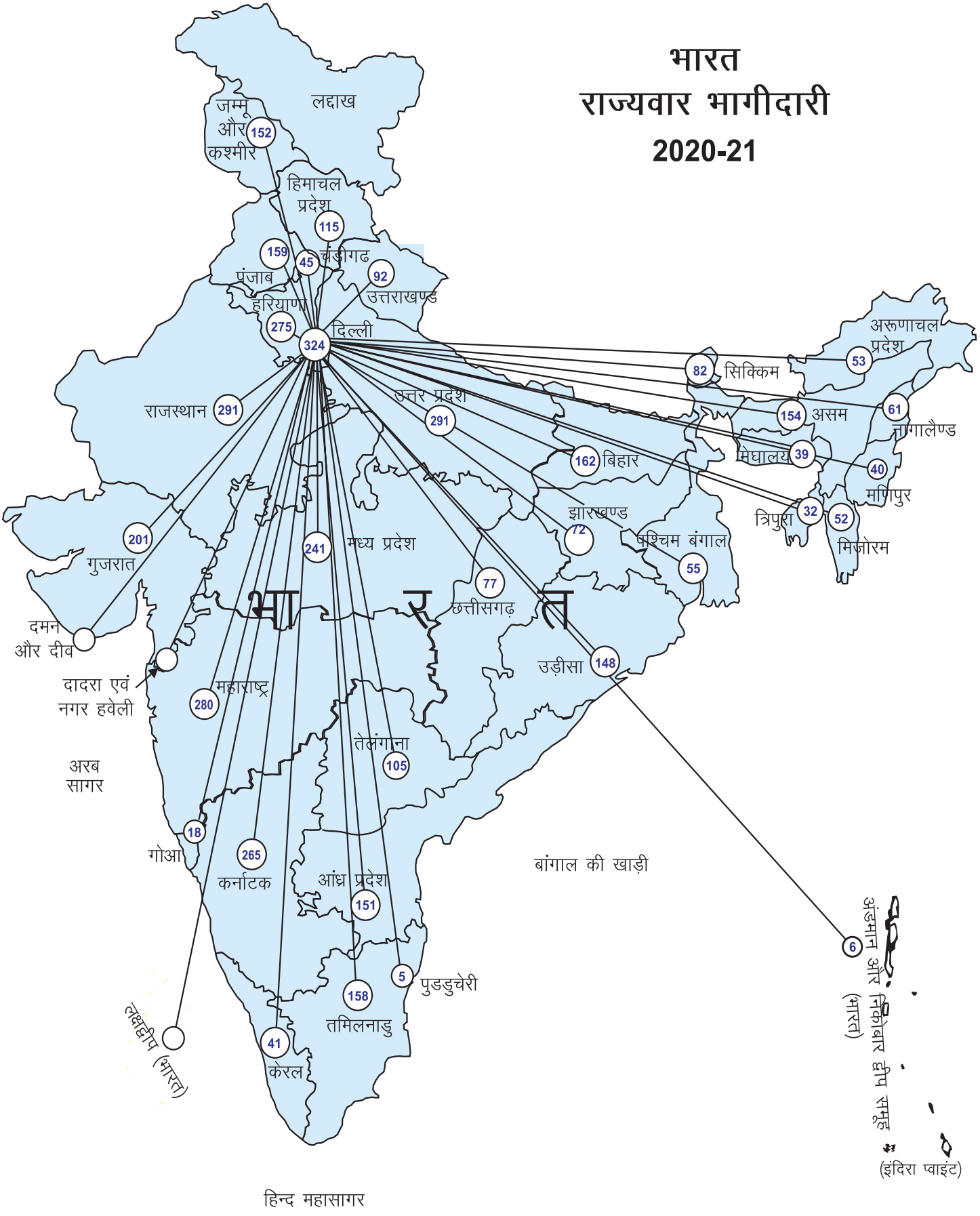

भारत
राज्यवार भागीदारी
2020-21

Map not to scale

3

अनुसंधान

अनुसंधान

संस्थान, शिक्षा क्षेत्र में विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु साक्ष्य आधारित विकल्पों और रणनीतियों को तैयार के लिए नवीन ज्ञान जुटाने हेतु, शैक्षिक नीति, योजना तथा प्रबंधन को विशेषकर ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विषयों में पारस्परिक शोध और अध्ययनों को बढ़ावा और सहायता प्रदान करता आ रहा है। संस्थान भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में भी गुणात्मक तथा गणनात्मक दोनों प्रकार के शोध, वर्तमान नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पुनरीक्षण और मूल्यांकन की तकनीकों तथा प्रशासनिक ढ़ांचों एवं प्रविधियों में तुलनात्मक अध्ययन करता है। अध्ययनों सहित ऐसे कार्य–शोध पर जोर दिया जाता है, जो शैक्षिक नीति,

योजना और प्रबंधन में सुधार के लिए मुख्य क्षेत्रों में नवीन ज्ञान को सृजित कर सकता है।

एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोध अध्ययनों, अन्य ऐजेंसियों द्वारा प्रायोजित शोध अन्तरर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त अध्ययनों कार्यक्रम मूल्यांकन अध्ययनों और आंकड़ा प्रबंधन अध्ययनों जैसे शोध कार्यक्रम को भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली में उठने वाले संभावित प्राथमिकता के मुद्दों अथवा भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तव में जिन मुद्दों से जूझ रही है, उनसे संबंधित शोध अध्ययन होते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 7 शोध अध्ययन पूर्ण किए गए, जबकि 26 अध्य्यन प्रगति पर हैं।

पूर्ण शोध अध्ययन

(31 मार्च, 2021 तक)

1. **भारत में उच्चतर शिक्षा का शासन और प्रबंधन**

   अन्वेषकः डा. गरिमा मलिक

   अध्ययन पूरा हुआ।

2. **स्कूल की पसंद और प्रक्रियाएं; पड़ोसी स्कूली शिक्षा का अध्ययन**

   अन्वेषकः डा. नरेश कुमार

   अध्ययन पूरा हुआ।

3. **भारत के शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक भागीदारी का समालोचनात्मक मूल्यांकन**

   अन्वेषकः डा. सुनीता चुग

   अध्ययन पूरा हुआ।

4. **भारत की उच्चतर शिक्षा में अनियत अधिगम मार्ग की योजना**

   प्रधान अन्वेषकः डा. गरिमा मलिक

   अध्ययन पूरा हुआ।

5. **स्कूल प्रबंधन समितियाँः भारत में शैक्षिक क्षेत्र में खुली सरकार की ओर एक कदम**

   अन्वेषकः डा. सुनीता चुग

   अध्ययन पूरा हुआ।

6. **भारत में सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों का शैक्षणिक नेतृत्व विकास**

   अन्वेषकः डा. एन. मैथिली

   अध्ययन पूरा हुआ।

7. **भारत में माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक–निजी मिश्रणः आकार और स्कूल सुविधाएं तथा प्रवेश रूपरेखा**

   अन्वेषकः डा. एन.के. मोहंती और प्रो. एस.एम. आई.ए. जैदी

   अध्ययन पूरा हुआ।

अनुसंधान अध्ययन (जारी)

(31 मार्च, 2021 तक)

1. शैक्षिक प्रशासन और विषयगत अध्ययन का तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश

शैक्षिक प्रशासन विभाग ने राज्यों के सहयोग से दिसंबर 2014 में शुरू किए गए सर्वेक्षण कार्य का तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन करने का प्रस्ताव किया। सभी राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे राज्यों में शैक्षिक प्रशासन का कार्य सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करें। विभिन्न राज्यों ने अलग–अलग समय पर अनुरोध पर प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया देने वाले राज्य भी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय सीमा में सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं कर सके। अतः विशिष्ट कार्यशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्रीय और राज्यों के नोडल अधिकारियों एवं संबंधित टीमों को सर्वेक्षण करने के उद्देश्य और पद्धति की ओर उन्मुख किया गया। उन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए जानकारी और डेटा एकत्र करने के साथ–साथ प्रारूप और सामग्री के लिए उपकरण भी प्रदान किए गए थे। अधिकांश राज्यों ने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया और अपने–अपने राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। हालांकि, छह राज्यों (झारखंड, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय) में सर्वेक्षण कार्य बहुत प्रगति नहीं कर सका। इन राज्यों को एक बार फिर सर्वेक्षण कार्य के लिए राजी किया गया। दिल्ली, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा में शैक्षिक प्रशासन का सर्वेक्षण अप्रैल 2018 में नीपा में नोडल अधिकारियों की कार्यशाला के साथ शुरू किया गया था। 12–13 अप्रैल 2018 को नए नोडल अधिकारियों और उनकी टीम के सदस्यों के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया और विधि के साथ राज्य रिपोर्ट तैयार करने और नोडल अधिकारियों को परिचित करने के लिए अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इन राज्यों के 17 अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। नोडल अधिकारी और टीम के सदस्य रिपोर्ट की तैयारी के लिए सर्वेक्षण कवरेज, कार्यप्रणाली, सामग्री और प्रारूप के बारे में उन्मुख थे। इस तरह इन छह राज्यों में सर्वेक्षण के दूसरे चरण के औपचारिक शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त हुआ।

छह राज्यों (दिल्ली, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा) में सर्वेक्षण की दिशा में प्रगति हुई।

2018 में फिर से शुरू होने के बाद सभी छह राज्यों में सर्वेक्षण कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है। राज्यों में सर्वेक्षण करने की पद्धति के एक भाग के रूप में, झारखंड, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा में राज्य स्तरीय कार्यशालाएं पूरी हो चुकी हैं। सर्वेक्षण कार्य पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकारियों की नीपा में कई बैठकें हुई। सर्वेक्षण के अनुसार, शैक्षिक प्रशासन के संस्थागत स्तर पर सचिवालय, निदेशालय, क्षेत्रीय, जिला, ब्लॉक और शिक्षा विभाग के संगठनात्मक सेट–अप, भूमिकाओं, कार्यों और गतिविधियों को कवर करते हुए राज्य, क्षेत्रीय, जिला ब्लॉक और से आंकड़े और जानकारी एकत्र किए जाने हैं। इसमें माध्यमिक तथा प्राथमिक डेटा और सूचना दोनों शामिल हैं। प्राथमिक डेटा वर्ष 2017–2018 से संबंधित होंगे। सर्वेक्षण के नमूने में तीन जिले सम्मिलित हैं– एक शैक्षिक रूप से उन्नत; एक मध्यम रैंकिंग और एक पिछड़ा; नमूने के प्रत्येक जिले से तीन ब्लॉक; और 24 स्कूल– प्रत्येक जिले से आठ स्कूल जिनमें 2 प्राथमिक, 2 उच्च प्राथमिक, 2 माध्यमिक और 2 वरिष्ठ माध्यमिक शामिल हैं। सर्वेक्षण कार्य पांच राज्यों में शुरू हुआ है। पांच राज्यों– झारखंड, जम्मू–कश्मीर, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं और बैठकों में सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मेघालय, झारखंड, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे चार राज्यों ने राज्य रिपोर्टों का पहला मसौदा पूरा कर लिया है। रिपोर्ट पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए नीपा में 13–14 मई 2019 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें नोडल समन्वयकों और सर्वेक्षण दल के सदस्यों ने भाग लिया। मसौदा रिपोर्ट की प्रतिक्रिया और समीक्षा के आधार पर, मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा ने अपने–अपने राज्यों की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और

संबंधित राज्यों के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट की अंतिम प्रति प्रस्तुत की। तीन राज्यों (मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा) के सर्वेक्षण की रिपोर्ट की अंतिम प्रति दिसंबर 2020 को प्राप्त हो गई है। इन रिपोर्टों की समीक्षा की जा रही है और परियोजना निदेशक द्वारा सामग्री संपादित की जा रही है। इन्हें मार्च 2021 तक तकनीकी संपादन और प्रसार/प्रकाशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। दिल्ली ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री विभाग को उपलब्ध कराई थी, लेकिन स्वयं रिपोर्ट तैयार करने में असमर्थता व्यक्त की। शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली से मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली रिपोर्ट तैयार की जा रही है। झारखंड के मामले में मसौदा रिपोर्ट की समीक्षा बैठक के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि मसौदा राज्य द्वारा साझा किया गया है, रिपोर्ट को सामग्री और सूचना के संदर्भ में पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है। अतः रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए हुई बैठक का परिणाम अनिर्णायक रहा। मिली जानकारी के अनुसार नोडल अधिकारी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी अकस्मात मृत्यु होने कारण तथा इस दौरान प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों का तबादला होने एवं कोविड–19 महामारी के कारण कार्य अवरूद्ध रहा है। एक बार फिर कार्य को लेने और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग को कहा जाएगा। जम्मू और कश्मीर में सर्वेक्षण का कार्य देर से शुरू हुआ था। इस कारण प्रतिक्रिया नहीं होने से सर्वेक्षण का कार्य लंबित था। रिपोर्ट पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए नीपा में 13–14 मई 2019 को समीक्षा बैठक के आयोजन के पश्चात प्रक्रिया में तेजी लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। नई टीम का गठन किया गया और जुलाई 2019 में जम्मू और कश्मीर में प्रक्रिया को फिर से शुभारंभ किया गया। राज्य ने 15–16 जुलाई को श्रीनगर में कार्यशाला आयोजित की, जिसमें अधिकारियों और संस्थागत प्रमुखों ने भाग लिया और प्रश्नावली और समूह चर्चाओं के माध्यम से जानकारी प्रदान की। जम्मू–कश्मीर में सर्वे का काम शुरू हो गया है. राज्य के अधिकारियों ने सर्वेक्षण पूरा करने में उत्सुकता दिखाई थी लेकिन राज्य में धारा 370 के निरस्त होने से स्थिति अवरूद्ध हो गई। हालांकि नोडल अधिकारी ने सर्वे का काम कराने के लिए समिति के पुनर्गठन की बात कही थी लेकिन मार्च 2020 में कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है. एक बार फिर राज्य को काम पूरा करने के लिए राजी किया जाएगा। अब एक अलग यूटी रिपोर्ट के रूप में फिर से शुरू होने की संभावना है।

सर्वेक्षण कार्य को निरंतर ध्यान में रखते हुए परियोजना को मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। परंतु को. विड–19 महामारी की भयावह स्थिति के कारण सर्वेक्षण की प्रक्रिया में और देरी हो रही है। प्रसार/प्रकाशन सहित कार्य को पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय लगेगा। दी गई परिस्थितियों में, परियोजना के सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारियों को एक अलग नोट प्रस्तुत किये जाएंगे।

2. शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्यों का अध्ययन (शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण के भाग के रूप में विषयगत अध्ययन)

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश, डा. मंजू नरूला और डा. विनीता सिरोही

अध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्य के पहलू पर संसाधन डाटा अंतराल को पूरा करना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रशासन की संरचना और कार्यों पर शायद ही जानकारी उपलब्ध है। शिक्षा विभाग की वेबसाइटों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शैक्षिक प्रशासन की संरचना की बुनियादी जानकारी शामिल है, लेकिन ये मुख्य रूप से सचिवालय और निदेशालय स्तरों तक सीमित हैं। अधिकांश मामलों में निदेशालय स्तर से नीचे शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे की जानकारी बहुत कम है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जिले में और जिला स्तर के नीचे के अधिकारियों के पदनाम, स्थिति और भूमिका में काफी भिन्नताएं हैं। क्षेत्र स्तर के शैक्षिक प्रशासन की स्थिति, भूमिका और कार्यात्मक जिम्मेदारियों का शैक्षिक सेवाओं के कुशल और प्रभावी वितरण पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। जिले और निचले स्तर पर शैक्षिक प्रशासन नीतियों और शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करना जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में शैक्षिक विकास के लिए

नीतिगत पहल, क्षेत्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की स्थिति, भूमिका और कार्यों में मानकीकरण कुछ हद तक आवश्यक है। वास्तव में, संरचनाओं और कार्यों में कोई समानता नहीं है। शैक्षिक प्रशासन से संबंधित कई समस्याएं और मुद्दे हैं। तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण शैक्षिक प्रशासन की राज्य रिपोर्टें इन्हें इंगित करती हैं। शैक्षिक प्रशासन की नई चुनौतियाँ किस हद तक प्रशासनिक संरचना नई मांगों और चुनौतियों के लिए पर्याप्त रूप से जवाबदेह है, इसके अन्वेषण की आवश्यकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई राज्यों ने विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से जिला और ब्लॉक स्तरों पर अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार किए हैं। बिहार कई अन्य राज्यों के साथ इस संबंध में उदाहरण है। कुछ राज्यों में शुरू किए गए सुधार के उपाय दूसरों के लिए शिक्षाप्रद हो सकते हैं। कई बार प्रशासनिक संरचना में किए गए सुधार और राज्य में इसकी कार्यात्मक जिम्मेदारियां अन्य राज्यों के लिए सीखने की संभावनाओं को खोलती हैं। सार्वजनिक डोमेन में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण, पारस्परिक रूप से सीखने की संभावना नहीं है। विभिन्न स्तरों शैक्षिक प्रशासन की संरचना पर जानकारी की अनुपलब्धता के अलावा; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रशासन के हर स्तर से जुड़ी कार्यात्मक जिम्मेदारी पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इस संदर्भ में वर्तमान अध्ययन किया गया है। वर्तमान अध्ययन ने तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण में शेष अंतरालों को और साथ ही साथ सूचना की आलोचनात्मकता को भरने के लिए शैक्षिक प्रशासन के चार महत्वपूर्ण स्तरों को लिया है: (1) संघ स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, जिसमें नियामक और पेशेवर निकायों की भूमिका और कार्य शामिल हैं; (2) केंद्र शासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रशासन; (3) राज्यों में शैक्षिक प्रशासन; और (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शैक्षिक प्रशासन।

कार्य प्रगति पर है लेकिन अनुसंधान दल के सदस्यों की अन्य अध्ययनों में संलग्नता और सेवानिवृति के कारण धीमी प्रगति कर रहा है (डॉ. मंजू नरूला अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक महिला शैक्षिक प्रशासकों पर अध्ययन पूरा करने में व्यस्त थीं और प्रो. विनीता सिरोही, गैर–शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अध्ययन पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थीं)। वास्तव में, शैक्षिक प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर आंकड़ों के माध्यमिक स्रोत एकत्र कर लिए हैं। सूचनाओं का प्रारंभिक संकलन प्रगति पर है। प्रारंभिक लेखन को तीन स्तरों– संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबोधित करते हुए नीपा/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाली तीन कार्यशालाओं में परिचर्चा के लिए साझा की जाएगी। अध्ययन के एक भाग के रूप में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा का प्रशासन और प्रबंधन पर एक कार्यशाला 22–23 जुलाई, 2019 आयोजित की गयी थी। जिसमें लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पांडिचेरी के मनोनीत अधिकारियों ने भाग लिया। पुडुचेरी ने सूचना की एक विस्तृत प्रपत्र प्रस्तुत की है। अन्य द्वारा प्रस्तुत करना बाकी है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक अलग रणनीति तैयार की जा रही है। अध्ययन रिपोर्ट के क्षेत्र स्तर/नीपा आधारित कार्यशालाओं के आधार पर तैयार होने की उम्मीद मार्च–अप्रैल 2020 में निर्धारित/संभावित थी, लेकिन सभी स्तरों पर शिक्षा क्षेत्र में व्यवधान के कारण अमल में नहीं आ सके। यह अब आंकड़े एकत्र करने के लिए मिश्रित माध्यम में शुरू होगा। सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

3. शैक्षिक प्रशासन में जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की स्थिति, भूमिका और जिम्मेदारियां (तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण प्रशासन का हिस्सा के रूप में विषयगत अध्ययन)

अन्वेषकः प्रोफेसर कुमार सुरेश, डा. मंजू नरूला और डा. वी. सुचरिता*

जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक अधिकारी होते हैं। वे स्कूलों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन उनकी निगरानी और समर्थन के मामले में स्कूलों से निकटता से जुड़े होते है; वे स्कूलों और उच्च स्तर के शैक्षिक प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्कूल स्तर पर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण कार्यकारी जिम्मेदारियों को दर्शाता है। भूमिका और जिम्मेदारियों के विस्तार

के संपूर्ण पहुंच को समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये अधिकारी क्षेत्र स्तर पर उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इस अध्ययन के आंकड़े प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन मुख्य रूप से तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण शैक्षिक प्रशासन के साथ जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलनों के साथ–साथ जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से संबंधित क्षेत्र–आधारित आंकड़ा संग्रह पर उपलब्ध डेटाबेस पर आधारित होगा। शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण की राज्य रिपोर्ट में विवरण ाात्मक प्रारूप के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तर के शैक्षिक प्रशासन के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियों के अलावा, जिसमें वर्णनात्मक प्रारूप के अनुसार स्थिति, भूमिका और कार्यकारी जिम्मेदारियां शामिल हैं। हालांकि, विश्लेषणात्मक आयाम शामिल नहीं हैं। वर्णनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य से किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों और जानकारी के अलावा आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होगा। विश्लेषणात्मक दृढ़ता के संदर्भ में वर्णनात्मक आंकड़ों के महत्व को जोड़ने के लिए, गुणात्मक आयामों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह जिलों और छह ब्लॉकों को जोड़ा जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों और क्षेत्र आधारित आंकड़ों की स्थिति, जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों और चुनौतियों दोनों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन किया जाना है।

कार्य प्रगति पर है लेकिन अनुसंधान दल के सदस्यों के अन्य अध्ययनों में संलग्नता/अवकाश/सेवानिवृत्ति के कारण अतिरिक्त समय लगने की संभावना है। (डॉ. मंजू नरूला अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक महिला शैक्षिक प्रशासकों पर अध्ययन पूरा करने में व्यस्त थीं और डॉ. वी. सुचरिता मातृत्व/शिशु की देखभाल अवकाश पर थीं)। दरअसल, आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत एकत्र कर लिए हैं। प्राथमिक आंकड़े एकत्र किये जाने बाकी है। क्षेत्र स्तर की गतिशीलता को पकड़ने के लिए अनुसंधान उपकरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आंकड़ों के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों को इकट्ठा करने और उनका मिलान करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अध्ययन के सितंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

4. भारत के शैक्षिक शासन में संघवाद और संघ–राज्य संबंध

अन्वेषकः प्रो. कुमार सुरेश

संघीय प्रणालियों में शैक्षिक प्रशासन संवैधानिक रूप से अनिवार्य न्यायिक विनिर्देश और सरकार के गठन के बाद से दो स्तरों– सरकारी और घटक इकाइयों के बीच जिम्मेदारियों को सौंपने पर आधारित है। कुछ मामलों में शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी विशेष रूप से घटक इकाइयों की होती है। संघीय इकाइयों के लिए नीति और वित्तीय स्वायत्तता स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारियों के वितरण के आधार पर होती हैं। अतः शिक्षा के शासन में संघीय सरकारों और घटक इकाइयों के बीच संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है।

भारत में शैक्षिक प्रशासन की अपनी गतिशीलता संघीय विविधता के तर्क और संदर्भ में गहराई से निहित है। संघ और राज्यों के संवैधानिक रूप से परिभाषित जिम्मेदारियों और यथोचित सीमांत क्षेत्राधिकार सरकार के दो स्तरों के रूप में भारत में शिक्षा के संघीय शासन का औपचारिक मॉडल है। यह एक स्तर पर संघीय इकाइयों की स्वायत्तता के अंतर्निहित आधार पर आधारित है और दूसरे स्तर पर बड़े संघीय आदेश के साथ जैविक कड़ी है। संघीय सरकार से राज्यों के शैक्षिक प्रयासों में सक्षम भूमिका निभाने और साथ ही संघीय विविधता के साथ राष्ट्रीय (संघीय) प्राथमिकताओं को सामंजस्य बनाने में भी उम्मीद की जाती है।

भारत में शिक्षा का प्रशासन संघ और राज्यों के बीच एक साझा जिम्मेदारी है। साझा जिम्मेदारी का संदर्भ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रभावित धाराओं के तर्क का विस्तार है। शासन के इस पहलू को संघ और राज्यों के बीच कुछ हद तक सहयोग की आवश्यकता है। संघ और राज्यों के बीच सहकारी साझेदारी की भाषा अक्सर भारत में शिक्षा के संघीय शासन के मॉडल का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है। सहकारिता साझेदारी (सहकारी संघवाद) का यह उपयोग प्रशासन की समन्वय संरचना के समरूप संबंधों में कितनी सक्षमता के साथ आ सका है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके अन्वेषण की आवश्यकता है। निस्संदेह, संवैधानिक व्यवस्था के

मूल स्कीमा ने शिक्षा के प्रशासन में राज्यों के लिए एक अपेक्षाकृत स्वायत्त डोमेन की परिकल्पना की थी। हालांकि, शिक्षा में सुधार के लिए संघीय सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधनों, अधीनस्थ विधानों और नीतिगत पहलों के रूप में संवैधानिक विकास ने संघ–राज्य संबंधों और शासी शिक्षा में राज्यों की क्षमता को काफी हद तक प्रभावित किया है। विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद पिछले कई दशकों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। केंद्र सरकार की दिशानिर्देशों में कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं और एजेंसियों के प्रसार, इस अवधि के महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। ये संघीय सरकार के विस्तार की भूमिका और राज्य सरकारों की सिकुड़ती क्षमता के साधन के रूप में हैं। इसी संदर्भ में अध्ययन आयोजित किया जा रहा है।

अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक आंकड़ों के आधार पर डेस्क और क्षेत्र आधारित अनुसंधान दोनों का संयोजन है। इसके तीन घटक हैं। पहले संघ–राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक और उत्तर संवैधानिक विकास का अध्ययन है। इसका प्रमुख उद्देश्य अधिनियम, अधीनस्थ विधान एवं नीतिगत पहल और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार करना। दूसरा मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा पर केंद्रित होगा और तीसरा उच्च शिक्षा पर केंद्रित होगा। अनुभवजन्य अध्ययन के लिए कुछ राज्यों को जानकारी के रूप में लिया जाएगा। परियोजना सलाहकार समिति के विशेषज्ञों और सदस्यों के परामर्श से अध्ययन में शामिल किए जाने वाले आयामों के विवरण पर काम किया जाएगा।

इस अध्ययन की जनवरी 2019 से शुरू हो गया है। माध्यमिक साहित्य और सामग्री एकत्र की गई है। परियोजना की प्रस्तावित अवधि जनवरी 2019 से शुरू होकर दो वर्ष है? लेकिन, सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने हेतु प्राथमिकता देने, राज्यों में कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित करने और सर्वेक्षण दल के सदस्यों के साथ बैठकों में परियोजना अन्वेषक की व्यस्तता के अलावा रजिस्ट्रार (प्रभारी), नीपा की अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के कारण परियोजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। जब तक क्र. सं. 2 और 3 सर्वेक्षण कार्य एवं अध्ययन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक कार्य धीमी गति से चलता रहेगा। सर्वेक्षण कार्य के साथ–साथ दो अध्ययनों के सितंबर, 2021 तक पूरो होने की संभावना है।

5. भारत में तुलनात्मक शैक्षिक लाभ की स्थानिक गतिशीलता

अन्वेषकः प्रो. मोना खरे

परियोजना मुख्य विशेषताएं: भारत में शैक्षिक विकास में अंतर राज्यीय भिन्नता के निर्धारकों की पहचान करने के लिए माध्यमिक आंकड़ा आधारित अनुसंधान अध्ययन; शैक्षिक विकास के संकेतकों की पहचान के बाद शैक्षिक विकास के बहुभिन्नरूपी सूचकांक का विकास करना।

गतिविधियों का प्रदर्शनः स्कूली शिक्षा के लिए सारणीकरण और आंकड़ा विश्लेषण कार्य पूर्ण हो चुका है और पहले तीन मसौदा अध्याय तैयार है। उच्च शिक्षा विकास के संकेतक की पहचान की गई है और माध्यमिक स्रोतों से डाटा संकलन प्रगति पर है। पहचान किए गए स्थानिक विकास और डाटा संकलन के समग्र सूचकांक के निर्माण के लिए संकेतक प्रगति पर हैं। जिला स्तर पर डाटा की उपलब्धता का पता लगाने के लिए, राज्य के चुनिंदा अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। सेमिनार में प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्रकाशित तीन पत्र, प्रकाशन के लिए स्वीकार किए गए हैं, कुछ महीनों में प्रकाशित होने की उम्मीद है।

राज्य स्तरीय विश्लेषण पूरा हो गया है।

जिला स्तर पर आंकड़े एकत्र किये गये हैं; संकलित एवं संपादित तालिकाएँ तैयार कर ली गई हैं। तीन राज्यों के शिक्षा और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए जिलेवार समग्र सूचकांक पूरे हो चुके हैं। अब जिला स्तरीय बहुभिन्नरूपी सूचकांकों का विश्लेषण किया जा रहा है।

6. मॉड्यूलः उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और भेदभाव

अन्वेषकः डा. निधि एस. सभरवाल और डा. सी.एम. मलिश

इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य छात्र विविधता, भेदभाव और नागरिक शिक्षा पर मॉड्यूल तैयार करना है। मॉड्यूल छात्रों की विविधता और नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक जुड़ाव में उच्च शिक्षा की भूमिका के मुद्दों पर उच्च शिक्षा में संकाय और प्रशासकों को संवेदनशील बनाना होगा।

मॉड्यूल की रूपरेखा के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया। आइसीएसएसआर, मा.सं.वि. मंत्रालय और नीति आयोग के शिक्षाविदों और प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। मॉड्यूलों की मसौदा रूपरेखा तैयार करने के बाद, विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक 7 जनवरी 2017 को आयोजित की गई जिसमें प्रत्येक मॉड्यूल को समिति के सामने प्रस्तुत किया गया।

मॉड्यूल के समग्र दृष्टिकोण और सामग्री की सामूहिक समझ विकसित करने में मदद के लिए मॉड्यूल के लेखकों की पहली बैठक 16 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी।

मॉड्यूल के लिए पहचाने गये क्षेत्रों में शामिल हैः

मॉड्यूल 1: उच्च शिक्षा में छात्र विविधता और सामाजिक समावेशः अवधारणा और दृष्टिकोण

मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्र विविधता, समानता और सामाजिक समावेश की अवधारणाओं पर चर्चा; और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोणों पर चर्चा; उच्चतर शिक्षा और कार्रवाई/हस्तक्षेप के क्षेत्रों में छात्र विविधता, समानता और सामाजिक समावेश को व्याख्यित करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों पर चर्चा करना है।

मॉड्यूल 2: उच्च शिक्षा में छात्र विविधता का वर्गीकरण

मॉड्यूल उच्च शिक्षा में छात्र विविधता के चरणों पर चर्चा करेगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र विविधता का आकलन करने की विधियों के बारे में परिचय देगा

मॉड्यूल 3: परिसरों में अकादमिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए दृष्टिकोण

मॉड्यूल का उद्देश्य छात्र सामाजिक विशेषताओं और पूर्व–महाविद्यालय शैक्षणिक पृष्ठभूमि में विविधता पर विकास और समझ; सामाजिक और पूर्व–महाविद्यालय की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षा के लिए अनुशासन और पारगमन के विकल्प के बीच संपर्क पर एक स्पष्ट समझ विकसित करना; और उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक एकीकरण और सफल पारगमन के प्रति दृष्टिकोण पर चर्चा करना है।

मॉड्यूल 4: उच्च शिक्षा में भेदभाव के रूप

मॉड्यूल का उद्देश्य परिसर में भेदभाव और प्रतीकात्मक हिंसा की अवधारणा पर एक समझ विकसित करना है; उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव के रूपों तथा शैक्षणिक और सामाजिक एकीकरण पर भेदभाव के परिणामों को समझना है।

मॉड्यूल 5: परिसर में सामाजिक समावेश

इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा परिसरों में सामाजिक समावेश की व्यापक समझ विकसित करना; छात्रों को विविध पृष्ठभूमि द्वारा सामना किए गए सामाजिक समावेश की चुनौतियों पर चर्चा तथा सामाजिक समावेशी परिसर की विशेषताओं को जानना है।

मॉड्यूल 6: छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र

इस मॉड्यूल का उद्देश्य यह समझना है कि एक सामूहिक प्रणाली में छात्र विविधता को संस्थागत रूप से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण क्यों है; छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र और संरचनाओं को जानना; छात्र विविधता के प्रबंधन के लिए सामाजिक समावेश और रणनीतियों के लिए विकसित और संस्थागत संस्कृति के दृष्टिकोण का परिचय देना।

मॉड्यूल 7: छात्र विविधता, नागरिक शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी

इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में नागरिक शिक्षा की अवधारणा को पेश करना है; नागरिक विविधता के बीच नागरिक शिक्षा के लिए एक संसाधन के रूप में स्पष्ट समझ विकसित करना; नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार की पहलों के लिए दृष्टिकोणों और प्रकारों को जानना।

मॉड्यूलों के मसौदा संस्करण को पूरा किया जा रहा है।

7 भारत में उच्चतर शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगार–परकता

अन्वेषकः प्रोफेसर मोना खरे

भारत की गणना विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में सक एक के रूप में की जाती है, शिक्षित स्नातकों

की रोजगार क्षमता को अक्सर देश के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में बताया जाता है। भारत विकास की गाथा इस अर्थ में अनुपम है कि यहाँ आर्थिक विकास के व्यापक स्वीकृत मॉडल अर्थात् कृषि से उद्योग और फिर सेवा के क्षेत्र में अंतरण को झूठला दिया है। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में विनिर्माण जगत से कोने वाली वृद्धि शीघ्र ही तृतीयक क्षेत्र की प्राधान्यता से प्रतिस्थापित हो गया। साथ ही, 1960 के दशक से 1980 के दशक तक की कम रोजगार वृद्धि और इस अवधि में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या की उदारीकरण युग अर्थात् 1990 के दशक में पुनरावृत्ति हुई। वस्तुतः 1990 के दशक में रोजगार विहीन विकास हुआ। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने औद्योगिक क्षेत्र में अग्रेसित हुआ जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3/4 हिस्सा योगदान है। रोजगार के मामले में यह बात सही नहीं बैठती। जहाँ एक बड़ी आवादी कृषि और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलाप में रत है। जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जीवन निर्वाह का स्तर पारंपरिक कृषि ही है। तथापि, भावी अनुमान से पता चलता है कि रोजगार के मामले में 60 प्रतिशत नौकरियों की बढ़ोतरी सेवा क्षेत्र में होगी। स्नातकों की रोजगारपरकता की समस्या में पूर्ति और मांग दोों पक्ष सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं रोजगार परकता और कौशल ह्रास को भी रोजगार, बेरोजगारी और श्रम बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान अध्ययन में बाह्य और आन्तरिक कारकों के साथ–साथ मांग और पूर्ति संबंधी कारक जिनका स्नातक रोजगार परकता पर प्रभाव पड़ता है, के प्रभाव को संयुक्त रूप से दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्ययन में तीन अन्तःसंबद्ध जगत अर्थात् सूक्ष्म, संस्थानिक और व्यक्तिगत स्तरों पर भारत में स्नातक रोजगार परकता और उच्चतर शिक्षा के विषय को समझने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार हैः– शिक्षित रोजगार/बेरोजगारी के रूझान के सूक्ष्म आर्थिक आयाम; उद्योग की बढ़ती हुई माँग और विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा के आयाम; व्यष्टिक हितधारकों का उच्चतर शिक्षा में भागीदारी के बारे में बदलते हुए अवबोध और प्रत्याशा तथा रोजगार की तैयारी के सन्दर्भ में प्रावधान। इस अध्ययन का उद्देश्य शोध संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना हैः (क) उच्चतर शिक्षा स्नातकों की रोजगारपरक कौशल क्या है; (ख) उनके कार्य स्थल अपेक्षाओं की तुलना में विश्वविद्यालय की शिक्षा के दौरान रोजगार की तैयारी के बारे में नए कर्मचारियों के क्या अनुभव हैं; (ग) रोजगार परकता के लिए कौशल विकसित करने के बारे में विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा संस्थानों से क्या उम्मीदें हैं; (घ) उद्योग के लिए तैयार स्नातकों को तैयार करने में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की भूमिका में विश्वविद्यालय के शिक्षक और प्रशासकों की क्या अनुक्रिया है? (ङ) क्या स्नातक रोजगार परकता कौशल नीति समय की माँग है? प्रमुख हितधारकों के संदर्श यथा नियोक्ता और नए कर्मचारी, विद्यार्थी और शिक्षकगण का पता लगाया जाता है जो शोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। यह देश में बहु–स्तरीय, बहु–राज्यीय अध्ययन है जिसमें देश के कई शहरों को शामिल किया गया है। चिन्हित छह शहरों में स्तर–I के चार शहर– मुम्बई, दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद हैं। स्तर–II के शहरों में लखनऊ प्रमुख रोजगार प्रदाता है; स्तर–III श्रेणी के शहरों में उदयपुर रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रथम तीन शहरों में से एक है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य स्नातक रोजगार परकता को सभी हितधारकों के अवबोध का विश्लेषण करना; नियोक्ता–कर्मचारी समुदाय और शैक्षणिक समुदाय (विद्यार्थी और शिक्षकों) में स्नातमक रोजगार परकता कौशल के बारे में प्रसरण व विभिन्नता को समझना, महिला और पुरुष, सामाजिक समूहों और क्षेत्रों के बीच कौशल अंतरक विभेद की रोजगार परकता का परिमाप, भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यमान ऑन–कैम्पस/ऑफ कैम्पस रोजगार परकता सहयोग का अध्ययन करना और उच्चतर शिक्षा स्नातकों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में आनेवाली संस्थानिक अड़चनों को चिन्हित करना है।

विश्लेषण फ्रेमवर्क कार्यशाला 18 और 19 जनवरी, 2018 को आयोजित की गयी। 5 राज्यों (महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की उच्चतर शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगार परकता के संबंध में सीपीआरएचई अध्ययन की समीक्षा की जा रही है। (चार की समीक्षा की गई, दो अंतिम संस्करण प्राप्त हुए हैं)। उच्चतर शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगार परकता के संबंध में सीपीआरएचई का संलिष्ट प्रतिवेदन तैयार किया जाना है (शीघ्र ही पूरी होने वाली है)।

8. भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ताः संस्थागत स्तर पर बाह्य और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन का एक अध्ययन

अन्वेषकः डा. अनुपम पचौरी

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन (IQAs) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की गुणवत्ता में कोई बदलाव आया या नहीं, ऐसे बहुत कम अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। इस शोध अध्ययन का व्यापक उद्देश्य यह समझना है कि संस्थागत स्तर पर बाहरी गुणवत्ता आश्वासन (EQA) और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन (IQA) गुणवत्ता को कैसे बढ़ाये जाए; और कैसे EQA एजेंसियां उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को प्रभावित करे और कैसे संस्थागत स्तर पर IQA की संरचना और कार्य का विश्लेषण करती हैं। एनएएसी मान्यता के दूसरे या आगामी चक्र में पांच विश्वविद्यालयों और प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालयों में से संबद्ध एक–एक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और तेलंगाना के पांच राज्यों से चुना गया है।

प्रमुख अन्वेषक ने परियोजना की प्रगति कार्यान्वयन का बारीकी से पालन किया और राज्य टीमों को मसौदा रिपोर्ट तैयार करने में मदद की। जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों के कोडिंग और विश्लेषण में मदद करना और राज्य रिपोर्ट का पहला मसौदा लिखना शामिल था। अध्ययन के लिए चयनित संस्थानों से पांच संस्थागत टीमों द्वारा राज्य स्तर की रिपोर्ट का पहला मसौदा तैयार किया गया। प्रत्येक टीम को प्रत्येक अध्याय के मसौदा पर विस्तृत प्रतिक्रिया लिखने की रिपोर्ट की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया था। इसके बाद रिपोर्ट के अंतिम प्रस्तुतिकरण से पहले संशोधन के लिए टीमों को भेजे गए प्रत्येक रिपोर्ट का संपादन और समीक्षा की गई। अनुसंधान पद्धति कार्यशाला सामग्री दस संस्थानों (चार राज्य विश्वविद्यालयों और इनमें से प्रत्येक के साथ संबद्ध एक महाविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध एक महाविद्यालय) को अनुसंधान परियोजना के लिए शामिल किया गया था। सामग्री में पांच संस्थागत टीमों द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्टों पर टिप्पणियों सहित विस्तृत समीक्षा पुस्तिकाएं शामिल थीं। पुस्तिका में संबंधित टीमों के लिए शोध रिपोर्ट में सुधार करने के लिए सुझाव भी थे ताकि बाहरी गुणवत्ता आश्वासन और आंतरिक सुरक्षा आश्वासन के कारण संस्थानों में परिवर्तन को उजागर और विश्लेषण कर सकें। तृतीय अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में टिप्पणियों के लिए मसौदा राज्य रिपोर्ट और संश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रत्येक प्रस्तुति के उपरान्त समीक्षा और टिप्पणियों को सहकर्मी दल के प्रमुख ने अनुसंधान रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कार्य सौंपा। इसके बाद टीम के अन्य सभी सदस्यों की टिप्पणियों का पालन किया गया। अंत में, परियोजना समन्वयक और अनुसंधान परियोजना के प्रधान अन्वेषक डा. अनुपम पचौरी द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। शोध पद्धति कार्यशाला में टिप्पणियों और चर्चाओं के मद्देनजर समीक्षा टिप्पणी पुस्तिका को और संशोधित करके सभी टीमों के साथ साझा किया गया ताकि दल की राज्य रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके। संस्थागत टीमों की प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए परियोजना अनुसंधान पद्धति की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई।

वर्तमान में, वेब अपलोड के लिए प्रधान अन्वेषक/ परियोजना समन्वयक द्वारा राज्य टीम की रिपोर्ट संपादित और संश्लेषण कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईक्यूए और ईक्यूए विषय पर एक शोध पत्र और नीति संक्षिप्त विकसित की जाएगी।

प्रोजेक्ट आउटपुटः (अ) 5 राज्य रिपोर्ट, (ब) 1 संश्लेषण रिपोर्ट (स) अनुसंधान पत्र (द) नीति संक्षेप, इसके अलावा, 2015 में आयोजित सेसी (CESI) के छठे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गुणवत्ता आश्वासन पर पैनल में एक लेख प्रस्तुत; इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट IHER: 2017 (2018 में प्रकाशित) पुस्तक संपादितः टीचिंग लर्निंग एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड; संपादित पुस्तक IHER 2017 में एक पुस्तक अध्याय; भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों पर गुणवत्ता आश्वासन के प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 2018 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर लेख प्रस्तुत किया गया; उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर रिपोर्ट (नीपा द्वारा 2019 में प्रकाशित)। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्रों पर

संपादित संस्करण (प्रकाशक को प्रस्तुत करने के लिए पांडुलिपि संपादित की जा रही है); दो नीति संक्षेपों की ढांचा/रूपरेखा विकसित की जा रही है।

9. उच्च शिक्षा की सफलता और सामाजिक गतिशीलताः विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों के कोचिंग योजनाओं पर अध्ययन

अन्वेषकः डा. सी.एम. मलिश और डा. निधि एस. सभरवाल

यू.जी.सी. के अनुरोध पर सीपीआरएचई/नीपा ने यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित कोचिंग योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया। ये योजनाएँ निम्नलिखित हैंः 1. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों के लिए सुधारात्मक कोचिंग; 2. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए नेट/सेट की कोचिंग; और 3. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग। योजना के प्रमुख उद्देश्य वंचित समूहों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाओं के रूप में अतिरिक्त शिक्षण इनपुट प्रदान करना ताकि शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और व्यवसाय की गतिशीलता को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके और आजीविका की गतिशीलता को सुगम बनाया जा सके। सीपीएचआरई दल द्वारा यूजीसी कोचिंग योजनाओं के समन्वयकों और दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वंचित समूहों के अकादमिक सशक्तिकरण से जुड़े संकाय सदस्यों के परामर्श से अनुसंधान उपकरण विकसित किए थे। इस योजना के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों का अध्ययन किया और आंकड़ों/सूचनाओं के संग्रहण और विश्लेषण के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों को अपनाया गया। जिसमें माध्यममिक आंकड़ा भी शामिल है, वर्तमान में कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के बीच प्रश्नावली प्रबंधन और छात्रों के साथ समूह चर्चा, संकाय समन्वयक संकाय सदस्यों/कोचिंग कक्षाओं के प्रशिक्षकों और संस्थागत प्रमुखों के साथ साक्षात्कार आदि शामिल हैं।

अनुसंधान उपकरण और कार्यान्वयन प्रक्रिया पर एक साझा समझ विकसित करने के लिए 02–03 मई, 2017 को शोध अध्ययन संस्थानों के अनुसंधान समन्वयकों के साथ पहली अनुसंधान कार्यप्रणाली कार्यशाला आयोजित की गई। सीपीआरएचई अनुसंधान समन्वयकों द्वारा क्षेत्र का दौरा पूरा किया गया है। अर्थात् पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र, गवर्नमेंट कॉलेज त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनवर्सिटी, मेघालय, एसबीएमपीजी कॉलेज, फाजिलनगर, कुशीनगर, यूपी, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात, गया कॉलेज, गया, बिहार, दोआब कॉलेज, जालंधर, पंजाब और चौधरी देवी लाल सिरसा विश्वविद्यालय, हरियाणा शामिल हैं। अनुसंधान समन्वयकों ने आंकड़ा संग्रह की निगरानी की तथा प्रधान जांचकर्ताओं और परियोजना कर्मचारियों के साथ आंकड़ा संग्रह में भाग लिया।

10. भारत में माध्यमिक शिक्षा में सरकारी–निजी संलयनः आकार, विद्यालय की सुविधाएं और प्रवेश की रूपरेखा

अन्वेषकः डा. एन.के. मोहंती और
प्रो. एस.एम.आई.ए. जैदी

सामान्य रूप से शिक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका और विशेष रूप से शिक्षा सेवा के वितरण में सार्वजनिक–निजी मिश्रण पर परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मैक्रो स्तरीय अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं–

(i) प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर संस्थागत मिश्रण (सार्वजनिक–निजी) के पैटर्न को स्थापित करना।

(ii) स्कूल प्रावधानों, स्टाफिंग पैटर्न और अन्तर्ग्रहण की विशेषताओं के आधार पर सार्वजनिक और निजी संस्थानों की प्रोफाईल

(iii) स्कूलों के मिश्रण और हिस्सेदारी पर संभावित प्रभावों के संदर्भ में विस्तारित पहुंच के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के निहितार्थ की पहचान करना; तथा

(iv) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रमों की योजना बनाना और संसाधनों के आवंटन हेतु निहितार्थ निकालना।

अध्ययन के प्रथम चरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

अध्ययन के पहले चरण के व्यापक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) यद्यपि 2009–10 और 2016–17 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में समान वृद्धि हुई है, सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी आई है और निजी गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रतिशत हिस्सेदारी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूर्वी राज्यों को छोड़कर पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण के अधिकांश राज्यों 2009–10 और 2016–17 के बीच बढ़ा है, इससे पता चलता है कि आरएमएसए देश में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच के समान अवसर के मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं है।

(ii) 2009–10 और 2016–17 दोनों में अधिकांश राज्यों में, कक्षा 9वीं – 10वीं में नामांकन का प्रतिशत सरकारी स्कूलों में अधिकतम था, इसके बाद निजी गैर–सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का स्थान रहा।

(iii) जैसे–जैसे हम नामांकन आकार के निम्न से उच्च श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मामले में उच्च नामांकन आकार वाले माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत बढ़ता है लेकिन निजी गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मामले में घट जाता है। इसलिए, लघु माध्यमिक विद्यालय सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र की घटना नहीं है और बड़ा विद्यालय/नामांकन आकार निजी क्षेत्र भी नहीं है।

(iv) सरकारी स्कूलों में लड़कियों का नामांकन का प्रतिशत निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मुकाबले सबसे अधिक है।

(v) क्षेत्रों के बीच और क्षेत्र के भीतर राज्यों के बीच भी माध्यमिक स्तर पर बच्चों की भागीदारी में काफी भिन्नता है।

(vi) महिलाओं के जीईआर में वृद्धि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अधिकांश राज्यों में पुरुषों की तुलना में अधिक है।

(vii) कुल शिक्षकों की स्थिति, सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कक्षा IX-X में नामांकन का लगभग 75 प्रतिशत था, 2016–17 में माध्यमिक स्तर (यानी कक्षा IX-X के लिए) केवल 67 प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध थे। जो ये दर्शाता है कि भारत में सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी एक प्रमुख मुद्दा है।

(viii) माध्यमिक स्तर पर छात्र–अध्यापक का अनुपात 25:1 (विषय शिक्षकों के दृष्टिगत) मानते हुए माध्यमिक स्तर पर शिष्य–अध्यापक अनुपात गैर–सहायता प्राप्त संस्थानों में सर्वाधिक अनुकूल था, जिसके बाद वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त और राजकीय संस्थाओं ने इसका अनुसरण किया। किन्तु 2016–17 में शिष्य–अध्यापक अनुपात सरकारी संस्थाओं में अनुकूल रहा। यह इस कारण है कि आर.एम.एस.ए. की विभिन्न कार्यनीतियों में एक नीति माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती और समनुदेशन, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक और वृत्तिक प्रवर्धन की चक्रीय आघूर्णन नीति को अंगीकरण करना था।

(ix) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं कक्षा में नामांकन के शेयर का प्रतिशत और राज्यों में साक्षरता दर और एनएसडीपी न केवल ऋणात्मक हैं, अपितु बहुत अधिक सार्थक भी हैं (जैसा कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक में प्रतिबिम्बित किया गया है)। इन ऋणात्मक संबंधों से निरूपित होता है कि माता–पिता की आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति जितनी अच्छी होती है, राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की मांग उतनी ही कम होती है। दूसरे शब्दों में, शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के लोग अपने बच्चों की शिक्षा–दीक्षा के लिए निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं।

(x) अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में राजकीय और निजी माध्यमिक विद्यालयों में अधिक अंतर नहीं है यद्यपि राजकीय माध्यमिक विद्यालय आर.एम.एस.ए. के विद्यमान होने के कारण निजी स्थापनाओं की तुलना में थोड़ा बेहतर हैं।

(xi) दसवीं कक्षा के लिए आयोजित बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों का उत्तीर्ण होने का प्रतिशत या उनका कार्य–निष्पादन निजी गैर–सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2016–17 में (85.7 प्रतिशत), उसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (83.9 प्रतिशत) था जबकि

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में यह प्रतिशत सबसे न्यूनतम अर्थात् 72.9 प्रतिशत था।

(xii) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में, दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों की तुलना में थोड़ा बेहतर था, जबकि निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों का प्रदर्शन 2016–17 में लड़कों की तुलना में बेहतर था।

माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रम की आयोजना के लिए निष्कर्ष और उसके महत्वपूर्ण परिणामों के होते हुए भीय इससे अतिरिक्त प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर अमूमन पूछा जाने वाला मौलिक प्रश्न यह है कि माता–पिता राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों के बीच चयन क्यों करते हैं। यह मौलिक प्रश्न ऐसे कई खोजपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है कि इस मूलभूत विषय को समझने के लिए प्रयास किया जाए। इस पृष्ठभूमि में, अध्ययन के दूसरे चरण में निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर दिये जाने का प्रयत्न किया जाएगा।

1. क्या गृहस्थियाँ अपने समुदायों में विद्यमान विद्यालयों की सम्मिश्र व जटिल सोपानिकी (पदानुक्रम) को समझती हैं? किन घटकों के आधार पर परिवार के लोग अपने संबंधित समुदाय के भीतर विद्यमान विद्यलायों की जटिल पदानुक्रम में जाने का निर्णय लेते हैं।
2. क्या गृहस्थियाँ विद्यालयों का चयन करने के क्रम में पुत्र और पुत्रियों में भेदभाव करते हैं? विशेषरूप से पुत्रों (लड़कों) को ऐसे विद्यालयों में भेजे जाने की अधिक संभावना प्रबल करती हैं जहाँ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, अर्थात् उन्हें निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने को प्राथमिकता दी जाती है
3. यदि लड़कों को निजी विद्यालयों में भेजे जाने की अधिक संभावना रहती है, तो प्रश्न उठता है कि किन कारकों के आधार पर परिवार के लोग लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति में निवेश करने का निर्णय लेते हैं? क्या पुरूष के पक्ष में अभिनत निजी विद्यालयों का चयन जिसे (प्रश्न सं. 2 के माध्यम से पता लगाया गया) राजकीय और निजी विद्यालयों में शिक्षण में आने वाली लागत से संबद्ध है? यहाँ आनुषंगिक प्रश्नों मे यह भी सम्मिलित है कि राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में अधिगम पर आने वाली लागत में कितना अंतर है?
4. माता–पिता की पसंद पर (विशेष रूप से राज्य में प्राइवेट शिक्षा की तुलना में सार्वजनिक शिक्षा की पसंद) के आधार पर स्कूली शिक्षा के निजीकरण के मामले में राज्य सरकारों की नीति का क्या प्रभाव पड़ता हैं?
5. सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता और अध्यापक गुणवत्ता तथा शिक्षण पद्धति में बहुत अधिक विविधताएं क्यों है? ये भिन्नताओं से सरकारी और निजी विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा के बच्चों का कार्य–निष्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है।
6. माध्यमिक विद्यालयों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी के क्या कारण हैं?
7. अध्यापिकाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित और सरकारी विद्यालयों की तुलना में शहरी और बिना राजकीय सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों को क्यों अधिक पसंद करती हैं?
8. विद्यालय के आकार और विद्यालय की प्रभाविकता में क्या संबंध है?
9. विद्यालय के प्रावधानों और विद्यालय के कार्य–निष्पादन के मध्य क्या कोई संबंध है? यदि हां, तो स्कूली शिक्षा के प्रावधानों और स्कूल के कार्य–निष्पादन के बीच क्या संबंध है?
10. क्या सरकारी और निजी विद्यालयों के चयन में विद्यालय परिसर में विद्यमान सुविधाओं की कोई भूमिका होती हैं? यदि हां, तो कैसे?

इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, इस अध्ययन के दूसरे चरण में निम्नलिखित बातों का पता लगाने का प्रयास किया गया हैः (i) विद्यमान शोध का परा–भौतिक; (ii) प्राथमिक आंकड़ा संकलन और उसका विश्लेषण और (iii) माध्यमिक शिक्षा के सभी हितधारकों से जानकारी एकत्र करना। यह उम्मीद की जाती है कि उपलब्ध और एकत्रित जानकारी के आधार पर उपरोक्त प्रश्नों के भारत के राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की साम्यता और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में अंतर्दृष्टि और इसके

परिणाम प्राप्त होंगे। अध्ययन के चरण–II महत्व रखता है।

11. लैंगिक पर शैक्षिक एटलस : एक जिला–स्तरीय प्रस्तुति

अन्वेषक : डा. सुमन नेगी और प्रो. मोना खरे

01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया।

12. ओडिशा में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना और शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन

अन्वेषकः डा. एस.के. मलिक

अध्ययन के उद्देश्यः

1. माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रकृति और सीमा का पता लगाना;
2. स्कूल पूर्ण होने पर अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की प्रभावशीलता और शिक्षा के उच्च स्तर पर उनकी गतिशीलता की जांच करना;
3. छात्रों को उनके अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाने और उपयोग करने में आने वाली समस्याओं और बाधाओं का पता लगाना;
4. योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार और स्कूल प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समस्याओं और बाधाओं का पता लगाना और
5. छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों का पता लगाना।

अध्ययन की पद्धति

वर्तमान में उड़ीसा राज्य का अध्ययन किया जा रहा है। वहाँ तीस जिले हैं। अध्ययन के प्रयोजनार्थ, जिले का चयन साक्षरता दर के आधार पर किया जाएगा। तीस जिलों में से अध्ययन के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अनुसूचित जाति के आवादी वाले दो जिले का चयन किया गया। (जगतसिंहपुर और खोर्दा) दो चयनित जिलों में से प्रत्येक जिले के दो प्रखण्डों का चयन माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के अधिक प्रयास के आधार पर किया गया। प्रत्येक प्रखंड से माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के सर्वाधिक नामांकन वाले 5 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। अध्ययन के प्रत्यर्थियों में प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थीगण, प्रशासकगण और माता–पिता थे।

अध्ययन की वर्तमान स्थिति

1. साहित्य की समीक्षा कार्य पूर्ण हो गया है।
2. रिपोर्ट लिखने का कार्य प्रगति पर है और अंतिम रिपोर्ट जून, 2021 तक प्रस्तुत की जाएगी।

13. चयनित राज्यों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान के कार्यान्वयन का अध्ययनः नीति और व्यवहार

अन्वेषकः प्रो. अविनाश कुमार सिंह

01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया।

14. भारत में उच्च शिक्षा सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाः सुधार के सिद्धान्तों, नीतियों और संस्थानों पर तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य (1991–2012)

अन्वेषकः डा. मनीषा प्रियम

01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया।

15. भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता

अन्वेषकः डा. नीरू स्नेही

भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता एजेंडा का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। स्वायत्तता देने का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि स्वायत्तता हमारे समक्ष उत्पन्न होने वाली बहुत सी समस्याओं के लिए रामबाण हो। इस अध्ययन का उद्देश्य इसका पता लगाना था कि सामान्यतया भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में और विशेष रूप से अधि–स्नातक महाविद्यालयों में किस हद तक स्वायत्तता है; अधि–स्नातक स्तर की संस्थाओं को

स्वायत्तता प्रदान करने में हितधारको ंकी क्या भूमिका है और साथ ही संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की तुलना स्वायत्तता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों के कार्यकरण से करना भी इसका उद्देश्य है।

इन उद्देश्यों के संदर्भ में 5 क्षेत्रों के 10 राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 40 महाविद्यालयों के नमूने से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। डेटा में अनुभवजन्य और द्वितीयक डेटा दोनों शामिल हैं। साक्षात्कार और फोकस, समूह चर्चा के माध्यम से विश्वविद्यालय के प्रशासकों/ महाविद्यालय के प्राचार्यों और शिक्षकों से अनुभवजन्य डेटा एकत्र किया गया। शोध प्रश्नों और आँकड़ों के आधार पर रिपोर्ट को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है। ये अध्याय सैद्धांतिक ढांचे, महाविद्यालयों में स्वायत्तता के तुलनात्मक विश्लेषण, स्वायत्तता और स्वायत्त कॉलेजों पर इसके प्रभाव और अन्य विनियामक/सांविधिक निकायों द्वारा स्वायत्तता के विनियमन और नियंत्रण और एक समापन अध्याय से संबंधित हैं।

फिलहाल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। विभागाध्यक्ष के साथ रिपोर्ट पर चर्चा और फीडबैक के आधार पर संशोधन के बाद जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी।

16. स्कूल शिक्षा के भू–स्थानिक सूचना प्रणाली का प्रायोगिक अध्ययन

अन्वेषकः श्री एनुगुला एन. रेड्डी

01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया।

17. प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए शैक्षिक प्रशासकों के वर्तमान की तुलना में भविष्यपरक कार्यों एवं भूमिकाओं की समलोचनात्मक जाँच करने हेतु गहन अध्ययन

अन्वेषकः प्रोफेसर बी.के. पांडा और डा. मोना सेदवाल

पृष्ठभूमि और समीक्षा

सभी स्तरों पर मानक संसाधन प्रबंध में सार्थक परिवर्तन आया है। संगठन अपने लोगों को प्रबंध और विकास को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। ऐसा भी महसूस किया गया है कि न केवल शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है प्रत्युत निरंतर उन शैक्षणिक प्रशासकों का भी क्षमता निर्माण किए जाने की आवश्यकता है जिन पर शैक्षणिक संस्थानां को कुशल और सफल प्रबंधन का दायित्व है। देश के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। तथापि, उनमें से अधिकांश संस्थाओं में या तो सेवा–पूर्व या सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, व्यावसायिक विकास के लिए कोई ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम नहीं हैं जिसे उन शैक्षणिक प्रशासकों के लाभार्थ बनाया गया हो जो कि जिला और अनुमंडल स्तर पर कार्य कर रहे हैं या सेवारत हैं। शैक्षणिक प्रशासकों के ये संवर्ग ज्यादातर मामलों में उपेक्षित रहते हैं और उन्हें चुनौतीपूर्ण नई नीति, सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाओं की सम्हलाई के लिए अपने सर्वांगीण व्यावसायिक कौशल और अभिक्षमताओं के कोटि उन्नयन का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है। समुचित व्यावसायिक विकास कार्यक्रम उपलब्ध नहीं होने के परिणामस्वरूप शैक्षणिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है।

शैक्षणिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण मॉडल पर बल

प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करने की गुंजाइश नगण्य होने की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर कार्यरत शैक्षणिक प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें शिक्षा संबंधी विद्यमान नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में समय–समय पर जानकारी दी जा सके। यह फ्रेमवर्क सतत रूप से शैक्षणिक प्रशासकों क आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो सकता है जिसमें संबंधित राज्यों में स्थापित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सम्यक् प्रभावी व्यावसायिक विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इनमें सेवा मे ंप्रवेश के समय और सेवावधि के मध्य में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के साथ साथ इसे व्यापक बनाने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में, शैक्षणिक प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण फ्रेमवर्क बनाकर शैक्षणिक प्रशासकों की क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है। इस फ्रेमवर्क का अभिकल्प कतिपय मुद्दों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है।

यथाः (अ) इन शैक्षणिक प्रशासकों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता है। (ख) जिन शैक्षणिक प्रशासकों के संवर्ग को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। (ग) इन शैक्षणिक प्रशासकों के मध्य किस प्राकर की व्यावसायिक क्षमता और कौशल निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, उनका अभिनिश्चय करना। (घ) विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं की राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर तक कोटि उन्नयन करना और उनके विकास हेतु योजना निर्माण।

अध्ययन का उद्देश्य

- शैक्षिक प्रशासकों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के भविष्य के आयामों की पहचान करना;
- शैक्षिक प्रशासकों की क्षमता के निर्माण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना;
- मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं और ऐसे संस्थानों की क्षमताओं को समझना जो शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं;
- शैक्षिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के संदर्भ में शैक्षिक प्रशासकों के व्यावसायिक विकास के लिए एक मॉडल प्रशिक्षण ढांचा विकसित करना; तथा
- एक मॉडल कार्यक्रम विकसित करना जो संसाधनों की दृष्टि से प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में स्थायी हो और लागत प्रभावी को बनाने और ई–लर्निंग विधियों के उपयोग की पहुँच व्यवहार्य हो।

ऑनलाइन आंकड़ा संग्रह की योजना बनाई गई तथा सूचना रिक्त स्थान चुनिंदा शैक्षणिक प्रशासकों को भेजे गये और डेटा एकत्र और विश्लेषण किया जाना था और एक बार जब कोरोना महामारी का खतरा समाप्त हो जाता है तो देश के शैक्षणिक प्रशासकों के भविष्य के आयामों को सामने लाने के लिए कुछ राज्यों के दौरे और एक कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव है।

18. राजस्थान के शैक्षिक रूप से और गैर–शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में सामाजिक गतिशीलता और स्कूल प्रबंधन का तुलनात्मक अध्ययन

अन्वेषकः डा. मोना सेदवाल

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 ने राष्ट्र भर के स्कूलों में बच्चों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में भी, आरटीई ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) और जमीनी स्तर पर काम कर रहे अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर प्रमुख जिम्मेदारियों को बढ़ावा देकर इसे एक वास्तविकता बना दिया है। इसी तर्ज पर, भारत सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) की पहचान की है जहाँ सभी के लिए शिक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

उपर्युक्त चर्चा से को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अध्ययन में स्कूल प्रबंधन में जाति की गतिशीलता के प्रकाश में एसएमसी की संरचना के प्रभाव की जांच करने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, राजस्थान में राज्य में अनुसूचित जाति की 59 श्रेणियां हैं। राजस्थान राज्य में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता 53 प्रतिशत है।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक और गैर–शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गांवों में स्कूल प्रबंधन पर इसके सामाजिक संरचना, इसके संबंध और प्रभाव का आकलन करने के लिए।
- स्कूल प्रबंधन के कामकाज और स्कूल प्रबंधन के सदस्यों के रवैये और ईबीबी और गैर–ईबीबी में अनुसूचित जातियों के समुदायों से आने वाले बच्चों के प्रति मुख्याध्यापक के दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- ईबीबी और गैर ईबीबी में बीईओ, डीईओ, डायट और एसआईईआरटी द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक इनपुटों की मदद से एसडीपी को विकसित करने और इसे लागू करने में स्कूल प्रबंधन की भागीदारी का अध्ययन करना।
- यह अध्ययन करने के लिए कि ईबीबी और गैर–ईबीबी में एससी जनसंख्या के लिए गाँव स्तर पर स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली कितनी समावेशी है।
- सामग्री और कार्यप्रणाली के साथ–साथ एसएमसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और ईबीबी और गैर–ईबीबी गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अ.जा. सदस्यों की भागीदारी दर का आकलन करना।

- वार्षिक आईडेपा कार्यक्रम और कोविड महामारी के कारण अनुसंधान के लिए क्षेत्र का दौरा न होने से विलंबित है।
- अध्ययन की वर्तमान स्थितिः परिचय अध्याय के साथ–साथ अध्ययन के प्रारूप की रूपरेखा तैयार की गई है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।
- आंकड़ा संग्रहः क्षेत्र निष्पादन हेतु प्रश्नावली के रूप में अनुसंधान के लिए उपकरण विकसित किए गए हैं। एफजीडी और व्यक्तिगत साक्षात्कारों के आधार पर विशिष्ट प्रारूप में आंकड़े एकत्र किये जाने बाकी हैं।

वार्षिक आईडेपा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोविड–19 महामारी के कारण अनुसंधान के लिए क्षेत्र दौरे में असमर्थता के कारण विलंबित है। परिचय अध्याय के साथ–साथ अध्ययन के प्रारूप डिजाइन का मसौदा तैयार किया गया है। शोध कार्य के लिए द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

19. भारतीय स्नातक महाविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाएं और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका प्रभाव

अन्वेषकः डा. संगीता अंगोम

पुस्तकालय शिक्षकों, शोधकर्ताओं, छात्रों के साथ–साथ जनता के लिए सीखने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अधिकांश पुस्तकालय छात्रों और शिक्षकों के लिए हैं, लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय जनता के लिए भी खुले हैं। दुनिया के उन्नत देशों की तुलना में भारत में महाविद्यालयों, कॉलेज पुस्तकालयों और कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्षों की स्थिति खराब है। अधिकांश कॉलेजों में पुस्तकालय की उचित सुविधाएँ नहीं हैं और जहाँ भी पुस्तकालय उपलब्ध हैं, वहाँ ठीक से प्रशिक्षित जनशक्ति द्वारा प्रबंधित पुस्तकालय नहीं है। इस समस्या के कई कारण हैं जिनमें बजट, स्थान, संसाधन, जनशक्ति, राष्ट्रीय नीतियों की कमी और मानक शामिल हैं। कॉलेज के पुस्तकालय छात्रों के समग्र विकास में उन्हें सुविज्ञ व्यक्ति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉलेज पुस्तकालय उनके पढ़ने के कौशल, जानकारियां प्राप्त करना और संसाधनों के बारे में ज्ञान में सुधार में मददगार है। हालांकि, कॉलेज पुस्तकालयों की स्थितियों के बारे में थोड़ा अनुभवजन्य आंकड़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल संसाधनों को अंडरग्रेजुएट्स द्वारा ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जा रहा है और भारत के अधिकांश कॉलेजों ने अपने पुस्तकालय संसाधनों का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण नहीं किया है। साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयों के पुस्तकालय में अकादमिक पुस्तकालयों या इनके सुविधाओं के उपयोग पर काफी अध्ययन किए गए हैं। लेकिन अधिकांश अध्ययन एक विशेष राज्य तक ही सीमित थे और उच्च शिक्षा संस्थानों विशेषकर स्नातक महाविद्यालयों के पुस्तकालय सुविधाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई अध्ययन किया गया हो।

वर्तमान अध्ययन दो विशिष्ट उद्देश्यों के साथ प्रस्तावित हैः i) पुस्तकालय सुविधाओं से संबंधित एनएएसी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना; ii) उपयोगकर्ता (छात्र) के शैक्षणिक प्रदर्शन पर कॉलेज पुस्तकालय के प्रभाव का आकलन करना।

अध्ययन के उद्देश्यः

1. पुस्तकालय निर्माण, कुल संग्रह और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तककालय सुविधाओं की जांच करना।
2. कॉलेज पुस्तकालय पर वित्त आवंटन का पता लगाना।
3. पुस्तकालयाध्यक्ष की योग्यता और काम करने की स्थिति (जैसे शिक्षा और प्रशिक्षण, काम करने का माहौल, अधिकार, अवकाश, वेतन आदि) का पता लगाना।
4. महाविद्यालयों में पुस्तकालय संसाधनों के उपयोग की सीमा की जांच करना।
5. यह पता लगाना कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनएएसी मापदंडों के अनुसार कॉलेज पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं का प्रबंधन या विस्तार कर रहे हैं या नहीं।
6. पुस्तकालयों की स्थिति और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का पता लगाना।
7. पुस्तकालय में उनकी व्यस्तताओं के संबंध में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का पता लगाना।

8. महाविद्यालयों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का पता लगाना, उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं, वित्त आपूर्ति और सेवाओं के प्रबंधन और सुधार के उपायों की पेशकश करना।

शोध पद्धतिः

यह अध्ययन एक सर्वेक्षण शोध है, जिसका उपागम विश्लेषण ात्मक होगा। अध्ययन में भारत के सभी अधि–स्नातक जनरल डिग्री कॉलेज शामिल होंगे। वर्तमान अध्ययन में देश के पाँच प्रदेश– पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उत्तर–पूर्व क्षेत्र के 20 राज्यों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक नमूना राज्यों से 10 कॉलेज का चयन नमूना राज्यों से यादृच्छिक रूप से किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा।

इस अध्ययन के लिए द्वितीयक और प्राथमिक दोनों आंकड़ों का उपयोग किया जाएगाः

(1) निर्मित साधन यथा प्रश्नावली और महाविद्यालय प्रशासकों, पुस्तकालयाध्यक्षों/पुस्तकालय प्रभारी, अध्यापकों और विद्यार्थियों से साक्षात्कार कार्यक्रम आदि के माध्यम से प्राथमिक आंकड़े संकलित किए जाएंगे। और (2) द्वितीयक आंकड़े महाविद्यालय के दस्तावेजों से संकलित किए जाएंगे।

अध्ययन की अवधिः 24 महीने

प्रोजेक्ट स्टाफ में शामिल होने की तिथिः एक कनिष्ठ परियोजना सहायक 22 नवंबर, 2018 को शामिल हुआ है। उसकी विस्तार अवधि 28 सितंबर 2020 को समाप्त हुई। उसने इस प्रोजेक्ट में कुल 22 महीने काम किया है। उसके कार्य संलग्नता के लिए और छह महीने वस्तार की जरूरत है।

परियोजना की वर्तमान स्थितिः अब तक फरवरी और मार्च, 2020 के दौरान प्रायोगिक अध्ययन किया गया। प्रायोगिक अध्ययन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध चार महाविद्यालयों का चयन नमूना महाविद्यालय के रूप में किया गया। केवल तीन महाविद्यालयों के कुछेक विद्यार्थियों और शिक्षकों से ही परिचर्चा और बैठकें संभव हो पायी थी। प्रायोगिक अध्ययन के दौरान निर्मित साधन (विद्यार्थी, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्राचार्य) का परीक्षण किया गया और तदनुसार मौलिक साधनों की समीक्षा की जा रही है। एसपीएसएस का उपयोग करके और एक छोटी प्रायोगिक अध्ययन रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में पायलट अध्ययन डेटा का विश्लेषण किया गया।

नमूना महाविद्यालयों से आंकड़े संकलित करने के लिए फील्ड सर्वे (क्षेत्र–सर्वेक्षण) मार्च के अंत से मई, 2020 तक किया जाना निर्धारित था। लेकिन, वर्तमान कोविड महामारी के कारण स्थिति में सुधार होने तक इसे स्थगित कर दिया गया है।

वर्तमान गतिविधियाँ और भविष्य की योजनाएँः वर्तमान में, प्रायोगिक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक क्षेत्र अध्ययन होने तक काम की प्रगति में देरी हो रही है।

20. भारत में शिक्षक शिक्षा का अभिशासन, अधिनियम और गुणवत्ता आश्वासन

अन्वेषकः प्रो. प्रणति पांडा

01.01.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया।

21. हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के कार्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रियाः एक प्रायोगिक अध्ययन

अन्वेषकः प्रो. विनीता सिरोही

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अध्ययन हालिया नहीं है। लगभग तीन सदियों से भी अधिक समय से बहुत सी विधाओं से किए गए अंशदान व उसके योगदान के आधार पर इसका उद्विकास होता रहा है। इसके फलस्वरूप निर्णय लेने संबंधी सिद्धान्तों में अनेक प्रचलित संप्रत्यय और निदेर्शों को समाविष्ट किया गया है जिसका प्रायः सभी जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विज्ञानों पर बहुत अधिक सार्थक प्रभाव पडऋा है। (डॉयल एंड थॉमसन, 1999)

ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में निर्णय लेने के प्रक्रम का निरंतर अध्ययन किया जाता रहा है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय का दूरगामी प्रभाव होता है, वहीं प्रशासक के निर्णय का भी अपना विशेष महत्व है क्योंकि इनसे उन सभी लोग प्रभावित होते हैं जो उन्हें तथा उनके द्वारा प्रबंधित संगठन को रिपोर्ट करते हैं। इसी कारण

ावश, बेहतर निर्णय लेना प्रशासकों और उनके संगठनों की मुख्य चिंता रहती है। प्रशासकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रति और अधिक सक्रिय तथा उत्तरोत्तर सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें इस मामले में भी जागरूक रहने की आवश्यकता है क उन्हें वस्तुस्थिति का विश्लेषण करना है। इस प्रक्रिया के बारे में जागरूकता उत्पन्ना करना है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब हमारे आधुनिक युग में निर्णय लेने की प्रक्रिया में नई जटिलताऐं उत्पन्न हो रही हैं। सफल प्रबंधन के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम हमेशा सकारात्मक परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते हैं इन परिणामों को प्रभावित करने वलो बहुत से कारक नियंत्रण से परे हैं। तथापि, इस जागरूकता से यह सुनिश्चित होता है कि हम ऐसी सुसंगत और प्रज्ञायुक्त प्रक्रिया को अपनाएं जिसके फलस्वरूप बेहतर निर्णय लिए जा सकें।

इस शोध कार्य की समीक्षा में, भारत की स्थिति के बारे में कुछ और अन्य बातों को सम्मिलित किया जाएगा। अध्ययन के नमूने में गुड़गांव में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्मिलित किया जाएगा। अर्द्ध–संरचनाबद्ध अंतर्वीक्षा और उपाख्यानों के माध्यम से आंकड़े संकलित किए जाएंगे। साक्षात्कार की समय सूची तैयार की जाएगी और शैक्षणिक प्रशासन और संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। क्षेत्रीय दौरा और जिला शिक्षा अधिकारियों के साक्षात्कार तथा स्थानांतरित किए जाने वाले कुछ अध्यापकों के साथ–साथ ऐसे अध्यापकवृंद जो स्थानांतरण चाहते थे किन्तु उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, उनके द्वारा आंकड़े संकलित किए जाएंगे। इस जानकारी के साथ उपाख्यान भी जोड़े जाएंगे। और इनका विश्लेषण गुणात्मक विधियों से किया जाएगा। इस प्रकार आंकड़ों के संकलन का कार्य पूर्ण हुआ।

22. छोटे विद्यालयों के लिए नेतृत्व संरचना, पद्धति और मॉडलः चुनौतियां और क्रमिक विकास

अन्वेषकः डा. कश्यपी अवस्थी

इस परियोजना को आई.यू.सी.टी.ई. शिक्षा विभाग, महाराजा सायाजीराव गायकवाड यूनिवर्सिटी, बड़ौदा द्वारा निधि पोषित किया गया है।

शोध प्रश्न हैं:

- छोटे विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की क्या संदर्भगत आवश्यकताएं हैं और उनके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं?
- छोटे विद्यालयों के लिए नेतृत्व संरचना, सहभागिता की प्रक्रिया और पद्धति क्या है?
- क्षेत्र से नेतृत्व के कौन से नए सिद्धांत या मॉडल उभरकर सामने आते हैं।

परियोजना में प्रत्यक्षवादी और निर्वचनात्मक उपागम अपनाया जाता है जिनमें छोटे विद्यालयों में नेतृत्व की आवश्यकता और चुनौतियों को समझने तथा नेतृत्व संरचनाओं, प्रक्रिया और पद्धति, यदि कोई हो के अध्ययन हेतु चरण–1 में सर्वेक्षण अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। चरण–2 का डिजाइन नेतृत्व प्रक्रियाओं और भागीदारी की पद्धति तथा स्कूल–रूप परिवर्तन में इनकी प्रभाविता के बारे में बेहतर सूझबूझ प्राप्त करने के लिए मामला अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया। गुजरात को प्रतिदर्श राज्य के रूप में चुना गया और यू–डाईस से आंकड़ों का प्रयोग करते हुए दो जिले अर्थात् छोटा–उदयपुर और कच्छ को प्रतिदर्श जिले के रूप में चुना गया और आगे जिला प्राधिकारियों के परामर्श से प्रत्येक जिले के दो प्रखंडों छाटा उदयपुर से सनखेड़ा और नसवाड़ी तथा कच्छ से भुज और लखपत प्रखंडों को चुना गया। चूँकि, तीसरा शोध प्रश्न छोटे विद्यालयों के लिए शोध मॉडल के उद्र विकास से संबंधित है, छोटे विद्यालयों के चयन में वांछित संकेतक था। गुणोत्सव में शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कार्य निष्पादन पर भी विचार करते हुए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का चयन किया गया और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के चयन में बोर्ड में उत्तीर्ण होने के प्रतिशत पर विचार किया गया।

दोनों जिले से आंकड़े संकलन का कार्य पूरा हो गया है और विश्लेषण हेतु परिमाणात्मक सूचना एक्सेल में संकलित की जाती है जबकि विद्यालय के प्रमुखों के साथ साक्षात्कार के रिकार्ड विषयवस्तु विश्लेषण के लिए लिपिबद्ध किए जाते हैं। शोध की समस्या, संबंधित साहित्य और शोध पद्धति की समीक्षा की संकल्पना

संबंधी अध्याय का पहला प्रारूप तैयार कर लिया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में और दो महीने का समय लगेगा। रिपोर्ट सितम्बर, 2020 तक प्रस्तुत हो जाएगी।

23. गैर–शैक्षणिक कार्यकलाप में अध्यापकों की अंतर्ग्रस्तता और शिक्षा पर इसका प्रभावः निर्वाचन और निर्वाचन से संबद्ध–कर्त्तव्य के निर्वहन में अध्यापकों द्वारा व्यतीत किए गए समय का एक अखिल भारतीय अध्ययन

अन्वेषकः प्रो. विनिता सिरोही

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीपा से आग्रह किया कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अध्यापकों द्वारा निर्वाचन और निर्वाचन से संबद्ध ड्यूटी के निर्वहन मे व्यतीत समय के यथार्थ आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक अध्ययन कराया जाए। इसलिए मा.सं.वि. मंत्रालय को प्रारूप प्रस्ताव भेजा गया और परवर्तीकाल में मा.सं.वि. मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार इसमें संशोधन किया गया। 12 अप्रैल, 2019 को नीपा के बजट सहित संशोधित प्रस्ताव के अनुमोदन संबंधी मा.सं.वि. मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ।

नीपा ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से 2 जिलों का चयन कर यह अध्ययन आरंभ किया। इस प्रकार नमूना 69 जिलों में चयनित सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे सभी शिक्षक शामिल हैं। यू–डाईस आंकड़ों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक जिले से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर से 10 विद्यालयों का चयन किया गया। शिक्षणेतर कार्यकलाप/गतिविधियों पर अध्यापकों द्वारा व्यतीत समय से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए विशेषज्ञों के परामर्श से अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक पृथक प्रश्नावली तैयार की गई। क्षेत्रीय दौरों के क्रम शिक्षकों और प्रशासकों से बातचीत व संवाद के लिए भी प्रश्न तैयार किए गए।

मसौदा रिपोर्ट मा.सं.वि. मंत्रालय को सौंपी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। अध्ययन से संबंधित राज्यों से बाद में प्राप्त कुछ प्रासंगिक आंकड़ों का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

24. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन

अन्वेषकः डा. मधुमिता बंध्योपाध्याय

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन संबंधी बर्तमान शोध परियोजना कार्य विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए भारत के छह राज्यों–हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश और ओडिशा स्थित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी सुधारने के लिए प्रतिभागी कार्य परियोजना थी, शीर्षक से हाल ही में किए गए अध्ययन (बंद्योपाध्याय, 2019) के पूर्ण किए जाने का विस्तार है।

पिछले अध्ययन में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर टिप्पणी की गई हैं और देखने में भी आया है कि कुछ वर्षों में बालिकाओं के नामांकन में सुधार हुआ है किन्तु अपने सहोदर भाई–बहनों की देखभागल सहित गृहस्थी के अन्य क्रियाकलापों में बालिकाओं की अन्तर्ग्रस्तता के कारण बहुत सी बालिकाएँ नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाती हैं जिससे जहाँ एक ओर उनका अधिगम प्रतिफल प्रभावित होता है वहीं उनकी प्रतिधारण क्षमता पर भी इसका दृष्प्रभाव पड़ता है। इसी अध्ययन में, बालश्रम का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आया है जिसके कारण विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति बाधित होती है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि अध्यापिकाओं की अपर्याप्त तैनाती का भी हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन और विद्यालय में उनकी उपस्थिति प्रभावित हुई है। बता दें कि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ स्कूली शिक्षा पूरी करने तक बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति का प्रयास किया जा रहा है। इसके अनुक्रम में, लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाने का विषय भी मध्य प्रदेश के एक विद्यालय में दिखाई दिया। यद्यपि यह अन्य राज्यों में भी आम बात है। ऐसी स्थिति से सरकारी विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता के अभाव की भी पुष्टि होती है जो बालिकाओं को स्कूली शिक्षा

प्राप्त करने में बाधक होती है और कुछ वर्षों में उनके चुपचाप पढ़ाई छोड़ने का खतरा उत्पन्न होता है।

जारी अध्ययन में तीन राज्यों–हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश का चयन राज्यों में और विशेष रूप से ऊपर वर्णित राज्यों में पूर्व में किए गए अध्ययन में भी बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति से प्राप्त विभिन्न निर्देशक बिन्दुओं के आधार पर किया गया है। उच्च साक्षरता दर होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में बच्चों विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने के बाद भी, अपने बच्चों के अध्ययन के लिए राजकीय विद्यालयों के चयन के मामले में माता–पिता में बहुत अधिक उदासीनता देखी गई है। ज्यादातर प्रवासी परिवारों के इन विद्यालयों के विद्यार्थी कुछ समय के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहकर अपनी पढ़ाई से समझौता करते हैं। ऐसे परिवार ज्यादातर राज्यों के बाहर से हैं और अक्सर अपने परिजनों के साथ अपने गृह–नगर की यात्रा करते हैं। मध्य प्रदेश, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में पाया गया है कि बीच में पढ़ाई छोडने वाली बहुत सी बालिकाओं को यौन आधारित सामाजिक प्रतिमानों का सामना करने के अलावा बाल–विवाह के अभिशाप को भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–4), (2014–15) में भी बाल–विवाह (विहित विवाह–योग्य आयु से पूर्व विवाह) की परिघटना को उजागर किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान अध्ययन में, चयनित राज्यों में बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में बदलती हुई स्थिति का अन्वेषण किया गया है ताकि बालिकाओं की शिक्षण उनके माता–पिता और समुदाय के संबंध में गहन और समग्र सूझबूझ उत्पन्न किया जा सके। साथ ही, इसमें इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि विद्यालयी शिक्षा से किस प्रकार बालिकाओं को अपनी कुशलता और आगे की शिक्षा ग्रहण करने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लेने में सहायता मिल रही है। अध्ययन से पूर्व निम्नांकित शोध प्रश्न और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

शोधपरक प्रश्नः

इस शोध में निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगाः

- भारतीय संदर्भ में बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
- भारत में और अध्ययनगत राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की वर्तमान प्रास्थिति (नीति और अभ्यास) क्या है?
- अध्ययनगत राज्यों में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में शिक्षकों सहित माता–पिता/समुदाय/हितधारकों की क्या राय है?
- क्या स्कूली शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी में सुधार लाने हेतु विभिन्न पहलों की शुरूआत किए जाने के फलस्वरूप स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता (पुरूष स्त्री समानता) की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है?
- शिक्षा जगत में और शिक्षा के माध्यम से पुरूष स्त्री समानता के लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- बालिकाओं की शिक्षा पर सरकार द्वारा की गई विभिन्न नीतिगत पहलों और हस्तक्षेपों (अभिनव और सर्वोत्तम प्रथाओं) के प्रभाव की जांच करना,
- अध्ययन के तहत क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा की वर्तमान स्थिति का पता लगाना
- बालिकाओं की शिक्षा का महत्व और माता–पिता में अंतर–पीढ़ी परिवर्तन और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समुदाय के रवैये को समझना
- बालिकाओं के नामांकन, प्रतिधारण और अधिगम की उपलब्धि के लिए निर्धारित कारकों (सामाजिक मानदंड, स्कूल और परिवार से संबंधित कारक आदि) का अध्ययन करना
- शिक्षा के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहल की सिफारिश करना।

अध्ययन के क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्रों का चयन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश से किया गया है। हरियाणा और मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में काफी लैंगिक अंतर से जूझ रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में काफी प्रगति देखी है,

परियोजना की वर्तमान स्थिति

आंकड़ा संग्रह के लिए निम्नलिखित उपकरण तैयार किए गए हैं

1. घरेलू सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली
2. स्कूल सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली
3. चयनित छात्रों और उनके माता–पिता, भाई–बहन और दादा–दादी (अलग–अलग) के लिए साक्षात्कार अनुसूची जिन्होंने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी की?
4. जिला एवं प्रखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए साक्षात्कार अनुसूची
5. प्रधान शिक्षक के लिए साक्षात्कार अनुसूची
6. शिक्षकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची
7. एसएमसी सदस्यों के लिए साक्षात्कार अनुसूची
8. आकलन उपकरण

- संगत साहित्य समीक्षा शोधकर्ता दल द्वारा संकलित किया जा रहा है ताकि इनका अध्ययन किया जा सके और इसके साथ–साथ अध्ययन के लिए द्वितीयक आंकड़े भी एकत्रित किये जा रहे हैं। द्वितीयक आंकड़े के आधार पर एक शोध पत्र भी लिखा गया है और पुस्तक में प्रकाशनार्थ भेजा गया है।
- स्कूल और जिन गाँवां में इनकी अवस्थिति है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए लॉकडाउन की अवधि से पूर्व अध्ययनगत क्षेत्रों में आंकड़े एकत्र किए जाने का कार्य आरम्भ हो चुका है। हम लंबे समय से फील्ड विजिट (क्षेत्रीय दौरा) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूंकि हम कोविड–19 महामारी के कारण क्षेत्र से आंकड़े एकतत्र करने में असमर्थ हैं। हमने आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रशासकों और अध्यापकों के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार किया है। एक अस्थायी समय–तालिका भी उपर्युक्त मुख्य प्रत्यर्थियों के साथ आभासी बैठक (वर्च्युअल मीटिंग) करने के लिए तैयार की गई है।
- अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के लिए तैयार समरूय–सूची के आधार पर 15–30 दिसम्बर, 2020 तक सैम्पल जिला/प्रखंड और विद्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी, खंड–शिक्षा अधिकारी, की आरसी/सीआरसी और सीआरसी और प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के साथ ऑनलाइन साक्षात्कर के माध्यम से संकलित आंकड़ों को एसपीएसएस फॉर्मेट में अब प्रविष्ट किया जा रहा है और रिपोर्ट के लिए मामले और कथानक भी तैयार किए जा रहे हैं)
- प्रधानाध्यापक और अध्यापकों की वैयक्तिक और पृष्ठभूमि जानकारी के लिए पृथक संसाधन फॉर्मेट भी इस अवधि में तैयार किए गए और सम्मानित प्रत्यार्थियों से मेल के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए गए हैं।
- हम इस अध्ययन में शामिल किए गए विद्यालयों के एसएमसी (विद्यालय प्रबंधन समिति) के सदस्यों का भी साक्षात्कार करने की योजना बना रहे हैं। हम चयनित विद्यार्थियों और उनके माता–पिता का भी साक्षात्कार करेंगे।
- फरवरी में हम गृहस्थी (हाउसहोल्ड) सर्वेक्षण करने की भी योजना बना रहे हैं जिसके लिए टिप्पणी (नोट) प्रस्तुत किया जा चुका है और अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है।

अतिरिक्त पहल

- 30 दिसंबर, 2020 को जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ''नई शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य से भारत में स्कूली शिक्षा में महिला–पुरुष समानता की स्थिति का लक्ष्य प्राप्त करने'' के

विषय पर ऑनलाइन विमर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रतिभागी राज्यों में विशेष रूप से महामारी के दौरान और महामारी के बाद बालिकाओं की शिक्षा की प्रास्थिति के संबंध में बहुत सी संगत जानकारी प्रदान की गई। विभिन्न राज्यों यथा– मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मिजोरम, हरियाणा के प्रतिभागियों ने इस बैठक में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया है। आभासी बैठक की रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है।

- दूसरा वेबिनार, 28 जून, 2020 को ''भारत में लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के पश्चात् बच्चों को शिक्षित करना'' विषय पर आयोजित किया गया। इस वेबिनार की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और माननीय कुलपति को सौंपी गई है।

25. भारतीय उच्चतर शिक्षा में अनुदेशात्मक अभिकल्पः प्रास्थिति, समीक्षा, चुनौतियाँ और संस्तुतियाँ

अन्वेषकः प्रो. के. श्रीनिवास

शिक्षण–अधिगम के क्षेत्र में बदलते हुए प्रतिमान के साथ हमने औपचारिक शिक्षा प्रणालियो और मुक्त एवं लचीली शिक्षा प्रणालियों के आधार पर अध्यापकों और अधिगमकर्ताओं की भूमिका में बदलाव देखा है। इक्कीसवीं सदी में इंटरनेट की मुख्य भूमिका होने के कारण शिक्षा प्रणाली में अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया के मूल में है। किसी भी रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का किसी भी रूप में प्रयोग (सरल से सम्मिश्र) का प्रभाव शैक्षणिक परिदान के सभी तीनों प्रकार्य पर पड़ा है भले ही वह औपचारिक या अत्यधिक संरचनाबद्ध, पारंपरिक विधि, अनौपचारिक विधि या मुक्त संरचना वाली और लचीली विधि और अनौपचारिक शिक्षा जो पूर्णतः गैर–संरचनाबद्ध है, ये सभी विधियाँ इससे प्रभावित हुई हैं। प्रभावी अधिगम में संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों अधिगम परिणामों पर विचार किए जाने के साथ–साथ अधिगमकर्ताओं की भावनात्मक स्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अधिगम से संलयित हैं। पाठ्यक्रम अभिकल्प संबंधी निर्णय में सहयोगात्मक और वैयक्तिक अधिगम परिवेश का निर्माण कर सामाजिक अधिगम के विभिन्न उपागम को आवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। जनवरी से मार्च, 2021 के दौरान इसी पृष्ठभूमि में सर्वेक्षण प्रश्नावली का प्रयोग करते हुए संकलित आंकड़े की जांच कर इनका परिमार्जन किया गया है। अगले कदम के रूप में क्षेत्रीय दौरा की युक्ति और एक साक्षात्कार समय तालिका को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, इस समय हमारे देश में महामारी की भयंकर स्थिति को देखते हुए हमारी योजना है कि क्षेत्रीय दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाए जब तक कि परिस्थिति आंकड़े (दत्त) संकलन के एिल यात्रा करने के अनुकूल नहीं हा जाए।

इसके अलावा इस परियोजना कार्य में संलिप्त कर्मचारी संबंधित अध्ययन का पता लगाकर इन्हें अभिलेखागार स्वरूप में संकलित करने में अपेक्षित सहयोग दे रहे हैं क्योंकि उन्हें विषय से संबंधित क्षेत्रों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है और संसाधनों की भी जानकारी दी गई है। इनमें SCOPUS, विज्ञान वेब (Web of Science) और अन्य महत्वपूर्ण डाटाबेस सम्मिलित है। इन अध्ययनों का विषय–परक विश्लेषण किया जाना जारी है, और यह इस परियोजना कार्य के मुख्य दत्त विश्लेषण का निर्मात्री अवयव होगा।

26. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलः संस्थागत विकास और पतन वाराणसी का एक केस अध्ययन

अन्वेषकः डा. नरेश कुमार

साहित्य की समीक्षा चल रही है। साक्षात्कार अनुसूची की संरचना प्रगति पर है।

4

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

ज्ञान और सूचना की साझेदारी

संस्थान ने शैक्षिक नीतियों, योजना और प्रबंधन से संबंधित मौजूदा और नवीनतम ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्य आरंभ किए हैं। संस्थान का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र शैक्षिक नीति, योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान और सूचना प्रलेखन और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र द्वारा वर्ष 2020–21 में की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं

संस्थान का पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों, देश–विदेश के शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालय के एम.फिल. तथा पी.एच.डी. के विद्यार्थियों, नीपा द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अतिथि संकाय सदस्यों तथा पाठकों की सूचना संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं अधिगम केंद्र के रूप में कार्य करता रहा है। पुस्तकालय, संस्थान के अध्यापन, अधिगम और शोध में सहयोग के लिए आधुनिक अध्यापन– अधिगम सामग्री, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रानिक सुविधाएं जैसे– वाई–फाई से सुसज्जित है।

पिछले सात–आठ वर्षों के अन्तर्गत पुस्तकालय ने अपनी संग्रह नीति में व्यापक परिवर्तन किया है। पुस्तकालय लगभग 80 प्रतिशत जर्नल मुद्रित और ऑनलाईन स्वरूप में मंगाता है। हालांकि, पुस्तकों को मुद्रित रूप में ही प्राथमिकता दी जाती है।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकों तथा अन्य सामग्री के संपूर्ण संग्रह को चार प्रमुख अनुभागों– सामान्य, संदर्भ, श्रृंखला, और क्षेत्र अध्ययन संग्रह में वर्गीकृत किया गया है। समीक्षित काल में पुस्तकालय में 18 नई पुस्तकों/दस्तावेजों का संग्रह किया गया। वर्तमान में पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास संयुक्त राष्ट्र, युनेस्को, ओ.ई.सी.डी, आई.एल.ओ., यूनिसेफ, विश्व बैक आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों इत्यादि के अलावा पुस्तकों और दस्तावेजों का समृद्ध संग्रह है। समीक्षाधीन वर्ष 2020–21 में पुस्तकालय ने शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंधन तथा इससे संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय तथा अतंर्राष्ट्रीय जर्नल एवम् पत्रिकाएं मंगाई। इन पत्र–पत्रिकाओं से 1,130 प्रमुख आलेखों का सूचीकरण किया गया। नीपा ने चार आनलाईन जर्नल डाटाबेस एलसेवियर सेज, एमेराल्ड, डाटाबेस तथा जे. स्टोर खरीदे। इसके अतिरिक्त ई.पी.डब्ल्यू.आर.एफ. से एक सांख्यिकी आंकड़ा आधार ई.पी.डब्ल्यू.आर.एफ. भारत समय श्रृंखला खरीदी। पुस्तकालय के पास 523 सेज शिक्षा सामग्री ई–बुक का संग्रह है। नीपा पुस्तकालय में मल्टीमीडिया केंद्र है। वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, फिल्म, माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप्स और सी.डी. के रूप में गैर–मुद्रित सामग्री उपलब्ध है।

नीपा पुस्तकालय ने नई आनलाइन सूचना सेवाएँ जैसे कि– ''न्यूज फ्लैश'', 'नीपा इन द प्रेस', एस.डी.आई. (नीपा संकाय के अकादमिक कार्य का प्रसार) तथा 'न्यू अराईवल' प्रारम्भ किया है। पुस्तकालय ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की ग्रन्थ सूची तैयार की है। उपभोक्ताओं को संदर्भ सामग्री, आलेखों, रिपोर्टों इत्यादि के लिये फोटोग्राफी सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

नीपा पुस्तकालय में सभी गतिविधियाँ, जैसे सूची बनाना, प्राप्तियाँ, प्रसार तथा श्रेणी नियंत्रण पूर्णरूप से कम्प्यूटरीकृत है। इसके लिये लिबसिस 10 साफ्टवेयर पैकेज का नवीनतम वर्ज़न का प्रयोग किया जा रहा है। नीपा में लैन से इंटरनेट या फिर इंटरानेट के माध्यम से सीधे या यू.आर.एल. के माध्यम से नीपा की वेबसाईट पर वेब ओपेक का प्रयोग करके ओपेक का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीपा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटाबेस देख सकते हैं।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु नीपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र डेलनेट का सदस्य हैं, इससे नीपा पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र में उपलब्ध शैक्षिक योजना और प्रशासन पर वृहद रूप से उपलब्ध अमूल्य अधिकारिक दस्तावेज़ों के पहचान की सुविधा उपलब्ध हुई है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुये सभी दस्तावेज़ों तथा रिकार्ड का डिजीटलीकरण हेतु परियोजना चलाई जा रही है। यह अपेक्षा की जा रही है कि इससे देश में शिक्षा पर वृहद ऑनलाईन अभिलेखीय सूचना उपलब्ध हो पायेगी।

नीपा प्रलेखन केंद्र

नीपा प्रलेखन केन्द्र में शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन पर 20,000 से अधिक का वृहद और समृद्ध संग्रह है। इसके संग्रह में केन्द्र –राज्य सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन जैसे राज्य तथा जिला गणना, राज्य तथा जिला गैजेटियर केन्द्र तथा राज्य विश्वविद्यालय के नियम और संविधि, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी.ई.पी.) तथा सर्व शिक्षा अभियान, राज्यों की सांख्यिकी पुस्तकें, अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आयोग तथा समिति की रिपोर्ट, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजनाएं, राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्टें तथा पंचवर्षीय योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान के विभिन्न प्रकाशनों जैसे अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, संस्थान की वार्षिक रिपोर्टें (1962–2016), प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्टें, विभिन्न मंत्रालयों की रिपोर्टें, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (आईआईईपी), पेरिस के प्रकाशन की शामिल हैं। केन्द्र में नीपा एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रम और अन्य विश्वविद्यालय के थीसिस का एक वृहद संग्रह है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन पर क्रमशः स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) और अन्तरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) पर शोध संग्रह उपलब्ध है। केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, (आई.आई.ई.पी.) पेरिस के प्रकाशनों का संग्रह–केन्द्र है। इसके पास गैर–पुस्तक पाठ्य सामग्री जैसे इंडैक्सिंग डाटाबेस, भारत की जनगणना, राज्य मानव संसाधन विकास रिपोर्ट तथा शिक्षा और इससे संबंधित क्षेत्रों पर अन्य प्रकाशनों पर संग्रह है।

गतिविधियाँ एवं प्रमुख क्षेत्र

प्रलेखन केंद्र आईसीटी के सहयोग से प्रतिवर्ष सभी विषयों के संकाय के लिए अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित करता है। 2020–21 के दौरान, इसने 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर 5 दिनों की संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित की। प्रलेखन केन्द्र ने अपने सभी कार्यकलापों का कंप्यूटरीकरण कर लिबसेस 7.0 (रिलीज 1.0) सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्त्ता को डेस्कटॉप पर ऑनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग (ओपेक) तथा सूचना संसाधन तथा सेवाओं की विस्तृत जानकारी के साथ इलैक्ट्रानिक डाटाबेस की पहुंच, प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, इसके समृद्ध संग्रह, विस्तृत सरणी और विविध सेवाएं तथा सुविधाएं भारत तथा विदेशों से उपयोगकर्ताओं को इसकी सूचना संसाधन और सेवाओं का प्रयोग करने के लिये आकर्षित करती है। उपयोगकर्त्ताओं को पठन हेतु प्रलेखन केन्द्र में सुविधाजनक शान्तिपूर्ण और अनुकूल परिवेश उपलब्ध है तथा उपयोगकर्त्ताओं के लिए वातानुकूलन, पर्याप्त रोशनी और जनरेटर बैक–अप की सुविधा उपलब्ध है। प्रलेखन केन्द्र की पठन सुविधाओं का लाभ संकाय, संस्थान के अनुसंधानविद् परियोजना स्टाफ, भारत तथा विदेश के अनुसंधानविद्, पीजीडेपा एवं आईडेपा के भागीदार तथा आगन्तुक संकाय द्वारा उठाया जाता है। डेलनेट (विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क) के सदस्य के रूप में, केंद्र ने अंतःपुस्तकालय संसाधनों को साझा करने की गतिविधियाँ सुदृढ़ की है। प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः नौ बजे से सायं 5.30 बजे तक खुला रहता है।

डिज़ीटल संसाधनों और सेवाओं तक पहुंच

इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय संकाय तथा अनुसंधानविदों के बीच विभिन्न प्रकार की सूचना की साझेदारी, संपर्कता, सहभाजन के लिए इंटरनेट गतिविधियों को सुदृढ़ तथा विकसित किया गया है। यह सूचना तथा ज्ञान का संग्रह, सृजन, हस्तांतरण तथा एकीकरण करता है। इसके डिज़ीटल संसाधन जैसे पुस्तकें, आलेख, अनुसंधान अध्ययन, समसामयिक आलेख श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, सम्मेलन संगोष्ठी के कार्यकलाप, विख्यात शिक्षाविद् व्याख्यान श्रृंखला, दृश्य–श्रव्य व्याख्यान, समिति तथा समिति रिपोर्टें, इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। डिजीटल अभिलेखागार शिक्षा तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के 12,000 नीतिगत दस्तावेज़ों के डिजीटल अभिलेख उपलब्ध कराता है। यह दस्तावेज़ इंटरनेट या इंटरानेट के माध्यम से [http://www.niepa.ac.in/darch.aspx or http://14.139.60.153/]. पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त नई प्राप्तियों की सूची, नए जर्नलों की सूची, पाक्षिकों के वर्तमान घटक; जे.स्टोर तथा ऑनलाईन जर्नल डाटाबेस का सम्पूर्ण टेक्स्ट एक्सेस; संदर्भ ग्रंथ सूची – मांग पर साहित्य की खोज तथा इलैक्ट्रानिक दस्तावेज़ वितरण प्रणाली (ई.डी.डी.एस.) के लिये इंटरनेट के माध्यम से चौबीस घंटे ऑनलाईन सूचना संसाधन तथा प्रलेखन सेवाएं पाठकों को प्रदान की गई है। यह 300 मुद्रित जर्नलों (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय) और ऑनलाईन डाटा बेस जैसे सेज ज्ञान, सेज शिक्षा संग्रह ऑनलाईन, एलसेवियर तथा जे. स्टोर की पहुंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पाठकों को भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (71,000,000 संसाधन), 125 देशों से मुक्त शैक्षिक संसाधन हेतु पहुंच (डीओएजे) जैसे 11,655 पूर्ण लिखित जर्नल के संदर्भ में मुक्त पहुंच जर्नल डायरेक्टरी, (59,78,365 आलेख), 611 प्रकाशकों से 40,601 अकादमिक सहकर्मी समीक्षा पुस्तकों की डायरेक्टरी, अप्रैल, 2021 तक इलैक्ट्रानिक शोध और अनुसंधान हेतु 6 मिलियन ई.टी.डी. (6,007,220 ई.टी.डी.) तथा शोधगंगा (3,00,000 ई.टी.डी.) एवं अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण–पठन डाटाबेस, इंडेक्सिंग डाटाबेस, पाक्षिकों की वर्तमान सामग्री और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण पठन–सामग्री उपलब्ध कराता है। इससे अंतः पुस्तकालय ऋण तथा डेलनेट के माध्यम से पुस्तकों, दस्तावेजों, आलेखों इत्यादि के लिए प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ण करने में सुदृढ़ीकरण हुआ है। प्रलेखन केन्द्र की सेवाओं का लाभ संकाय, नीपा के अनुसंधानकर्त्ताओं, परियोजना स्टाफ, पीजीडेपा तथा आईडेपा, आई.पी.ई.ए., प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत और अन्य देशों के विश्वविद्यालयों अनुसंधानकर्त्ताओं द्वारा उठाया जाता है।

व्यक्तिगत योगदान (डॉ. डी.एस. ठाकुर का शैक्षणिक योगदान – 2020–21)

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत और प्रकाशित शोध पत्र/लेखः

i. ठाकुर, डी.एस. (2020)। शिक्षा और अनुसंधान में एमओओसीः नई पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए स्वयंः एक अभिनव अधिगम शिक्षण उपकरण। आर.सी. पटेल और सुजाता श्रीवास्तव (सं।), शिक्षा में नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास। वडोदराः शिक्षक शिक्षा के लिए इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर (आईयूसीटीई), पीपी। 98–109। (आईएसबीएनः 978–93–5406–947–5)

व्याख्यान

i. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली (29 जून 2020 से 3 जुलाई 2020 तक) द्वारा आयोजित लेखन कौशल पर पांच दिवसीय कार्यशाला में 'उरकुंड साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयरः उरकुंड का उपयोग कैसे करें' विषय पर 3 जुलाई, 2020, नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

ii. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा (1 सितंबर 2020 से 30 नवंबर 2020) तक आयोजित 10 महीने के पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (पीजीडीईपीए) में 'साहित्यिक चोरीः वास्तविक सीखने में बाधा और उरकुंड साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें' पर 22 सितंबर, 2020, नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

iii. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा (1 सितंबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020) तक आयोजित 10 महीने के पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (पीजीडीईपीए) में 'उच्च शिक्षा में मुक्त शिक्षा संसाधन' पर 22 सितंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

iv. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम में 'भारत में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के लिए आभासी शिक्षण वातावरण' पर (23 नवंबर, 2020 से 27 नवंबर 2020) 23 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

v. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिनों के संकाय विकास कार्यक्रम में 'डिजिटल युग में अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की भूमिका' पर (23 नवंबर, 2020 से 27 नवंबर, 2020) 24 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

vi. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिनों के संकाय विकास कार्यक्रम में 'शिक्षा और अनुसंधान में एमओओसी स्वयंः शिक्षार्थियों की नई पीढ़ी के लिए एक अभिनव शिक्षण अधिगम उपकरण' पर (23 नवंबर, 2020 से 27 नवंबर, 2020) 24 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

vii. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिनों के संकाय विकास कार्यक्रम में 'ओईआरः अवधारणा और लाइसेंसिंग और खोज, उपयोग और पुनः उपयोग' पर (23 नवंबर, 2020 से 27 नवंबर, 2020) 24 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

viii. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली (23 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक) द्वारा आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम में 'सूचना साक्षरता' पर 25 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।।

ix. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा (23 नवंबर, 2020 से 27 नवंबर, 2020) तक आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम में 'यूट्यूब और गूगल पर सृजानात्मक समान वीडियो के लिए स्क्रीनकास्टिफाई वीडियो सामग्री विकास और पहुंच पर 26 नवंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान और व्यावहारिक अभ्यास दिया गया।

x. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा 23 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 तक) आयोजित शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर पांच दिनों के संकाय विकास कार्यक्रम में 'ओबीएस स्टूडियो वीडियो सामग्री विकास' पर 26 नवंबर 2020 को नीपा, नई दिल्ली में एक ऑनलाइन व्याख्यान और व्यावहारिक अभ्यास दिया।

संकाय, विद्वानों, डिप्लोमा कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और संकाय विकास कार्यक्रमों के लिए बनाए गए माइक्रो वीडियो

i. उरकुंड साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु सॉफ्टवेयरः एक परिचय
ii. उरकुंड पीडीएस में दस्तावेज कैसे अपलोड करें
iii. उरकुंड पीडीएस में समानता की जांच कैसे करें
iv. भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी
v. भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें
vi. भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की उन्नत खोज

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी

i. 19 मई 2020 को टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप द्वारा आयोजित 'टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल्स के लिए पहुंच' पर वेबिनार में भाग लिया।
ii. 20 मई 2020 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा आयोजित 'पांडुलिपि संपादन की पुरानी परंपरा' पर वेबिनार में भाग लिया।
iii. 27 मई 2020 को मानव रचना द्वारा आयोजित 'संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में मध्यस्थता' पर वेबिनार में भाग लिया।
iv. 2 जून 2020 को एमराल्ड पब्लिशिंग द्वारा आयोजित 'डिस्कवर एमराल्ड जर्नल्स फॉर योर रिसर्च' पर एमराल्ड पब्लिशिंग के वेबिनार में भाग लिया।
v. 3 जून 2020 से 5 जून 2020 के दौरान पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 'पोस्ट कोविड–19: पुस्तकालयों और पुस्तकालय पेशेवरों के लिए चुनौतियां और अवसर' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भाग लिया।
vi. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के डॉ जाकिर हुसैन पुस्तकालय द्वारा आयोजित 'अकादमिक प्रकाशन और अनुसंधान प्रभावशीलता बढ़ाने' पर एक दिवसीय वेबिनार में भाग लिया

कार्यशालाएं/सम्मेलन/एफडीपी/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

23.11.2020–27.11.2020	प्रो. आईसीटी के सहयोग से प्रलेखन केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए नीपा, नई दिल्ली में ऑनलाइन मोड में अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अन्य शोध संगठनों के सभी विषयों के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। यह एक आईसीटी आधारित कार्यक्रम था जहां मूडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डॉ. डी.एस. ठाकुर लर्निंग पोर्टल से प्रतिभागियों द्वारा एक्सेस किए गए लेख, वीडियो, चर्चा मंच, कार्य योजना सहित सीखने के संसाधन सम्मिलित थे।
10.01.2021–07.02.2021	भागीदारी और पांच सप्ताह के लिए अथाबास्का विश्वविद्यालय, कनाडा और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा संचालित एमओओसी का परिचय प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण एमओओसी (टीईएल एमओओसी) शीर्षक से पूरा किया।
07.02.2021–07.03.2021	भागीदारी और चार सप्ताह के अथाबास्का विश्वविद्यालय, कनाडा और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा संचालित एमओओसी शीर्षक मिश्रित शिक्षण अभ्यास एमओओसी (बीपीएल एमओओसी) पूरा किया।

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान विकसित/संचालित प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम

i. अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर संकाय विकास कार्यक्रम की एक

सूचना गाइड तैयार की (23 नवंबर – 27 नवंबर 2020)। नई दिल्लीः नीपा, 2019। 34पी।

ii. मूडल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर 5 दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिजाइन, विकसित, वितरित और लेनदेन किया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान और बाद में प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों और मुद्दों को हल करने के लिए प्रेरणा, संलग्नता और चर्चा मंच का उपयोग किया गया।

iii. संकाय विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों के व्हाट्सएप ग्रुप (नीपा एआरएल वर्कशॉप) का गठन किया गया था और प्रतिभागियों को व्हाट्सएप ग्रुप ख्नीपा एआरएल वर्कशॉप, के माध्यम से दूसरे, तीसरे और चौथे सप्ताह के ऑनलाइन कार्यक्रम को डिजाइन और विकसित करने और सूचना और लिंक के प्रसार के लिए 30 दिनों की ऑनलाइन संसाधनों की तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। डॉ. डी.एस. ठाकुर लर्निंग पोर्टल के माध्यम से प्रतिभागियों द्व ारा एक्सेस किए गए सभी संसाधन (पूर्ण–पाठ लेख, पीपीटी, वीडियो और अन्य ओईआर)

[https://dsthakur.moodlecloud.com/]

iv. श्रीनिवास, के. और ठाकुर, डी.एस. (2021)। अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर संकाय विकास कार्यक्रमः एक रिपोर्ट (23 नवंबर – 27 नवंबर 2020)। नई दिल्लीः राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 47पी। (अप्रकाशित)

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए सूचना एकत्र की।

i. नीपा की गतिविधियों के बारे में सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासन के प्रमुखों, छात्र एकक, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, परियोजना प्रबंधन एकक से एकत्रित जानकारी जैसे– पूर्ण/जारी अनुसंधान अध्ययन, एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों में नामांकन, सम्मनित की गई पीएच.डी. डिग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएँ, वर्ष 2020–21 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के लिए तैयारी के लिए हर साल आयोजित की जाती हैं।

अन्य अकादमिक और व्यावसायिक योगदान

विभिन्न प्रशासनिक और अकादमिक समितियों में सदस्य

i. नीपा में डिजिटल पहल के कार्यान्वयन के लिए नीपा डिजिटल अधिगम अनुश्रवण कक्ष के सदस्य।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक पुरस्कारों के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भण्डार गृह बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत शैक्षणिक संस्थान अधिकारी।

iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के इनफ्लिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) के साथ शोधगंगा से संबंधित गतिविधियों के लिए संस्थान समन्वयक।

iv. नीपा की शासन प्रक्रिया को मजबूत करने और नॉक मूल्यांकन को औपचारिक बनाने के लिए साहित्यिक चोरी और दुर्व्यवहार की जांच करने के लिए आचार संहिता विकास समिति के सदस्य

v. नीपा की शासन प्रक्रिया को मजबूत करने और नॉक मूल्यांकन को औपचारिक बनाने के लिए कर्मचारियों के लिए आईसीटी, ई–गवर्नेंस, वित्त प्रबंध आदि के क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम समिति के सदस्य

vi. नीपा की शासन प्रक्रिया को मजबूत करने और नॉक मूल्यांकन को औपचारिक के लिए ई–गवनेंस और विभिन्न गतिविधियों में आईसीटी उपयोग हेतु समिति के सदस्य।

vii. सदस्य सचिव, नीपा एम.फिल. और पीएच.डी डिग्री के प्रारूप को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) पर अपलोड के लिए समिति।

आईसीटी और अधिगम प्रबंधन व्यवस्था (एलएमएस) कौशलः

अधिगम प्रबंधन	मूडल (मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट–ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट)
व्यवस्था (एलएमएस)	एनवायरनमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
साहित्यिक चोरी का पता लगाने	मूल पीडीएस
वाला सॉफ्टवेयर (पीडीएस)	
वीडियो निर्माण एवं संपादन	स्क्रीनकॉस्टिफाइ, ओबीएस स्टूडिओ, शाटकट एडिटिंग, यूट्यूब प्रजेंटेशन
सॉफ्टवेयर	स्क्रीन–कॉस्ट–ओ–मेटिक साफ्टवेयर इत्यादि
कम्प्यूटर प्रवीणता	विंडोज 2000, हाइपरटैक्स्ट मार्कअप लैग्वेज़ (एचटीएमएल), फ्रंटपेज 2002
काम का ज्ञान	लिबसिस–4, टैक्लीबप्लस, ज्ञानोदया, विद्या
लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर/ पैकेज	सीडीएस/आईएसआईएस 3.0।

विकसित और अद्यतन इंट्रानेट

नीपा के पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण केंद्र की वेबसाइट बनाई और अद्यतन किया गया और पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के डिजीटल और ऑनलाइन संसाधनों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए नीपा में एक इंट्रानेट विकसित किया, जैसे कि भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं की सदस्यता, गैर–पुस्तक सामग्री मद, समय–समय पर विविध सामग्री, डिजिटल संसाधनों, मुक्त शैक्षिक संसाधन, इलैक्ट्रोनिक थीसिस और शोध प्रबंध (ईटीडी) ऑनलाइन डेटाबेस की सूचना, बड़े पैमोन पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक्स)। इसके अलावा, प्रलेखन केंद्र द्वारा दी जाने वाली प्रलेखन सेवाएं जैसे अनुसंधान अध्ययन की सूची, सामयिक पेपर श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, पीजीडेपा और आईडेपा के शोध प्रबंध, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपीएसी) और शोध अध्ययन के अन्य पूर्ण पाठ दस्तावेज, सामयिक पेपर श्रृंखला, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट और नीपा वृत्तचित्र, प्रख्यात विद्वान व्याख्यान श्रृंखला इंट्रानेट पर भी उपलब्ध हैं।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

i. भारतीय पुस्तकालय संघ, दिल्ली (आईएलए),। (आजीवन सदस्य)

ii. भारत सरकार पुस्तकाध्यक्ष संघ (जी.आई.एल.ए.), नई दिल्ली। (आजीवन सदस्य)

iii. भारत तुलनात्मक शिक्षा समिति (सीईएसआई), नई दिल्ली (आजीवन सदस्य)

वर्ष 2020–21 के दौरान विभाग की गतिविधियों से संबंधित कोई अन्य जानकारी जो विभागाध्यक्ष जोड़ना चाहते हैं

i. संस्थान समन्वयक, ओरिजनल (पहले उरकुंड) साहित्यिक चोरी डिटेक्शन सॉफ्टवेयर पर शोधार्थियों, संकायों और कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए शोध–प्रबंधों, और अन्य अकादमिक और शोध प्रकाशनों की समानता की जांच करने हेतु प्राधिकृत और थीसिस को शोधगंगा पर अपलोड करने के लिए भेजा।

ii. संस्थान समन्वयक, मूल साहित्यिक चोरी डिटेक्शन साफ्टवेयर द्वारा शोध प्रकाशनों की समता की जांच करने और थीसिस को शोधगंगा पर अपलोड करने हेतु

iii. शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा अनिवार्य राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के कार्यान्वयन के लिए एनएडी के साथ डिजीलॉकर के माध्यम से समन्वय करने के लिए अधिकृत शैक्षणिक संस्थान अधिकारी, संस्थान/विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक पुरस्कारों को एनएडी को अपलोड करना।

iv. नीपा द्वारा प्रदान की जाने वाली एम.फिल. और पीएच.डी. डिग्री का प्रारूप तैयार करने हेतु सदस्य सचिव। कार्य को पूरा करने के लिए, विभिन्न बैठकों का आयोजन/व्यवस्थता, समितियों का गठन, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दौरा, पेपर के चयन के लिए 2 फर्मों का दौरा किया, सुरक्षा सुविधाओं की जांच की और कोटेशन प्राप्त किए और अंतिम कार्यवृत्त/रिपोर्ट प्रस्तुत की।

v. अतिरिक्त कार्यभार : प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी), नीपा, के रूप में कार्यरत

5

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

कंप्यूटर केंद्र संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेटवर्क संस्थान की रीढ की हड्डी है तथा इसके सक्रिय संघटकों को कंप्यूटर केंद्र द्वारा संचालित, अनुरक्षित तथा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर केंद्र एन.एम. ई.आई.सी.टी परियोजना के अंतर्गत **एन.के.एन./एम.टी.एन.एल.** द्वारा प्रदान की गई 1 जी.बी.पी.एस ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट संपर्कता से सुसज्जित है। संस्थान में सतत रूप से हर समय इंटरनेट की संपर्कता 24x7x365 सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर केंद्र सभी स्टाफ सदस्यों, प्रशिक्षुओं, परियोजना स्टाफ, कार्यक्रम भागीदारों, अनुसंधानविदों को कंप्यूटर सुविधा तथा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराता है।

नेटवर्क संसाधनों का प्रयोग करने हेतु सभी स्टाफ सदस्यों तथा संकाय सदस्यों को उच्च गति वाली इंटरनेट संपर्कता तथा नेटवर्क प्वाइंट प्रदान किये गये हैं। **नीपा डोमेन** पर सभी स्टाफ तथा संकाय सदस्यों को व्यक्तिगत ई–मेल खाता की सुविधा दी गई है। सभी संकाय सदस्यों को डैस्कटाप/लैपटाप कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं तथा सभी स्टाफ सदस्यों को उनके डेस्क पर डैस्कटाप कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया है। कंप्यूटर केंद्र की सुविधाएं बिना किसी व्यावधान के लगातार 12 घंटे उपलब्ध रहती हैं। कंप्यूटर केन्द्र पर तृतीय पक्ष कम्पनी के सहयोग से संस्थान के अपने कंप्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों के रखरखाव की जिम्मेदारी है।

कंप्यूटर केन्द्र संस्थान की दैनिक अकादमिक तथा गैर अकादमिक गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रकार के नवीनतम डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप तथा मल्टी–फंक्शन प्रिंटरों से सुसज्जित है।

नीपा भवन से नीपा हास्टल को **उच्च गति इंटरनेट संपर्कता** उपलब्ध कराई गई है। नीपा छात्रावास के सभी मंजिलों के सभी कमरों में अतिथियों के लिये प्रमाणित तथा सुरक्षित वाई–फाई संपर्कता उपलब्ध–कराई गई है।

यह केंद्र अकादमिक विभागों को प्रशिक्षण, अनुसंधान, मात्रात्मक आंकड़ा विश्लेषण और प्रणाली स्तर के प्रबंधन संबंधी मुद्दे तथा दूसरे कार्यकलापों में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त गैर–अकादमिक एककों जैसे– पुस्तकालय, प्रशासन तथा वित्त विभागों को भी सहायता प्रदान की जाती है। संस्थान की डाटा प्रोसेसिंग तथा वर्ड प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा कंप्यूटर केंद्र विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों/ कार्यक्रमों के लिए अन्य विशिष्ट कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है।

लेखा अनुभाग को भी कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए समर्थन दिया जाता है। इसमें शामिल है, वेतन संगणना, आयकर गणना, पेंशन, भविष्य निधि गणना आदि। इसके लिए **एस.पी.एस.एस. सांख्यिकी पैकेज (एसपीएसएस)** नेटवर्क वर्जन सर्वर के साथ स्थापित किया गया है ताकि प्रयोगकर्त्ता नेटवर्क पर गणना कर सकें। कंप्यूटर केंद्र दैनिक गतिविधियों के लिये ओपन स्रोत साफ्टवेयरों को प्रोत्साहन देता है।

संस्थान की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक डाटा केन्द्र स्थापित किया गया है। डाटा केन्द्र उच्च गुणवत्तायुक्त डाटा सर्वर तथा वेब सर्वर से जुड़ा है जोकि चौबीसों घंटे 24x7x365 उपभोक्ताओं के लिये ऑन–लाईन उपलब्ध है। डाटा सेंटर समर्पित समानांतर यू.पी.एस. सिस्टम से समर्थ है जो सर्वर को पावर बैक–अप प्रदान करता हैं।

कम्प्यूटर केंद्र भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत जाने–माने कार्यक्रम एकीकृत शैक्षिक जिला प्रणाली सूचना (यू–डाईस) के लिये सर्वर का रखरखाव संगणक केंद्र करता है। इसके अलावा संगणक केंद्र का डाटा केंद्र राष्ट्रीय विद्यालय मानक एवं मूल्यांकन–शाला सिद्धि के राष्ट्रीय कार्यक्रम के वेब पोर्टल का रखरखाव भी करता है।

नीपा आंकड़ा केन्द्र नेटवर्क संरचना

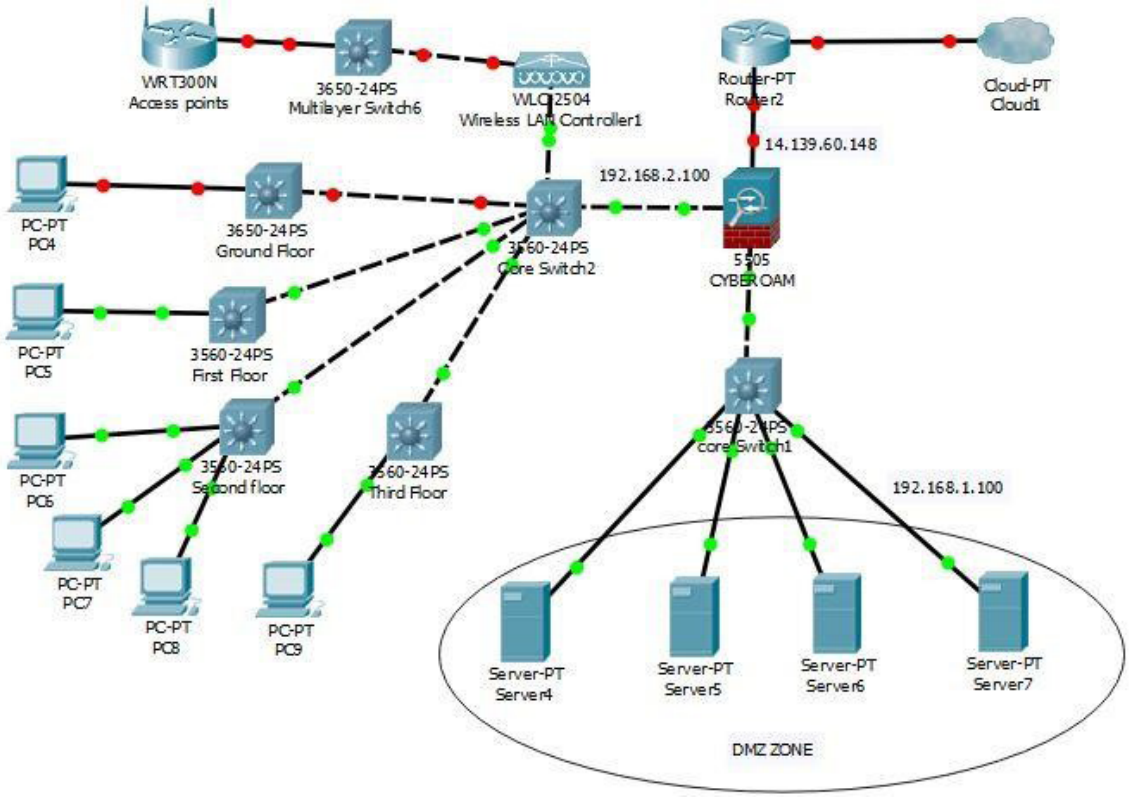

- डेटा सेंटर नेटवर्क आर्किटेक्चर में फायरवॉल, कोर स्विच वायरलेस, वाई–फाई कंट्रोलर और आईएसपी राउटर शामिल हैं।
- 8 आइबीएम सर्वर हैं जो यू–डाईस, शाला सिद्धि, ओरेकल सर्वर, एसडीएमआईएस, डेटा विजुअलाइज़ेशन, niepa.ac.in] छात्र प्रबंधन सूचना प्रणाली, स्कूल निर्देशिका प्रबंधन प्रणाली और स्कूल रिपोर्ट कार्ड जैसे कई वेब अनुप्रयोगों से जुड़े हैं
- दो डेल सर्वर हैं जो डिजिटल अभिलेखागार और डेटाबेस सर्वर से जुड़े हैं।
- एच.पी. सर्वर मूडल पोर्टल, एनसीएसएल पोर्टल, क्विक हील एंडपॉइंट सुरक्षा और प्रिंटिंग सर्वर से जुड़े हैं।
- लिबसिस के लिए आईबीएम टॉवर सर्वर (ओपेक)

नीपा डाटा सेंटर में चल रहे एप्लिकेशन – आंतरिक तकनीकी टीम द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किये जाते हैं।

1. www.niepa.ac.in
2. http://www.nrce.niepa.ac.in/
3. http://cprhe.niepa.ac.in/
4. http://niepa.ac.in/UIC/uic1.html
5. http://niepa.ac.in/darch.aspx
6. www.antriep.net,

एन्ट्रीप एशिया में राष्ट्रीय संस्थानों का एक नेटवर्क है, जो इस क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रबंधन में कौशल विकास के लिए बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं का जवाब देने और अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भागीदार संस्थानों के बीच तालमेल बनाने के लिए एक दृष्टिकोण है।

7. www.udise.in

इस वेबसाइट का उपयोग प्रकाशन के रूप में स्कूल के आंकड़ों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है।

8. http://ncsl.niepa.ac.in/

नीपा में 2012 में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केन्द्र (एनसीएसएल) देश में स्कूलों के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य उद्देश्य के रूप में स्कूलों के रूपांतरण के साथ, एनसीएसएल–नीपा देश भर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 679 जिलों और 6500 ब्लॉकों में नेतृत्व की आवश्यकता और प्रासंगिक स्कूल के मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य रूप

से केंद्र की सभी गतिविधियाँ प्रत्येक राज्य के प्रत्येक स्कूल के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं। केंद्र विभेदक और व्यावहारिक नेतृत्व मॉडल विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

9. वेब अनुप्रयोग

अ. www.school report card.in,

ब. Student.udise.in

स. Sdms.udise.in

द. http://udise.schooleduinfo.in/

य. www.semisonline.net (यू.डाईस के साथ विलय)

10. http://shaalasiddhi.niepa.ac.in/

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

11. moodle.niepa.ac.in – मुक्त स्त्रोत अधिगम प्रंधन प्रणाली : मूडल इस उप–डोमेन को विश्वविद्यालयों के स्वयं के डेटा केंद्र पर भी होस्ट किया जाता है।

आईसीटी विभाग की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

- डाटा सेंटर और सर्वर हार्डवेयर की नियमित रूप से निगरानी की जाती थी।
- नेटवर्क और वाई–फाई से संबंधित मुद्दों को नियमित रूप से प्रबंधित किया जाता है। नेटवर्क विलंबता का निरीक्षण करके संगठन के नेटवर्क प्रदर्शन को नियमित रूप से ट्यून किया गया था।
- संगठन के आंकड़ा केंद्र और नीपा छात्रावास में 24x7 नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- संस्थान का सोशल मीडिया प्रबंधन (ट्विटर और फेसबुक)
- यूट्यूब और फेसबुक घटनाओं का सीधा प्रसारण
- उपलब्ध नीपा डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ लाइव वेबिनार का आयोजन
- बैठक और वेबिनार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन
- साइबर खतरा अनुश्रवण नीपा आंकड़ा केन्द्र और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हमलों की निगरानी
- ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस प्रबंधन
- ई–निविदा के लिए ई–विजार्ड की सुविधा और क्रियान्वयन
- जीईएम में तकनीकी बोली का मूल्यांकन
- संगठन की वेबसाइटों की निगरानी और बार–बार अद्यतन करना।
- सर्वर एएमसी का प्रबंधन
- नियमित रूप से पूरे सर्वर के सुरक्षा पैच अपडेट किए जाते हैं।
- नीपा डेटा सेंटर का सर्वर बैकअप नियमित अंतराल पर किया जाता है।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का बैकअप नियमित रूप से किया जाता है।
- ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का निर्माण और नीपा एलएमएस में उपयोगकर्ताओं का नामांकन
- एंटी–वायरस पैच को सर्वर से क्लाइंट्स तक पहुंचाना
- ऑनलाइन यूपीएस का रखरखाव और निगरानी बार–बार की जाती है।
- संस्थान की सीसीटीवी निगरानी।
- सभी डोमेन की निगरानी
- niepa.ac.in मेल डोमेन का प्रबंधन
- ऑनलाइन भर्ती की निगरानी और प्रबंधन (स्थायी और अस्थायी)

आईटी का उपयोग करने के लिए पिछले एक वर्ष में की गई नई पहल एक निवारक सतर्कता उपकरण है		
क्र. सं.	**लक्ष्य / उद्देश्य**	**उपलबिध्याँ**
1.	हमने एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए क्लाउड–आधारित एंटी–वायरस सॉल्यूशंस के तहत सभी सिस्टम्स को कवर करने की योजना बनाई है	हां, हमने क्लाउड–आधारित एंटी–वायरस समाधान के तहत सभी प्रणालियों को कवर किया है
2.	हमने केंद्रीकृत ई–मार्क्स कार्ड के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार बनाने की योजना बनाई है	हमने संस्थान के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार को लागू करने की सुविधा प्रदान की है
3.	हमने ई–विजार्ड पोर्टल को लागू करने की योजना बनाई है जो ई–निविदाओं की सुविधा प्रदान करता है	हमने संस्थान के लिए ई–विज़ार्ड पोर्टल को लागू करने की सुविधा प्रदान की
4.	हमने ई–निविदाओं के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लागू करने की योजना बनाई है	हमने उच्च मूल्य की निविदाओं के लिए केंद्रीय खरीद पोर्टल को लागू करने की सुविधा प्रदान की
5.	हमने पीओई सिस्को स्विच के साथ हॉस्टल में मौजूदा कैट 5 टू कैट 6 केबलिंग को बदलने की योजना बनाई है	हमने पीओई स्विच के साथ हॉस्टल में कैट 5 से कैट 6 केबलिंग को बदल दिया
6.	हम पुराने एचपी डीएल 380 सर्वर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं ताकि ओईएम की मरम्मत हो सके	हमने पुराने सर्वर का उपयोग किया है जिसमें वास्तविक विंडोज 2012 मानक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एंटी–वायरस सर्वर है
7.	हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की खरीद की योजना बनाई है	हां, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए खरीदा और इस्तेमाल किया गया है
8.	हमने उपयोगकर्ताओं को गुगल ड्राइव हेतु सिस्टम डेटा को सिंक करने के लिए उपयोग करने की सुविधा देने की योजना बनाई है	हमने गुगल ड्राइव के उपयोग के बारे में शिक्षित किया
9.	हमने वित्त अनुभाग के लिए पीएफएमएस को लागू करने की सुविधा देने की योजना बनाई है	हां, हमने वित्त अनुभाग के लिए पीएफएमएस को लागू करने की सुविधा दी है
10.	हमने बैठक की सुविधा को ऑनलाइन करने की योजना बनाई है	हां, हमने ऑनलाइन मीटिंग के लिए गुगल बैठक का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है

क्र. सं.	लक्ष्य / उद्देश्य	उपलबिध्याँ
11.	हमने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर की खरीद की योजना बनाई है	हां, हमने नेटवर्क मोड में खरीद और इंस्टॉल किया
12.	42 नए डेस्कटॉप खरीदे गए	सभी डेस्कटॉप में पुराने सिस्टम को स्थापित और प्रतिस्थापित किया गया
13.	4 हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स की खरीद की	स्थापित हैवी ड्यूटी प्रिंटर्स फ्लोर वाइज
14.	एक सर्वर पर पेरोल एप्लीकेशन परिनियोजन	सर्वर में पेरोल सॉफ्टवेयर स्थापित किया
15.	एम.फिल. / पीएच.डी. 2020 परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की योजना बनाई	हां, हमने ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है
16.	लैपटॉप की खरीद	महामारी के दौरान घर से काम करने के लिए 12 लैपटॉप स्थापित और प्रसदन किए गए
17.	महामारी के दौरान बैठकों और वेबिनार को ऑनलाइन आयोजित करने की योजना बनाई	एक ऑनलाइन मीटिंग और वेबिनार का संचालन किया
18.	वेबिनार को सीधा प्रसारण करने की योजना बनाई है	हां हमने इवेंट्स का लाईव स्ट्रीम किया है
19.	हाई एंड सर्वर हासिल करने की योजना बनाई	हां हमने नीपा डाटा सेंटर में दो नए सर्वर स्थापित किये है
20.	नेटवर्क भंडारण की खरीद की योजना बनाई	हां हमने स्टोरेज को नीपा डाटा सेंटर में स्थापित कर दिया है

Teaching Learning and New Technologies in Higher Education
Concepts and Terms used in Educational Planning and Administration
Education, Democracy and Development
GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION IN INDIA
NIEPA Publications (for Display Only)
Education and Empowerment in India
A Financial Code for University Systems
GENDER IN CONTEMPORARY EDUCATION RESEARCH

6

प्रकाशन

Priced Publications
Unpriced Publications
Folders and Flyers
DISE Publications
English & Hindi Journals
हिंदी प्रकाशन

प्रकाशन

राष्ट्रीय संस्थान का प्रकाशन एकक संस्थान द्वारा की गई शोध और विकास गतिविधियों के निष्कर्षों के प्रकाशन और प्रसारण द्वारा ज्ञान की साझेदारी संबंधी कार्यकलापों का अनुसमर्थन व्यापक स्तर के लिए करता रहा है। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के अनुक्रम में प्रकाशन एकक समसामयिक आलेख/जर्नल/पाक्षिक न्यूजलेटर, पुस्तकें, एम.फिल. और पी–एच.डी. की विवरणिका और प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेण्डर प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षणों की रिपोर्टों की श्रृंखला भी प्रकाशित करता है। उपरोक्त प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण और वैधनिक प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के अलावा, आवश्यकता के अनुसार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशन एकक में कुशल और तकनीकी रूप से योग्य पेशेवर है और यह विश्वविद्यालय के विभिन्न डी.टी.पी. कार्यों को करने के लिए कम्प्यूटर और प्रिंटर से लैस है।

वर्ष 2020–21 के अंतर्गत नीपा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले गए– जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (अंग्रेजी), परिप्रेक्ष्य (हिंदी) जर्नल और सी.पी.आर.एच.ई. अनुसंधान आलेख, एम.फिल तथा पी–एच.डी. कार्यक्रमों की विवरणिका तथा पाठ्यचर्या गाईड नीपा का पर्सपेक्टिव प्लान 2020–2030, नॉर्डिक पर रिपोर्ट– उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारत शिखर सम्मेलन, आदि। संस्थान ने अनेक शोध और संगोष्ठियों/सम्मेलनों की रिपोर्टें पुस्तक और मोनोग्राफ के रूप में प्रकाशित की। समीक्षाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थान ने निम्नांकित प्रमुख प्रकाशन निकाले :

पत्रिकाएं

- जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिल्द XXXIII, अंक 3, 2019; जिल्द XXXIII, अंक 4, 2019; जिल्द XXXIV, अंक 1, 2020; जिल्द XXXIV, अंक 2, 2020 और जिल्द XXXIV, अंक 3, 2020।
- परिप्रेक्ष्य (शैक्षिक योजना और प्रशासन में सामाजिक–आर्थिक संदर्भ पर हिन्दी जर्नल) जिल्द XXV, अंक 3, 2018; (प्रेस में)

एंट्रीप न्यूज़लेटर

- एंट्रीप न्यूज़लेटर, (जिल्द 25, अंक 1, जनवरी–जून 2019 और जिल्द 25, अंक 2, जुलाई–दिसंबर 2019)

सम–सामायिक आलेख

- समसामयिक आलेख सं. 53: उच्च शिक्षा के लिए छात्र गतिशीलता; मधुरिमा नंदी और रामा वी. बारू द्वारा चीन में चिकित्सा अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों का मामला: नई दिल्ली, नीपा 56 पृष्ठ।
- नीपा समसामयिक आलेख आलेख सं. 54: शिक्षा का अधिकार और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों की सार्वभौमिक भागीदारी: मुद्दे, अंतराल और चुनौतियां, सुनीता चुग, नई दिल्ली, नीपा, 47 पृष्ठ।

सी.पी.आर.एच.ई. शोध आलेखः

- सीपीआरएचई अनुसंधान आलेख 13 : ''निजी उच्च शिक्षा संस्थनों में शुल्कः भारत में मानित विश्वविद्यालयों का एक अध्ययन, जिणुशा पाणिग्रही।
- सीपीआरएचई अनुसंधान आलेख 14: मोना खरे, भारत में स्नातक रोजगार और सतत रोजगार कौशल, नीपा, नई दिल्ली, 64पृष्ठ।

सःशुल्क प्रकाशन

- इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019: एन.वी. वर्गीज, गरिमा मलिक द्वारा संपादित, भारत उच्च शिक्षा का शासन और प्रबंधन, सेज प्रकाशन, ₹1595.00 (एच.बी.)
- एन.वी. वर्गीज, और एस. मंडल द्वारा संपादित, अध्यापन अधिगम और उच्च शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी, स्प्रिंगर नेचर प्रकाशन, €103.99 (एच. बी.)

निःशुल्क प्रकाशन :

1. उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर नॉर्डिक–इंडिया शिखर सम्मेलन पर रिपोर्ट (31 अक्टूबर, 2019)
2. नीपाः एक परिप्रेक्ष्य योजना 2020–2030
3. सीपीआरएचई रिपोर्ट 2019–20
4. एम.फिल–पीएच.डी. कार्यक्रम अनुसूची 2020–21
5. एम.फिल–पीएच.डी. डिग्री विनियम 2020
6. नीपा संकाय
7. उच्च शिक्षा में शासन और स्वायत्तता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (20–21 फरवरी, 2020)
8. शहरों के बाहरी इलाकों में शिक्षाः हैदराबाद और लुधियाना में मलिन बस्तियों का एक अध्ययन सुनीता चुग द्वारा
9. एनईपी 2020: कार्यान्वयन रणनीतियां (दिसंबर 2020)
10. नीपा वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 (अंग्रेजी संस्करण)
11. नीपा वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 (हिंदी संस्करण)
12. उच्च शिक्षा का भविष्यः प्रोफेसर ध्रुव रैना द्वारा इतिहास और विज्ञान के दर्शन के लेंस के माध्यम से (नीपा ग्यारहवां मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान) (नवंबर 2020)

अन्य

इन प्रकाशनों के अलावा, नीपा ने नीपा 2020–21 के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर भी निकालाय प्रॉस्पेक्टस (एम. फिल–पीएच.डी. कार्यक्रम) 2020–2021 और 2021–2022; आईडेपा, पीजीडेपा और विभिन्न अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए घोषणाएँ (ई–संस्करण), नीपा स्थापना दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के पोस्टर; लेखन पैड; डॉकेट फोल्डर्स और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों की सामग्री, आदि प्रकाशित की।

मिमियोग्राफ प्रकाशनः इसके अलावा, नीपा ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों के अनुसंधान अध्ययन, रिपोर्ट, पठन सामग्री से संबंधित कई मिमियोग्राफ/जेरोक्स्ड प्रकाशन भी निकाले।

नीपा वेबसाइट के लिए सामग्रीः प्रकाशन इकाई ने अपने प्रकाशनों से संबंधित नीपा वेबसाइट को नियमित अपडेट प्रदान किया। अद्यतनों में निजी प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशित मूल्य और बिना मूल्य वाले प्रकाशनों और प्रकाशनों की व्यापक सूची शामिल थीय जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के वर्तमान और आगामी मुद्दों के बारे में जानकारी; नीपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेंडर; न्यूपा–एक नजर में, और एम.फिल.–पीएच.डी. की विवरणिका। निगम ज्ञापन और नियम हिंदी जर्नल (त्रि–वार्षिक) परिप्रेक्ष्य का पूर्ण पाठ संस्करण; नीपा समसामयिक पत्रों का पूर्ण पाठ संस्करण; सीपीआरएचई शोध पत्रों का पूर्ण पाठ संस्करण; नीपा वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) का पूर्ण पाठ संस्करण और एनसीएसएल, शाला सिद्धि, सीपीएचआरई, और डाईस प्रकाशन आदि के वेब संस्करण।

7

नीपा में सहायता अनुदान योजना

नीपा में सहायता अनुदान योजना

कार्य योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यवाही योजना में उनकी पुनः व्याख्या के विभिन्न मानकों का क्रियान्वयन हेतु उद्देश्यों का वृहद प्रचार आवश्यक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों तथा सामाजिक संगठनों के साथ निकटतम सहयोग आवश्यक है। नीति के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वयन हेतु, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर समर्थन व्यवस्था समेत अंतःशास्त्रीय उपागम आवश्यक है।

इस संदर्भ में ये आवश्यक हैं: (अ) देश में शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति वृहद जागरूकता पैदा करना, (ब) नीति उन्मुख अध्ययनों तथा संगोष्ठियों को आरंभ करना ताकि मध्य–पाठ्यक्रम सुधार, संशोधन तथा नीति हस्तक्षेपों के साथ समायोजन किया जा सके (स) अध्यापकों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं और संचार माध्यमों को प्रायोजित संगोष्ठी के आयोजन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके साझा मंच प्रदान करना। (द) शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी तथा अच्छे व्यवहार एवं सफल प्रयोग को बढ़ावा देना (य) राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना की समीक्षा को सुविधाजनक बनाना।

उपरोक्त प्रयोजन के लिये, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सहायता अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसके अंतर्गत योग्य संस्थानों तथा संगठनों को वित्तीय सहायता शिक्षा नीति के प्रबंधन तथा क्रियान्वयन पक्ष पर सीधे प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के आधार पर प्रदान की जायेगी। इसके अंतर्गत सम्मेलनों का आयोजन, प्रभावी तथा मूल्यांकन अध्ययन, सर्वोत्तम विकल्पों पर परामर्शकारी अध्ययन, भारत सरकार को सलाह देने हेतु तथा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु मॉडल, विडियो फिल्म इत्यादि का निर्माण सम्मिलित हैं।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से यह योजना संचालित की है जो सहायता अनुदान समिति के द्वारा इसे संचालित करता है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता अनुदान योजना के तहत विभिन्न संस्थानों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा अनुमोदन के लिए समिति का पुनर्गठन 11 मार्च, 2021 को किया गया है। 31 मार्च, 2021 के अनुसार इस समिति के निम्नांकित सदस्य हैं:

प्रोफेसर ए.के. सिंह	–	अध्यक्ष
प्रोफेसर इलियास हुसैन	–	सदस्य
प्रोफेसर उमा मेदुरी	–	सदस्य
प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति	–	सदस्य
प्रोफेसर कुमार सुरेश	–	सदस्य
प्रोफेसर वीरा गुप्ता	–	सदस्य
प्रोफेसर प्रमिला मेनन	–	सदस्य
प्रोफेसर के. बिस्वाल	–	सदस्य
डॉ. संदीप चटर्जी	–	सदस्य सचिव

कोरोना महामारी के कारण, सभीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की कोई भी बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका।

8

प्रशासन और वित्त

प्रशासन और वित्त

प्रशासन

संस्थान के पास हाउसकीपींग तथा सुरक्षा सेवाओं के लिये बाह्य सेवा–स्रोतों के अतिरिक्त निम्नांकित स्वीकृत पद हैं।

प्रशासन तथा अकादमिक एंव तकनीकी समर्थन सेवाएं प्रशासन के कार्य के अनुसार स्थापित अनुभागों द्वारा नियंत्रित तथा समन्वित की जाती हैं।

इसके अनुभाग कार्यकलापों के अनुसार स्थापित किये गए हैं जिन्हें संगठनात्मक आरेख में प्रदर्शित किया गया है। विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के अलावा विभिन्न अकादमिक और अनुसचिवीय पदों पर 93 परियोजना कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं।

बाह्य संवर्ग पद	संख्या
कुलपति	01
कुलसचिव	01
संवर्ग पद	
संकाय (प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर)	42
अकादमिक समर्थन स्टाफ़	07
प्रशासन, वित्त, सचिवीय तथा अन्य तकनीकी स्टाफ	79
सहायक स्टाफ (एम.टी.एस.)	37
कुल	167

समीक्षाधीन वर्ष 2020–21 के दौरान, निम्नांकित सेवानिवृत्तियां की गईं।

सेवानिवृत्तियां

समूह 'बी'

क्र. सं.	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री सतीश कुमार	आशुलिपिक ग्रेड–I	31.07.2020
2.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	निजी सचिव	30.09.2020
3.	श्रीमती अंजली अरोड़ा	आशुलिपिक ग्रेड–I	31.01.2021

समूह 'सी'

क्र. सं.	नाम	पद	तिथि
1.	श्री पंचम प्रसाद	एमटीएस	31.05.2020
2.	श्री बिक्रम सिंह नेगी	उच्च श्रेणी लिपिक	28.02.2021

नई नियुक्ति

क्र. सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. संदीप चटर्जी	कुलसचिव	24.09.2020

वित्त तथा लेखा विभाग

नीपा में वित्त तथा लेखा सेवाएं लेखा अनुभाग द्वारा संचालित की जाती हैं जिसका अध्यक्ष वित्त अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखाकार और कार्यालय के आठ सदस्य तथा अनुसचीवीय स्टाफ होता है। यह अनुभाग बजट की तैयारी, मासिक वेतन तथा पेंशन बिल, अन्य व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति जैसे चिकित्सा, एल.टी.सी. बिल, अग्रिम इत्यादि, वस्तुओं की खरीद के लिये बिल भुगतान प्रक्रिया, कार्य, संविदा इत्यादि, पूर्व लेखा परीक्षा, बाह्य परीक्षा के साथ समन्वयन तथा वित्त तथा लेखा से जुड़े अन्य मसलों के लिये उत्तरदायी होता है। यह सभी वित्तीय मसलों पर समयबद्ध परामर्श देता है तथा वित्तीय भागीदारी, लेखा बयान, उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि हेतु सभी प्रस्तावों के परीक्षण हेतु प्रभावी सहायता प्रदान करता है। वित्त अधिकारी वित्त समिति का सदस्य सचिव होता है जो विश्वविद्यालय के वित्त, निर्देशन तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये व्यय की सीमा तय करता है। पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय से प्राप्त अनुदान निम्नांकित है :

प्राप्त अनुदान का व्यौरा (2016–2021) (रु. लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	सहायता अनुदान (योजना)	1010.87	2612.95	3184.71	4559.46	3688.00
	सहायता अनुदान (योजनेतर)	1816.11				
	आंतरिक प्राप्तियां	74.47	59.32	34.69	39.15	66.76
	योग	**2901.45**	**2672.27**	**3219.40**	**4598.61**	**3,754.76**
2.	व्यय (योजना)	1078.42	2956.09	3491.89	4314.43	3352.41
	व्यय (योजनेतर)	1721.81				
	योग	**2800.23**	**2956.09**	**3491.89**	**4314.43**	**3352.41**
3.	आंतरिक प्राप्तियां व्यय के प्रतिशत के रूप में	1%	2%	1%	0.91%	2%
4.	सहायता अनुदान व्यय का प्रतिशत	96.51%	100%	100%	94.63%	90.90%

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान सहायता अनुदान में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है और इसी अनुपात में इसका व्यय भी बढ़ा है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नीपा अपनी मुख्य गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दे रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन/ हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष अनुवाद की सुविधा के माध्यम से अनुसंधान प्रशिक्षण और प्रशासन में अकादमिक सहायता प्रदान करता है। यह कक्ष विभिन्न प्रकाशनों के हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के साथ–साथ राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दैनिक कार्य के अलावा नीपा के हिंदी कक्ष ने कई निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए:

1. प्रकाशन के लिए निम्नलिखित प्रमुख मदों का हिंदी में अनुवाद किया गया:
    i. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 का हिंदी अनुवाद।
    ii. नीपा परिप्रेक्ष्य योजना 2020–2030 का हिंदी अनुवाद।
    iii. वार्षिक रिपोर्ट 2017–18 का हिंदी अनुवाद।
    iv. वार्षिक रिपोर्ट 2018–19 का हिंदी अनुवाद।
    v. नीपा एम.फिल–पीएचडी विवरणिका 2021–22 का हिंदी अनुवाद।
2. वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 का हिंदी में प्रकाशन।
3. राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में चार त्रैमासिक रिपोर्ट और एक समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी गई।
4. हिंदी दिवस समारोहः हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर 2020 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
5. उपरोक्त कार्य के अलावा संस्थान के हिंदी कक्ष ने विज्ञापन, परिपत्र, नोटिस, पत्र आदि का भी अनुवाद किया।

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

अनुलग्नक

संकाय का अकादमिक योगदान

एन.वी. वर्गीज

कुलपति

प्रकाशन

पुस्तकें

टीचिंग–लर्निंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन हायर एजूकेशन (सायंतन मंडल के साथ), स्प्रिंगर, नई दिल्ली, 2021

इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्टः गर्वनेंस एंड मेंनेजमेंट आफ हायर एजुकेशन (गरिमा मलिक के साथ) सेज, नई दिल्ली, 2020

पत्र/आलेख

इंटरनेशनलाइजेशन एंड क्रास बोर्डर मोबिलिटी इन हायर एजुकेशन', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अफ्रीकन हायर एजुकेशन,* वाल्यूम 7, नं. 2, 2020 पीपी.23–39।

''इंटरनेशनलाइजेशन एंड इंडियाज न्यू एजूकेशन पॉलिसी (एल्डो मैथ्यू के साथ) *इंटरनेशनल हायर एजूकेशन* नं. 106, 2021, पीपी. 19–20।

''फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजूकेशन इन इंडिया इन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) एड. *क्वालिटी मेंडेट फॉर हायर एजूकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया,* नई दिल्ली, यूजीसी, 2021 पीपी. 223–235।

''यूनिवर्सिटीज, नॉलेज प्रोडक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ लर्निंग' इन ओरॉजबयेवा, बी; मीरमन, ए; मूरॉस, वी.जी.; देवे एंड पलेवा. सी. द *फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटी थॉट बुकः यूनिवर्सिटी डूरिंग टाइम्स ऑफ क्राईसिस,* यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इनोवेशन नेटवर्क (यूआईआईएन), एम्सटरडम, 2020 पीपी. 72–73,

''द रोल ऑफ डाक्टरल एजुकेशन इन डवलपिंग रिसर्च कैपासिटीज'', मारिया यूडकेविच, फिलिप जी. अल्टबाक एंड हैन्स डे विट, संपादक, *ट्रैंड्स एंड इश्यूज इन डॉक्टरल एजुकेशनः ए ग्लोबल पर्सपैक्टिव,* लॉस एंजिल्स और नई दिल्ली, सेज, 2020, पीपी 295–315

''इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशनः ग्लोबल ट्रैण्ड्स एंड इंडियान इनिसियेटिव्ज'' पंकज मित्तल एंड सिस्टला रमा देवी पनी संपादक. *''रिइमेजनिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज''*, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीजः नई दिल्ली, 2020

संगोष्ठियों/बैठकों में भागीदारी

10 जून, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित शिक्षा–विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति (एसटीआईपी) पर समिति की बैठक

12 जून, 2020 को शिक्षा–विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति (एसटीआईपी) पर समिति की बैठक

12 जून, 2020 को उच्च शिक्षा और विकास पर माइकल पीक के साथ बैठक, ब्रिटिश काउंसिल, लंदन

16 जून, 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित शिक्षा–विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति

(एसटीआईपी) पर मनीष सेबरवाल के साथ समिति की बैठक

23 जून, 2020 को विश्वविद्यालयों की क्यूएस रैंकिंग द्वारा आयोजित छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण पर वेबिनार

3 जुलाई 2020 को (बोस्टन में स्थित मेक्सिको) में प्रोफेसर ऑरेल के साथ यूनेस्को पुरस्कार बैठक

7 जुलाई, 2020 को सन्नम (SANNAM) द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से संस्थागत विकास को बढ़ावा देना'' पर आयोजित वेबिनार में वक्ता

11 जुलाई, 2020 को ओपी जिंदल द्वारा आयोजित उच्चतर शिक्षा नेतृत्व पर वेबिनार में ''सार्वजनिक भलाई के रूप में शिक्षाः सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच बाधाओं का निराकरण और तालमेल बनाना'' पर वार्तालाप में अध्यक्ष

14 जुलाई 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा महिला सशक्तिकरण पर आयोजित वेबिनार में अध्यक्ष और वक्ता

14 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र के विशेषज्ञों की निर्देशिका के सत्र में उद्घाटन भाषण

15 जुलाई 2020 को क्यू.एस. छात्र सर्वेक्षणः अंतर्राष्ट्रीय छात्र क्या चाहते हैं पर वेबिनार

27 जुलाई, 2020 को एआईयू द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में पात्र नामांकन अनुपात (ईईआर) पर एक बैठक में पैनलिस्ट

6 अगस्त, 2020 को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गुणवत्ता आश्वासन, शैक्षणिक मानकों और संस्थागत उत्कृष्टता और नई शैक्षिक नीति पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में सत्र के अध्यक्ष

18 अगस्त, 2020 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में उत्कृष्टता, अंतर्राष्ट्रीयकरण और ग्लोबल रैंकिंग पर एक सत्र की अध्यक्षता

19 अगस्त, 2020 को नई शिक्षा नीति पर नीपा वेबिनार की अध्यक्षता

20 अगस्त, 2020 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित वेबिनार में नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान

20 अगस्त, 2020 को तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान

26 अगस्त, 2020 को केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद (केएससीएचई) द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी में नई शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान

03 सितंबर, 2020 को राज्य उच्च शिक्षा परिषद तेलंगाना के लिए नई शिक्षा नीति (वेबिनार) पर व्याख्यान

7 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति पर वेबिनार

10 सितंबर, 2020 को 'उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020' इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा आयोजित वेबिनार में व्याख्यान,

10 सितंबर, 2020 को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ फिक्की और यूके इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से 'नई शिक्षा नीति 2020: अंतर्राष्ट्रीयकरण और आगे के मार्ग' पर आयोजित वेबिनार में वक्ता।

15 सितंबर, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नीपा द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति कार्यान्वयन के लिए शिक्षक सशक्तिकरण पर वेबिनार की अध्यक्षता

24 सितंबर, 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 (एनसीईआरटी) में प्रभावी मानकीकरण और प्रत्यायन पर वेबिनार में वक्ता

24 सितंबर, 2020 को वैश्विक शिक्षा तथा आजीविका समूह और उच्च शिक्षा आयुक्त तेलंगाना द्वारा आयोजित वेबिनार में नई शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान

25 सितंबर, 2020 को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के लिए नियामक ढांचा पर वेबिनार में वक्ता

06 अक्टूबर, 2020 को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित नवोदय विद्यालयों की बैठक में उद्घाटन भाषण

2 नवंबर, 2020 को एमजी विश्वविद्यालय, कोट्टायम द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में अभिशासन और नेतृत्व पर व्याख्यान

02 नवंबर, 2020 को शिक्षकों हेतु यूजीसी द्वारा आयोजित एनईपी पर समिति की बैठक

06 नवंबर, 2020 को शिक्षकों हेतु यूजीसी द्वारा आयोजित एनईपी पर समिति की बैठक

09 नवंबर, 2020 को शिक्षकों हेतु यूजीसी द्वारा आयोजित एनईपी पर समिति की बैठक

10 नवंबर 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति–कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों के साथ बैठक

24 नवंबर, 2020 को पेकिंग विश्वविद्यालय में 'शैक्षिक योजना परः वैश्विक रुझान और नई शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा पर भारतीय दृष्टिकोण' पर व्याख्यान

26 नवंबर, 2020 को आईआईईपी/यूनेस्को द्वारा आयोजित कोविड और उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में वक्ता।

09 दिसंबर, 2020 को ऑस्ट्रेलियाई दूतावास द्वारा आयोजित एनईपी 2020 और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बैठक में अध्यक्ष

5 जनवरी, 2021 को एनसीईआरटी में स्कूल प्रशासन पर व्याख्यान

06 जनवरी 2021 को सीमैट केरल की कार्यकारी समिति की बैठक

18 जनवरी, 2021 को नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर आयोजित विशेषज्ञ समूह बैठक

18 जनवरी, 2021 को एनवीएस आयुक्त के साथ बैठक

18 जनवरी, 2021 को सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के सलाहकार बोर्ड की बैठक

29 जनवरी 2021 को आईजीटीयूडब्ल्यू में नई शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान

2 फरवरी, 2021 कोट्रांसनेशनल एजुकेशन (टीएनई) पर यूयूकेआई 2021 में एक पैनल में अध्यक्ष।

9 फरवरी, 2021 को एआईयू द्वारा आयोजित कुलपति बैठक में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर वक्ता

11 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय साख अंतरण समिति की बैठक

16 फरवरी 2021 को एसएनडीटी–मुंबई द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा की चुनौतियों पर वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर वेबिनार में वक्ता

18 फरवरी 2021 को ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा स्थिरता के मुद्दों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ाने पर आयोजित वेबिनार में अध्यक्ष

19 फरवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 पर बैठक।

23 फरवरी को केरल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एनईपी 2020 पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण

23 फरवरी 2021 को अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में उच्च शिक्षा मंच समिति की बैठक।

23 फरवरी 2021 को उच्च शिक्षा में व्यापक पहुँच (डब्ल्यूएएचईडी लंदन) द्वारा आयोजित कोविड और इक्विटी पर वेबिनार में वक्ता।

24 फरवरी 2021 को सीएचईए अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता समूह (सीआईक्यूजी, वाशिंगटन) की बैठक।

25 फरवरी 2021 को शास्त्री भवन में नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की कार्यकारी समिति की बैठक।

26 फरवरी 2021 को फिक्की द्वारा आयोजित विनियमन और गुणवत्ता मानक पर फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष।

09 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय गुणवत्ता आश्वासन अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड (यूक्यूएआईबी) की बैठक।

25 मार्च 2021 को राष्ट्रीय साख ढांचे की बैठक।

नई शिक्षा नीति 2020 पर विश्व बैंक सलाहकार समूह की बैठक, 30 मार्च 2021।

शैक्षिक योजना विभाग

के. बिस्वाल

प्रकाशन

पुस्तकें/नियमावली/रिपोर्ट

2017–18 के आंकड़ों के आधार पर यू–डाइस डेटा विजुअलाइज़ेशन पोर्टल का अद्यतन किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पर जनसंख्या अनुमान 2011–36, तकनीकी समूह की रिपोर्ट के आधार पर (http://udise.in/ पर) स्कूल शिक्षा 2017/18 (अनंतिम) की फ्लैश सांख्यिकी का अद्यतन और ऑनलाइन प्रकाशित, जुलाई 2020।

शोध पत्र/लेख/टिप्पणी

'अध्याय 2: एनईपी 2020 नामांकन लक्ष्य प्राप्त करना ''एनईपी 2020: कार्यान्वयन रणनीतियाँ,'' नीपा प्रकाशन का शीर्षक, में (प्रो. गीता रानी, डॉ. एन. के. मोहंती और डॉ. सुमन नेगी के साथ) योगदान, दिसंबर 2020।

आयोजित/आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं

कोविड–19 महामारी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित नहीं की जा सकीं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भागीदारी

21–25 सितंबर, 2020 तक नीपा द्वारा आयोजित 'शिक्षा में नीति–निर्माण संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम' में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में भागीदारी।

नीपा के एम.फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों के सहकर्मी और संकाय समीक्षा सेमिनार में भागीदारी।

प्रशिक्षण सामग्री/पाठ्यक्रम विकसित और संचालित

एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम, 2020/21 में अनिवार्य पाठ्यक्रम संख्या सीसी–1 (शिक्षा में आर्थिक परिप्रेक्ष्य) का सहयोगी संकाय के रूप में संचालन।

एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम, 2020–21 में अनिवार्य पाठ्यक्रम संख्या सीसी–6 (शिक्षा में उन्नत योजना तकनीक) का पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में संचालन।

सितंबर 2020 में 'पीजीडेपा पाठ्यक्रम सं. 903: शैक्षिक योजना: अवधारणा, प्रकार और दृष्टिकोण' का सह–संकाय के रूप में संचालन।

मूडल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जुलाई 2020 में पीजीडेपा (चरण–II) 'ऑनलाइन उन्नत पाठ्यक्रम संख्या 907: शैक्षिक योजना' का पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में आयोजन।

मार्च/अप्रैल 2020 में 'आइडेपा पाठ्यक्रम सं. 205: शैक्षिक योजना की कार्यप्रणाली और तकनीक' का सह–संकाय के रूप में संचालन।

एम.फिल./पीएच.डी., डेपा और आईडेपा शोध प्रबंधों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

सुरेंद्र सिंह नेगी (पीईएस), उप शिक्षा अधिकारी, कीर्तिनगर ब्लॉक, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड द्वारा ''टिहरी जिला, उत्तराखंड के ब्लॉक कीर्तिनगर में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन'' शीर्षक से पीजीडेपा शोध प्रबंध कार्य का मूल्यांकन।

मोहम्मद हामिद गनी, अफगानिस्तान द्वारा ''अफगानिस्तान में सामान्य शिक्षा विकास'' शीर्षक से डेपा शोध प्रबंध का मूल्यांकन।

निधि रावत द्वारा ''भारत में प्राथमिक शिक्षा में जीआईएस आधारित स्कूल मैपिंग का अध्ययन'' शीर्षक से पीएच.डी. थीसिस कार्य का पर्यवेक्षण ।

दीपेंद्र कुमार पाठक द्वारा ''पश्चिम बंगाल में स्कूल आधारित प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारीः बर्दवान और पुरुलिया जिलों में चुनिंदा माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन'' शीर्षक से पीएच.डी. थीसिस कार्य का पर्यवेक्षण।

सुहैल अहमद मीर द्वारा ''भारत में शिक्षा और श्रम बाजार के परिणामों में अवसर की असमानता का अध्ययन'' शीर्षक (अंशकालिक) पीएचडी थीसिस का पर्यवेक्षण।

आयशा मलिक द्वारा ''राजस्थान में स्कूल विलय नीति के परिणामों का एक जीआईएस आधारित विश्लेषण'' शीर्षक से पीएचडी थीसिस कार्य का पर्यवेक्षण किया।

काव्या चंद्रा द्वारा ''शिक्षा सुधार, कार्यान्वयन और एकाधिक जवाबदेही संबंधः दक्षिण दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार कार्यान्वयन का अध्ययन'' शीर्षक पीएचडी थीसिस कार्य का पर्यवेक्षण।

गौहर राशिद गनी द्वारा ''व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्र की पसंद के निर्धारक'' शीर्षक पीएचडी थीसिस कार्य का पर्यवेक्षण किया।

शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदान की गई महत्वपूर्ण परामर्श और सलाहकार सेवाएं

सदस्य, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग के विभागीय सलाहकार बोर्ड, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

सदस्य, पीएमडी के विभागीय सलाहकार बोर्ड, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

सदस्य, वार्षिक कार्यक्रम सलाहकार समिति, एससीईआरटी, दिल्ली।

सदस्य, डाइट की वार्षिक कार्यक्रम सलाहकार समिति, कड़कड़डूमा, दिल्ली।

सदस्य, फरवरी 2021 में एनएएस में डेटाबेस मैनेजर की नियुक्ति के लिए चयन समिति, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

सदस्य, फरवरी 2021 में एनएएस में वरिष्ठ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए चयन समिति, शैक्षिक सर्वेक्षण प्रभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

यूनिसेफ–एमओई रोलिंग प्लान 2021–22 की समीक्षा की और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमओई, भारत सरकार को टिप्पणियां प्रस्तुत की।

यूनिसेफ–एमओई रोलिंग प्लान पर चर्चा करने के लिए 16 फरवरी, 2021 को आयोजित एसई एंड एल विभाग, एमओई, भारत सरकार की ऑनलाइन बैठक में भागीदारी।

12 मार्च 2021 को शिक्षा विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'बिहार में मदरसों के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम पर यूएनएफपीए प्रायोजित परियोजना के तहत संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए संस्थागत योजना के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन विशेषज्ञों की बैठक' में विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

शैक्षिक आयोजना विभाग की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021–22 तैयार कर 15 फरवरी, 2021 को विभागीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन।

4 जनवरी, 2017 से यू–डाईस परियोजना में प्रभारी के रूप में, नीपा में यू–डाईस परियोजना का प्रबंधन किया।

सदस्य, स्थायी सलाहकार समिति, एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम, नीपा।

सदस्य, पर्यवेक्षक आवंटन समिति (सीएएस), एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम, नीपा।

सदस्य, अध्ययन बोर्ड, नीपा।

सदस्य, अकादमिक परिषद, नीपा।

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, शैक्षिक वित्त विभाग, नीपा।

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, शैक्षिक नीति विभाग, नीपा।

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग, नीपा।

सदस्य, नीपा फैलोशिप के संवितरण के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए समिति।

अध्यक्ष, नीपा अनुसंधान और नवाचार नीति पर उप–समिति।

सदस्य, नीपा पुस्तक चयन समिति।

सदस्य, नीपा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी)।

अध्यक्ष, नीपा तकनीकी समिति।

सदस्य, नीपा प्रकाशनों के लिए दिशानिर्देश विकसित करने के लिए समिति।

सदस्य, नीपा एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा की रूपरेखा के लिए समिति।

एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम 2015–16 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में सहायता प्रदान की।

सदस्य, नीपा 2021–22 के एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए साक्षात्कार बोर्ड।

सदस्य, कोर ग्रुप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नीपा के संलग्नता।

सदस्य, सीएएस के तहत प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के हेतु नीपा आंतरिक समीक्षा समिति।

सदस्य, योजना और निगरानी समिति, नीपा।

अनुसंधान अध्ययन

''तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास'' पर चल रही कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के चरण I के अध्ययन को पूरा किया गया था और 2014 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। कार्रवाई अनुसंधान के दूसरे चरण में, तमिलनाडु और ओडिशा में चार नमूना जिलों की कार्रवाई अनुसंधान दल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (डीएसईपी) को विकसित किया गया। ये मॉडल योजनाएं और अनुसंधान के प्रमुख खोजों को नीपा, नई दिल्ली में 4–6 जून, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की साझा कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कार्रवाई अनुसंधान दलों को मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (डीएसईपी) को अंतिम रूप देने में काफी समय लगा और इसे फरवरी 2020 को नीपा में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के (चरण I और II) को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे फरवरी 2021 तक नीपा को प्रस्तुत की जायेगी।

एन. के. मोहंती

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, वेबिनार और सम्मेलनों में भागीदारी

7 अगस्त, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार'' पर कॉन्क्लेव में भागीदारी।

8 अगस्त, 2020 को शाला सिद्धि एकक, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''भारत में स्कूल कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं: शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि'' पर वेबिनार में भागीदारी।

19 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाएं, चुनौतियां और रास्ते'' पर वेबिनार में भागीदारी।

14 जुलाई, 2020 को सीपीआरएचई/नीपा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण'' पर वेबिनार में भागीदारी।

14 जुलाई, 2020 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) और केएपीएसएआरसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''विकासशील देशों में ऊर्जा परिवर्तन प्रबंधन'' पर वर्चुअल वर्कशॉप में भागीदारी।

24 जुलाई 2020 को उच्च शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा'' पर वेबिनार में भाग लिया।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

कोविड महामारी की स्थिति के कारण आयोजित नहीं किये जा सके।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और संचालित

एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम, 2020–21 के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम सं. सीसी–6 (शिक्षा में उन्नत योजना तकनीक) (प्रो. के. बिस्वाल के साथ) का संचालन।

सितंबर–नवंबर 2020 के दौरान 'पीजीडेपा पाठ्यक्रम 903: शैक्षिक योजना: अवधारणा, प्रकार और दृष्टिकोण' के पाठ्यक्रम समन्वयक।

मूडल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर जुलाई 2020 में ''पीजीडीईपीए (चरण II) ऑनलाइन उन्नत पाठ्यक्रम संख्या 907: शैक्षिक योजना'' के पाठ्यक्रम समन्वयक।

संशोधित क्षेत्र निदान पर संशोधित अनुकरण अभ्यास: पहुंच और भागीदारी के संकेतक, अगस्त 2020।

संशोधित (डॉ. सुमन नेगी के साथ) क्षेत्र निदान पर संशोधित अनुकरण अभ्यास: आंतरिक दक्षता के संकेतक, अगस्त 2020।

शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदान की गई महत्वपूर्ण परामर्श और सलाहकार सेवाएं

सदस्य, एनसीआर योजना बोर्ड के अध्ययन समूह VIII (सामाजिक आधारभूत संरचना), प्रो अविनाश के. सिंह, नीपा के साथ शिक्षा पर अध्ययन समूह की अंतिम रिपोर्ट तैयार की और एनसीआर के लिए क्षेत्रीय योजना 2041 में शामिल करने के लिए एनसीआर योजना बोर्ड को प्रस्तुत किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

शैक्षिक आयोजना विभाग की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021–22 तैयार कर 18 फरवरी, 2021 को विभागीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन।

एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह के सदस्य, नीपा वर्किंग पेपर सं. 2 की तैयारी में योगदान, ''एनईपी 2020 लक्ष्य प्राप्त करना: स्कूल शिक्षा की आंतरिक दक्षता, परिवर्तन दर और भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन का प्रक्षेपण"।

एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह के सदस्य, नीपा वर्किंग पेपर सं. 9, ''स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यावसायिकता और कौशल विकास'' की तैयारी में योगदान।

एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह के सदस्य, नीपा वर्किंग पेपर सं. 13, ''नेशनल रिसर्च फाउंडेशन'' की तैयारी में योगदान।

सूरज कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लिंगीपायोंग सिक्किम के पीजीडेपा 2020 शोध प्रबंध ''माध्यमिक स्तर पर छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर माता–पिता की भागीदारी का प्रभाव: सरकारी माध्यमिक विद्यालय, लिंगीपायोंग, दक्षिण सिक्किम का अध्ययन'' शीर्षक का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

एलियास जे. केटेम्बो, तंजानिया के आईडेपा 2020 शोध प्रबंध ''निम्न माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट को प्रभावित करने वाले कारक:: तंजानिया में मबेया क्षेत्र में कायला जिले का अध्ययन'' शीर्षक का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

सदस्य, एम.फिल./पीएच.डी. प्रवेश समिति के रूप में, एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम 2020–22 में प्रवेश के लिए आवेदनों और अन्य संबंधित गतिविधियों को संसोधित करने में सहायता प्रदान की।

एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम 2020–22 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में सहायता की।

अनुसंधान अध्ययन

तमिलनाडु और ओडिशा में आरएमएसए के तहत जिला माध्यमिक शिक्षा योजना के विकास पर जारी कार्रवाई अनुसंधान परियोजना पर अध्ययन के चरण I को पूरा किया गया था और 2014 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। कार्रवाई अनुसंधान के चरण II में, तमिलनाडु और ओडिशा में चार नमूना जिलों की कार्रवाई अनुसंधान

दल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (डीएसईपी) को विकसित किया गया। ये मॉडल योजनाएं और अनुसंधान के प्रमुख खोजों को नीपा, नई दिल्ली में 4–6 जून, 2018 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की साझा कार्यशाला में प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्रवाई अनुसंधान दलों को मॉडल जिला माध्यमिक शिक्षा योजनाओं (डीएसईपी) को अंतिम रूप देने में काफी समय लगा और इसे फरवरी 2020 को नीपा में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई अनुसंधान परियोजना के (चरण I और II) को अंतिम रूप दिया जाा रहा है और इसे दिसंबर 2021 तक नीपा को प्रस्तुत की जायेगी।

''भारत में माध्यमिक शिक्षा में सार्वजनिक–निजी मिश्रणः आकार, स्कूल में सुविधाएं और प्रवेश प्रोफाइल'' पर एक शोध परियोजना शुरू की। अध्ययन का चरण I पूरा हो चुका है और रिपोर्ट 20 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत की गई है। अध्ययन का चरण II प्राथमिक डेटा और नमूना राज्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी पर आधारित है। कोविड महामारी की स्थिति के कारण, अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा और जानकारी एकत्र करने के लिए क्षेत्र/राज्यों का दौरा करना संभव नहीं हो पाया है।

सुमन नेगी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

7–9 अक्टूबर, 2020 को वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा द्वारा ''प्रवास और विकासः मुद्दे और परिप्रेक्ष्य'' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

17–23 दिसंबर, 2020 तक यूजीसी–एचआरडीसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ''अनुसंधान पद्धति'' पर एक सप्ताह की ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन।

कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

6–17 जुलाई, 2020 तक ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ''शैक्षिक अनुसंधान में सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोग'' पर दो सप्ताह की एम.फिल. कार्यशाला का समन्वय।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और संचालित

पाठ्यक्रम लेन–देन

एम.फिल. अनिवार्य पाठ्यक्रम (सीसी6): शैक्षिक योजना

शैक्षिक अनुसंधान में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के उपयोग पर एम.फिल. कार्यशाला

शैक्षिक योजना पर पीजीडेपा पाठ्यक्रम सं. 903:

शैक्षिक योजना पर पीजीडेपा उन्नत पाठ्यक्रम – ऑनलाइन

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

4 जनवरी, 2021 को एचआरडीसी, जामिया मिलिया इस्लामिया में आयोजित तीसरा एक महीने का संकाय प्रेरण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

21–25 सितंबर, 2020 को ''नीति निर्माण में साक्ष्य के उपयोगः आंकड़ों के उपयोग; भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सर्वोत्तम अभ्यास, शैक्षिक नीति निर्माण संरचना और प्रक्रिया पर अभिविन्यास कार्यक्रम'', में सत्र के चर्चाकार।

3–4 दिसंबर, 2020 को प्रशिक्षण और क्षमता विकास विभाग, नीपा, द्वारा आयोजित विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चों (एसएलडी) की शिक्षा पर समावेशी शिक्षा समन्वयकों की ऑनलाइन बैठक में संसाधन व्यक्ति।

शैक्षिक आयोजना विभाग की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021–22 तैयार कर 18 फरवरी 2021 को विभागीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया।

एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह के सदस्य, नीपा वर्किंग पेपर सं. 2 की तैयारी में योगदान, ''एनईपी 2020 लक्ष्य प्राप्त करना: स्कूल शिक्षा की आंतरिक दक्षता, परिवर्तन दर और भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा में नामांकन का प्रक्षेपण''।

एनईपी 2020 की कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह के सदस्य, नीपा वर्किंग पेपर सं. 13, ''नेशनल रिसर्च फाउंडेशन'' की तैयारी में योगदान।

जुलाई 2020 में ''भारत में स्कूली शिक्षा में असमानता: पहुंच और भागीदारी में क्षेत्रीय असमानताओं पर अध्ययन'' शीर्षक एम.फिल. शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

अगस्त 2020 में ''भूटान में प्राइमरी स्कूल असेसमेंट सिस्टम की जांच के लिए अध्ययन: नोरबुगांग प्राइमरी स्कूल, समत्से जिले का अध्ययन'' शीर्षक आईडेपा परियोजना कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

मार्च 2020 में ''राजस्थान में लड़कियों के लिए स्कूल में विभिन्न मंचों की भूमिका'' शीर्षक पीजीडेपा परियोजना कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

नीपा एम.फिल.–पीएच.डी. डिग्री विनियम 2020 तैयार किया।

एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए नीपा प्रवेश और संचालन समिति के सदस्य के रूप में, नीपा विवरणिका 2020 तैयार करने की जिम्मेदारी।

जांच समिति के भाग के रूप में आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच में योगदान।

जुलाई 2020–अप्रैल 2021 से दो सेमेस्टर के लिए एम.फिल.–पीएच.डी. कार्यक्रम अनुसूची तैयार किया।

सदस्य, एम.फिल./पीएच.डी. कार्यक्रम संचालन समिति।

सदस्य, स्थायी क्रय समिति।

सदस्य, नीपा परीक्षा समिति

16. सदस्य, नीपा प्रवेश समिति

17. सदस्य, समान अवसर प्रकोष्ठ

18. सदस्य, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नॉक) कोर टीम

शैक्षिक प्रशासन विभाग

कुमार सुरेश

प्रकाशन/आधार पत्र में योगदान

एनईपी 2020 में शिक्षा के संघीय ढांचे में शासन सुधार संरचना: कार्यान्वयन रणनीतियाँ के मुख्य समूह के सदस्य के साथ–साथ समूह के समन्वयक के रूप में आधार पत्र के विकास में योगदान दिया, नीपा, नई दिल्ली (नीपा द्वारा एक समेकित दस्तावेज के रूप में प्रकाशित)

शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय को प्रदान किए गए जानकारी के एक हिस्से के रूप में केब (सीएबीई) के सुदृढ़ीकरण पर आलेख तैयार किया।

समूह के सदस्य के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल और उच्चतर शिक्षा में समानता, विविधता और समावेशन: कार्यान्वयन रणनीतियाँ पर आधार पत्र के विकास में योगदान दिया, नीपा नई दिल्ली (नीपा द्वारा एक समेकित दस्तावेज़ के रूप में प्रकाशित)

वर्ष के दौरान संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

(अ) वेबिनार/कार्यशालाओं में संसाधन व्यक्ति के रूप में भागीदारी

26 जून 2020 को ''सार्वजनिक शिक्षा की पुर्नकल्पना पर राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति'' पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार द्वारा नेहू, शिलांग और केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु के सहयोग से द्वारा आयोजित वेबिनार में नई शिक्षा नीति और सार्वजनिक शिक्षा पर मुख्य वक्ता।

16 अगस्त 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में विशेष अतिथि आमंत्रित सह–वक्ता।

22–23 अगस्त, 2020 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कन्स्टीटयूएंट कॉलेजेज टीचर एसोसिएशन (AUCCTA) द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत में शिक्षा हेतु भविष्य का रोडमैप'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य वक्ता।

24 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा में सुधार की दिशा में भारत की पहल एषिया–अफ्रीका नेटवर्क संवाद के सदस्यों के लिए संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की।

06 सितंबर 2020 को ग्रामीण उच्च अध्ययन संस्थान, भोगराई, ओडिशा, द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा में आभासी अधिगम चुनौतियां और संभावनाएं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य वक्ता

13 सितंबर 2020 को डाईट, हापुड़ उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाओं और चुनौतियों पर आयोजित चर्चा वेबिनार में मुख्य वक्ता

14–16 सितंबर, 2020, को स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में 15 सितंबर को 'नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा' पर संसाधन व्यक्ति/मुख्य वक्ता

संसाधन व्यक्ति/मुख्य वक्ता, 11 नवंबर 2020 को शिक्षा विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आभासी मंच के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020: 'उच्च शिक्षा के लिए रोडमैपः संभावनाएं और बाधाएं' पर राष्ट्रीय वेबिनार में व्याख्यान दिया।

संसाधन व्यक्ति/मुख्य वक्ता, 26 नवंबर, 2020 को भारतीय संविधान में बहुलवाद, समानता और नागरिकता के विचार की पुष्टि पर विशेष आमंत्रित व्याख्यान दिया।

18 दिसंबर 2020 को नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नौसेना शिक्षा निदेशक द्वारा नौसेना शिक्षा समिति के वार्षिक सम्मेलन में नई शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए इसके निहितार्थ पर व्याख्यान देने के लिए रिसोर्स पर्सन/मुख्य अध्यक्षीय व्याख्यान के लिए आमंत्रित।

16 फरवरी, 2021 को आभासी माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय श्यामलाल कॉलेज के यूबीए के सहयोग से आईक्यूएसी द्वारा, नई शिक्षा नीति 2020–भारत को सशक्त बनाने के लिए एक नया प्रतिमान' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उच्च शिक्षा में शासन सुधारः नीति प्रस्ताव, चुनौतियां और संभावनाएं पर अध्यक्षीय अभिभाषण के लिए पूर्ण अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित।

25–26 मार्च 2021 को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, द्वारा ''नई शिक्षा नीति 2020 और भारत में उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरणः अवसर और चुनौतियां'' पर विश्व बैंक–ओएचईपीई प्रयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 25 मार्च 2021 को ''उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्टीयकरण के लिए संस्थागत शासन सुधार और तैयारी'' पर विषेशज्ञ वक्ता के रूप में प्रस्तुति

22 से 26 मार्च, 2021 तक मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशासनिक कौशल के मूल तत्व पर 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में अकादमिक नेतृत्व और प्रशासनिक कौशलः क्यों, क्या और कैसे? पर व्याख्यान दिया। (24 मार्च 2021 को एमएनआईटी)

18–19 मार्च, 2021 को उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र, नीपा, नई दिल्ली में आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन पर 19 मार्च, 2021 को राज्य उच्च षिक्षा परिषदों की सलाहकारी बैठक में एक सत्र की अध्यक्षता की।

(ब) मानव संसाधन विकास केंद्र और अन्य कार्यक्रमों में अध्यक्ष/व्याख्यान

16 नवंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित द्वितीय ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम में 21 नवंबर 2020 को भारत में उच्च शिक्षा के अभिशासन पर व्याख्यान दिया।

2 दिसंबर, 2020 को मानव संसाधन विकास केंद्र, जेएनयू द्वारा विविधता बहुसंस्कृतिवाद और नागरिक शिक्षा पर शिक्षक शिक्षा का चौथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में व्याख्यान दिया

2 जनवरी 2021 को मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीसरे ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम में भारत के लिए उच्च शिक्षा के अभिशासन–वैश्विक रुझान और प्रभाव पर व्याख्यान दिया।

13 जनवरी 2021 को यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश और स्कूल ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा में गुणवत्ता के लिए शैक्षिक सुधार पर व्याख्यान दिया गया।

03 फरवरी 2021 को एचआरडीसी, पीआरएसयू, रायपुर में प्रारंभिक शिक्षण पद्धतियों में उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना पर व्याख्यान

03 फरवरी 2021 को एचआरडीसी, पीआरएसयू, रायपुर में प्रारंभिक अनुदेशनात्मक व्यवहारों में संस्थागत योजना और विकास पर व्याख्यान

11 फरवरी 2021 को एफ.आई.पी. मा.सं.वि. केंद्र, एलएनआईपीई, ग्वालियर में संस्थागत नियोजन और विकासात्मक निर्देशात्मक अभ्यासों पर व्याख्यान दिया,

13 फरवरी 2021 को मानव संसाधन विकास केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित चौथे ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम में उच्च शिक्षा का अभिशासन–भारत के लिए वैश्विक रुझान और प्रभाव पर व्याख्यान दिया गया।

12 मार्च से 18 मार्च 2020 तक यूजीसी–एचआरडीसी, मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में 15 मार्च 2021 को उच्च शिक्षा के संस्थागत संदर्भ में अभिशासन और नेतृत्व पर व्याख्यान दिया।

16 मार्च, 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ लाईफलॉंग लर्निंग (आईएलएलएल), दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा में समावेश पर अल्पावधि पाठ्यक्रम में एक्सेस एंड इक्विटीः अंडरस्टेंडिंग डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन विषय पर आमंत्रित व्याख्यान दिया।

17 मार्च 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित अनुसंधान पद्धति पाठ्यक्रम में संसाधन व्यक्ति/अध्यक्ष।

कार्यशाला/सम्मेलन /प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

17–19 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व पर कार्यशाला सह–उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।

15 जनवरी, 2021 को गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित 2018–2019 के दौरान नवाचारों और अच्छे कार्याभ्यासों के लिए पुरस्कारों पर विचार के लिए अधिकारियों (डीईओ और बीईओ) के साथ अभिविन्यास बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को नामित किया।

29 जून–03 जुलाई, 2020 तक शोधार्थियों के लिए लेखन कौशल पर ऑनलाइन कार्यशाला

22–27 फरवरी, 2021 तक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भोपाल के एम.एड. छात्रों के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और संचालित

पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर मुख्य पाठ्यक्रम सीसी–07 ने पाठ्यक्रम के संचालन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की और पाठ्यक्रम दल के सदस्यों के साथ सत्र का संचालन किया।

इक्विटी और बहुसांस्कृतिक शिक्षा पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–07 के पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में पाठ्यक्रम के संचालन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की और 10 सत्रों का संचालन किया

सीसी–01 के पाठ्यक्रम दल के सदस्य के रूप में शिक्षा पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर 11 सत्रों का संचालन किया

ऑनलाइन माध्यम में शैक्षिक प्रशासन पर पीजीडेपा पाठ्यक्रम का संचालन

पीजीडेपा पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रशासन पर उन्नत पाठ्यक्रम (एडवांस कोर्स) का 50 प्रतिशत निष्पादन किया

आईडेपा पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रशासन पर पाठ्यक्रम का निष्पादन किया

नीपा में शैक्षिक प्रशासन विभाग और अन्य विभागों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/क्षमता विकास कार्यक्रमों में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में सेवा की और कई व्याख्यान दिए।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

रिसर्च एंड रिफ्लैक्शंस ऑन एजुकेशन जर्नल के संपादकीय बोर्ड के सदस्य,, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पालमकोट्टई

जामिया जर्नल ऑफ एजुकेशन के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य

दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि के एम.फिल./पी–एच.डी. शोध प्रबंध/विषयों के मूल्यांकन विशेषज्ञ

शैक्षिक अध्ययन विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के अध्ययन बोर्ड के सदस्य

समाजशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के अध्ययन बोर्ड के सदस्य,

अन्य अकादमिक और व्यावसायिक योगदान

23 सितंबर 2020 तक कुलसचिव (प्रभारी) रहे। इस क्षमता में पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिशासन में आसानी के सिद्धांत के अनुरूप सुदृढ़ीकरण के लिए की गई पहलों के साथ जारी रहा। इनमें से कुछ पहल निम्न हैं

संस्थान में नियमों/दिशानिर्देशों का निर्माण/संशोधन (सेवा विनियमों में संशोधन, भर्ती नियम, आवास आवंटन नियम, शक्तियों का प्रत्यायोजन, यूजीसी के अनुसार

मानित विश्वविद्यालय के लिए संशोधित विनियमों के साथ–साथ संस्थागत नीति दिशानिर्देशों में संशोधन)

इस अवधि के दौरान प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अध्ययन बोर्ड की दो–दो बैठकें आयोजित की गईं। मेरी जानकारी और समग्र पर्यवेक्षण के तहत सभी कार्यसूची पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए थे

शैक्षिक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष के रूप में विभाग की विभिन्न गतिविधियों का नेतृत्व किया जिसमें विभागीय सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन और विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियां तैयार करना शामिल है। साथ ही नवाचार योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की अभिविन्यास बैठक भी आयोजित की।

मा.सं.वि.मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर करने के लिए समझौता ज्ञापन के दस्तावेज तैयार करने हेतु समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

समिति के अध्यक्ष के रूप में नॉक (एनएएसी) प्रक्रिया द्वारा संस्था के मूल्यांकन के लिए एसएसआर तैयार करने हेतु शुरू की गई बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से संकाय, कर्मचारियों और छात्रों को उन्मुख किया गया।

शैक्षिक प्रशासन में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के कार्यक्रम निदेशक के रूप में जिला एवं प्रखंड स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कई दायित्वों का निर्वहन किया।

परियोजना निदेशक के रूप में शैक्षिक प्रशासन के तीसरे अखिल भारतीय सर्वेक्षण की प्रमुख परियोजना का नेतृत्व। इसमें अकादमिक जानकारी, मार्गदर्शन और निगरानी से संबंधित कई गतिविधियां शामिल थीं

संपादक के रूप में योगदान

संपादकः नीपा समसामयिक पत्र श्रृंखला (समीक्षाधीन की अवधि के दौरान 2 अंक प्रकाशित) अन्य तीन प्रकाशनाधीन

संपादकः नीपा नीति संक्षिप्त

एम.फिल./पी–एच.डी. पर्यवेक्षण

पांच डॉक्टरेट विद्वानों (अनुराधा बोस, मोनिका मैनी, प्रतीक्षा त्रिपाठी, निदा खान, और सुमन साहा) का अनुसंधान पर्यवेक्षण

सुश्री आरुषि कौशिक द्वारा प्रस्तुत एम.फिल. शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण और सम्मानित किया है।

पीजीडेपा/आईडेपा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा और आईडेपा उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पर परियोजना पर्यवेक्षण

नीपा के विभिन्न शैक्षणिक निकायों के सदस्य के रूप में योगदान

अकादमिक परिषद और अध्ययन बोर्ड के सदस्य

पर्यवेक्षकों के आवंटन समिति के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए समिति के सदस्य

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन एकक के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. स्थायी सलाहकार समिति के सदस्य

सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) के सदस्य।

एम.फिल. प्रवेश साक्षात्कार समिति और संयम समिति के सदस्य

संगोष्ठी अनुदान प्रस्ताव की समीक्षा के सदस्य

कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित नीपा के विभागों की सलाहकार समिति और विभिन्न कार्यबलों के सदस्य

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के अकादमिक परिषद के सदस्य

यूजीसी–सीईसी, नई दिल्ली की अकादमिक परिषद के सदस्य

पीएमएमएमएनएमटीटी, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र के तहत मा.सं.वि. मंत्रालय के अरपित–स्वयम पाठ्यक्रम की अकादमिक परिषद के सदस्य।

आजीवन सदस्य, भारतीय समाजशास्त्रीय सोसायटी

आजीवन सदस्य, आईआईपीए, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ के सदस्य

अफ्रीका एशिया अनुसंधान समूह के सदस्य

नीपा में समितियों की सदस्यता

योजना और निगरानी बोर्ड के सदस्य

अकादमिक परिषद और अध्ययन बोर्ड के सदस्य

पर्यवेक्षकों के आवंटन समिति के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. कार्य के प्रगति की समीक्षा समिति के सदस्य

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन एकक के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. स्थायी सलाहकार समिति के सदस्य

सहायता अनुदान समिति (जीआईएसी) के सदस्य,

एम.फि प्रवेश साक्षात्कार समिति और संयम समिति के सदस्य

संगोष्ठी अनुदान के प्रस्ताव समीक्षा समिति के सदस्य

अनुसंधान समीक्षा समिति के सदस्य

परिप्रेक्ष्य की संपादकीय टीम के सदस्य

प्रकाशन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए समिति के अध्यक्ष

कार्यक्रमों के संचालन से संबंधित नीपा के विभागों की सलाहकार समिति और विभिन्न कार्यबलों के सदस्य

सीएएस योजना के तहत संकाय की पदोन्नति के लिए आवेदनों की जांच समिति के सदस्य

विनीता सिरोही

प्रकाशन

''स्किल डवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया : पालिसीज एंड प्रैक्टिसेज'' वॉल्यूम 25, नंबर 1, जनवरी–जून 2019, न्यूज़लेटर एंट्रीप (जून 2020 में प्रकाशित)।

''कौशल निर्माण के अनौपचारिक तरीके'' पर आईएचईआर रिपोर्ट 2020 में अध्याय (रूटलेज द्वारा मुद्रित)।

यूनेस्को रिपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन फस्ट के संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में योगदान दिया। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (टीवीईटी), दिसंबर, 2020 में प्रकाशित।

समन्वयक के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 पर ''स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण और कौशल विकास'' विषय पर आधार पत्र के विकास में योगदान दिया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

26 मई, 2020 को तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा ''संस्थागत नेतृत्व में समकालीन मुद्दों'' पर राष्ट्रीय वेबिनार में अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित (ऑनलाइन)

08 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में यूनेस्को, दिल्ली द्वारा आयोजित ''बेहतर योजना और निगरानी के लिए साक्ष्य–आधारित अनुसंधान का विस्तार'' पर यूनेस्को टीवीईटी रिपोर्ट के समारोह के शुभारंभ पर पैनल अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित (ऑनलाइन)

5 अक्टूबर 2021 को भोपाल में पीएसएससीआईवीई (एनसीईआरटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) – नई शिक्षा नीति 2020 के लिए ''पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा'' पर आधार पत्र के विकास के लिए एनसीईआरटी द्वारा गठित कार्य समूह के सदस्य के रूप में योगदान। (ऑनलाइन)

2 फरवरी 2021 को अहमदाबाद, गुजरात में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च द्वारा आयोजित आईसीएसएसआर गुणात्मक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान द्वारा समर्थित अनुसंधान क्रियाविधि पाठ्यक्रम में ''अनुसंधान रचना'' पर अंतःविषय परिप्रेक्ष्य से तरीके और दृष्टिकोण पर दो सत्रों में रिसोर्स पर्सन (ऑनलाइन)

2–3 मार्च 2021 को नई दिल्ली में एनसीईआरटी द्वारा स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा में अभिनव प्रथाओं और प्रयोग हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित (ऑनलाइन)

कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

एम.फिल.–पी.एच.डी प्रोग्राम 2020–2021 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के नए बैच के लिए ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

एम.फिल./पी–एच.डी. मूल पाठ्यक्रम सीसी–1 – शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संचालन और मूल्यांकन

एम.फिल./पी–एच.डी. मूल पाठ्यक्रम सीसी–7 का संचालन और मूल्यांकन

वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी 2 – शिक्षा और कौशल विकास का समन्वयन, संचालन और मूल्यांकन

आईडेपा पाठ्यक्रम – 202 का समन्वयन, लेनदेन और मूल्यांकन

शैक्षिक प्रबंधन पर पीजीडेपा पाठ्यक्रम – 904 का समन्वयन, संचालन और मूल्यांकन

उन्नत पाठ्यक्रम – 908 का संचालन और मूल्यांकन

एम.फिल. और पी–एच.डी. विद्वानों को अनुसंधान मार्गदर्शन

पीजीडेपा और आईडेपा प्रतिभागियों के लिए अनुसंधान मार्गदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

एससीईआरटी/डाईट के पुनर्गठन के बाद सृजित शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और तैनाती पर एससीईआरटी दिल्ली को अकादमिक सहायता

अनुसंधान अध्ययन (एमएचआरडी प्रायोजित ''गैर–शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी और शिक्षा पर इसका प्रभावः मतदान और इससे संबंधी कर्तव्यों पर शिक्षकों द्वारा खर्च किए गए समय का एक अखिल भारतीय अध्ययन'' – एमएचआरडी को प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट।

प्रशिक्षण सलाहकार समिति की बैठक में सीबीएसई सदस्य के रूप में योगदान

यूनेस्को टीवीईटी रिपोर्ट 2020 में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में योगदान

''अपरेंटिसशिप/इंटर्नशिप'' एम्बेडेड डिग्री कार्यक्रम'' पर यूजीसी के दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रिया प्रदान की

''स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण और कौशल विकास'' पर आधार पत्र में समन्वय और योगदान द्वारा एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय को अकादमिक समर्थन।

जामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित बिहार में मदरसों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने हेतु विशेषज्ञ समिति की बैठक में भागीदारी

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में दिल्ली के दो डाईट की बैठकों में भागीदारी

एससीईआरटी, केरल के शासी निकाय की बैठक में भागीदारी

दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट थीसिस का मूल्यांकन।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

नीपा में विभाग और विभाग के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान दिए।

जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेपा) में प्रकाशनार्थ प्रस्तुत शोध पत्रों की समीक्षा में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में अकादमिक समर्थन

संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम की योजना, समन्वय, प्रशासन और प्रबंधन और विभिन्न गतिविधियों को पूरा किया जिसमें पी–एच.डी. थीसिस पर प्रस्तुत दिशानिर्देशों का संशोधन, एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम 2021–2022 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र और विवरणिका का संशोधन; गतिविधियों का समन्वित और नियोजित कैलेंडर और कार्यक्रम की अनुसूची; एम.फिल./पी–एच.डी. स्कॉलर्स के संकाय और सहकर्मी समीक्षा सेमिनार की अध्यक्षता; पी–एच.डी. विद्वानों के प्री–सबमिशन सेमिनार का समन्वय और अध्यक्षता; सैक बैठकों में समन्वय और भागीदारी; सदस्य सचिव के रूप में सीएएस की बैठकों में समन्वय और भागीदारी, छात्रों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता से वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता छात्रवृत्ति में उन्नयन के लिए बैठक में भागीदारी।

नीपा, अध्ययन बोर्ड की बैठक में भागीदारी

अकादमिक परिषद, नीपा की बैठक में भागीदारी

शैक्षणिक पदों के लिए आवेदनों की जाँच

अनुसंधान समीक्षा समिति की बैठकों में भागीदारी और योगदान

जेपा संपादकीय बोर्ड की बैठकों में भागीदारी

डीएसी 2021 की बैठक में भागीदारी

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

शासी परिषद के सदस्य, एससीईआरटी, दिल्ली

कार्यकारी समिति के सदस्य, एससीईआरटी, दिल्ली

भर्ती नियम समिति के सदस्य, एससीईआरटी, दिल्ली

इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पीएसएससीआईवीई) की संपादकीय टीम के सदस्य।

नैदानिक मनोवैज्ञानिक संघ के आजीवन सदस्य।

भारतीय अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान संघ के आजीवन सदस्य।

प्रशिक्षण सलाहकार समिति सीबीएसई के सदस्य।

भारत 2020: तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट के संपादकीय बोर्ड के सदस्य, यूनेस्को, नई दिल्ली

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) – एनईपी 2020 के लिए ''पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा'' पर आधार पत्र के विकास के लिए एनसीईआरटी द्वारा गठित एनसीएफ कार्यकारी समूह के सदस्य

संस्थान सलाहकार बोर्ड, पीएसएससीआईवीई (एनसीईआरटी) के सदस्य

एससीईआरटी, दिल्ली में जाँच मानदंड, प्रक्रिया/प्रगति/भर्ती की योजना विकसित करने हेतु समिति के सदस्य

नीपा में समितियों की सदस्यता

अध्यक्ष, संचालन समिति

अध्ययन बोर्ड की बैठक में विशेष आमंत्रिति

सदस्य, अकादमिक परिषद, नीपा

सदस्य, स्थायी सलाहकार समिति

सदस्य सचिव, (एम.फिल./पी–एच.डी.) पर्यवेक्षकों के आवंटन हेतु समिति

अध्यक्ष, प्रवेश समिति

सदस्य, अनुसंधान के प्रसार के लिए अनुसंधान समीक्षा समिति

अध्यक्ष, समान अवसर एकक

सदस्य, आंतरिक शिकायत समिति

सदस्य, जेपा संपादक मंडल

वी. सुचरिता

आधार पत्र में योगदान

एनईपी 2020 में शिक्षा के संघीय ढांचे में शासन के सुधार संरचनाः कार्यान्वयन रणनीतियां, पर आधार पत्र में योगदान, नीपा, नई दिल्ली

एनईपी 2020 में स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण और कौशल विकासः कार्यान्वयन रणनीतियाँ, पर आधार पत्र में योगदान, नीपा, नई दिल्ली

सम्मेलनों/पाठ्यक्रमों में भागीदारी

1–14 दिसंबर, 2020 तक मानव संसाधन केंद्र–जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षक शिक्षा पर चौथे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भागीदारी

वेबिनार/व्याख्यान में भागीदारी

7 अगस्त, 2020 को शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति–2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सम्मेलन

19 अगस्त, 2020 को एनआईईपीए, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर वेबिनार

5 सितंबर, 2020 को नई शिक्षा नीति–2020 के आलोक में उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों के क्षमता विकास पर राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, उच्चतर शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वेबिनार

5–13 अक्टूबर, 2020 तक एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, मैसूर द्वारा मानवशास्त्रीय सिद्धांतों पर ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में भागीदारी

26 फरवरी, 2021 को आईएएसई, त्रिशूर, केरल द्वारा आयोजित भारतीय शिक्षा के इतिहास पर वेबिनार में भागीदारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयेजित

8–12 फरवरी, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम में ''जिला स्तर के अधिकारियों के लिए शैक्षिक शासन में नेतृत्व'' पर उन्मुखीकरण–सह–कार्यशाला आयोजित की

22–27 फरवरी, 2021 तक आरआईई भोपाल से एम.एड. छात्रों के लिए ऑनलाइन इंटर्नशिप आयोजित की

पाठ्यक्रम संपादित

एम.फिल.:

शैक्षिक प्रशासन (सीसी 07) तथा समानता और बहुसांस्कृतिक शिक्षा (ओसी 7) पर एम.फिल. पाठ्यक्रम में शिक्षण

पीजीडेपाः

शैक्षिक प्रशासन पर पीजीडेपा पाठ्यक्रम 904 के शिक्षण के साथ–साथ संयोजक

मार्गदर्शन और पर्यवेक्षणः

पीजीडेपा प्रतिभागी, अबीनुओ के शोध प्रबंध ''कोहिमा जिला, नागालैंड के अंतर्गत ईबीआरसी विश्वेमा के विशेष संदर्भ में नागालैंड में ईसीसीई'' शीर्षक का पर्यवेक्षण

एम.फिल. प्रतिभागी, मुहम्मद यासीन के शोध प्रबंध ''माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण और पर्यवेक्षण को समझना– ठाणे जिले, महाराष्ट्र के विभिन्न स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण'' शीर्षक का पर्यवेक्षण

अन्य अकादमिक और व्यावसायिक योगदानः

नीपा, नई दिल्ली की अकादमिक परिषद के सदस्य

नीपा, नई दिल्ली के अध्ययन बोर्ड के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदनों की जांच हेतु जाँच समिति के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. उत्तर लिपियों के मूल्यांकन हेतु समिति के सदस्य

निविदा एवं मूल्यांकन समिति के सदस्य।

व्यावसायिक निकायों में सदस्यता

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआई)

आजीवन सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ और मानवविज्ञान अकादमी (आईएनसीएए)

शैक्षिक वित्त विभाग

मोना खरे

अनुसंधान अध्ययनः पूर्ण और जारी अनुसंधान परियोजनाः

अंतरराष्ट्रीय

चुनिंदा एशियाई देशों में उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण यूनेस्को, बैंकॉक और टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान परियोजना। (इंडिया केस स्टडीः मसौदा रिपोर्ट संशोधित और अंतिम रिपोर्ट मार्च 2020 में प्रस्तुत की गई।

भविष्य के उद्योगों के लिए मानव संसाधन के विकास हेतु राष्ट्रीय रणनीति पर अध्ययन, एशिया उत्पादकता संगठन, टोक्यो, जापान। मसौदा रिपोर्ट संशोधित और अंतिम रिपोर्ट मई 2020 में प्रस्तुत की गई।

भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के विश्लेषण पर चल रहे क्वालइंडिया प्रोजेक्टः आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज (क्वालइंडिया), कोलोन विश्वविद्यालय के साथ, अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक शिक्षा जर्मनी के अध्यक्ष। संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय, जर्मनी।

नवउदारवाद बनाम राजनीतिक पूंजीवाद, उच्चतर शिक्षा के वित्त पोषण में वैश्विक सार्वजनिक हित स्थानांतरण प्रतिमानों में निवेश पर हांगकांग विश्वविद्यालय और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा नीति की हस्तपुस्तिका (यूकेः एडवर्ड एल्गर प्रकाशन) के लेखक के रूप में के योगदान।

राष्ट्रीय

''कर्नाटक राज्य में बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त पर क्षमता निर्माण और अनुसंधान'' यूनिसेफ तथा वित्तीय नीति संस्थान, बेंगलुरु के साथ साझा अनुसंधान परियोजना में वरिष्ठ सलाहकार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर रिपोर्ट कर्नाटक राज्य के बाल बजट में शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय प्रभाव पर प्रथम मसौदा रिपोर्ट फरवरी 2021 में जमा की गयी।

वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय और कर्नाटक सरकार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश पर ग्रुप ए एंड बी कैडर के अधिकारियों के लिए ''लैंगिक बजट'' पर प्रशिक्षण सामग्री का विकास। ''एजुकेशन सैक्टर जैंडर बजटिंग इन इंडिया'' विषय के साथ उनके प्रकाशन के लिए 'जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एफर्ट्सः इश्यू एंड चैलेंजेज' शीर्षक वाले अध्याय के लिए योगदानकर्ता लेखक।

शैक्षिक विकास में तुलनात्मक लाभ की स्थानिक गतिशीलता– एक राज्यवार अध्ययन (नीपा); अध्ययन के आधार पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 3 लेख प्रस्तुत, जिनमें एक प्रकाशित और दो प्रकाशनाधीन हैं। भारत में विकास, रोजगार और शिक्षा का कलाप्रवीण चक्र – समान विकास का मार्ग, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत जिला स्तर पर आंकड़े एकत्रित, संकलित और अंतिम तालिका तैयार की गई है। जिला स्तर पर विश्लेषण अंतिम चरण में है और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगारशीलता पर अध्ययन (सीपीआरएचई, नीपा)। इस

प्रकार प्रकाशित अध्ययन से तैयार किए गए छह लेख और भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट का एक संपादित खंड प्रकाशित अध्ययन से तैया किया गया और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आधारित इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारत उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2020: उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता। वर्गीज एन.वी. के साथ सह–संपादित, रूटलेज (आगामी)।

भारत में स्नातक रोजगार और सतत रोजगार कौशल, वर्गीज एन.वी. और सी.एम. मलिस, सीपीएचआरई रिसर्च पेपर नंबर 14, सीपीएचआरई, नीपा, नई दिल्ली (2020)।

''भारत में उच्च शिक्षा स्नातकों का रोजगार और रोजगारशीलता – एक बहु–हितधारक परिप्रेक्ष्य'' उच्च शिक्षा स्नातकों के रोजगार और रोजगारपरकता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत, 19 फरवरी 2019, आईएचसी, नई दिल्ली।

''भारतः स्नातक और रोजगार'', अन्तर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा बोस्टन कॉलेज केन्द्र बोस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए, नंबर 95, (2018)।

''स्नातक रोजगार कौशल में अंतर समूह असमानताएँ'' वर्गीज एन.वी. और अन्य संपादक इंडिया हायर रिपोर्ट 2016, सेज पब्लिकेशन (2018)।

''भारत में कैशल मार्च को अग्रणी बनाना–कार्य की दुनिया में परिवर्तनकारी क्रांति'', (2016) मैथियाज पिल्ज़ एड इंडियाः कार्य की दुनिया के लिए तैयारी, स्प्रिंगर वी.एस.

स्नातक रोजगार योग्यताः भारत की चुनौती पोस्ट 2015 विकास कार्यसूची, इंडियन इकोनॉमिक जर्नल में, दिसंबर 2015, पीपी 97–111।

संबंधित विषय पर आईएचईआर 2020 रूटलेज में प्रकाशनाधीन है। अध्ययन के साथ–साथ अन्य आमंत्रिति लेखक के कुछ दस्तावेज को आकर्षित करते हुए, दो लेखक की बैठकें उसी के लिए आयोजित की गईं और अंतिम पांडुलिपि को दिसंबर 2020 में रूटलेज को प्रस्तुत की गयी।

पांच राज्य मसौदा रिपोर्टों की समीक्षा के पश्चात संशोधन के लिए राज्य टीमों को भेजा गया है। एक राज्य की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और संश्लेषण रिपोर्ट का अपूर्ण मसौदा पूरा होने के करीब है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रकाशित कार्य

पुस्तकें

इंडिया हायर एजूकेशन रिपोर्ट 2020: इम्प्लायमेंट एंड इम्प्लायबिलिटी ऑफ हायर एजूकेशन ग्रेजुएट वर्गीज एन.वी. के साथ सह–सम्पादन (आगामी)।

एजूकेशन फानेंसिंग इन इंडियाः शिफ्टिंग पैराडिज्म – राष्ट्रीय संगोष्ठी, नीपा पर आधारित एक संपादित पुस्तक। रूटलेज प्रकाशक द्वारा जारी पुस्तक अनुबंध की समीक्षा रिपोर्ट के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में है ड्राफ्ट अध्यायों की समीक्षा की जा रही है और पांडुलिपि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

लेख/पुस्तक अध्याय

टीचिंग लर्निंग एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इन हायर एजुकेशन, वर्गीज एन.वी. और सायंतन मंडल (संपादक) में ट्रींगुलर मॉडल ऑफ आउटकम–बेस्ड हायर एजूकेशन परफॉरमेंस, स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, 2020

ट्रैंड एंड स्ट्रैटेजीज टूवार्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजूकेशन इन इंडिया, (2021), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्परेटिव एजूकेशन एंड डवलपमेंट, एमराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड, यूके 16 जनवरी, 2020 को स्वीकृत, डी.ओ.आई. 10.1108/आईजेसीईडी–10–2020–0067

ग्रेजुएट इम्प्लायमेंट एंड ससटेनेबल इम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन इंडिया, वर्गीज एनवी और सी.एम. मलिश, सीपीएचआरई रिसर्च पेपर नंबर 14, सीपीएचआरई, नीपा, नई दिल्ली (2020)

एफपीआई, वित्त विभाग और डब्ल्यूसीडी, कनार्टक सरकार, द्वारा ''एजूकेशन सैक्टर जेंडर बजटिंग इन इंडिया'' में 'जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एफर्ट्सः इश्यूज एंड चैलेंजेज' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल। बेंगलुरु, (2020)

इनबॉण्ड स्टूडेंट मोबिलिटी इन इंडियन हायर एजूकेशनः अ कर्न्सन फॉर ग्रेजुएट रियलिटीज, यूनिवर्सिटी न्यूज, वॉल्यूम. 58, संख्या 30, जुलाई –अगस्त 02, 2020, एआईयू, नई दिल्ली सोनम अरोड़ा के साथ।

नीड एंड रेशनल फॉर जेंडर बजटिंग इन हायर एजूकेशन इन इंडिया (2020) अर्थिक चर्चे, खंड 5, नंबर 1, जनवरी–जून, वित्तीय नीति संस्थान, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

गोविंदा आर. और पूर्णिमा एम. (संपादक) एक्सप्लोरिंग द रिलेशनसिप बिटवीन इकोनोमिक ग्रोथ, इम्प्लायमेंट एंड एजूकेशन इन इंडियन स्टेट्स में इंडियाज सोशल सैक्टर एंड एसडीजी, रूटलेज, टेलर और फ्रांसिस, न्यूयॉर्क (2019)।

शिक्षा में लैंगिक बजट पर कार्यशाला की रिपोर्ट, हाल ही में हैदराबाद में तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से आयोजित।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय

3 दिसंबर, 2020 को कोलोन विश्वविद्यालय, जर्मनी द्वारा क्वालइंडिया प्रोजेक्ट वर्चुअल मीटिंग में विशेषज्ञ/परियोजना सहभागी।

2 दिसंबर, 2020 को ओसाका, साप्पोरो, टोक्यो द्वारा 'एशिया और प्रशांत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा और नवाचार' पर वेबिनार में भागीदारी।

बुधवार, 2 दिसंबर 2020 को कोविड–19 और उसके बाद शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश पर यूनेस्को वेबिनार।

राष्ट्रीय

शनिवार, 19 दिसंबर 2020 को कर्नाटक सरकार के लाइन विभागों में अधिकारियों के लिए बाल बजट 2021–22 तैयार करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण के उद्देश्य से अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति।

16 अक्टूबर 2020 को वित्तीय नीति संस्थान, कर्नाटक द्वारा "कर्नाटक राज्य में बच्चों के लिए सार्वजनिक वित्त पर क्षमता निर्माण और अनुसंधान" पर 2020–21 में यूनिसेफ–परियोजना की पहली तकनीकी सलाहकार समूह की ऑनलाइन बैठक में विशेषज्ञ।

15–27 फरवरी, 2021 तक ''औद्योगीकरण, निगमित क्षेत्र और विकास'' पर आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित आगामी आईएसआईडी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में से 22 फरवरी, 2021 को संसाधन व्यक्ति।

6 अक्टूबर, 2020 को इनर व्हील क्लब ऑफ भोपाल लिगेसी द्वारा आयोजित 'नई शिक्षा नीति 2020 में एक अर्न्तदृष्टि' पर वेबिनार के सम्मानित अतिथि और मुख्य वक्ता।

शुक्रवार, 18 सितंबर 2020 को एसोचैम द्वारा आयोजित 'एनईपी 2020 नॉलेज सिरीज – ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन – फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स' पर वेबिनार में प्रख्यात वक्ता।

25 सितंबर, 2020 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में ''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' पर वेबिनार ।

28 अगस्त, 2020 को शिक्षा विभाग और आईक्यूएसी, राजकीय ज़वलनुआम कॉलेज, मिजोरम द्वारा आयोजित ''नई शिक्षा नीति 2020 और भारत में उच्चतर शिक्षा'' पर राष्ट्रीय वेबिनार में रिसोर्स पर्सन।

31 अगस्त, 2020 को ''नई शिक्षा नीति 2020 और उच्चतर शिक्षा'' पर विमर्श द्वारा, यूसीएसएसएच ऑनलाइन डायलॉग सीरीज़ (यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ द्वारा एक पहल), मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर में वेबिनार आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन।

29 जून, 2020 से 9 जुलाई, 2020 तक हाथरस, उत्तर प्रदेश में आयोजित डाईट द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में 8 जुलाई, 2020 को ''संकट के समय नेतृत्व – नवाचार, एकीकरण और धैर्य'' विषय पर वेबिनार आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए रिसोर्स पर्सन।

11 जुलाई, 2020 को राजकीय गृह विज्ञान लीड कॉलेज, होशंगाबाद (म.प्र.) और श्री माखनलाल चतुर्वेदी राजकीय महाविद्यालय, बाबई (जिला– होशंगाबाद) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'कोविड–19 संकट और विश्व जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव' मानव संसाधन विकास और नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता।

क्यूएसआई–गेज द्वारा 11 दिसंबर 2020 को ''उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन – समय की आवश्यकता'' पर आभासी गोलमेज चर्चा

24 जुलाई, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित 'कोविड महामारी के दौरान उच्चतर शिक्षा' पर वेबिनार।

14 जुलाई, 2020 को सीपीएचआरई, नीपा द्वारा आयोजित 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना' विषय पर वेबिनार।

1 अगस्त, 2020 को आयोजित क्यूएस आईजीएयूजीई रेटिंग–पद्धति 2.0 और विषय निर्धारण' पर पैनलिस्ट।

8 अगस्त, 2020 को विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक और मूल्यांकन एकक, एनआईईपीए द्वारा आयोजित ''भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि' पर वेबिनार।

13 अगस्त, 2020 को वीईआरआईएस द्वारा आयोजित 'भविष्य के कार्यस्थल की पुनर्कल्पना' पर वेबिनार।

19 अगस्त, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियां और रास्ते' पर राष्ट्रीय वेबिनार।

20 अगस्त, 2020 को 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर नीपा द्वारा आयोजित 'शिक्षा और सामाजिक अवसर: अंतराल को पाटना' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार।

25 अगस्त, 2020 को 'कोविड–19 के बाद आर्थिक विकास और कार्य शैलियों में परिवर्तन' पर वेबिनार।

8 अक्टूबर, 2020 को यूनेस्को, दिल्ली द्वारा '2020 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट' के ऑनलाइन शुभारंभ में भागीदारी।

कार्यशालाएं / सम्मेलन / प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

श्री सुमित कुमार की पी–एच.डी. प्री–सबमिशन सेमिनार

सुश्री संजू चौधरी की मौखिक परीक्षा – पीजीडेपा शोध निबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित / संचालित

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शिक्षण:

एम.फिल. / पी–एच.डी. – सीसी3, अनुसंधान पद्धति की पृष्ठभूमि / पठन सामग्री विकसित और संचालन तथा मूल्यांकन

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा): शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन पर आईडेपा पाठ्यक्रम सं. 207 में कक्षाओं का संचालन

शैक्षिक योजना और प्रशासन में राष्ट्रीय डिप्लोमा (डेपा और पीजीडेपा)

एम.फिल. / पी–एच.डी. / पीजीडेपा अनुसंधान मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण

पी–एच.डी.– सुमित कुमार (रिसर्च स्कॉलर) – ज्ञान आधारित उद्योगों के स्थानिक वितरण और भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रवास के बीच अंतर–संबंध। (शोध प्रबंध प्रस्तुत)

पी–एच.डी.– संध्या दुबे ''उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में पहुंच और गुणवत्ता की गतिशीलता'' प्रगति के तहत विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन

पी–एच.डी.– सोनम अरोड़ा : के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और कार्य प्रगति पर है

पी–एच.डी.– पारुल शर्मा : के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया और कार्य प्रगति पर है

पी–एच.डी.– राज गौरव : के प्रस्ताव को सारांश प्रस्तुत, आगे परिष्कृत किया जा रहा है

एम.फिल. शोध प्रबंध : करिका दासः को शोध प्रबंध प्रस्तुत

दक्षिण सूडान से, आईडेपा–XXXVI के प्रतिभागी श्री ओचनलिनो विक्टर ओविनी के ''दक्षिण सूडान में विज्ञान विषयों में माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले स्कूल कारक, सेंट्रल इक्वेटोरिया राज्य में चयनित माध्यमिक विद्यालयों का अध्ययन शीर्षक से आईडेपा शोध प्रबंध प्रस्तुत।

श्री पंकज उप्रेती, उप–शिक्षा अधिकारी, पीईएस, उत्तराखंड द्वारा राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय, तपोवन ब्लॉक–नरेंद्र नगर जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के कामकाज और प्रदर्शन पर अध्ययन विषय से पीजीडेपा शोध प्रबंध को अंतिम रूप से प्रस्तुत, मूल्यांकन और सम्मानित किया।

संजू चौधरी द्वारा पीजीडेपा शोध प्रबंध समग्र बाल विकास केंद्र के रूप में विद्यालयः कोविड–19 के दौरान चुनौतियों का जवाब – राजस्थान में चुनिंदा सरकारी स्कूलों का केस अध्ययन शीर्षक का सारांश और अध्याय योजना को अंतिम रूप दिया, विकास के तहत अनुसंधान उपकरण (प्रस्तुत और मौखिक रूप से आयोजित)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

सदस्यः 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2020–21 से 2024–25 तक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 2018 के लिए निधि की आवश्यकता का अनुमान तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति (शिक्षा क्षेत्र)।

सदस्यः शिक्षा क्षेत्र में सेवा उत्पादन के सूचकांक पर उप–समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार।

राष्ट्रीय विशेषज्ञ और समन्वयक (भारत): भविष्य के लिए मानव संसाधन विकास पर परियोजना। एशिया उत्पादकता संगठन, टोक्यो, जापान ''भारत में भविष्य के उद्योग के लिए मानव संसाधन विकसित करने में राष्ट्रीय रणनीति'' (अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत)

राष्ट्रीय विशेषज्ञ और समन्वयक (भारत): चयनित एशियाई देशों में उच्चतर शिक्षा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर यूनेस्को, बैंकॉक–टोक्यो विश्वविद्यालय परियोजना। ''उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण – भारत का अध्ययन'' अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

सदस्य, बाल बजट विकास के लिए तकनीकी सलाहकार समिति, वित्तीय नीति संस्थान, कर्नाटक सरकार।

कोलोन विश्वविद्यालय, जर्मनी के साथ क्वालइंडिया प्रोजेक्ट में परियोजना सहभागी।

आमंत्रित सदस्य आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन एकक, एनएलआईयू, गुजरात, भारत।

ऑक्सफोर्ड रिव्यू ऑफ एजूकेशन, जून, 2019 के लिए पांडुलिपि आईडी कोर–2019–0063 की समीक्षा।

सूक्ष्मअर्थशास्त्र में अध्ययन, 'पूर्वस्कूली के दीर्घकालिक प्रभावः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए एनएलएसवाई से साक्ष्य, पांडुलिपि की समीक्षा सेज प्रकाशन।

सेज, एमराल्ड, ऑक्सफोर्ड के लिए समीक्षा कार्य।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, जेपा, संपादकीय बोर्ड, सदस्य,

सदस्य सचिव, एम.फिल./पी–एच.डी. प्रगति समीक्षा समिति

सदस्य, एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश समिति (साक्षात्कार बोर्ड)

सदस्य, एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न निर्धारण समिति

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, उच्च शिक्षा विभाग

सदस्य, विभागीय सलाहकार समिति, शैक्षिक वित्त विभाग

सदस्य, एम.फिल. पाठ्यचर्या संशोधन और पुनर्गठन समिति

सूक्ष्मअर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए समीक्षक, सेज प्रकाशन

लाइफ साइंस ग्लोबल, कनाडा के विशेष अंक के अतिथि संपादक

प्रबंधन और अर्थशास्त्र अनुसंधान जर्नल के लिए समीक्षक

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्यः अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नोएडा) की स्थायी उप समिति।

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड (डीएबी) योजना और निगरानी प्रभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

यूजीसी–मुक्त शिक्षा ब्यूरो में जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर के डीई कार्यक्रम के लिए एसएलएम के मूल्यांकन विशेषज्ञ सदस्य।

स्प्रिंगर्स, सिंगापुर के लिए पुस्तक प्रस्ताव के समीक्षक।

संपादकीय सलाहकार बोर्डः हिमगिरी एजुकेशन रिव्यू" आईएसएसएन 2321–6336

पी–एच.डी. मूल्यांकन हेतु विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए बाहरी परीक्षक

विभिन्न विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी निकायों के लिए चयन समिति सदस्य।

वेटुकुरी पी.एस. राजू

अनुसंधान पत्र/आलेखः

शिक्षा विभाग (सीएएसई एंड आईएएसई), आईयूसीटीई, शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय, एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा द्वारा 'शिक्षा में नवाचार और सर्वोत्तम कार्याभ्यास' आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास, (2020), पृष्ठ 40–49, संदर्भ, 978–93–5406–947–5।

भारत में जनजातीय शिक्षा का वित्तपोषण, 'भारत में जनजातीय विकासः जनजातीय शिक्षा में चुनौतियां और संभावनाएं', सेज प्रकाशन भारत, 2020, पृष्ठ. 301–314, संदर्भित, 978–93–5388–427.7 (एचबी)।

उच्च शिक्षा का वित्त पोषणः जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधान मंत्री की विशेष छात्रवृत्ति योजना का अध्ययन (विचाराधीन)।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के लिए छात्र सहायता प्रणाली (विचाराधीन)।

उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का गैर–नामांकन और ड्रॉप–आउट (विचाराधीन)।

अनुसंधान अध्ययनः पूर्ण और जारी अनुसंधान परियोजनाएं

प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के बीच गैर–नामांकन और ड्रॉप–आउट के कारणः आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन (परियोजना पूर्ण हुई)

केंद्र प्रायोजित 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का मूल्यांकन अध्ययन (परियोजना प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत)।

केंद्र प्रायोजित योजना 'माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना' का मूल्यांकन अध्ययन (परियोजना प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत)।

संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

7 अगस्त 2020 को यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 'उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

8 अगस्त 2020 को शाला सिद्धि ईकाई, नीपा, नई दिल्ली द्वारा 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैंः शाला सिद्धि से अर्न्तदृष्टि पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

20 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर प्रो. ए.के.

शिव कुमार, विकास अर्थशास्त्री और नीति सलाहकार द्वारा 'शिक्षा और सामाजिक अवसरः अंतराल को पाटना' पर वेबिनार में भागीदारी

11 अगस्त, 2020 को जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 – आगे का एक नया सफर' पर वेबिनार में भागीदारी।

19 अगस्त 2020 को नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग' पर वेबिनार में भागीदारी।

26 अगस्त, 2020 को सेंट एलॉयसियस कॉलेज (स्वायत्त), मंगलुरु द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (यूजीसी–परामर्श स्कीम की एक गतिविधि) पर वेबिनार में भागीदारी।

28 अगस्त, 2020 को आईयूसीटीई के सहयोग से आईक्यूए सेल, एम.एस. विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालयों की पुर्नकल्पना पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी।

28 अगस्त, 2020 को 'शिक्षा विभाग और आईक्यूएसी, राजकीय ज़वलनुआम महाविद्यालय, मिजोरम द्वारा आयोजित 'नई शिक्षा नीति 2020 और भारत में उच्चतर शिक्षा' पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी।

28 अगस्त, 2020 को जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'शिक्षा का भविष्य, एनईपी 2020 को लागू करना, नेतृत्व के लिए कार्यसूची की व्यवस्था करना' विषय पर प्रख्यात शिक्षकों के संगोष्ठी में भागीदारी।

29 अगस्त, 2020 को शिक्षा संकाय, आरबीएस कॉलेज, आगरा द्वारा आयोजित शिक्षक शिक्षा के विशेष संदर्भ में 'नई शिक्षा नीति 2020' पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी।

शिक्षा पर सामान्य विषय

7–8 मई, 2020 को केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, जम्मू और कश्मीर के द्वारा आयोजित 'कोविउ–19 के दौरान शिक्षा की क्या कीमत चुकानी है?' पर वक्ता और 'संकट के दौरान शिक्षा और नेतृत्व' पर दो दिवसीय वेबिनार में भागीदारी।

16 से 18 जून, 2020 तक शिक्षक और शिक्षण पर पीएमएमएमएनएम की योजना के तहत स्कूल ऑफ एजूकेशन, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपकरणों के विकास और मानकीकरण पर तीन दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में भागीदारी।

1 जुलाई, 2020 को डॉ बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 'कोविड–19 के लिए शिक्षा क्या कीमत चुकाएगी' पर वक्ता और 'सतत विकास में अकादमिक की भूमिका' पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला संकाय के लिए तीन सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम में भागीदारी।

28 मई, 2020 को एनएएसी बंगलौर द्वारा आयोजित, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी द्वारा 'चुनौतियों को अवसरों की ओर मोड़ेंः कोविड–19 महामारी और भारत की उच्च शिक्षा में मुकाबला करने के उपायों' पर वेबिनार में भागीदारी।

24 जुलाई, 2020 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा' (सर्वेक्षण के आधार पर) पर वेबिनार में भाग लिया।

6–7 अगस्त, 2020 के दौरान ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'विश्वविद्यालयों की पुनर्कल्पना और परिवर्तनः कोविड–19 व्यवधान के दौरान और उसके बाद विचारों का संगम' पर वैश्विक आभासी सम्मेलन में भागीदारी।

14 जुलाई को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।

31 अक्टूबर, 2020 को ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ''21वीं सदी की आजीविका के लिए कौशल निर्माण'' पर वेबिनार में भाग लिया।

9 अक्टूबर 2020 को ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'प्रख्यात शिक्षकों के वार्तालाप पर वेबिनार में भाग लिया।

20 नवंबर 2020 को सीपीआरईई/नीपा और आईआईईपी/यूनेस्को, पेरिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'लचीले अधिगम के मार्गः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार में भागीदारी।

6 नवंबर, 2020 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'प्रख्यात शिक्षकों के वार्तालाप' पर वेबिनार में भागीदारी

11 नवंबर, 2020 को (राष्ट्रीय शिक्षा दिवस) मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान पर वेबिनार में भागीदारी।

3 मार्च, 2021 को एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में प्रबंधन अनुशासन शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार में भाग लिया।

14 मई, 2020 को ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ''तनाव प्रबंधन और प्रदर्शन में वृद्धि पर वेबिनार में भागीदारी।

26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर 'भारतीय संविधान में बहुलवाद, समानता और नागरिकता के विचार की पुष्टि' पर वेबिनार में भागीदारी।

26 नवंबर, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित कोविड काल में क्या करें और क्या न करें और हृदय संबंधी समस्याओं के प्रबंधन पर वेबिनार में भाग लिया।

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

नीपा, नई दिल्ली में ''शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा'' के लिए शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन (पाठ्यक्रम 207) के समन्वयक।

नीपा, नई दिल्ली में ''शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा'' के लिए शैक्षिक योजना पाठ्यक्रम (905) के समन्वयक।

नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 23–27 नवंबर, 2020 से 'अकादमिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम' के लिए संसाधन व्यक्ति।

नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) पाठ्यक्रम सं. 905: 'परियोजना कार्य और लेखन' के लिए संसाधन व्यक्ति।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और संचालित

नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (XXXVI–आईडेपा) में पाठ्यक्रम संख्या 207: 'शिक्षा में वित्तीय योजना और प्रबंधन' पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित और संचालित

नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) में पाठ्यक्रम संख्या 903: 'शैक्षिक योजना' पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित और संचालित

नीपा, नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) में पाठ्यक्रम संख्या। 905: में 'परियोजना कार्य और लेखन' पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित और संचालित

शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में आईसीटी के अनुप्रयोगों पर ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित करी।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

''स्कूल तथा उच्च शिक्षा में व्यवसायीकरण और कौशल विकास'' पर एनईपी–2020 विषयगत कार्य समूह के सदस्य।

''राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के संचालन'' पर एनईपी–2020 विषयगत कार्य समूह के सदस्य।

7 से 8 मई, 2020 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, जम्मू और कश्मीर द्वारा आयोजित 'कोविड–19 के दौरान शिक्षा की क्या कीमत चुकानी है?' 'संकट के दौरान शिक्षा और नेतृत्व' पर दो दिवसीय वेबिनार में पर अध्यक्ष और भागीदारी।

1 जुलाई, 2020 को डॉ बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित' कोविड–19 के लिए शिक्षा क्या कीमत चुकाएगी?' पर वक्ता और 'सतत विकास में अकादमिक की भूमिका' पर विज्ञान, इंजीनियरिंग और कला संकाय के लिए तीन सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम में भागीदारी।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

पर्यवेक्षणः पीजीडेपा के प्रतिभागी डॉ. विजेंद्र गौड़, एससीईआरटी, हरियाणा को 'हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन (नीपा को प्रस्तुत)' पर अपने शोध प्रबंध को अंतिम रूप देने के लिए अनुसंधान मार्गदर्शन।

पर्यवेक्षणः 36वें आईडेपा प्रतिभागी श्री रामधनी के परियोजना कार्य शीर्षक ''सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयों के अकादमिक प्रदर्शन पर सामुदायिक भागीदारी का प्रभावः मिटिंबवानी सेकेंडरी स्कूल, तांगा–तंजानिया का अध्ययन (नीपा को प्रस्तुत) पर अनुसंधान मार्गदर्शन

परियोजना कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन और पीजीडेपा प्रतिभागी की मौखिक परीक्षा

आईडेपा परियोजना कार्य रिपोर्ट का मूल्यांकन

विभाग के लिए विभागीय सलाहकार समिति की बैठक की कार्यसूची तैयार करना

एम.फिल./पी–एच.डी. के प्रवेश परीक्षा आयोजन समिति के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के निरीक्षक

एम.फिल./पी–एच.डी. के अनुप्रयोग जाँच समिति के सदस्य

नीपा छात्रावास के वार्डन

नीपा डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल के सदस्य।

नीपा की विभिन्न प्रशासनिक समितियों के सदस्य

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

संयुक्त सचिव और आजीवन सदस्य, कम्पेरेटिव एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

शैक्षिक योजना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (आईआईईपी/यूनेस्को), पेरिस, फ्रांस के पूर्व छात्र सदस्य।

शैक्षिक नीति विभाग

अविनाश कुमार सिंह

प्रकाशन

नई शिक्षा नीति 2020: कार्यान्वयन रणनीतियां, नीपा, नई दिल्ली, दिसंबर, पृ. 1–194

2021 ''द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशनल गवर्नेंस इन द नॉर्थ–ईस्टः चेंज एंड कंटीन्यूटी'' इन 'प्राब्लम्स एंड प्रॉसपैक्ट्स ऑफ सिक्स्थ शेड्यूलः ट्रूवर्ड्स ट्राइब्स ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस' एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

अनुसंधान पूर्ण और जारी

जारी

'चुनिंदा राज्यों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत निजी

स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के प्रावधान के क्रियान्वयन का अध्ययनः नीति एवं व्यवहार'

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय)

21–25 सितंबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में आयोजित 'शिक्षा में सार्वजनिक नीति निर्माण' पर उन्मुखीकरण कार्यशाला में नीति निर्माण पर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पर अभिभाषण।

15–17 फरवरी, 2021 को नीपा, नई दिल्ली में आयोजित आरटीई के तहत वंचित और कमजोर वर्गों की शिक्षाः नीतिगत मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेप' पर अभिविन्यास कार्यशाला में 'नीति और अनुसंधान लिंकेज' पर व्याख्यान।

1 जून 2020 को शिक्षा उत्थान न्यास, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित 'बच्चों के अधिकारों पर परिप्रेक्ष्य' पर परामर्शदात्री बैठक में आरटीई पर एक विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी।

9–10 जून, 2020 को वसंत महिला कॉलेज, बीएचयू, वाराणसी द्वारा आयोजित 'शिक्षण, अधिगम और आभासी दुनियाः मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य' पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 'शिक्षा में प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका' पर अभिभाषण।

6 जून, 2020 को एस.एस. कॉलेज, जहानाबाद, मगध विश्वविद्यालय, बिहार द्वारा आयोजित 'कोविड के समय शिक्षा' पर वेबिनार में मुख्य अभिभाषण।

1–2 जून, 2020 को '21वीं सदी में शिक्षा और कौशल वितरण में परिवर्तन' पर वेबिनार में अभिभाषण।

ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीएनसीई), नोएडा (यूपी) द्वारा 30 जून, 2020 को 'शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी' पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में एक महत्वपूर्ण अभिभाषण।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर द्वारा 28–29 जुलाई, 2020 को आयोजित 'शिक्षा पर गांधीवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता' पर राष्ट्रीय वेबिनार में 'शैक्षिक नीतियों और प्रथाओं पर गांधीवादी विचारः एक संवाद' पर भाषण दिया।

23 अगस्त, 2020 को शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' पर राष्ट्रीय वेबिनार में भाषण दिया।

28–29 सितंबर, 2020 को सामाजिक कार्य विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020' पर राष्ट्रीय वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया।

27 अगस्त, 2020 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आयोजित 'शिक्षा के साथ गांधी के प्रयोगों की प्रासंगिकता– नीतिगत दृष्टिकोण' पर वार्ता।

22 अक्टूबर, 2020 को एनआईएएस बैंगलोर द्वारा आयोजित 'कोविड –19 के बाद शिक्षा' पर वेबिनार में 'एनईपी–2020 और समावेशन का विषय' पर एक वार्ता।

23–24 मार्च, 2021 को एनसीएसएल, नीपा द्वारा आयोजित 'विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण और व्यवहार' पर राष्ट्रीय वेबिनार में 'आपातकाल में स्कूल नेतृत्व की बदलती भूमिका' पर एक सत्र की अध्यक्षता।

16–22 जनवरी, 2021 को हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर द्वारा 'सामाजिक विज्ञान के लिए अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता' पर आयोजित वेबिनार में 'अम्बेडकर के साथ संवादः एक सामाजिक विज्ञान वार्ता के लिए महत्वपूर्ण विचार' पर वेबिनार में भाषण दिया।

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

15–17 फरवरी, 2021 को नीपा, नई दिल्ली में 'आरटीई के तहत वंचित और कमजोर वर्गों की शिक्षाः नीतिगत मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेप पर उन्मुखीकरण कार्यशाला।

1 अक्टूबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में) 'गांधीवादी शैक्षिक विचारों और प्रयोगों की प्रासंगिकताः नीति और व्यवहार के लिए निहितार्थ' पर वीडियो वृत्तचित्र का ऑनलाइन प्रदर्शन।

11 नवंबर, 2020 को (राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में) 11वें मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान का आयोजन, प्रो. ध्रुव रैना द्वारा ''उच्च शिक्षा का भविष्य– इतिहास के दर्पण और विज्ञान के दर्शन'' पर व्याख्यान (ऑन लाइन)

19 अगस्त, 2020 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियाँ और मार्ग' पर राष्ट्रीय वेबिनार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रस्तुत/विकसित प्रशिक्षण सामग्री

एम.फिल./पी–एच.डी. पाठ्यक्रम दिशानिर्देश का संशोधन, नीपा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

28 सितंबर, 2020 (ऑनलाइन) पर आईआईटी, दिल्ली में वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप समिति की बैठक में बाहरी विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी

28 जनवरी, 2021 को एनसीईआरटी, नई दिल्ली में विशेष आवश्यकता वाले समूहों के शिक्षा विभाग (डीईजीएसएन) के विभागीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में बाहरी विशेषज्ञ के रूप में भागीदारी।

इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली, में एनएचईक्यूएफ विकसित करने के लिए यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में भागीदारी।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एम.फिल. और डिप्लोमा कार्यक्रम में पाठ्यक्रम शिक्षण

सीसी–1 पर एम.फिल. अनिवार्य पाठ्यक्रम' 'शिक्षा पर परिप्रेक्ष्य'

वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–7: 'निष्पक्ष और बहुसांस्कृतिक शिक्षा'

अनिवार्य पाठ्यक्रम सीसी–902: 'भारतीय शिक्षाः एक परिप्रेक्ष्य' शैक्षणिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (पीजीडेपा) के तहत

पी–एच.डी. विद्वानों को मार्गदर्शन

श्री अजय कुमार चौबे, पी–एच.डी. स्कॉलर (अंशकालिक), नीपा को उनके शोध प्रबंध 'स्टडी ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ एक्सक्लूजन इन स्कूल एंड कम्युनिटी' शीर्षक पर 2020–21 में डिग्री प्रदान की गई)

सुश्री खुशबू सिंह पी–एच.डी. स्कॉलर को उनके अध्ययन विषय 'सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बीच शैक्षिक अवसर और स्कूल प्रगति की समानताः अनुसूचित जाति के बच्चों का एक नृवंशविज्ञान अध्ययन' में मार्गदर्शन और 2020–21 में डिग्री प्रदान की गई)

सुश्री लैबोनी दास, पी–एच.डी. स्कॉलर (अंशकालिक) को उनके अध्ययन 'वंचित समूहों की भागीदारी के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन' पर जारी अध्ययन विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया।

सुश्री नीलांजना मोइत्रा पी–एच.डी. स्कॉलर को उनके अध्ययन 'झारखंड, भारत के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में जनजातीय एजेंसी और उच्च शैक्षिक शासन' पर जारी अध्ययन विषय में मार्गदर्शन प्रदान किया।

सुश्री डालसी गंगमेई, पी'एच.डी. स्कॉलर को उनके अध्ययन 'उच्च शिक्षा में पहचान और भागीदारीः दिल्ली में चयनित शैक्षणिक संस्थानों में पूर्वोत्तर जातीय अल्पसंख्यक छात्रों का एक अध्ययन' पर मार्गदर्शन प्रदान किया। (अध्ययन जारी है)

श्री बागेश कुमार, पी–एच.डी. स्कॉलर को उनके अध्ययन 'उच्च शिक्षा में पहचान संभाषणः दलित–बहुजन छात्र संगठनों का अध्ययन' विषय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। (अध्ययन जारी है)

सुश्री वंदना तिवारी पी–एच.डी. स्कॉलर को उनके अध्ययन 'कक्षा, भाषा और शैक्षिक उपलब्धिः दिल्ली में चयनित निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों में आरटीई अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों का अध्ययन' में मार्गदर्शन प्रदान किया। (अध्ययन जारी है)

श्री प्रियांक शर्मा, एम.फिल. विद्वान को उनके अध्ययन 'स्कूली शिक्षा में बहुसंस्कृतिवाद का समावेश' पर मार्गदर्शन और 2020–21 में डिग्री प्रदान की गई)।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

अध्यक्ष, सहायता अनुदान योजना, मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2015 से 5 वर्षों से अधिक के लिए

सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआई)

सदस्य, जर्नल ऑफ आदिवासी एंड इंडिजेनस स्टडी (जेएआईएस) संपादकीय सलाहकार बोर्ड

सदस्य, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) को वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में सुदृढ़ीकरण हेतु समिति

सदस्य, विभागीय सलाहकार बोर्ड, विशेष आवश्यकता वाले समूहों के शिक्षा विभाग, (डीईजीएसएन), एनसीईआरटी, नई दिल्ली

सदस्य, एनएचईक्यूएफ, यूजीसी, नई दिल्ली को विकसित करने हेतु विशेषज्ञ समिति

नीपा में अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ

अध्यक्ष, अनुसंधान और प्रकाशन समीक्षा समिति, नीपा

परीक्षा नियंत्रक, नीपा

अध्यक्ष, एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए पर्यवेक्षकों के आवंटन हेतु समिति, नीपा

संपादक, जर्नल ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेपा)

सदस्य, प्रबंधन बोर्ड, नीपा

सदस्य, अध्ययन बोर्ड, नीपा

सदस्य, अकादमिक परिषद, नीपा

मनीषा प्रियम

प्रकाशन

2021: प्रियम, एम.एड. सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को पुनः प्राप्त करना: सुधारों के लिए तुलनात्मक चिंतन, रूटलेज (आगामी)।

2021: ''द मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन ए लोकल एरिना: द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन प्रिंसली मैसूर'', रॉब जेनकिंस और लुईस टिलिन (संपादक) डिके एंड पॉलिटिकल रीजेनरेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स: एसेज इन ऑनर ऑफ जेम्स मैनर, ओरिएंट ब्लैकस्वान (पुस्तक में अध्याय) (आगामी)

2021: ''एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉर्डनिटी एडमिस्ट द रूरल फील्ड ऑफ मैसूर: रिफ्लैक्शंस ऑन द महाराजा कॉलेज, श्रीवास्तव, आरती (सं.) में द सेंटेनेरियन्स, (पुस्तक अध्याय) रूटलेज, (आगामी)।

2021: "ह्वैदर टीचर्स? एजूकेशन रिफार्म्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन'', रज्जाक, अज़रा, पद्म सारंगपाणि और मनीष जैन (संपा.) पुस्तक में अध्याय एजूकेशन टीचिंग एंड लर्निंग: डिस्कोर्सेज, कल्चर्स एंड कन्वर्जेशन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।

2021: ''बाउंडेड एस्पीरेशन एंड यूथ कैपासिटी: इंट्रोगेटिंग पब्लिक हायर एजूकेशन इन नॉर्थ इंडिया'', जर्नल ऑफ साउथ एशियन कल्चर एंड हिस्ट्री – जर्नल आलेख, आगामी।

2021: ''अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यूथ एस्पिरेशंस, एंड एजुकेशन इन इंडिया'', जर्नल ऑफ साउथ एशियन कल्चर एंड हिस्ट्री, मोना मेहता और दिव्या वैद के साथ। (आगामी)

2020: ''मार्जिन एंड मार्जिनलिटी: द पत्थलगड़ी मूवमेंट एंड झारखंड इलेक्शन 2019'', मुकुलिका बनर्जी के साथ, द इंडिया फोरम, 5 जून, 2020। (https://www.theindiaforum/in/article/margins-and-marginality पर उपलब्ध)

अनुसंधान पूर्ण और जारी

जारी अनुसंधान

उच्च शिक्षा सुधारों की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाः एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, नीपा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

7 अगस्त, 2020 को ''नीति विनियमन और विश्वविद्यालय स्थिरता के लिए शासन'', विश्वविद्यालय की पुर्नकल्पना और परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर पैनल चर्चाः कोविड 19 के दौरान और उससे आगे विचारों का संगम, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी।

8 अगस्त, 2020 को गोवा विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020ः अच्छा, बुरा और अज्ञात पर शिखर वेबिनार श्रृंखला।

21 अगस्त, 2020 को सेंट टेरेसा में कोच्चि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः अवसर और चुनौतियां पर केरल के माननीय राज्यपाल, श्री आरिफ एम खान की अध्यक्षता में वेबिनार।

22 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूलों में इसका कार्यान्वयन, स्कूल प्राचार्यों और प्रशासकों के साथ वेबिनार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,

24 अगस्त, 2020 को भारत की ओर 75% विकासशील सामाजिक चित्रण, नौसेना युद्ध कॉलेज गोवा, विशेष व्याख्यान।

29 अगस्त, 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूलों में इसका कार्यान्वयन पर स्कूल के प्राचार्यों, प्रशासकों और शिक्षकों के साथ वेबिनार,

4 सितंबर, 2020 को बिहार युवा विचारक मंच, नई शिक्षा नीति 2020 और बिहारः आगे का मार्ग

5 सितंबर, 2020ः नई शिक्षा नीति 2020ः ग्रामीण बिहार का संदर्भ

11 सितंबर, 2020ः नई शिक्षा नीति 2020, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ज़ी लर्निंग

25 सितंबर, 2020ः मानवाधिकारों के बारे में सोच, मानव संसाधन विकास केंद्र जबलपुर।

14 अक्टूबर, 2020ः आठ का समूह, ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान, नई शिक्षा नीतिः भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के लिए संभावनाएं, मेलबर्न।

20 नवंबर, 2020ः भारत में चुनाव और चुनावी राजनीति, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।

12 नवंबर, 2020ः लैंगिक, शक्ति और सामाजिक–आर्थिक विकास, विकास के लिए लैंगिक समावेशी शासन पर राजनयिकों के साथ कार्यक्रम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का आई–टेक कार्यक्रम।

17 फरवरी, 2021ः शहरी सीमांतता को समझनाः लोकतंत्र में आशा, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, नई दिल्ली।

18 फरवरी, 2021ः लैंकिग, शक्ति और सामाजिक–आर्थिक विकासः ब्राजील से अवधारणा और नीति अनुभव, विकास के लिए लैंगिक समावेशी शासन पर राजनयिकों के साथ कार्यक्रम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का आई–टेक कार्यक्रम।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सदस्य, लैंगिक बजट पर व्यापक आधारित समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

सदस्य, राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारत सरकार, मसूरी।

लिंग और सामाजिक विकास पर आमंत्रित शिक्षण संकाय, भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारत सरकार, मसूरी।

नीतिगत गतिविधियों में भागीदारी

नई शिक्षा के लिए संस्थागत विकास योजना तैयार करना

मंत्रालयों में लैंगिक रणनीतियों पर नीति पत्र, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

एस.के. मलिक

प्रकाशन

2021: 'द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड डिसेंट्रीलाइज्ड एजुकेशनल गवर्नेंस इन द नॉर्थ–ईस्ट: चेंज एंड कंटीन्यूटी' में 'प्राब्लम एंड प्रॉसपैक्ट्स ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल: टूवर्ड्स ट्राइब्स ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस' एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता

अनुसंधान पूर्ण और जारी

जारी अनुसंधान

ओडिशा में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच छात्रवृत्ति योजना और शैक्षिक गतिशीलता का अध्ययन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

7 अगस्त, 2020 को सामाजिक विकास परिषद, दिल्ली द्वारा नई शिक्षा नीति क्या है, पर वेबिनार आयोजित

8 अगस्त, 2020 को शाला सिद्धि एकक, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं: शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि पर वेबिनार

19 अगस्त, 2020 को शैक्षिक नीति विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर वेबिनार

23 अगस्त, 2020 को प्रशासन, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर और श्री रावलनाथ को–ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड, अजारा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अकादमिक के लिए अकादमी पर राष्ट्रीय वेबिनार। हाउसिंग

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

आरटीई के तहत वंचित और कमजोर वर्गों की शिक्षा: नीतिगत मुद्दे और कार्यक्रम हस्तक्षेप 'पर ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला (नीपा, नई दिल्ली: 15–17 फरवरी, 2021) (प्रो. ए.के. सिंह के साथ संयुक्त रूप से आयोजित)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रस्तुत/विकसित प्रशिक्षण सामग्री

परियोजना कार्य के लिए ग्रंथ सूची/संदर्भ कैसे तैयार करें?

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा जर्नल) को संपादकीय अनुसमर्थन

पाठ्यक्रम प्रभारी: प्रतिभागियों की संगोष्ठी

1. पीजीडेपा

2. आईडेपा

आईडेपा प्रतिभागी – 1 को मार्गदर्शन

पीजीडेपा प्रतिभागी– 1 को मार्गदर्शन

एम.फिल./पी–एच.डी. वैकल्पिक पाठ्यक्रम सं. 05 (शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय शासन) में अध्यापन,

प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान समूह के सदस्य

एम.फिल./पी–एच.डी. पाठ्यक्रम के सदस्य अवधि

एम.फिल./पी–एच.डी. में दाखिला के लिए जांच समिति के सदस्य।

योग समिति के सदस्य

शिकायत निवारण समिति के सदस्य

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

शैक्षिक योजना और प्रशासन संघ के सदस्य

नरेश कुमार

पूर्ण और जारी अनुसंधान

पूर्ण अनुसंधान

स्कूल की पसंद और प्रक्रियाएंः पड़ोसी स्कूली शिक्षा का अध्ययन

समीक्षावर्ष के दौरान सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

2020–21 के दौरान विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन

26 नवंबर, 2020 को भारतीय संविधान में बहुलता, समानता और नागरिकता के विचार की पुष्टि' अध्यक्षः प्रो. कुमार सुरेश।

26 नवंबर, 2020 डॉ. रिपेन गुप्ता, निदेशक और इकाई प्रमुख, कार्डियोलॉजी, मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल, साकेत, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान अपने दिल की देखभाल।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रस्तुत/विकसित प्रशिक्षण सामग्री

एम.फिल./पी–एच.डी. पाठ्यक्रम दिशानिर्देश में शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम और गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर मुख्य पाठ्यक्रम का संशोधन और अद्यतन किया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एम.फिल. और डिप्लोमा कार्यक्रम में पाठ्यक्रम का शिक्षण

सीसी–5ः अनुसंधान पद्धति–II

ओसी–5ः सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय सरकारी शिक्षा

पीएचडी विद्वानों को मार्गदर्शन

सुश्री सुरवी को उनके विषय भारत में एलपीजी सुधारों और स्कूल की पसंद के तहत परिवर्तित शिक्षा प्रणाली पर मार्गदर्शन

नीपा में अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियाँ

नीपा में पूर्णकालिक प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) के रूप में कार्य किया

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

कम्परेटिव एजुकेशन सोसायटी ऑफ इंडिया

इंडियन सोशियोलॉजीकल सोसायटी

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग

प्रणति पांडा

प्रकाशन

''स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए मानक निर्धारण'' पर कार्य समूह का नेतृत्व किया और ''स्टैन्डर्ड्स सैटिंग एंड एक्रेडिटेशन इन स्कूल एजूकेशन'' एनईपी, 2020ः कार्यान्वयन रणनीतियाँ, पर अध्याय का योगदान दिया, दिसंबर, 2020, नीपा।

''शिक्षक प्रबंधन और विकास' पर कार्य समूह का नेतृत्व किया और ''शिक्षक प्रबंधन और विकास'', एनईपी, 2020ः कार्यान्वयन रणनीतियों, पर अध्याय में योगदान दिया दिसंबर, 2020, नीपा।

संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय

27 मई, 2020, यूनेस्को, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'भारत–अफ्रीका चर्चा कोविड–19 के दौरान शिक्षकों पर साझा अनुभव' में अन्तर्राष्ट्रीय अध्यक्ष

21 मई, 2021, यूनेस्को, नई दिल्ली में 'यूनेस्को की 2021 की शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति' पर वेबिनार में वक्ता,

राष्ट्रीय

08 अगस्त, 2020, को नीपा, नई दिल्ली में 'भारत में स्कूल कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं'? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि', में समन्वयक और अध्यक्ष।

22 अगस्त, 2020 को फोरम फॉर इंडियन टीचर्स एजुकेटर्स (सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय), नई दिल्ली द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षाः आगे का मार्ग और 'एनईपी और शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन' पर प्रस्तुत राष्ट्रीय वेबिनार में वक्ता।

15 जून, 2020, को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली के 'प्रारंभिक बचपन शिक्षा और ईसीसी तथा शिक्षक प्रबंधन' पर प्रस्तुत राष्ट्रीय सम्मेलन' वेबिनार में अध्यक्ष।

10 सितंबर, 2020 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली के 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के निहितार्थ' और ''नई शिक्षा नीति और स्कूली शिक्षाः संभावनाएं और अवसर'', पर प्रस्तुत वेबिनार में अध्यक्ष।

12 सितंबर, 2020, को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), उत्तर प्रदेश के 'नई शिक्षा नीति और शिक्षाशास्त्रीय सुधारः भविष्य रोडमैप' और ''शिक्षक शिक्षा में शैक्षणिक सुधार'', पर वेबिनार में अध्यक्ष।

14–15 सितंबर, 2020 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रकाश में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पथ' पर राष्ट्रीय पैनल चर्चा' और 'शिक्षक विशरदः शिक्षक शिक्षा को बदलने के लिए प्रमुख प्रतिनिधि पर प्रस्तुत वेबिनार में अध्यक्ष ।

19 अक्टूबर, 2020 को 'शिक्षक, शिक्षण और शिक्षक शिक्षाः प्रक्रियाएं, चिंताएं और संभावनाएं' और ''एनईपी 2020 के प्रकाश में शिक्षक शिक्षा को बदलनाः चुनौतियां और विकल्प'', पर प्रस्तुत वेबिनार में अध्यक्ष, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वीमेन एंड टीचिंग लर्निंग सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

29 जनवरी, 2021, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020' के आलोक में स्कूली शिक्षा का पुनर्गठन' और ''स्कूलों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए गुणवत्ता की रूपरेखा'' पर प्रस्तुत वेबिनार में वक्ता।

11 मार्च, 2021 को शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई)– शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत शिक्षक शिक्षा में प्रमुख विषयों और 'शिक्षक शिक्षा में विविधता, असमानता और गुणवत्ता' पर प्रस्तुत पर वेबिनार श्रृंखला में वक्ता।

27 जुलाई, 2020 को आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान (एपीएचआरडीआई), आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित ऑनलाईन शिक्षा– शिक्षण और अधिगम की नई खोज पर प्रस्तुत वेबिनार में वक्ता।

13 जनवरी, 2021, सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय (एमओई), नई दिल्ली द्वारा 'मानकों की स्थापना के लिए कार्य समूह' पर आयोजित वेबिनार में अध्यक्ष।

20 फरवरी, 2021 को ग्रीन मेंटर्स, गुजरात द्वारा पाठ्यचर्या तुलना सम्मेलन 2021 पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार के लिए प्रेरक वक्ता के रूप में आमंत्रण।

05 मई, 2021, यूनेस्को और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा 'भारत में शिक्षा की स्थितिः शिक्षक, शिक्षण और शिक्षक व्यावसायिक विकास' पर आयोजित वेबिनार में वक्ता।

03 फरवरी, 2021 को काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (कोबसे), नई दिल्ली द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में स्कूली शिक्षा में आकलन' पर आयोजित वेबिनार में वक्ता।

12 मार्च, 2021, नीपा, नई दिल्ली में आयोजित 'स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियाँ और अवसर' तथा ''लैंगिक दृष्टिकोण से शिक्षक शिक्षण'' पर वेबिनार में अध्यक्ष।

01 अप्रैल, 2021 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली 'स्कूल शिक्षा और संबंधित सेवाओं' पर वेबिनार में अध्यक्ष,।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में 'एनईपी–2020 से जुड़े शाला सिद्धि कार्यक्रम के शत–प्रतिशत कवरेज की शुरुआत और 'शाला सिद्धि कार्यक्रम की प्रगति और उपलब्धि' पर प्रस्तुत पर वेबिनार का समन्वय किया।

24 मार्च, 2021 को केन्द्रीय विद्यालय में आयोजित विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य और व्यवहार पर राष्ट्रीय वेबिनार पर वक्ता।

10 मार्च, 2021 को नीपा, नई दिल्ली में विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और शाला सिद्धि की सलाहकार समिति,

अनुसंधान अध्ययन और परियोजनाएं

'भारत में शिक्षक शिक्षा के शासन, विनिमय और गुणवत्ता आश्वासन का अध्ययन, नीपा अनुसंधान परियोजना का समन्वय और प्रबंधन।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/निष्पादिन

एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रम के लिए मूल पाठ्यक्रम (सीसी–2) 'भारत में शिक्षा' संशोधित और विकसित।

एम.फिल. और पी–एच.डी. कार्यक्रम के लिए मूल पाठ्यक्रम (सीसी–2) 'भारत में शिक्षा' के समन्वयक।

गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन पर प्रशिक्षण पैकेज के लिए स्कूल गुणवत्ता और सुधार पर मॉड्यूल विकसित किया, नीपा।

पी–एच.डी./एम.फिल./पीजीडेपा/आईडेपा के प्रतिभागियों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण

सुश्री ट्विंकल पांडा, पी–एच.डी. स्कॉलर, के शीर्षकः संस्थागत प्रक्रिया और परिणाम पर माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के शासन और गुणवत्ता आश्वासन की प्रभावशीलता।

सुश्री कोमल, पी–एच.डी. विद्वान, के शीर्षकः माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षिक सुधार और सतत व्यावसायिक विकासः नीतिगत व्यवहार और प्रभावशीलता

सुश्री टीना थंकुर, एम.फिल. स्कॉलर के शीर्षकः अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक अध्ययनः रुझान, दृष्टिकोण और व्यवहार।

श्री खीसानो नागी, के शीर्षकः सेचु जुब्जा ब्लॉक, कोहिमा, नागालैंड, के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थिति, पीजीडेपा परियोजना कार्य, 2020–21।

श्री मोलेन चिंगोबे चेलो, (ज़ाम्बिया) के आईडेपा शोध प्रबंध 'जाम्बिया में विशेष रूप से माज़ाकुबा जिले, में कृषि कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि' शीर्षक का पर्यवेक्षण नीपा

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

'शिक्षक शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु दिशानिर्देश और शिक्षक शिक्षकों के लिए (एम.एड. स्तर) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एनसीटीई और यूजीसी) को विस्तारित शैक्षणिक सहायता।

शिक्षक शिक्षा पर थिंक टैंक, ओडिशा सरकार और एससीईआरटी, ओडिशा।

4 पी–एच.डी. दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि की शोध प्रबंध के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ता और परीक्षक।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

कार्यकारी मंडल के सदस्य, स्कूल शिक्षा बोर्ड की परिषद (कोबसे)

कार्यकारी संपादकीय बोर्ड के सदस्य, भारत में शिक्षा की स्थिति, यूनेस्को, नई दिल्ली

सदस्य, जर्नल सलाहकार बोर्ड, एनसीटीई

भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सेसी) की आजीवन सदस्य

सदस्य, एससीईआरटी कार्यक्रम सलाहकार बोर्ड, नई दिल्ली।

सदस्य, कार्यकारी बोर्ड, शिक्षक शिक्षा में सुधार, यूनिसेफ और एससीईआरटी, पुणे।

जर्नल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी (केजेईपी) केईडीआई के अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड के सदस्य।

सदस्य, स्कूल प्रभावशीलता और सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस।

सदस्य, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स।

संस्थापक सदस्य, शिक्षा में शोधकर्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईआरओआरई)।

सदस्य, पूर्व छात्र संघ, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ।

मधुमिता बंद्योपाध्याय

प्रकाशन

पुस्तक में अध्याय:

भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण की नीति और व्यवहार, कोविड–19 के बाद के विश्व विकल्पों और परिणामों में लोकतंत्र और सार्वजनिक नीति पर पुस्तक में अध्याय, रुमकी बसु द्वारा संपादित, रूटलेज इंडिया, 30 दिसंबर, 2020, पृष्ठ 140–157 आईएसबीएन 9780367679781

भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति: चुनौतियां और नीतिगत मुद्दों की समीक्षा, भारत में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा पर मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं, जंध्याला बी. जी. तिलक द्वारा संपादित, पुस्तक में अध्याय: स्प्रिंगर, नई दिल्ली, अगस्त 2020, पृष्ठ 17–50, आईएसबीएन: 978–981–15–5365–3 (सह–लेखक)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रकाशित शोध पत्र / आलेख

'भारत में स्कूली शिक्षा और अधिगम, स्कूलों में अधिगम के परिणाम: सुधार के लिए मुद्दे और पहल, एन्ट्रीप न्यूज़लेटर, नीपा, नई दिल्ली, वॉल्यूम 25 सं. 2, जुलाई–दिसंबर, 2019 नीपा, आईएसबीएन: 0972–7507 (सह–लेखक)

माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा: नीति निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास में भारतीय परिप्रेक्ष्य: नीतियां और व्यवहार, एन्ट्रीप न्यूज़लेटर, नीपा, नई दिल्ली, वॉल्यूम 25 सं. 1, जनवरी–जून, 2019 नीपा, आईएसबीएन: 0972–7507 (सह–लेखक)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित वेबिनारों / सम्मेलनों में भागीदारी

2 अगस्त, 2020 को एएसपीआईआरई इंडिया द्वारा स्कूली शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020: कार्यान्वयन के मुद्दे पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

3 अगस्त, 2020 को टिस्स प्रगतिशील मंच द्वारा अयोजित नई शिक्षा नीति और राजनीति को समझना पर वेबिनार में भागीदारी

7 अगस्त, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन में भागीदारी

7 अगस्त, 2020 को आरटीई मंच द्वारा नई शिक्षा नीति 2020: स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बाधा? पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

10 अगस्त, 2020 को टाटा स्टील द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

8 अगस्त, 2020 को शाला सिद्धि यूनिट, नीपा, नई दिल्ली द्वारा भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं: शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

19 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

14 जुलाई, 2020 नीपा, नई दिल्ली में लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता को आगे बढ़ाना पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

कार्यशालाएं/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

28 जून, 2020 को लॉकडाउन अवधि के दौरान और इसके पश्चात बच्चों को शिक्षित करने पर वेबिनार

30 दिसंबर, 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य से स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना पर ऑनलाइन चर्चा बैठक

8–12 मार्च, 2021 को 'स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

लॉकडाउन अवधि के दौरान और उसके पश्चात बच्चों को शिक्षित करने पर वेबिनार, 28 जून, 2020

30 दिसंबर, 2020 को भारत में नई शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य से स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना पर ऑनलाइन चर्चा बैठक

8–12 मार्च, 2021 को 'स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार

लैंगिक और शिक्षा पर प्रस्तुति

स्कूलों में माता–पिता की भागीदारी पर प्रस्तुति

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भविष्य की योजनाओं पर राज्यों की प्रस्तुति पर सत्र की अध्यक्षता

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एन्ट्रीप के लिए नीपा के केन्द्र बिन्दु और एन्ट्रीप न्यूजलेटर के संपादक

नीपा द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ 'नई शिक्षा नीति–2020: कार्यान्वयन रणनीतियाँ', के विकास में भागीदारी (http://www.niepa.ac.in/download/NEP%20 2020%20Implementation%20Strategy_W.pdf)

एम.फिल पाठ्यक्रम में शिक्षण

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में 'बालिकाओं की शिक्षा पर एक तुलनात्मक अध्ययन' पर चल रही शोध परियोजना।

स्कूलों में अधिगम के परिणामः सुधार के लिए मुद्दे और पहल, पर एंट्रीप न्यूज़लैटर का संपादन, वॉल्यूम 25 सं. 2, जुलाई–दिसंबर, 2019 नीपा, आईएसबीएनः 0972–7507 (2021 में प्रकाशित)

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकासः नीतियां और व्यवहार, एंट्रीप न्यूज़लेटर का संपादन, वॉल्यूम 25 सं. 1, जनवरी–जून 2019, नीपा, आईएसबीएनः 0972–7507 (2020 में प्रकाशित)

एम.फिल. छात्र के ''प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश और भागीदारी में लैंगिक समानताः ग्वालियर, मध्य प्रदेश का अध्ययन'' विषय पर शोध प्रबंध के लिए मार्गदर्शन

पी–एच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन

सामाजिक संरचना, अभिकरण और आकांक्षाएंः ग्वालियर, मध्य प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में किशोरियों का अध्ययन

स्कूली शिक्षा में सामाजिक असमानताः दिल्ली में चयनित स्कूल का अध्ययन

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और अधिकारिताः पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले का अध्ययन

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्य, भारत तुलनात्मक शिक्षा समिति (सेसी)

दिल्ली के गैर–सरकारी संगठन ASPIRE भारत, की सदस्यता

बीएआईसीई यूके के सदस्य

भारतीय शैक्षिक अनुसंधान पत्रिका के सलाहकार बोर्ड के सदस्य, कलकत्ता विश्वविद्यालय

रस्मिता दास स्वैन

प्रकाशन

लर्निंग आउटकम इन इंडियन स्कूल्सः पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूवमेंट. एन्ट्रीप न्यूजलेटर वाल्यूम 25, सं. 2, जुलाई–दिसंबर, 2019

सेमीनार / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय)

स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः अवसर और चुनौतियाँ" 8–12 मार्च, 2021

26 नवंबर, 2020 को ''भारतीय संविधान में बहुलवाद, समानता और नागरिकता के विचार की पुष्टि'' संविधान दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर वेबिनार।

18–19 मार्च, 2021 को राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की परामर्शदात्री बैठक

26 नवंबर, 2020 को कोविड समय के दौरान क्या करें और क्या न करें, और हृदय संबंधी समस्याओं के प्रबंधन पर नीपा, वेबिनार

26 अक्टूबर, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में 'एनईपी कार्य पत्र' पर समन्वयकों की बैठक।

प्रारंभिक बचपन शिक्षाः नई शिक्षा नीति–2020 प्रस्ताव और संलग्नता, नीपा कार्य पत्र प्राथमिकता क्षेत्र– प्री–स्कूल शिक्षा का सार्वभौमीकरण और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, रणनीतिक कार्यान्वयन के लिए ईसीसीई जानकारी, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, 17 सितंबर, 2020।

21–22 सितंबर, 2020 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) द्वारा 7वां राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन, महामारी और उसके पश्चात् माध्यम से प्राप्त करना पर वेबिनार https://aima.onconf.in/47nmc/

उच्च शिक्षा में शासन और स्वायत्तता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नीपा, 2020।

डॉ. डी.एस ठाकुर प्रलेखन अधिकारी द्वारा साहित्यिक चोरी की जाँच –उरकुंड सॉफ्टवेयर, 3 जुलाई, 2020, नीपा।

अकादमिक अखंडता, कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी मुक्त अकादमिक कार्य सुनिश्चित करना, आर.सी. गौड़ – 2 जुलाई, 2020, नीपा

कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा, 24 जुलाई, 2020, नीपा

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार पर नीति संवाद वेबिनार, सीपीआरएचई, नीपा, 15 दिसंबर, 2020

15 दिसंबर 2020 को ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर नीति संवाद सीपीआरएचई द्वारा तैयार नीति संक्षिप्त पर आधारित वेबिनार http://cprhe.niepa.ac.in/Policy-Briefs

20 नवंबर, 2020 को 'लचीले अधिगम के रास्तेः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार

21 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2020 तक एनसीएसएल, नीपा में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यशाला

15 से 17 जुलाई, 2020 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) नई दिल्ली–110016 द्वारा आयोजित, गूगल मीट पर प्रारंभिक बचपन शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन शिक्षा का प्रशासन और प्रबंधनः चुनौतियां और सामरिक प्राथमिकताएं पर पत्र प्रस्तुत।

10 अगस्त 2020 को इंफ्लिबनेट (INFLIBNET) (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र ने विशेष रूप से हरियाणा और दिल्ली के लिए साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (पीडीएस) शोध शुद्धि पर राज्यस्तरीय ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

सी.ई.एस.आई.–अनुसंधान रूचि समूह (आरआईजी)–5 पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति–2020 और उच्च शिक्षा, पर एक वेबिनार 24 सितंबर को आयोजन किया।

पेपर प्रस्तुत – भारत में जनजातीय आश्रम स्कूलों का प्रदर्शनः अंतर्दृष्टि, स्कूल मानक और मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जनवरी 2020

कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

शाला सिद्धि इकाई में उल्लेख किया गया है। ये शाला सिद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति पर एम.फिल. मूल पाठ्यक्रम सं. 5 का संशोधन।

ओडिशा, पंजाब और केरल में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन शिक्षा के लिए शासन, प्रबंधन और नेतृत्व पर अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव में संशोधन

पूर्वोत्तर राज्यों में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के प्रबंधन के मानचित्रण के लिए प्रशिक्षण सामग्री का संयोजन

बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के लिए पठन और प्रशिक्षण सामग्री एकत्रित

ईसीसीई के शासन और प्रबंधन पर कैप्चर के लिए उपकरण

संसाधन व्यक्ति के रूप में शैक्षणिक कार्यक्रमों में आमंत्रित व्याख्यान

15 अक्टूबर, 2020 से 13 नवंबर, 2020 तक बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत (हरियाणा), मानव संसाधन विकास केंद्र के संकाय प्रेरण कार्यक्रम ''शिक्षण–अधिगम पर पुनर्विचारः प्रक्रिया, जुड़ाव और चुनौतियाँ, विषय पर आयोजित 22 अक्टूबर, 2020 को ''व्यक्तिगत–भावनात्मक विकास और परामर्श पर सत्र।

संकाय प्रेरण कार्यक्रम II, 09 दिसंबर, 2020 से 08 जनवरी 2021 तक ''शिक्षा, लचीलापन और शैक्षणिक की परिवर्तनकारी भूमिकाः नए युग में आजीवन अधिगम के विचार की ओर 31 दिसंबर, 2020 को ''भावनात्मक बुद्धि मत्ता और परामर्श'' विषय पर व्याख्यान।

यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) में संसाधन व्यक्ति दिनांक 7 नवंबर 2020 के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक विकास परामर्श में आमंत्रित व्याख्यान।

सार्वजनिक निकायों को परामर्शकारी और अकादमिक सहायता

शिक्षा मंत्रालय

राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए नीति कार्यान्वयन।

यूनिसेफ

योजना अनुमोदन बोर्ड बैठकें (पीएबी)

दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली के कॉलेजों के मनोविज्ञान विभाग,

जम्मू विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

विभिन्न विश्वविद्यालयों का दूरस्थ शिक्षा केंद्र

प्रबंधन अध्ययनों के संकाय,

दिल्ली विश्वविद्यालय;

प्रबंधन संस्थान,

मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मूल्यांकन सेवा केंद्र,

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रकाशकों के मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा,

गैर सरकारी संगठन,

जम्मू और कश्मीर पुलिस अकादमी के विशेषज्ञ।

अन्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान

एम.फिल.पाठ्यक्रम में अध्यापन

शिक्षा पर परिप्रेक्ष्य (सीसी–1) मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

अनुसंधान पद्धति–I (सीसी–3)

अनुसंधान पद्धति–II (सीसी–5)

पीजीडेपा/आईडेपा परियोजना कार्य– 1+1 का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा/आईडेपा पाठ्यक्रम में अध्यापन

दो डॉक्टरेट विद्वानों और एक एम.फिल. विद्वान का पर्यवेक्षण

कश्मीर में स्कूल प्रबंधन पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभावः राज्य और गैर–राज्यीय अभिनेताओं के दृष्टिकोण को समझना, मोहम्मद इलियास (2019)

हरियाणा के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में समावेशी संस्कृति और छात्र विकास के लिए संस्थागत अभिशासन और प्रबंधन के संदर्भ में विकलांग छात्रों के अनुभवों पर अध्ययन, हरलीन कौर (2018 बैच)

'जवाहर नवोदय विद्यालय नीतियों और प्रथाओं के संदर्भ में छात्र विकास पर संस्कृति और शिक्षक–छात्र संबंध का प्रभाव' एम.फिल. प्रतिभागी, यश्मिता, सत्र (2018– 2020)

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों में सदस्यता

राष्ट्रीय मनोविज्ञान अकादमी, नई दिल्ली

भारतीय अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान संघ, चेन्नई

भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सेसी), नई दिल्ली

अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (एआईएईआर), भुवनेश्वर, ओडिशा

भारतीय स्कूल मनोविज्ञान संघ

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कलकत्ता

भारतीय सकारात्मक मनोविज्ञान संघ, नई दिल्ली

प्राची एसोसिएशन ऑफ क्रॉस–कल्चरल साइकोलॉजी, मेरठ

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास नेटवर्क, हैदराबाद

इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली

स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पटियाला

भारतीय क्रीड़ा मनोविज्ञान संघ, पटियाला

आजीवन सदस्य– एनएओपी, आईएएपी, सेसी, एआईएईआर

नीपा के विभिन्न शैक्षणिक निकायों के सदस्य के रूप में योगदान

संचालन समिति के सदस्य

छात्र परामर्श के सदस्य

नीपा की वार्षिक रिपोर्ट का संपादन

एम.फिल./पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन समिति के सदस्य

परियोजना कनिष्ठ सलाहकार अनुवीक्षण समिति

परियोजना सलाहकार अनुवीक्षण समिति

परियोजना कनिष्ठ सलाहकार के साक्षात्कार चयन समिति

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग

सुधांशु भूषण

प्रकाशन

अनुसंधान परियोजना/आलेख/अध्याय

2021 में रूटलेज द्वारा प्रकाशित ''बिहार में उच्च शिक्षा का अभिशासनः शक्ति केंद्रों का प्रभाव'' नामक पुस्तक।

एनआरसीई के तहत कोविड और उच्च शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट तैयार करी।

यूजीसी छात्रवृत्ति योजना मूल्यांकन रिपोर्ट का पर्यवेक्षण और तैयार की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य विषयों पर व्याख्यान और वेबिनार

3 जुलाई, 2020 को अर्थशास्त्र विभाग, डी.जी. वैष्णव कॉलेज द्वारा कोविड–19 का अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास पर प्रभाव पर आयोजित वेबिनार

24 जुलाई, 2020 को नीपा द्वारा कोविड 19 और उच्च शिक्षा पर आयोजित वेबिनार

26 जुलाई, 2020 को शिक्षण अधिगम केन्द्र (टीएलसी), रामानुजन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छात्र संतुष्टि सर्वेक्षणः शिक्षक और शिक्षण अधिगम के निहितार्थ पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

07 अगस्त, 2020 को समाजशास्त्र विभाग, निज़ाम कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा नई शिक्षा नीति–2020 पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

16 अगस्त, 2020 को शिक्षक मंच द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक विकास पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

21 अगस्त, 2020 को सेंट टेरेसा कॉलेज (स्वायत्त), एर्नाकुलम द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः अवसर और चुनौतियां'' पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित

27 अगस्त, 2020 को एसोचैम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

02–03 सितम्बर 2020 को पी.के. रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, झारखंड द्वारा नई शिक्षा नीति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

08 सितम्बर, 2020 को महिला कॉलेज, सिलचर, असम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः उच्च शिक्षा से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

17 अक्टूबर, 2020 को बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत), हरियाणा द्वारा सीबीसीएस और परिणाम आधारित अधिगम पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

17 अक्टूबर, 2020 को बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत), हरियाणा द्वारा एनईपी 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

30 अक्टूबर, 2020 को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020ः शिक्षकों के मुद्दे और चुनौतियां पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

5 दिसंबर, 2020 को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा परिणाम आधारित अधिगम का उपयोग एवं छात्र मूल्यांकन पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली का इतिहास और विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का विकास (सीबीसीएस) के साथ संबंध

8 दिसंबर, 2020 को भारतीय दलित अध्ययन संस्थान द्व ारा भारत में शैक्षिक असमानताएं पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

9 दिसंबर, 2020 को जेएनयू द्वारा शिक्षक शिक्षा शुरुआत में 4जी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

18 दिसंबर, 2020 को बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत द्वारा अकादमिक शिक्षा, लचीलापन और परिवर्तनकारी भूमिकाः नए सामान्य युग में आजीवन सीखने के विचार की ओर पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

23 दिसंबर 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक शिक्षाः परिणाम अधिगम और शैक्षिक सुधार– शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

20 जनवरी, 2021 को यूजीसी–एचआरडीसी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र का विकास और संस्थान के रूप में विश्वविद्यालय/

कालेज–संरचना और कार्य पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

27 जनवरी, 2021 को अर्थमिति विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रो नल्ला गौडेन प्रतिभा व्याख्यान 2020–21 में भागीदारी

10 फरवरी, 2021 को आईक्यूएसी, भारती कॉलेज द्वारा एनईपी के बाद की बारीकियों को समझना पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

17 फरवरी 2021 को भारती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक नेतृत्व में संकाय विकास कार्यक्रम और उच्च शिक्षा का वर्तमान लैंगिक चरण पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

24 फरवरी, 2021 को सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संताल परगना में उच्च शिक्षा पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

26 फरवरी, 2021 को जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान पद्धति पर राष्ट्रीय कार्यशाला में भागीदारी

5 मार्च, 2021 को गोवा विश्वविद्यालय एनईपी 2020 पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

3 अप्रैल 2021 को एनईपी 2020 भारतीय आर्थिक संघ पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

समितियों के सदस्य

29 मार्च 2019 को स्कूल ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया में पीएसएसएसएनएसटीटी योजना के तहत अनुसंधान परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ सदस्य।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र, पीएमएमएमएनएमटीटी योजना

इंटरनेशनल जर्नल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के संपादकीय बोर्ड के सदस्य।

यूजीसी यात्रा अनुदान योजना के मूल्यांकन के सदस्य जो 2020 में संपूर्ण हुई

संपादक, द इंडियन इकनोमिक जर्नल

अकादमिक संपादक, परिप्रेक्ष्य

आरती श्रीवास्तव

प्रकाशन

जेम्स अर्वानिताकिस, सुधांशु भूषण, नयनतारा पोथन और आरती श्रीवास्तव द्वारा संपादित पुस्तक ''टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया' में सह–संपादक, 2020; रूटलेज। आईएसबीएनः 9780367275228

श्रीवास्तव, ए. और लिंड, जेएम (2020). वीमेन इन हायर एजुकेशन रिसर्च. जेम्स अर्वानिताकिस, सुधांशु भूषण, नयनतारा पोथन और आरती श्रीवास्तव द्वारा संपादित पुस्तक ''टीचिंग एंड लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया'' 2020; रूटलेज। आई एस बी एनः 9780367275228

श्रीवास्तव, ए. और घोष, एस. (2021)। फॉर्म टू रिफॉर्मः द शेपिंग ऑफ नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन, विशेष अंक, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: रीइमेजिनिंग टीचर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन; यूनिवर्सिटी न्यूज़, वॉल्यूम। 59 (4), 25–31 जनवरी, 54–57। आईएसएसएनः 0566–2257

श्रीवास्तव, ए. और तनेजा, ए. (2020). इंडिया मस्ट कॉम्बैट हैल्थकारे थ्रेट्स थ्रू रिसर्च, एजुकेशन; 12–18 अप्रैल, द संडे गार्जियन

आगामी / स्वीकृत

श्रीवास्तव, ए. और तनेजा, ए. (2021)। स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एंड डेवलपमेंट साउथ एशियाः ए कम्पेरेटिव एनालिसिस, इन डेवलपमेंट गवर्नेंस एंड रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, स्प्रिंगर।

अरोड़ा, ए. और श्रीवास्तव, ए. (2021). रीइमेजिन इंटरनेशनलाइज़ेशनः पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडिया इन थे इंटरकनेक्टेड ग्लोबल आर्डर; सीआईएसई हायर एजुकेशन एसआईजी जर्नल ऑफ कम्पेरेटिव एंड इंटरनेशनल हायर एजुकेशन

2020–21 के दौरान सेमिनारों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी

14 जुलाई, 2020 सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

14 सितंबर, 2020, को अमेरिकी दूतावास कार्यक्रम (अमेरिकी दूतावास, शिकागो विश्वविद्यालय और एआईयू के सहयोग) उच्च शिक्षा श्रृंखला का भविष्य पर आयोजित कार्यक्रम भागीदारी।

सितंबर 14, 2020 को शास्त्री इंडो–कैनेडियन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः अवसर, चुनौतियाँ और आगे की राह पर वेबिनार में भागीदारी

24 सितंबर, 2020 को नीपा पैनल चर्चा में भागीदारी, (वीरा गुप्ता)

11 नवम्बर, 2020 को डब्ल्यूआईसीसीआई वेबिनार के शुभारम्भ में भागीदारी

20 नवम्बर, 2020 सीपीएचआरई, नीपा द्वारा 'लचीले अधिगम के राहः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

20 नवंबर, 2020 को अमेरिकी दूतावास में एनईपी 2020 और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया

12 जनवरी, 2021 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट पर सीपीआरएचई, नीपा के वेबिनार में भागीदारी

17–19 फरवरी, 2021 तक विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासकों और कॉलेजों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व पर कार्यशाला सह–अभिविन्यास कार्यक्रम में 19 फ़रवरी, 2021 को सत्र में भागीदारी

8 मार्च, 2021 को सामाजिक कार्य विभाग (डीएसडब्ल्यू) (सामाजिक कार्य दिल्ली स्कूल) दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव पर आयोजित वैश्विक संकट और महिलाओं एवं उनके अस्तित्व पर सेमिनार में भागीदारी

8 मार्च, 2021 को शास्त्री इंडो–कैनेडियन इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा और अनुसंधान में महिलाओं पर काँच की छत तोड़ना, सीखे गये सबक और बदलाव का रास्ता बनाना पर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस विशेष वेबिनार में भागीदारी

18 मार्च 2021 को उप–सहारा अफ्रीका में सहायता और वित्तपोषण शिक्षा के लिए सामान्य रूप में व्यापार से परे (आईजेईडी वॉल्यूम 78, अक्टूबर 2020, 102247), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशनल डवलपमेंट के वेबिनार में भागीदारी

31 मार्च, 2021को डब्ल्यूआईसीसीआई वेबिनार में भागीदारी

कौशल पर अध्याय जामिया सम्मेलन, डेट

पत्र प्रस्तुति

01–05 मई 2020 को कोविड संकट वेबिनार पर प्रस्तुति मंजू गुप्ता

25 मई 2020 को जीएलए पर वेबिनार पर प्रस्तुति

10 जून 2020 को एआरएसडी एफडीपी में नृवंशविज्ञान. पर एक ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

18 जून 2020 को स्कूल नेतृत्व पर डाइट वाराणसी में एक ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

28 मई 2020 को नॉर्डिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार पर प्रस्तुति

16 अगस्त 2020 को शिक्षा विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नीति शिक्षा 2020: भारतीय शिक्षा में सुधार की दिशा में एक कदम पर एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित अध्यक्ष

7 अगस्त, 2020 को नेशनल एपेक्स चैंबर (पी–एच.डी. चैंबर) द्वारा आयोजित एनईपी, 2020: सार्वभौमिकरण, वैश्वीकरण और समावेश पर ई–बैठक में आमंत्रित अध्यक्ष

24 अगस्त, 2020 को यूजीसी–एचआरडीसी, डीएवीवी, इंदौर में शिक्षक शिक्षा में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम: अधिगम के परिणाम और शैक्षिक सुधार–शिक्षाशास्त्र, आकलन और गुणवत्ता आश्वासन, एनईपी, 2020 और शिक्षक शिक्षा में आमंत्रित अध्यक्ष

18 अगस्त, 2020 को पुडुचेरी विश्वविद्यालय में हुए गांधी और नेतृत्व पर आमंत्रित अध्यक्ष

24 सितंबर, 2020 को सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन फॉर वीमेन, गुंटूर द्वारा आयोजित एनईपी 2020: भारतीय शिक्षा में बदलाव पर वेबिनार पर आमंत्रित अध्यक्ष

3 अक्टूबर, 2020 को भारतीय शिक्षक फोरम (एफआईटीई) द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत की ओर एक राह के रूप शिक्षा पर राष्ट्रीय वेब सम्मेलन में आमंत्रित अध्यक्ष

7 अक्टूबर, 2020 को जामिया एचआरडीसी संकाय प्रेरण कार्यक्रम में चुनौतियां और उच्च शिक्षा की संभावनाएँ पर प्रस्तुति

12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2020 तक एसजीटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम द्वारा आयोजित एसजीटी विश्वविद्यालय में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन एक सप्ताहिक संकाय विकास पाठ्यक्रम में 17 अक्टूबर, 2020 को उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए चुनौतियों पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

15 अक्टूबर, 2020 को एचआरडीसी, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, सोनीपत, के संकाय प्रेरण कार्यक्रम, पर प्रस्तुति

24 अक्टूबर 2020 को एसजीटी विश्वविद्यालय, गुरुग्राम में उच्च शिक्षा में महिलाएं: चुनौतियां और अवसर, पर एक ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

19 अक्टूबर 2020 को यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद द्वारा ''संकाय प्रेरण कार्यक्रम'' में ''संस्थागत योजना और विकास'' पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

20 अक्टूबर, 2020 को यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, द्वारा आयोजित समाज में उच्च शिक्षा की भूमिका: गुणवत्ता और प्रासंगिकता के संकाय प्रेरण कार्यक्रम पर समापन भाषण

29 अक्टूबर, 2020 को एसजीटी यूनिवर्सिटी, गुरूग्राम में उच्च शिक्षा में महिलाएं: चुनौतियां और अवसर पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

28 अक्टूबर, 2020 को यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के संकाय प्रेरण कार्यक्रम पर प्रस्तुति

23 नवंबर, 2020 को एसजीटी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए चुनौतियां पर ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत किया

14 दिसंबर, 2020 को फूल सिंह विश्वविद्यालय, सोनीपत में एफआईपी में शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा पर आमंत्रित व्याख्यान प्रस्तुत किया

21 दिसम्बर, 2020 को जामिया एचआरडीसी द्वारा उच्च शिक्षा में नेतृत्व पर प्रस्तुति

24 दिसंबर, 2020 को कश्मीर कॉलेज में कौशल पर प्रस्तुति

5 जनवरी, 2021 को एमएएनयूयू, हैदराबाद में आईडीपी पर प्रस्तुति

10 फरवरी, 2021 को राजस्थान विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टाफ कॉलेज में एनईपी पर अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति

11 फरवरी, 2021 को एचआरडीसी–गौहाटी यूनिवर्सिटी के संकाय प्रेरण कार्यक्रम में एनईपी की मुख्य विशेषताएं के लिए संसाधन व्यक्ति (ऑनलाइन मोड में)

23 फरवरी, 2021 को एचआरडीसी, गौहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षा पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में संसाधन व्यक्ति

8 मार्च, 2021 को गंगा देवी महिला महाविद्यालय, पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रित अध्यक्ष

25–27 मार्च, 2021 को बड़ौदा में को आईयूसीटीई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ऑनलाइन) पर उच्च शिक्षा में शिक्षक मचानः आभासी संसाधनों का भंडार पर प्रमुख वक्ता

30 मार्च 2021 को ''शिक्षक शिक्षाः अभिशासन, विनियमन और गुणवत्ता आश्वासन'' पर लेखक वेबिनारः हस्तपुस्तिका प्रस्तुत किया गया।

विभागीय/एनआरसीई कार्यक्रम आयोजित

18–19 जून, 2020 को एनआरसीई कार्यशाला

22–23 जून, 2020 को एनआरसीई कार्यशाला

25–26 जून, 2020 को एनआरसीई कार्यशाला

18–19 अगस्त, 2020 को एनआरसीई कार्यशाला

20–21 अगस्त, 2020 को एनआरसीई कार्यशालाएं

24–25 अगस्त, 2020 को एनआरसीई कार्यशालाएं

5 सितंबर, 2020 को एनआरसीई शिक्षक दिवस वेबिनार

यूजीसी फैलोशिप का मूल्यांकनः बीएसआर और एमेरिटस योजनाएं

6–7 अक्टूबर, 2020 को एनआरसीई कार्यशाला

8–9 अक्टूबर, 2020 को एनआरसीई कार्यशालाएं

10 दिसंबर, 2020 को एनआरसीई परिचयात्मक वेबिनार

उच्च शिक्षा में शिक्षा के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार 7 जनवरी, 2021

उच्च शिक्षा में जीवन विज्ञान के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 14 जनवरी, 2021

उच्च शिक्षा में समाजशास्त्र के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 28 जनवरी, 2021

उच्च शिक्षा में अर्थशास्त्र के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 4 फरवरी, 2021।

उच्च शिक्षा में रसायन विज्ञान के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार 11 फरवरी, 2021

उच्च शिक्षा में राजनीति विज्ञान के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार 18 फरवरी, 2021

उच्च शिक्षा में प्रबंधन के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 3 मार्च 2021

उच्च शिक्षा में भौतिकी के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 12 मार्च 2021।

उच्च शिक्षा में इतिहास के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार, 18 मार्च 2021।

उच्च शिक्षा में गणित के शिक्षकों के लिए एनआरसीई संकाय संवर्धन वेबिनार 24 मार्च 2021।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संपादन

एम.फिल./पी–एच.डी. के लिए किए गए पाठ्यक्रम

अनिवार्य पाठ्यक्रम (सीसी–2): भारत में शिक्षा

ओसी–12: वैश्वीकरण और शिक्षा

ओसी 11

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, नीपा के समन्वयक

एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश के लिए परीक्षा समिति (नीपा)

एम.फिल./पी–एच.डी. परीक्षण (नीपा) के लिए मूल्यांकन समिति

एनएएसी की नीपा कोर कमेटी के सदस्य

कुलपति बैठक समन्वयक

लीप समन्वयक

सामाजिक चिंतन पुस्तक के समीक्षा संपादक

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में लैंगिक मुद्दे; वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य

25 अगस्त, 2018 से जेआरएनआर विद्यापीठ, उदयपुर में अतिथि प्रोफेसर

नेहु कोर्ट सदस्य

केन्द्रीय विद्यालय संगठन सलाहकार परिषद सदस्य, जून 2019

21 जून, 2019 से नीपा पर कम्यूनिकेशन एंड आउटरीच के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रभावी प्रचार टीम के अध्यक्ष

14 जुलाई, 2019 को एनसीटीई अतिथि दल के सदस्य के रूप में नियुक्ति

स्ट्राइड के लिए समीक्षक

स्पार्क के लिए समीक्षक।

नीपा पूर्व छात्र समिति के संयोजक

मोनिका बिष्ट की पी–एच.डी. शोध के समीक्षक

डीएसएस डब्ल्यू की प्रशिक्षुता (रोशन और अखिल)

शिक्षा का अधिकार पर पुस्तक प्रस्ताव, रूटलेज, अक्टूबर, 2020 समीक्षित

3 दिसंबर, 2020 को नेहू न्यायालय बैठक

स्वीडन की पी–एच.डी. के लिए परीक्षक, 16 दिसंबर, 2020

6 जनवरी 2021 से प्रभावी तीन साल तक, की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध डिवीजन के एनसीईआरटी विभाग सलाहकार बोर्ड के सदस्य

जामिया पाठ्यक्रमः अर्थशास्त्र, वाणिज्य और जनसंख्या अध्ययन, बी.एड. पाठ्यक्रम का संशोधन, 15 जनवरी, 2021

अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना और पूर्व छात्र एकक स्थापित करने के लिए यूजीसी को पत्र दिनांकित 13 जनवरी, 2020

19 जनवरी, 2021 से शिक्षा विभाग, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सह–मार्गदर्शक

29 जनवरी, 2021 से एनईपी–2020 के कार्यान्वयन के बारे में एएमयू की सलाहकार समिति सदस्य

22 जनवरी, 2021 से नीपा में राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क समिति के सचिवालय सदस्य ।

एआरयू परियोजना

17 फरवरी, 2021 को एनसीएफ बैठक

19 फ़रवरी, 2021 को दयालबाग अध्ययन बोर्ड की बैठक

एचईएफ–2020–0105: भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का वित्त पोषणः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक खोजपूर्ण अध्ययन, हायर एजुकेशन फॉर द फ्यूचर जर्नल फरवरी 2021 में लेख के समीक्षक

साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य–10/03/2021 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) में आयोजित सलाहकार (अकादमिक प्रशासन और लेखा परीक्षा और आईसीटी) के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू

नीपा अध्ययन बोर्ड के सदस्य, 19 मार्च 2021

नीपा शैक्षणिक परिषद के सदस्य, 23 मार्च 2021

नीपा प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, 26 मार्च, 2021

एनसीएफ बैठक, 25 मार्च, 2021

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

निम्नलिखित निकायों के आजीवन सदस्य

प्रौढ़ शिक्षा संगठन, आईटीओ, नई दिल्ली (1999)

भारतीय ज्ञानपीठ परिवार, नई दिल्ली (1999)

भारतीय आर्थिक संघ (2004)

इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (1998)

नेशनल बुक ट्रस्ट (1998)

यूपी भारत स्काउट एंड गाइड्स (2003)

थियोसोफिकल सोसायटी, वाराणसी (2004)

सीईएसआई, नई दिल्ली (2010)

अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (2009)

इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन (2015)

भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी (2016)

भारत–अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अल्पकालिक सदस्यता, मार्च, 2021 से आगे

अन्य सूचना

पी–एच.डी. पर्यवेक्षण

अ. पी–एच.डी. – अपराजित गन्तायत

ब. अर्चना कुमारी

एमफिल पर्यवेक्षण

अ. अर्चना कुमारी (पुरुस्कृत)

ब. बबीता बलोदी

पीजीडेपा पर्यवेक्षण

अ. बिथिका सैकिया

आईडेपा पर्यवेक्षण

अ. अमीनाथ साध

नीरू स्नेही

प्रकाशन

शोध पत्र/लेख/नोट्स

एन.वी. वर्गीस और सायंतन मंडल, (संपा.) 2020. उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम और नई प्रौद्योगिकियां में 'स्नातक स्तर पर शिक्षण अधिगम' पर अध्याय, स्प्रिंगरः नीपा पीपी. 179

अजीत मंडल और नीरू स्नेही, (संपा.) (आगामी) भारत में महिला शिक्षा की गतिशीलता में ''विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में महिलाएं'' पर अध्याय।

अनुसंधान रिपोर्ट

डॉ. आरती श्रीवास्तव, डॉ. नीरू स्नेही और डॉ. संगीता अंगोम द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 'यूजीसी फैलोशिप और छात्रवृत्ति योजना मूल्यांकन' पर अध्ययन रिपोर्ट

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भागीदारी

प्रस्तुति/व्याख्यान–वेबिनार

17 से 22 अगस्त 2020 तक एस.सी.एम.एस. प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विभाग, अलुवा, कोचीन द्वारा आयोजित एआईसीटीई द्वारा प्रायोजित लघु अवधि ट्रेनिंग प्रोग्राम 'आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन टीचिंग 'फेज 1: विषयः परिणाम आधारित शिक्षा' के एक भाग के रूप में 'किर्कपैट्रिक ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल' और 'कंस्ट्रक्टिव एलाइनमेंट' शीर्षक वाले सत्रों में दो–दो व्याख्यान दिए

19 नवंबर, 2020 को उन्नत भारत अभियान, एस.सी.एम.एस. प्रौद्योगिकी और प्रबंधन स्कूल, कोचीन द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'', वेबिनार पर व्याख्यान

16–21 नवंबर 2020 तक चल रहे एआईसीटीई प्रायोजित एसटीटीपी के हिस्से के रूप में शिक्षण में परिणाम आधारित अधिगम और गुणवत्ता आश्वासन – चरण 3: विषय– शिक्षण में गुणवत्ता आश्वासन पर 21 नवंबर, 2020 को 'शैक्षणिक गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना' पर व्याख्यान दिया

यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, गोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 22 सितम्बर, 2020 से 27 अक्टूबर, 2020 तक चल रहे 107 ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम में भारत में उच्च शिक्षा पर 4 व्याख्यान दिए

यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, गोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 17 नवंबर, 2020 से 23 दिसम्बर, 2020 तक चल रहे 108 ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम में भारत में उच्च शिक्षा मॉड्यूल पर 4 व्याख्यान दिए

11 सितंबर से 10 अक्टूबर, 2020 के दौरान मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू), रायपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम (गुरुदक्षता) में एक व्याख्यान दिया

01 फरवरी से 05 मार्च, 2021 के दौरान मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू), रायपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन संकाय प्रेरण कार्यक्रम (गुरुदक्षता) में एक व्याख्यान दिया ।

21–25 सितंबर 2020 के दौरान शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विभाग, नीपा द्वारा आयोजित शिक्षा में नीति निर्माण संरचना और प्रक्रिया पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम के एक सत्र में भागीदारी

08–12 मार्च, 2021 के दौरान नीपा में ऑनलाइन आयोजित ''स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानता पर कार्यशालाः चुनौतियां और अवसर'' में 'छाया शिक्षा में लैंगिक समानता' पर व्याख्यान दिया

08–12 मार्च, 2021 के दौरान नीपा में ऑनलाइन आयोजित ''स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियां और अवसर'' पर कार्यशाला में ''राज्यों के अनुभवः दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब' पर एक सत्र की अध्यक्षता की

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों में भागीदारी

14 मई, 2020, क़तर फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'कोविड–19 के बाद के युग में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरणः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' विषय पर वेबिनार में भागीदारी

23 मई, 2020 को स्कूल शिक्षा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ द्वारा ऑनलाइन आयोजित ''एसटीईएम में महिलाएं'' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

3 जून 2020 को स्कूल शिक्षा, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ द्वारा आयोजित ''संदर्भ–आधारित शिक्षाशास्त्र और उच्च शिक्षा में आकलन'' पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

06 और 07 अगस्त, 2020 के दौरान कतर फाउंडेशन की सहभागिता से ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू), भारत द्वारा आयोजित 'विश्वविद्यालय की पुनर्कल्पना और परिवर्तनः कोविड–19 व्यवधान के दौरान और उससे परे विचारों का संगम' विषय पर आयोजित वैश्विक आभासी सम्मेलन में भागीदारी

28 अगस्त 2020 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा द्वारा आयोजित ''शिक्षा का भविष्य – एनईपी 2020 को लागू करना'', विषय पर प्रख्यात शिक्षक संवादः नेतृत्व के लिए एजेंडा सेटिंग में भागीदारी

3 सितंबर 2020 को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर द्वारा आयोजित ''नई शिक्षा नीतिः एक मूल्यांकन'' पर एकदिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

11 नवंबर, 2020 को शिक्षा विभाग, ए.एम. स्कूल ऑफ एजुकेशनल साइंसेज, असम विश्वविद्यालय, सिलचर, असम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर आयोजित 'एनईपी 2020 उच्च शिक्षा के लिए रोड मैपः संभावनाएं और बाधाएं' राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

10 सितंबर 2020, सीईएसआई इंडिया उच्च शिक्षा और भारत में महामारी 22 सितंबर 2020 को सीजीएचई वेबिनार शैक्षिक सुधारों की राजनीतिक जांचः एनईपी 2020, में भागीदारी

10 नवंबर 2020 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ''कोविड–19 से निपटने में समाज के लिए विज्ञान" पर यूनेस्को आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

20 नवंबर, 2020 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी), यूनेस्को, पेरिस के साथ सह–मेजबानी करके सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन (सीपीआरएचई), नीपा द्वारा आयोजित

''लचीले अधिगम के राहः चुनौतियां और भारत में उच्च शिक्षा के अवसर'' वेबिनार में भागीदारी

2–6 नवंबर 2020, को शैक्षणिक विज्ञान स्कूल, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

15 दिसंबर 2020, को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार नीति संवाद वेबिनार में भागीदारी

24 जुलाई, 2020, डीएचपीई, नीपा द्वारा आयोजित ''कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा'' पर वेबिनार में भागीदारी

11 जुलाई, 2020 को ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में आयोजित सार्वजनिक भलाई के रूप में शिक्षाः सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बाधाओं को तोड़ना और पाटना विषय पर उच्च शिक्षा नेतृत्व के संवाद संगोष्ठी में भागीदारी

16 जुलाई, 2020 को भारत प्रवासन केन्द्र (आईसीएम), सुषमा स्वराज भवन, रिज़ाल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता के नए दृश्य पर आभासी चर्चा में भागीदारी

14 जुलाई, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण' पर वेबिनार में भागीदारी

22 जून, 2020 को एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए शिक्षा संसाधनों की पहचान पर वर्चुअल कार्यशाला में भागीदारी

25–26 जून, 2020, एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए समाजशास्त्र विषय संसाधनों के मिलान पर आभासी कार्यशाला में भाग लिया

1 जून, 2020 को अकादमिक जर्नल, सीओडीएटीए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, में प्रकाशन के लिए एक शोध लेख लिखने में भागीदारी

अकादमिक सत्यनिष्ठा, कॉपीराइट, साहित्यिक चोरी मुक्त अकादमिक कार्य सुनिश्चित करने पर 02 जुलाई 2020 को नीपा द्वारा आयोजित व्याख्यान में भागीदारी

19–20 मार्च, 2021 को एचएसएस आईआईटी, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार और नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर), भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित ''एसटीईएम में मुख्य धाराः नीतियां और व्यवहार'' पर पैनल चर्चा में भागीदारी

21 सितंबर 2020 को सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इन हायर एजुकेशन, नीपा द्वारा आयोजित निजी उच्च शिक्षा पर आईएचईआर 2021 की पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक में भागीदारी

11 नवंबर 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा दिवस) पर प्रो. ध्रुव रैना द्वारा इतिहास के लेंस और विज्ञान के दर्शन के माध्यम से उच्च शिक्षा के भविष्य? पर आयोजित 11वें मौलाना आजाद स्मृति व्यख्यान में भागीदारी

07 जनवरी, 2021 को एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में शिक्षा अनुशासन शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार में भागीदारी

उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग की विभाग सलाहकार समिति में भागीदारी

17–19 फरवरी 2021, को नीपा में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व पर तीन दिवसीय कार्यशाला सह–अभिविन्यास कार्यक्रम में भागीदारी

18–19 मार्च, 2021 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की सलाहकारी बैठक में भागीदारी

इनके अलावा नीपा द्वारा संकाय और शोध छात्रों के वार्षिक और सहकर्मी और संकाय समीक्षा सेमिनारों एवं अन्य सेमिनारों/बैठकों में भागीदारी

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

समकालीन शिक्षा संवाद के लिए एक पांडुलिपि सीईडी–2019–0218.आरवी1 की समीक्षा की

सीआईईटी पत्रिका, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सीआईईटी–एनसीईआरटी. के लिए पांडुलिपि की समीक्षा की

नीपा द्वारा 'एनईपी 2020: कार्यान्वयन रणनीतियां' में योगदान दिया

पर्यवेक्षण और मूल्यांकन

मोहम्मद रौफ भट के 'जम्मू और कश्मीर में उच्च शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं और संभावनाएं– जिला कुलगाम का अध्ययन' शीर्षक एम.फिल. शोध प्रबंध कार्य का मूल्यांकन किया।

खीकुओनुओ पिएन्यु के शीर्षक ''कोहिमा, नागालैंड में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अध्ययन'' पीजीडेपा शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया।

मोस ओलुकुनले एडियो के ''नाइजीरियाई माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रबंधन की चुनौतियाँ: शिक्षा जिला IV, लागोस राज्य, नाइजीरिया का केस अध्ययन'' शोध प्रबंध कार्य का पर्यवेक्षण किया।

सृष्टि भाटिया के शीर्षक ''अकादमिक स्वतंत्रता की रूपरेखा की खोज: सामाजिक विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट अनुसंधान का अध्ययन'' एम.फिल शोध प्रबंध का पर्यवेक्षण किया।

सुश्री हर्षिता शर्मा के ''भारत में निजी शिक्षण का मताधिकार'' शीर्षक पीएचडी शोध कार्य का पर्यवेक्षण किया

मोहम्मद रौफ भाट के शीर्षक ''जम्मू–कश्मीर में स्कूली शिक्षा का विकास में निजी स्कूलों की भूमिका को समझना: जिला कुलगाम का अध्ययन" पी–एच.डी. शोध कार्य का पर्यवेक्षण किया

पाठ्यक्रम समन्वय

संयोजक के रूप में पाठ्यक्रम 211: आईडेपा में अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी, फरवरी 2020 – अप्रैल 2020 का संचालन किया

संयोजक के रूप में पाठ्यक्रम 902: भारतीय शिक्षा– पीजीडेपा में एक परिप्रेक्ष्य, सितंबर 2020 का संचालन किया

शिक्षण

आईडेपा में पाठ्यक्रम 212: अनुसंधान पद्धति और सांख्यिकी के संचालन में भागीदारी

पीजीडेपा में पाठ्यक्रम 902: भारतीय शिक्षा– एक परिप्रेक्ष्य के संचालन में भागीदारी

पीजीडेपा में पाठ्यक्रम 905: अनुसंधान के तरीके और सांख्यिकी के संचालन में भागीदारी

अन्य गतिविधियां

नीपा में वित्त अधिकारी पद के लिए आवेदनों की जांच हेतु जाँच कमेटी की सदस्य

स्थायी खरीद समिति के सदस्य (2.5 लाख से कम)

10 जून को आयोजित (ऑफलाइन) एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश–जाँच समिति की बैठक

जून 2020–21, नीपा एम.फिल./पी–एच.डी. में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के दौरान 'निरीक्षण/पर्यवेक्षण समिति' की सदस्य

जून 2020–21, नीपा एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन के दौरान 'मूल्यांकन समिति' की सदस्य

सदस्यता

आजीवन सदस्य, भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी(सीईएसआई)

आजीवन सदस्य, भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी

संगीता अंगोम

प्रकाशन

शोध पत्र/संपादित वाल्यूम/पुस्तक में अध्याय के रूप में लेख

एम. अमरजीत सिंह और एच. शुखदेव शर्मा, द्वारा संपादित ''माइग्रेशन एंड एथनिकिटी इन नॉर्थईस्ट इंडिया'' नामक पुस्तक में ''पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा पर पुनर्विचार'' (अध्याय), पीपी. 136–152 शिप्रा

संदीप कुमार और एम. राजेंद्रन, 2020 द्वारा संपादित ''एंथोलॉजी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन'' नामक पुस्तक में ''भारत में निजी विश्वविद्यालयः प्रमुख निष्कर्षों पर प्रतिबिंब'' (अध्याय), वी.एल. मीडिया सॉल्यूशंस, पीपी 91–108

अध्याय 6 : इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट प्लान्स इन हायर एजुकेशन, ''एनईपी 2020, कार्यान्वयन रणनीति में, नीपा प्रकाशन 2020, पृ. 121–126 (सुधांशु भूषण, आरती श्रीवास्तव, नीरू स्नेही, मनीषा प्रियम तथा ए. मैथ्यू के साथ वर्किंग पेपर में योगदान)

भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2021 में इंस्टीट्यूशनल ऑटोनामी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया चैप्टर : प्राइवेट हायर एजुकेशन, संव एन.वी. वर्गीज तथा जिणुशा पाणिग्रही, राउटलेज (आगामी)।

ए सेंचुरियन कॉलेज केस स्टडी : सेंट जोसेफ कॉलेज, दार्जिलिंग, पुस्तक में अध्याय : इंस्टीट्यूशनल बायोग्राफीज : द सेंटेनेरियन, सं. आरती श्रीवास्तव, राउटलेज (आगीमी)।

संगोष्ठियों और सम्मेलनों में प्रस्तुत पत्र

13–14 नवंबर, 2020 को सीएचईआर–हांगकांग 2020 द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा अनुसंधान–हांगकांग 2020 के लिए आभासी सम्मेलन में भागीदारी और ''भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण अधिगम और अनुसंधान पर महामारी का प्रभावः शिक्षकों की धारणा'' शीर्षक से पत्र प्रस्तुत किया।

25–26 फरवरी, 2021 को भारतीय मानव सुरक्षा और शासन संस्थान (आईआईएचएसजी), दिल्ली द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आभासी) में भागीदारी और ''रिथिंकिंग हायर एजुकेशनः जेंडर इक्विटी कंसर्न'' शीर्षक से पत्र प्रस्तुत किया।

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और बैठकों में भागीदारी

19–20 मार्च 2021 को मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित (आभासी सम्मेलन) ''एसटीईएम उच्च शिक्षा में मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए रोडमैप'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी।

08–12 मार्च, 2021 को नीपा द्वारा आयोजित ''स्कूली शिक्षा में लैंगिक समानताः चुनौतियां और अवसर'' पर पांच दिवसीय कार्यशाला में भागीदारी इस कार्यशाला में ''राज्यों के अनुभवः त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड'' पर एक सत्र की अध्यक्षता की।

21 सितंबर, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित निजी उच्च शिक्षा पर पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक, आईएचईआर 2020 में भागीदारी

17 दिसंबर, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित निजी उच्च शिक्षा पर दूसरी सहकर्मी समीक्षा बैठक, आईएचईआर 2020 में भागीदारी

12 जनवरी, 2021 को द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, संपादकों की अंतर्दृष्टि पर आयोजित परिसर कार्यशाला अनुसंधान अकादमी में भागीदारी

14–15 अक्टूबर 2020 को राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार ''इंडिया इन द इंडो–पैसिफिकः इंटरेस्ट्स, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स'' में भागीदारी

5 जून से 15 अगस्त, 2020 तक आईसीएसआई इंटरनेशनल चैंबर फॉर सर्विसेज़ इंडस्ट्री द्वारा 'शिक्षा को प्रासंगिक बनाना' पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार श्रृंखला में भाग लिया

06–07 अगस्त, 2020 के दौरान ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, भारत द्वारा कतर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित ''विश्वविद्यालय की पुनर्कल्पना और परिवर्तनः कोविड 19 व्यवधान के दौरान और उसके बाद के विचारों का संगम विषय पर वैश्विक आभासी सम्मेलन में भागीदारी

03 जून, 2020 को स्कूल शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा आयोजित ''संदर्भ आधारित शिक्षाशास्त्र और उच्च शिक्षा में मूल्यांकन'' पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

23 मई, 2020 को स्कूल शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा द्वारा आयोजित ''एसटीईएम में महिलाएं'' पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

09 जून 2020 को डॉ. जाकिर हुसैन पुस्तकालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अकादमिक प्रकाशन और अनुसंधान प्रभावशीलता बढ़ाने पर एक दिवसीय वेबिनार में भागीदारी

29 मई, 2020 को आईसीएसआई, भारत द्वारा आयोजित ''वैश्विक उच्च शिक्षा कौशल–प्रौद्योगिकी–अवसर पूर्वोत्तर भारत और आसियान पर विशेष केन्द्रित'' पर आभासी सम्मेलन में भागीदारी

14 मई, 2020 को जियो इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित ''कोविड–19 के बाद उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरणः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर वेबिनार में भागीदारी

27 अगस्त 2020 को बंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (सह–विषयः नई शिक्षा नीति डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी एकीकरण) के मुख्य आकर्षण और कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी

20–21 अगस्त, 2020 को शिक्षा विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित 'एनईपी 2020ः आगे का राह' पर (आभासी) राष्ट्रीय संगोष्ठी में भागीदारी

19 अगस्त, 2020 को शैक्षिक नीति, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एनईपी–2020ः संभावनाएं, चुनौतियाँ और रास्ते पर राष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में भागीदारी

18–19 मार्च, 2021 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की सलाहकारी बैठक में भागीदारी

3 मार्च 2021 को एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में प्रबंधन अनुशासन शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार में भागीदारी

14 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में जीवन विज्ञान शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार में भाग लिया

15 दिसंबर, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर नीति संवाद वेबिनार में भागीदारी

10 दिसंबर, 2020 को रिसर्च इंटरेस्ट ग्रुप (आरआईजी)–3 हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन सीईएसआई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ''भविष्य के नागरिकों को शिक्षित करनाः 1920 और 1930 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में अनिवार्य शिक्षा का परिचय'' शीर्षक से स्थापना दिवस व्याख्यान व्याख्यान में भागीदारी

20 नवंबर, 2020 को सीपीआरएचई/नीपा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी), यूनेस्को, पेरिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''लचीले अधिगम के रास्तेः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर वेबिनार में भागीदारी

5 सितंबर, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित ''एनईपी–2020 के आलोक में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की क्षमता विकास'' वेबिनार में भागीदारी

3 सितंबर, 2020 को रिसर्च इंटरेस्ट ग्रुप (आरआईजी)–5 पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, सेसी द्वारा आयोजित ''शैक्षिक सुधारों की राजनीतिक जांच एनईपी 2020'' पर वेबिनार श्रृंखला में भाग लिया ।

20 अगस्त, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित प्रोफेसर ए.के. शिव कुमार द्वारा शिक्षा और सामाजिक अवसरः अंतराल को पाटना पर 14वें नीपा स्थापना दिवस व्याख्यान में भागीदारी

8 अगस्त, 2020 को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई, नीपा द्वारा आयोजित ''भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन भारत में? शाला सिद्वी से अन्तर्दृष्टि, पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

24 जुलाई, 2020 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित 'कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा' पर वेबिनार में भागीदारी

14 जुलाई, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा और यूजीसी द्वारा संयुक्त रूप से ''शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना'' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

अन्य शैक्षणिक गतिविधियां

अनुसंधान अध्ययन (जारी और पूर्ण)

अक्टूबर 2020 में सर्वेक्षण टीम के सदस्य के रूप में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, द्वारा आयोजित यूजीसी फैलोशिप और छात्रवृत्ति मूल्यांकन पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को पूरा किया और प्रस्तुत किया

शोध अध्ययन शीर्षक, ''भारतीय स्नातक महाविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाएं और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर इसका प्रभाव'', नवंबर 2018 में शुरू हुआ – जारी

पी–एच.डी. और एम.फिल. छात्र का पर्यवेक्षण

पी–एच.डी. विद्वान सुश्री फातिमा ज़राह के पी–एच.डी. शोध कार्य शीर्षक ''लद्दाख में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण के लिए इसकी संभावना'' का पर्यवेक्षण किया।

सुश्री गोड्डम मिहिरा (2019–21 बैच) के एम.फिल. शोध प्रबंध शीर्षक, ''उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान और मानविकी पाठ्यक्रम 2021'' का पर्यवेक्षण किया।

नीपा प्रशिक्षुओं का पर्यवेक्षण

सातवीं–पीजीडेपा प्रतिभागी श्री इंद्रजीत गाम द्वारा आयोजित, ''शिक्षण सीखने प्रक्रिया को बढ़ाने में आईसीटी की स्थितिः लखीमपुर जिले, असम में सरकारी और निजी स्कूलों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन'' शीर्षक के शोध प्रबंध कार्य का पर्यवेक्षण किया।

आईडेपा–37 प्रतिभागी एडसन मापुंडा द्वारा आयोजित ''माध्यमिक विद्यालय प्रमुखों पर प्रेरण प्रशिक्षण का आकलनः डोडोमा शहर का अध्ययन'' पर निबंध कार्य का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया।

पाठ्यक्रम समन्वयक

आईडेपा पाठ्यक्रम 201–विषयगत संगोष्ठी

पीजीडेपा पाठ्यक्रम 905–अनुसंधान पद्धति, परियोजना कार्य और लेखन

पाठ्यक्रमों का संचालन

आईडेपा कार्यक्रम

आईडेपा पाठ्यक्रम 201–विषयगत संगोष्ठी

आईडेपा पाठ्यक्रम 212–अनुसंधान पद्धति तथा सांख्यिकी

पीजीडेपा कार्यक्रम

पीजीडेपा पाठ्यक्रम 906: प्रतिभागियों की संगोष्ठी

पीजीडेपा पाठ्यक्रम 905 अनुसंधान पद्धति परियोजना कार्य और लेखन

पीजीडेपा पाठ्यक्रम 902 भारतीय शिक्षाः एक परिप्रेक्ष्य

अन्य विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के संचालन में शामिल

संसाधन व्यक्ति के रूप में सितंबर 2020, दिसंबर 2020, और मार्च 2021 के दौरान यूजीसी–एचआरडीसी, गोवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन अलग–अलग फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के लिए ''उच्च शिक्षा और इसके पारिस्थितिकी तंत्र'' पर पाठ्यक्रम का संचालन किया।

नीपा एनईपी दस्तावेज़ के विकास

''उच्च शिक्षा में संस्थागत विकास योजनाएं'' विषयगत समूह के सदस्य के रूप में एनईपी 2020: नीपा की कार्यान्वयन रणनीतियां का विकास

नीपा समिति के सदस्य

नीपा परीक्षा समिति के सदस्य

कनिष्ठ परियोजना अध्येता, नीपा के लिए जांच समिति के सदस्य

परियोजना ग्राफिक डिजाइनर एवं परियोजना सलाहकार के पद हेतु चयन समिति के सदस्य

परियोजना वरिष्ठ सलाहकार के पदों के लिए चयन समिति के सदस्य

अध्ययन बोर्ड के सदस्य

अकादमिक परिषद के सदस्य

एनईपी 2020: कार्यान्वयन रणनीतियाँ के विकास के लिए विषयगत समूह के सदस्य

नीपा के बाहर प्रतिष्ठित निकायों की सदस्यता

नॉर्थ ईस्ट इंडिया एजुकेशन सोसाइटी, शिलांग (एनईआईईएस) के आजीवन सदस्य

भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआई) के आजीवन सदस्य

शिक्षा और विस्तार विभाग, सावित्रीभाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे के उच्च शिक्षा में जीवन कौशल में एक पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह समिति के सदस्य

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग

बी.के. पांडा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के लिए योगदान

नवंबर 2020 को नीपा में ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कार्यान्वयन रणनीतियां'', पर दस्तावेज़ को तैयार करने में निम्नलिखित दो क्षेत्रों में योगदान दिया।

स्कूल परिसरों के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन।

शासन के संघीय ढांचे में सुधार संरचनाएं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की रचना और संचालन

शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों के लिए संस्थागत योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें उनके कार्यक्रमों और नीतियों पर प्रकाश डाला है ताकि शैक्षिक प्रमुख एक केंद्रित दृष्टि और मिशन के साथ अपने संस्थानों की सेवा और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। यह आत्मनिरीक्षण करने की अनुमति देता है कि अब तक क्या किया गया है, कमियां कहां थीं और संस्थान की सफलता के लिए इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

शैक्षिक प्रशासकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को विकासशील देशों में सेवारत शैक्षिक प्रशासकों की प्राथमिकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। यह कार्यक्रम उन्हें समस्याओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल से सज्जित करता है और शैक्षिक प्रशासन में व्यवस्थित परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नवाचारों को अपनाता है।

डॉक्टरेट छात्रों को मार्गदर्शन

पी–एच.डी. छात्र ज्योत्सना सोनल के ''उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा में आदिवासी बच्चों की भागीदारी में अंतर–जनजातीय भिन्नता'' विषय का पर्यवेक्षण।

''ओडिशा के कोरापुट जिले के स्कूलों में आदिवासी बच्चों की समस्या'' विषय पर सत्य गरदा के पी–एच.डी. कार्य का पर्यवेक्षण।

''नीति के संदर्भ में शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान का एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण'' विषय पर पूनम चौधरी के पी–एच.डी. कार्य का पर्यवेक्षण

अनुसंधान परियोजना प्रगति पर

''प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान के लिए शैक्षिक प्रशासकों की भूमिका और कार्यों पर अध्ययन'' प्रगति पर है अध्ययन का पहला भाग सितंबर 2020 में पूरा हो गया है और ''प्रशिक्षण विषयों'' पर महत्वपूर्ण परिणाम नीपा की संकाय बैठक में प्रस्तुत किए गए।

अध्ययन के दूसरे भाग के लिए आवश्यक माध्यमिक जानकारी संग्रह के साथ पहले ही शुरू किया जा चुका है।

अकादमिक गतिविधियों में भागीदारी/वेबिनार–राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय

24 जुलाई, 2020 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित ''कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा'' पर एक वेबिनार में भागीदारी

13 जुलाई, 2020 को नीपा में आयोजित सुश्री मोनिका बिष्ट, पी–एच.डी. स्कॉलर की मौखिक परीक्षा में भागीदारी

7 जुलाई, 2020 को आयोजित श्री अजय कुमार चौबे, पी–एच.डी. (अंशकालिक) विद्वान की मौखिक परीक्षा में भागीदारी

19 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर आयोजित वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

20 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर प्रोफेसर ए.के. शिव कुमार, विकास अर्थशास्त्री और नीति सलाहकार द्वारा 'शिक्षा और सामाजिक अवसर: अंतराल को पाटना', पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

28 अगस्त, 2020 को नीपा में आयोजित सुश्री यशमिता और श्री त्यागराजन एम,, एम.फिल विद्वानों की मौखिक परीक्षा में भागीदारी।

7 सितंबर, 2020 को आयोजित सुश्री ज्योत्सना सोनल, पी–एच.डी. विद्वान की मौखिक परीक्षा में भागीदारी।

14 सितंबर, 2020 को आयोजित श्री सुमन साहा की मौखिक परीक्षा में भागीदारी।

19 सितंबर, 2020 को सुश्री अंशुल सलूजा की पी–एच. डी. मौखिक परीक्षा में भागीदारी ।

15 अक्टूबर, 2020 को 2020 बैच के विद्वानों के लिए सहकर्मी और संकाय समीक्षा संगोष्ठी का आयोजन

22 अक्टूबर, 2020 को सुश्री लक्ष्मी जायसवाल, पी–एच. डी. विद्वान, का प्री–सबमिशन सेमिनार का आयोजन।

30 अक्टूबर, 2020, को यूनेस्को द्वारा ''कोविड–19 महामारी के दौरान हमारे मस्तिष्क का ध्यान रखना: स्कूल जाने वाले बच्चों को उनके मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन करने में मदद करना'' विषय पर एक वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

20 नवंबर, 2020, को भारत में सीपीआरएचई, नीपा और आईआईईपी, पेरिस द्वारा लचीले अधिगम के मार्ग: भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

8 दिसंबर, 2020 को यूनेस्को द्वारा '2020 शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट' के ऑनलाइन शुभारंभ में भागीदारी।

9 दिसंबर, 2020 को श्री रजनीश क्लेर, पी–एच.डी. की मौखिक परीक्षा में भागीदारी।

10 दिसंबर, 2020 को एनआरसीई, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संकाय संवर्धन श्रृंखला में भागीदारी।

15 दिसंबर 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर नीति संवाद वेबिनार में भागीदारी।

9–14 दिसंबर, 2020 ए.आई.ए.ई.आर. और आई.एफ.ओ. आर.ई. द्वारा आयोजित दुनिया भर में शिक्षक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान श्रृंखला में भागीदारी।

9 दिसंबर, 2020 को निर्देशात्मक निर्णय मॉडल: भविष्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए पिछड़ा अभिकल्प दृष्टिकोण, पर डॉ. बृजू थंकाचन, ओहियो यूनिवर्सिटी हेरिटेज कॉलेज ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन, एथेंस, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका के वेबिनार व्याख्यान भागीदारी।

9 दिसंबर, 2020 को श्रीमती सू क्रोनिन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम cronins@hope-ac-uk और डॉ. (सुश्री) नम्रता राव, शिक्षा संकाय, लिवरपूल होप यूनिवर्सिटी, यू.के. द्वारा यूनाइटेड किंगडम में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

10 दिसंबर, 2020 को प्रो. (श्रीमती) बासंती डे चक्रवर्ती, प्रारंभिक बचपन शिक्षा विभाग, न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

10 दिसंबर, 2020 को डॉ. सुश्री सिल्विया क्रिस्टीन अल्मेडा, शिक्षा संकाय, मोनाश विश्वविद्यालय, फ्रैंकस्टन, वीआईसी, ऑस्ट्रेलिया, द्वारा ऑस्ट्रेलिया में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

11 दिसंबर, 2020 को प्रो. (सुश्री) रोजा वलीवा, मनोविज्ञान और शिक्षा संस्थान, कज़ान संघीय विश्वविद्यालय, कज़ान, टार्टन, रूस, द्वारा रूस में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

11 दिसंबर, 2020 को प्रो. (सुश्री) जी. दयालता लेकमगे, शिक्षा संकाय, श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय, श्रीलंका द्वारा आयोजित श्रीलंकार में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान भागीदारी।

12 दिसंबर, 2020 को डॉ. (सुश्री) लियू वून चिया, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, सिंगापुर द्वारा सिंगापुर में शिक्षक शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

12 दिसंबर, 2020 को प्रो. क्रिस रेड्डी, शिक्षा संकाय, स्टेलनबोश विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका द्वारा रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका में शिक्षक शिक्षाः एक संक्षिप्त ऐतिहासिक अवलोकन, पर आयोजित वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

13 दिसंबर, 2020 को डॉ. सुनील बिहारी मोहंती द्वारा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण – एक अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन पर एक वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

13 दिसंबर, 2020 को सुश्री एने–सिल्विया सर्व, एस्टोनिया द्वारा एस्टोनिया में शिक्षक शिक्षा पर एक वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

14 दिसंबर, 2020 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली में आयोजित डॉ (श्रीमती) रमादेवी पाणि, संपादक, विश्वविद्यालय समाचार, द्वारा भारत में उच्च शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी

14 दिसंबर, 2020 को प्रो. (सुश्री) रोज़मेरी पपा, 22822 अर्बेला रोड, लगुना निगुएल, सीए 92677 यूएसए द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा पर वेबिनार व्याख्यान में भागीदारी।

22 दिसंबर, 2020 को पी–एच.डी. विद्वान सुश्री शास्वती प्रमाणिक, की मौखिक परीक्षा में भागीदारी।

18 दिसंबर, 2020 को आयोजित पी–एच.डी. विद्वानों के लिए आयोजित वार्षिक संगोष्ठी में भागीदारी।

25 जनवरी 2021 को 'अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवसः कोविड–19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनर्प्राप्त और पुनर्जीवित करें' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

29 जनवरी 2021, को प्रो. एन.वी. वर्गीज, कुलपित, नीपा, नई दिल्ली द्वारा नई शिक्षा नीति पर आई.जी.डी.टी.यू. डब्ल्यू. दिल्ली में आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

03 फरवरी, 2021 को ''असमानता और शिक्षा प्राप्तिः बिहार में अंतरजनपदीय गतिशीलता का अध्ययन'' पर सुश्री मनिका बोरा की डॉक्टरेट शोध विषय की गूगल मीट में भागीदारी।

26 मार्च 2021 को आयोजित सुश्री लैबोनी दास, पी–एच. डी. (अंशकालिक) छात्रा के प्री–सबमिशन सेमिनार में भागीदारी।

18–19 मार्च, 2021 को आयोजित उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र, नीपा द्वारा आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की सलाहकार बैठक में भागीदारी।

22–23 मार्च, 2021 को आयोजित 2019 बैच के एम.फिल. स्कॉलर्स के लिए प्री–सबमिशन सेमिनार में भागीदारी।

नीपा के कार्यक्रम

29 मार्च से 12 अप्रैल, 2021 तक शिक्षा अधिकारियों के लिए संस्थागत योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 15 देशों के 40 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) के साथ संबद्ध और अगस्त 2020 से जुलाई 2021 तक चलने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन किया। कार्यक्रम प्रगति पर है क्योंकि अंतिम चरण VI पूरा नहीं हुआ है, लगभग 25 प्रशिक्षुओं ने ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया।

वीरा गुप्ता

प्रकाशन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें

''इक्विटी एंड इन्क्लूजन'' और ''टीचर एजूकेशन'' पर अध्याय एनईपी दस्तावेज़ का संचालन; ईमेल दिनांक 29 सितंबर; नीपा; दल के सदस्य

''इन्क्लूडिंग चिल्ड्रेन विद एसएलडी इन रेगुलर स्कूल्स'' पर विकसित प्रशिक्षण पैकेज ईमेल दिनांक 22 जनवरी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित

शोध पत्र/आलेख प्रकाशित

''विकलांग बच्चों के लिए अधिगम के वातावरण और अधिगम की प्रक्रियाओं की पहुंच'' जर्नल ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 32, नंबर 1 और 2, जून और दिसंबर 2020, आईएसएसएन 0970–9827

वर्ष के दौरान सेमीनार/सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भागीदारी

(राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)

18–19 अप्रैल, 2020 को विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज नई दिल्ली द्वारा ''परामर्श कौशल और इसके संसाधन'' पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष।

18 मई, 2020 को त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा ''समावेशी शिक्षा नीतियों और प्रथाओं'' पर आयोजित वेबिनार के अध्यक्ष

22 मई, 2020 को सीबीएम, आरसीआई और यूनेस्को द्वारा ''सीडब्ल्यूडी और कोविड'' पर आयोजित वेबिनार के अध्यक्ष

9 जून, 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा ''अकादमिक प्रकाशन और अनुसंधान प्रभावशीलता को बढ़ाना'' पर आयोजित वेबिनार के अध्यक्ष

20–21, जून, 2020 को डीएलएस, यूके द्वारा विद्यालय नेतृत्व विकास पर आयोजित एक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भागीदारी

8 जुलाई, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना' पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

23 जुलाई, 2020 को नीपा द्वारा ''कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा'' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

7 अगस्त को यूजीसी एमएचआरडी द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में भागीदारी

19 अगस्त को नीपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

5 सितंबर, 2020 को एनआरसीई, नीपा द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति–2020 के आलोक में उच्च शिक्षा में शिक्षकों का क्षमता विकास'' पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

16 सितंबर, 2020 को शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: ''परिवर्तनकारी सुधार को समझना'' पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

1 अक्टूबर, 2020 को नीपा में गांधीवादी शैक्षिक विचारों और प्रयोग की प्रासंगिकता पर वृत्तचित्र प्रदर्शन में भागीदारी।

15 अक्टूबर, 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बैंगलोर द्वारा ''विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

7 नवंबर, 2020 को श्याम लाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''कोविड–19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण अधिगम की चुनौतियाँ'' पर एसएलसी वेबिनार में अध्यक्ष

11 नवंबर को नीपा द्वारा आयोजित मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान (राष्ट्रीय शैक्षिक दिवस) में भागीदारी

20 नवंबर, 2020 को सीपीआरएचई/नीपा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी), यूनेस्को, पेरिस द्वारा ''लचीले अधिगम के मार्ग: भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर आयोजित कार्यक्रम भागीदारी

26 नवंबर, 2020 को नीपा द्वारा संविधान दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर ''भारतीय संविधान में बहुलवाद, समानता और नागरिकता के विचार की पुष्टि'' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

26 नवंबर, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित स्पीकर कोविड के दौरान क्या करें और क्या न करें तथा हृदय संबंधी समस्याओं का प्रबंधन; पर वेबिनार के वक्ता

15 दिसंबर, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर संगोष्ठी में भागीदारी

5 जनवरी, 2021 को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), नॉर्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलांग द्वारा आयोजित ''समावेशी शिक्षा: अभ्यास के लिए नीतियां'' पर राष्ट्रीय वेबिनार में अध्यक्ष

25 जनवरी, 2021 को यूनेस्को द्वारा आयोजित तीसरे 'अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवसः कोविड–19 पीढ़ी के लिए शिक्षा को पुनर्प्राप्त और पुनर्जीवित करें' के आभासी समारोह भाग लिया।

28 नवंबर 2020 को वर्सगने सोसाइटी ऑफ टीचर्स द्वारा डिस्लेक्सिक बच्चों की शिक्षा पर आयोजित वेबिनार के अध्यक्ष

16 जनवरी, 2021 को पॉलिसी टाइम्स द्वारा ''लड़कियों और विशिष्ट बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष पहल'' पर विश्व शिक्षा सम्मेलन में अध्यक्ष (डब्ल्यूईसी ऑनलाइन 2021)।

15–16 मार्च, 2021 को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित ''यूडीएल आधारित सुलभ पाठ्यपुस्तकें और सभी के लिए पूरक पाठक'' पर कार्यशाला के आयोजक सदस्य और 'एनसीईआरटी' यूडीएल डिजिटल एक्जाम्प्लर पर 15 मार्च को सत्र की अध्यक्षता

16–17 मार्च, 2021 को समग्र अभियान द्वारा आयोजित ''चंडीगढ़ के विशेष शिक्षकों के लिए सीबीएसई प्रावधान'' पर अध्यक्ष

17 मार्च, 2021 को पश्चिम बंगाल पुनर्वास पेशेवर मंच द्वारा ''आरपीडब्ल्यूडी 16 अधिनियम और एनईपी 20 के आलोक में शिक्षक शिक्षा सुधार'' पर अध्यक्ष डब्ल्यूबीएफआरपी पैनल चर्चा

18–19 मार्च, 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की परामर्शदात्री बैठक में प्रतिभागी

कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

कार्यक्रम निदेशक, 37वां आईडेपा 2019–20

कार्यक्रम निदेशक, 7वां पीजीडेपा 2019–20

कार्यक्रम निदेशक, 8वीं पीजीडेपा 2020–21

पाठ्यक्रम निदेशक, एम.फिल. 2020 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (समावेशी शिक्षा)

कार्यक्रम निदेशक, एम.फिल. 2020 क्षेत्र संलग्न

7वें पीजीडेपा 2019–20 के नीति निर्माण पर अग्रिम पाठ्यक्रम के निदेशक

पाठ्यक्रम निदेशक, एम.फिल. 2021 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (समावेशी शिक्षा)

कार्यक्रम निदेशक, एम.फिल. 2021 क्षेत्र संलग्न

5–6 नवंबर, को नीपा में अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आयोजित ''क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका और कार्यः एसीसईआरटी और सीमैट'' के ऑनलाइन बैठक के कार्यक्रम निदेशक।

3–4 दिसंबर, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित ''विशिष्ट अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा (एसएलडी)'' पर ऑनलाइन बैठक के कार्यक्रम निदेशक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

नियमित स्कूलों में विशिष्ट अधिगम की अक्षमता (एसएलडी) वाले बच्चों को शामिल करने के लिए विकसित प्रशिक्षण पैकेज, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित

22 फरवरी, 2021 को एनसीईआरटी द्वारा (पीएसी स्वीकृत कार्यक्रम 3.02): नागालैंड में नियमित स्कूलों में विशिष्ट अधिगम की अक्षमता (एसएलडी) वाले बच्चों को शामिल करने पर प्रयास कार्यशाला के लिए पूर्व–कार्यशाला योजना बैठक के सदस्य

दयाल बाग मानित विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में बी.एड., एम.एड., और डी.एड., के पाठ्यक्रम के समीक्षक

जामिया मिल्लिया इस्लामिया को आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट सौंपी

प्रशिक्षण सामग्री विकसित/प्रस्तुत और रिपोर्ट तैयार किये

व्यावसायिक नीति निर्माण पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित

समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण सामग्री विकसित

'विशिष्ट अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा' पर ऑनलाइन बैठक के लिए रिपोर्ट तैयार की

''क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका और कार्य पर एससीईआरटी और सीमैट'' ऑनलाइन बैठक के लिए रिपोर्ट तैयार की

37वें आईडेपा कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट तैयार की

7वें पीजीडेपा कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट तैयार की

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आंतरिक शिकायत समिति के बाहरी सदस्य, फाइल सं. जनरल 311/जेएमआई/आरओ/ईएसटीटी/2020, जामिया मिलिया इस्लामिया

18 फरवरी 2020 को डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, जामिया मिलिया इस्लामिया के शासी बोर्ड की बैठक, पत्र दिनांक 5 फरवरी

27 जून 2019 से तीन वर्ष के लिए दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य; पत्र दि. 27/6/2019 को 27/6/2019–26/6/2022 दिल्ली एजुकेशन सोसायटी

20 जुलाई 2019 को अमर ज्योति शासी निकाय के सदस्य, ईमेल 20 जून 2019

28 मई, 2020 से 3 वर्ष के लिए सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केन्द्र के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य। फा. सं. एसी12(5) आरओ/2020 दिनांक 4.6.2020; जामिया मिलिया इस्लामिया की बैठक में 29 सितंबर को भागीदारी

दयाल बाग आगरा के पी–एच.डी. प्रस्ताव के समीक्षा के लिए अनुसंधान डिग्री समिति (आरडीसी) सदस्य; ईमेल दिनांक 14 अक्टूबर

अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट के वार्षिक आम बैठक के सदस्य ईमेल दिनांक 25 दिसंबर अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट

एंग्लो अरबिक मॉडल स्कूल दिल्ली की प्रबंध समिति के सदस्य। ईमेल दिनांक 28 जनवरी

दयाल बाग मानित विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड के सदस्य ईमेल दिनांक 18 फरवरी

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एआईएईआर के शासी बोर्ड के सदस्य

ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च जर्नल के लिए आलेख की पांडुलिपि सं. 2020126 के समीक्षक

ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च जर्नल के लिए आलेख की पांडुलिपि सं. 202062 के समीक्षक

दयाल बाग आगरा के पी–एच.डी. प्रस्ताव की समीक्षा के लिए अनुसंधान डिग्री समिति (आरडीसी) सदस्य; ईमेल दिनांक 14 अक्टूबर

29 दिसंबर, 2020 को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित नियमित स्कूलों में आत्मकेंद्रित और एसएलडी वाले बच्चों को शामिल करने हेतु प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने पर बैठक की शुरू की

जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित सुश्री रुचिरा गुगलानी के ''दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा पर आरटीई 2010 के प्रभाव का अध्ययन'' थीसिस के लिए परीक्षक ईमेल दिनांक 11 दिसंबर, 2020

दयाल बाग मानित विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रूप में बी.एड,, एम.एड., और डी. एड. के पाठ्यक्रम समीक्षक ईमेल दिनांक 18 फरवरी

22 फरवरी, 2021 को एनसीईआरटी द्वारा (पीएसी स्वीकृत कार्यक्रम 3.02): नागालैंड में नियमित स्कूलों में विशिष्ट अधिगम की अक्षमता (एसएलडी) वाले बच्चों को शामिल करने पर प्रयास कार्यशाला के लिए पूर्व–कार्यशाला योजना बैठक के सदस्य ईमेल दिनांक 9 फरवरी

18 फरवरी, 2021 को एम.एस. यूनिवर्सिटी बड़ौदा द्व ारा आयोजित सुश्री वल्ली के ''गुजरात शांति शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' विषय का मूल्यांकन ईमेल दिनांक 18 फरवरी

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्ययूट, आगरा द्वारा आयोजित 6 अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा। ईमेल दिनांक 2 मार्च

अंतःविषय पत्रिका नव रचना विश्वविद्यालय के संपादक; ईमेल दिनांक 4 मार्च 2021

2 मार्च, 2021 को एम.एस. यूनिवर्सिटी बड़ौदा द्वारा आयोजित सुश्री वल्ली के ''गुजरात शांति शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यचर्या का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' विषय के मौखिक परीक्षक ईमेल दिनांक 18 फरवरी

दयाल बाग मानित विश्वविद्यालय, आगरा के दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्ययूट, एफओईआरएए के संपादकीय बोर्ड के सदस्य ईमेल 2 फरवरी 2021

व्याख्यान दिये

8 जून, 2020 को एसएनडीटी विश्वविद्यालय और आरसीआई द्वारा ''गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों'' पर आयोजित संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में सत्र

8 जून, 2020 को श्याम लाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी और यूबीए द्वारा आयोजित ''कोविड–19 के दौरान महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता''

एनईपी 2020 के प्रभावः शिक्षक शिक्षा के निहितार्थ, एसओई, इग्नू के राष्ट्रीय वेबिनार पर संसाधन व्यक्ति

12 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया में ''शिक्षण के दायरे को समझना'' पर जामिया मानव संसाधन विकास केन्द्र में सत्र, ईमेल दिनांक 8 अक्टूबर

चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित ''आईसीटी के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा'' पर व्याख्यान ईमेल दिनांक 6 अक्टूबर

24 नवंबर, 2020 को एचआरडीसी जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा आयोजित ''शिक्षण के दायरे को समझना'' पर व्याख्यान

9 जनवरी, 2021 को एचआरडीसी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय आयोजित ''छात्रों और उनकी आवश्यकताओं को समझना'' पर सत्र। ईमेल दिनांक 2 जनवरी।

11 फरवरी, 2021 को नीपा द्वारा स्कूली शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भः शैक्षिक शासन में नेतृत्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष

15–17 फरवरी, 2021 को नीपा में ''आरटीई अधिनियम के तहत वंचितों की शिक्षा'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला। ईमेल दिनांक 12 फरवरी

विशेष शिक्षकों के लिए ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विषयः आरपीडब्ल्यूडी 2016 के साथ परिचित होना (यूएनसीआरपीडी और सिंहावलोकन) हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए) द्वारा 15, 16, 22, 25 और 26, 2021 को सत्र आयोजित।

1–3 मार्च, 2021 को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित विशिष्ट सीखने की अक्षमता प्रशिक्षण ऑनलाइन पैकेज नागालैंड मॉड्यूल पर कार्यशाला

अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षक

पीएच.डी. छात्रा संगीता डे का शोध विषय 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नीतिगत विश्लेषण पर शासन के दृष्टिकोण' का पर्यवेक्षण।

पीएच.डी. छात्र, दीपिन्दर सेखों का शोध विषय 'समग्र विकास के ढ़ांचे के साथ सीडब्ल्यूडी के समावेशी के लिए नीति दस्तावेजों का विश्लेषण'' का पर्यवेक्षण

सुश्री निवेदिता सहनी के पी–एच.डी छात्र के शोध प्रबंध "विशिष्ट अधिगम की अक्षमता (एसएलडी) के साथ और बिना एसएलडी आवश्यकताओं वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन'' का पर्यवेक्षण।

एम.फिल. छात्रा, सुश्री प्रीति शर्मा के शोध का शोध विषय ''श्रवण बाधित छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा में समावेशिता का आकलनः हरियाणा में क्षेत्रीय अध्ययन'' की आंतरिक मूल्यांकन रिपोट का पर्यवेक्षण

सुश्री प्रीति शर्मा, पी–एच.डी. छात्रा के शोध ''माध्यमिक स्तर पर हरियाणा के मुख्यधारा के स्कूलों में सीडब्ल्यूडी के लिए अधिकार आधारित समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिक–आर्थिक बाधाएंः एक अनुभवजन्य अध्ययन'' पंजीकरण के तहत विषय का पर्यवेक्षण

सुश्री बनश्री मंडल, एम.फिल. छात्रा का शोध विषय ''निगरानी तंत्र की स्थिति विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार'' का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा विषय ''हरियाणा राज्य में कक्षा–3 के विद्यार्थियों को एनएएस–2017 पर आधारित पठन दोष से संबंधित मुद्दों का अध्ययन'', अन्वेषकः सुश्री तनु भारद्वाज

आईडेपा शोध प्रबंधः 'तंजानिया में नियमित प्राथमिक विद्यालयों में विकलांगता के साथ शिक्षार्थियों के समावेश को प्रभावित करने वाले कारकः तमेके जिले का केस अध्ययन, श्री जोसेफ चाल्ले, तंजानिया

आईडेपा शोध प्रबंधः 'मंगोलिया में उच्च शिक्षा में नेतृत्व और परिवर्तन की जांच' चिनटुंगाल्ग एर्डेनेबातर, मंगोलिया

सदस्यता

अध्ययन बोर्ड की बैठक के सदस्य

अकादमिक परिषद के सदस्य;

योजना और निगरानी बोर्ड नीपा के सदस्य

सदस्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत अधिसूचना फा.सं. 11018/02.2019–ईबीएसबी (भाग–1) दिनांक 1 जून, 2020 नीपा

03 जुलाई 2020 को आयोजित एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के अध्यक्ष

2.5 लाख से ऊपर एसपीसी के सदस्य, एन.एफ. 37–25/2009–10/जीए

2.5 लाख से कम एसपीसी के अध्यक्ष, एन.एफ. 37–25/2009–10/जीए

नीपा जर्नल की चयन समिति के सदस्य

सहायता अनुदान समिति के सदस्य

मोना सेदवाल

प्रकाशन

इलूशिव वोकेशनल एजूकेशन प्रोग्रामः एन अनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स इन इंडियन सेकण्डरी स्कूल्स तिलक जे. (संपा), *यूनिवर्सल सेकेण्डरी एजूकेशन इन इंडियाः एन इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू ऑफ इश्यूज, चैलेंजेज एंड प्रॉसपैक्ट्स,* स्प्रिंगर, सिंगापुर, 2020, पृ. 301–322, मुद्रित आइएसबीएनः 978–981–15–5365–3; ऑनलाइन आइएसबीएनः 978–981–15–5366–0

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

प्रस्तुतकर्ता के रूप में

25–27 जनवरी 2021 को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा द्वारा स्कूलों में 'मिश्रित' अधिगम दृष्टिकोण के उपयोगः भारतीय प्रसंग में कोविड 19 महामारी के संदर्भ में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता पर मुद्दे और चुनौतिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शिक्षा से परे आमने–सामने के माध्यमः अवसर और चुनौतियां शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत किया। संगोष्ठी का आयोजन इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन (आईयूसीटीई) और शिक्षा विभाग (केस और आईएएसई), शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय द्वारा किया गया।

26 फरवरी 2021 को नीपा में आयोजित संकाय बैठक में क्षमता विकास के क्षेत्रों पर प्रस्तुति।

10 से 12 मार्च 2021 तक यूएनएफपीए के सहयोग से शैक्षिक अध्ययन विभाग, शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा मदरसा छात्रों के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (आरआरसी) के लिए संस्थागत योजनाएं नामक परियोजना रिपोर्ट पर ऑनलाइन कार्यशाला सह–बैठक में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित

प्रतिभागी के रूप में

एनईपी 2020 और शिक्षा पर कोविड 19 के प्रभाव पर कई वेबिनारों में भागीदारी जिनमें कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं–

18 अप्रैल, 2020 को एसोचैम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा कोविड–19: उच्चतर शिक्षा के लिए अधिगम का अवसर पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

4 मई 2020 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू), लंदन द्वारा आयोजित कोविड–19 विश्व में उच्च शिक्षा के भविष्य पर वेबिनार में भागीदारी

4 मई 2020 को कतर फाउंडेशन (क्यूएफ) और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) के बीच साझेदारी के माध्यम आयोजित 'ऑनलाइन कार्यक्रम नये विचार के विद्यालयः उच्च शिक्षा देने के लिए अभिनव मॉडल रिपोर्ट के शुभारंभ पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

14 मई 2020 को जियो इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एलन ई. गुडमैन, अध्यक्ष और सीईओ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और फ्रांसिस्को मार्मोलेजो, शिक्षा सलाहकार,

कतर फाउंडेशन द्वारा 'कोविड–19 के बाद का युगः उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत के लिए चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार में भागीदारी

28 मई 2020 को नॉर्डिक सेंटर ऑफ इंडिया (एनसीआई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनुसंधान, नवाचार और उच्च शिक्षा – नॉर्डिक्स और यूरोपीय संघ में अवसर' पर वेबिनार में भागीदारी

1 जून 2020 को कॉर्विन द्वारा एक जिज्ञासु विद्यालय के निर्माण पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

12 जून 2020 को 'बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले स्कूल बंद और लॉकडाउन पर वेबिनार में भागीदारी

13 जून 2020 को बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित कोविड 19 माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के सामने चुनौतियाँ पर वेबिनार में भागीदारी

17 जून 2020 को एसोचौम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित श्री अनुराग त्रिपाठी, आईआरपीएस, सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा संबोधित ''स्कूलों को फिर से कहाँ और कैसे? खोलें पर वेबिनार में भागीदारी

20 जून 2020 को बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित 'स्कूलों को फिर से खोलनाः माता–पिता और बच्चों की अपेक्षा' पर वेबिनार में भागीदारी

22–23 जून 2020 तक नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशन (एनआरसीई), नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (नीपा), नई दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षा में शिक्षकों के लिए शिक्षा संसाधनों की पहचान पर आयोजित आभासी कार्यशाला में भागीदारी

26 जून 2020 को आरटीई फोरम, नई दिल्ली द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा का अधिकार पर कोविड–19 के प्रभाव पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 26 जून 2020 को दोपहर 3–5 बजे से आयोजित बच्चों के जीवन में कोविड–19 के सिल्वर लाइनिंग्स पर वेबिनार।

26 जून, 2020 को मानव विकास संस्थान द्वारा आयोजित कोविड–19 और महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर आभासी पैनल चर्चा में भागीदारी

27 जून, 2020 को बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित स्कूल फिर से खुलने के बाद बच्चों की सुरक्षा पर वेबिनार में भागीदारी

29 जून 2020 को टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षाः निरंतरता या व्यवधान? दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद द्वारा चर्चा पर वेबिनार में भागीदारी

3 जुलाई 2020 को नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रो. आर.सी. गौड़ द्वारा अकादमिक सत्यनिष्ठा, कॉपीराइट, शैक्षणिक चोरी मुक्त साहित्यिक कार्य सुनिश्चित करना पर वेबिनार

3 जुलाई 2020 को डॉ. डी.एस. ठाकुर प्रलेखन अधिकारी, नीपा द्वारा साहित्यिक चोरी की जांच–उरकुंड सॉफ्टवेयर पर नीपा, नई दिल्ली में वेबिनार में भागीदारी

7 जुलाई 2020 को सनम एस4 द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से संस्थागत विकास को बढ़ावा देने पर भारतीय उच्च शिक्षा श्रृंखला के अंतर्राष्ट्रीयकरण के तहत आयोजित वेबिनार में भागीदारी

9 जुलाई, 2020 को एसोचौम शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित उच्च शिक्षाः कोविड–19 खतरे को शिक्षा के नए मॉडल में बदलना पर वेबिनार में भागीदारी।

11 जुलाई 2020 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा द्वारा शिक्षा और एक सार्वजनिक भलाई के रूप में सार्वजनिक भलाई सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बाधाओं को तोड़ना और सामंजस्य निर्माण पर आयोजित उच्च शिक्षा नेतृत्व की संगोष्ठी में भागीदारी

14 जुलाई 2020 को सीपीआरएचई, नीपा, नई दिल्ली और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को को आगे बढ़ाने पर वेबिनार में भागीदारी।

15 जुलाई 2020 को सामाजिक विकास परिषद और भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा वार्षिक दुर्गाबाई देशमुख स्मृति व्याख्यान क्या आज का संकट नव शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों और नव उदारवादी राजनेताओं के लिए अपनी मानसिकता बदलने के लिए पर्याप्त है? डॉ. अशोक खोसला, भारतीय पर्यावरण और विकास विकल्प समूह के संस्थापक द्वारा आयोजित वेबिनार में भागीदारी

17 जुलाई 2020 को एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमिस्ट्स क्लब, ढाका स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित अनिश्चितता के साथ महामारी की स्थिति में मानव के मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी

18 जून 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित कोविड–19 के दौर में महिलाएं और बच्चेः नीतियों और आगे की राह पर चर्चा वेबिनार में भागीदारी

23 जुलाई 2020 को सौराष्ट्र कॉलेज, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा आयोजित प्रो. रश्मि दीवान द्वारा कोविड –19 संकट के बीच शैक्षिक नेतृत्व बाधाओं और संभावनाओं की बदलती दुनिया पर वेबिनार आयोजित किया

24 जुलाई 2020 को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, द्वारा आयोजित कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा पर वेबिनार में भागीदारी

26 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित स्कूल बंद के दौरान बच्चों की ऊर्जा को चैनलाइज़ करने पर वेबिनार में भागीदारी

27 जुलाई 2020 को महावीर महाविद्यालय, कोल्हापुर प्रोफेसर पूनम बत्रा द्वारा नई शिक्षा नीति 2019 के आलोक में शिक्षक शिक्षा पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

30 जुलाई, 2020 को एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन द्वारा शोभित विश्वविद्यालय और व्हीबॉक्स के सहयोग से आयोजित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन दृष्टिकोण क्या हो सकता है – ऑनलाइन या ऑफलाइन पर वेबिनार में भागीदारी

6–7 अगस्त 2020 को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडिया द्वारा कतर फाउंडेशन और एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज (एसीयू), एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू), कोयम्बटूर ग्रुप ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी लास्पाऊ (हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध नेटवर्क), और स्टार स्कॉलर्स नेटवर्क सहित अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित विश्वविद्यालय की पुनर्कल्पना और परिवर्तन पर वैश्विक आभासी सम्मेलन; कोविड–19 के दौरान और उससे आगे के विचारों का संगम पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

5 अगस्त 2020 को ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया द्वारा आयोजित 'बचपन और छूटी हुई स्कूली शिक्षा को बहाल करनः ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के बंद होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना' पर वेबिनार में भागीदारी

7 अगस्त 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया।

7 अगस्त 2020 को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण को झटका? पर वेबिनार में भागीदारी

7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड–19 इंपैक्टिंग स्कूल ड्रॉपआउट्स पर वेब सेमिनार आयोजित किया

7 अगस्त 2020 को साउथ इंडियन स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (SISGIS) द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः भारत के लिए इसका क्या अर्थ है? पर वेबिनार आयोजित किया

7 अगस्त 2020 को अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली और भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारत द्वारा आयोजित डॉ मार्क इलियट, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वाइस प्रोवोस्ट,

हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 'उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरणः महामारी सब कुछ बदल देती है, महामारी कुछ भी नहीं बदलती', पर वेबिनार

8 अगस्त 2020 को विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, स्कूल मानक और मूल्यांकन इकाई, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए), नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

10 अगस्त 2020 को इनफ्लिबनेट (सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र, द्वारा साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (पीडीएस) शोध शुद्धि पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

19 अगस्त 2020 को शैक्षिक नीति विभाग, नीपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020ः संभावनाएँ, चुनौतियाँ और रास्ते पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

20 अगस्त 2020 को नीपा में चौदहवें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर प्रोफेसर ए.के. शिव कुमार, विकास अर्थशास्त्री और नीति सलाहकार द्वारा शिक्षा और सामाजिक अवसरः अंतराल को पाटना पर व्याख्यान वेबिनार में भागीदारी

27 अगस्त, 2020 को नेक्सस ऑफ़ गुड द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर्दा उठाने वालाः मौजूदा प्रतिकृति प्रथाओं और आगे के मार्ग से सीख' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

27 अगस्त 2020 को एसोचौम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 – उच्च शिक्षा को बदलने वाली ज्ञान श्रृंखलाः संरचना और प्रक्रियाएं पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

29 अगस्त 2020 को एसोचौम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः एक नया प्रतिमान – उच्च शिक्षा – परिवर्तन और प्रभाव पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा कोविड 19 और बाल श्रम पर उभरती हुई चिंता पर वेब सेमिनार आयोजित

1–3 सितंबर 2020 को यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईईपी) द्वारा आयोजित क्यों? क्या; और एक बेहतर समाज के लिए शिक्षा पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

3 सितंबर, 2020 को एसोचैम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020ः शिक्षा का उज्जवल भविष्य पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी।

3–4 सितंबर 2020 को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन (आईयूसीटीई), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी द्वारा एनईपी 2020 और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक शिक्षा में प्रतिमान बदलाव विषय पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

3 सितंबर 2020 को भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआई) रिसर्च इंटरेस्ट ग्रुप (आरआईजी)–5 ऑन पॉलिटिक्स एजुकेशन द्वारा आयोजित शैक्षिक सुधारों की राजनीति की जांचः एनईपी 2020 पर वेबिनार में भागीदारी।

5 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षा में शिक्षकों के क्षमता विकास पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

7 सितंबर 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की भूमिका पर राज्यपालों का आभासी सम्मेलन में भागीदारी

8–25 सितंबर, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 8–9 सितंबर को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर दो दिवसीय कॉन्क्लेव, एनईपी पर अभ्यासकर्ता सभा, तकनीकी सत्र और 14–25 सितंबर 2020 तक विभिन्न विषयों में बारह वेबिनार– प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, स्कूलों, एचईआई, टीईआई, सरकारी स्कूल शिक्षा अधिकारियों, शिक्षाविदों, सीएसओ आदि के

लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय पर शिक्षक पर्व के तहत आभासी कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन में भागीदारी।

15 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा कोविड–19 के दौरान मिश्रित अधिगम एवं पाठ्यक्रम वितरण पर वेब सेमिनार आयोजित किया।

21 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2020 तक आदिवासी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से एनसीएसएल, नीपा द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व विकास पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यशाला।

10 अक्टूबर 2020 को एसोचौम राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर नियामक और मानक निर्धारण निकायों की भूमिका और कार्य एसोचौम ज्ञान श्रृंखला पर वेबिनार का आयोजन

13 अक्टूबर 2020 को आईआईईपी–यूनेस्को द्वारा कोविड–19 के दौरान शिक्षा पर रणनीतिक बहस क्या आकस्मिक योजना आगे बढ़ने का रास्ता है? पर आयोजित में भागीदारी।

20 अक्टूबर 2020 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एआईसीटीई की संस्थागत विकास पहल पर ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में भागीदारी।

28–30 अक्टूबर 2021 को आईपीएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (एआईएईआर) और आईएफओआर के सहयोग से कोविड 19 के दौरान शैक्षिक परिवर्तन चुनौतियाँ और मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

11 नवंबर 2020 को नीपा द्वारा आयोजित उच्चतर शिक्षा का भविष्य? इतिहास के दर्पण और विज्ञान के दर्शन के माध्यम पर प्रो. ध्रुव रैना द्वारा ग्यारहवां मौलाना आजाद स्मृति व्याख्यान में भागीदारी।

20 नवंबर 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग (आईआईईपी), यूनेस्को, पेरिस के साथ सह–मेजबानी में आयोजित 'लचीले अधिगम के मार्गः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार में भागीदारी

22 नवंबर 2020 को श्री रावलनाथ को–ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड, अजारा और आर. बी. मडखोलकर महाविद्यालय, चांदगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा की गुणवत्ता (NAAC) पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

7–10 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईईपी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) (यूएन 75 2020 और बियॉन्ड शेपिंग अवर फ्यूचर टुगेदर) द्वारा आयोजित शिक्षा की पुर्नकल्पना संवाद तथा शिक्षा पर पीढियों से वार्ता पर आभासी वेबिनार में भागीदारी

9–12 दिसंबर से अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (एआईएईआर) और शिक्षा शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मंच के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर द्वारा आयोजित दुनिया भर में शिक्षक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान श्रृंखला में भागीदारी

10 दिसंबर, 2020 को अनुसंधान रूचि समूह (आरआईजी)–3 शिक्षा का इतिहास भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सीईएसआई) द्वारा आयोजित भविष्य के नागरिकों को शिक्षित करनाः 1920 और 1930 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में अनिवार्य शिक्षा का परिचय, स्ट्रैथेलीड विश्वविद्यालय से डॉ कैट्रिओना एलिस द्वारा स्थापना दिवस व्याख्यान में भागीदारी

15 दिसंबर 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार पर नीति संवाद पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

6 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार डिजिटल डिवाइडः बच्चों के मुद्दे और चिंताएं पर आयोजित वेब सेमिनार में भागीदारी

7 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र (एनआरसीई), नीपा द्वारा आयोजित उच्चतर शिक्षा में

शिक्षा अनुशासन शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार में भागीदारी

12 मार्च 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आयोजित ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आपदा प्रबंधन योजना के एकीकरण पर ई ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण में युवाओं की भूमिका पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

19 मार्च 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों के लिए विशेष संदर्भ के साथ आपदा मनो–सामाजिक देखभाल पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

24–26 मार्च 2021 को जेएनटीयू हैदराबाद के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन की मूल बातें पर 3–दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

कार्यशालाओं / सम्मेलनों / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में 1 फरवरी से 30 अप्रैल, 2020 तक शैक्षिक योजना और प्रशासन में 36वां अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) कार्यक्रम के समन्वयक

1 अगस्त 2019 से 17 जुलाई 2020 तक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में छठे स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) के लिए कार्यक्रम समन्वयक। इस डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए नई दिल्ली में ग्यारह राज्यों के तेईस प्रतिभागियों ने कोविड महामारी के कारण ऑनलाईन माध्यम से भाग लिया।

1 अगस्त 2020 से 9 जुलाई 2021 तक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली में शैक्षिक योजना और प्रशासन में सातवें स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) के लिए कार्यक्रम समन्वयक। इस डिप्लोमा कार्यक्रम में नौ राज्यों, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौ सेना के तीस शिक्षा अधिकारियों ने कोविड–19 महामारी के कारण गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में भाग लिया।

कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन माध्यम से 21 से 25 सितंबर 2020 तक नीपा नई दिल्ली द्वारा शिक्षा में नीति निर्माण संरचनाएं और प्रक्रियाएं पर आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए समन्वयक

कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन माध्यम से 5–6 नवंबर 2020 नीपा, नई दिल्ली से आयोजित क्षमता निर्माण संस्थानों की भूमिका और कार्यों पर राष्ट्रीय नीति संवादः एससीईआरटी और सीमैट के लिए कार्यक्रम समन्वयक

कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन माध्यम से 3–4 दिसंबर 2020, नीपा, नई दिल्ली से आयोजित विशिष्ट अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों (एसएलडी) की शिक्षा पर समावेशी शिक्षा समन्वयकों की ऑनलाइन बैठक के लिए कार्यक्रम समन्वयक

कोविड महामारी के कारण गूगल मीट पर ऑनलाइन माध्यम से 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2021 तक नीपा, नई दिल्ली से शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के लिए संस्थागत योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम समन्वयक।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित

कोविड महामारी के कारण गूगल मीट पर ऑनलाइन के माध्यम से 30 मार्च से 12 अप्रैल, 2021, तक नीपा, नई दिल्ली से आयोजित शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों के लिए संस्थागत योजना और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कार्यक्रम को तैयार और विकसित किया। इस ई–आईटीईसी कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

मार्च 2021 में बी.के. पांडा, प्रोफेसर, नीपा, के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों हेतु प्रशिक्षण के लिए उपयोगी प्रशिक्षण मॉड्यूल संस्थागत योजना हस्तपुस्तिका की संरचना एवं विकास किया।

मार्च 2021 में बी.के. पांडा, प्रोफेसर, नीपा, के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों हेतु प्रशिक्षण के लिए उपयोगी प्रशिक्षण मॉड्यूल संस्थागत योजनाः कार्यपुस्तिका की संरचना एवं विकास किया।

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2020 के दौरान सतर्कता जागरूकता पखवाड़ा 2020 के दौरान आयोजित निबंध लेखन, नारा लेखन और पोस्टर बनाने पर प्रतियोगिता के लिए जूरी के सदस्य।

यूएनएफपीए, नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक प्रायोजित 'मदरसा छात्रों के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु दल के सदस्य, राज्य संसाधन केंद्र (एसआरसी) संस्थागत योजनाएं और शैक्षिक अध्ययन विभाग क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (आरआरसी), शिक्षा संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली। बिहार के मदरसों के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम पर परियोजना के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया, सहयोगी भागीदारों में से एक था।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपीईटी) पाठ्यक्रम के संशोधन पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन। पीडीपीईटी छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है जो उन सेवारत शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स के रूप में कार्य करता है जिन्होंने पहले ही बी.एड. कर चुके हैं लेकिन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल विषयों में शिक्षाशास्त्र, स्कूल आधारित और कार्यशाला आधारित गतिविधियों पर टिप्पणियाँ पाठ्यक्रम 524 के संबंध में थीं। उसी पर चर्चा करने के लिए 14 दिसंबर 2020 को दोपहर 2 बजे से एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया।

अन्य शैक्षणिक/व्यावसायिक योगदान

नीपा मार्च 2021 तक प्रकाशित हिंदी जर्नल परिप्रेक्ष्य के लिए एक लेख की समीक्षा की।

पर्यवेक्षक के रूप में

शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडेपा) प्रतिभागी वायु सेना से श्री गुरदीप एस. चौहान को उनके परियोजना कार्य ''छात्रों के समग्र विकास में स्कूल नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की भूमिका की खोजः आर्मी पब्लिक स्कूल अंबाला में मिडिल सैक्शन का केस अध्ययन, हरियाणा, 2020'' का पर्यवेक्षण

एम.फिल. छात्र श्री सुमन साहा को उनके शोध प्रबंध 'पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यान्वयनः राज्य उच्च शिक्षा परिषद की भूमिका पर विश्लेषण, 2020' का पर्यवेक्षण

शैक्षिक योजना और प्रशासन में छत्तीसवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) प्रतिभागी फिजी से श्री अमित चंद शिउनाथ को उनके परियोजना कार्य 'फिजी में भर्ती की ओपन मेरिट सिस्टम के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पर नीति विश्लेषण, 2021' का पर्यवेक्षण

शैक्षिक योजना और प्रशासन में छत्तीसवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा) प्रतिभागी जाम्बिया के श्री एवरिस्टो फिरी को उनके परियोजना कार्य 'जाम्बिया के कब्बे जिले में माध्यमिक विद्यालयों से लड़कियों के ड्रापआउट के कारण, 2021' शीर्षक के पर्यवेक्षक

प्रख्यात निकायों की सदस्यता

भारतीय तुलनात्मक शिक्षा सोसायटी (सेसी), के आजीवन सदस्य। जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में सचिवालय, सदस्यता सं. सेसी/एलएम/39.

आजीवन सदस्य, अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ (एआईएईआर), भुवनेश्वर, भारत। सदस्यता सं. 3129

आजीवन सदस्य, इंडियन सोशिलॉजिकल सोसायटी (आईएसएस), नई दिल्ली, भारत सदस्यता संख्याः एलएमआई–3791।

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र

रश्मि दीवान

एनसीएसएल के प्रमुख के रूप में, केंद्र के सभी सदस्यों को समन्वित गतिविधियों में मार्गदर्शन, विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को संबोधन एवं अन्य सलाहकारी समितियों की बैठकों आदि का आयोजन किया।

इंटरमीडिएट ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए स्कूल–आधारित सुधार के लिए नेतृत्व उत्तराधिकार पर एक मॉड्यूल प्रस्तुत करके भौतिक विकास में योगदान दिया (4 चतुर्थांश के साथ 3 इकाइयां)

नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन

स्कूल परिसरों/क्लस्टरों के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन पर कार्यकारी समूह के लिए समन्वयक

एम.फिल. में शिक्षण

डॉ कश्यपी अवस्थी के साथ स्कूल नेतृत्व पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम (ओसी 15)

प्रो कुमार सुरेश, प्रो विनीता सिरोही और डॉ सुचरिता के साथ शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन (सीसी 7) पर अनिवार्य पाठ्यक्रम

पीएचडी विद्वानों को मार्गदर्शन

शिवानी बख्शी को 'स्कूल सुधार के लिए नेतृत्व मार्गः केरल के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों पर अध्ययन' विषय पर मार्गदर्शन

सुश्री परविंदर कौर को ''एकीकृत शिक्षक शिक्षाः आरआईई में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी पर अध्ययन' विषय पर मार्गदर्शन

कुमारी पल्लवी को 'स्कूली शिक्षा और कोविड–19 महामारी पर अध्ययनः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए सामान्य के साथ आगे बढ़ना' विषय पर मार्गदर्शन

डेपा प्रतिभागी को मार्गदर्शन

स्क्वाड्रन लीडर विनोद कुमार को जैसलमेर वायु सेना स्कूल में प्रधानाध्यापकों के निर्देशात्मक नेतृत्व की शिक्षकों की धारणा पर अध्ययन' विषय पर मार्गदर्शन

ऑनलाइन वेबिनार

22 जुलाई 2020 को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 संकटों के बीच शैक्षिक नेतृत्व बाधाओं और संभावनाओं की बदलती दुनिया पर मुख्य भाषण

31 अक्टूबर 2020 को एससीईआरटी, जम्मू और कश्मीर द्वारा एनईपी–2020 के संदर्भ में स्कूल परिसरों में जम्मू और कश्मीर राज्य में क्या काम करता है आयोजित वेबिनार में मुख्य भाषण

12 जून 2020 को (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में यंग लाइव्स द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, कोविड–19 के दौरान स्कूल बंद होने पर छात्रों के लिए समर्थन, भारत में बाधित शिक्षा पर चर्चा वेबिनार में भागीदारी

ऑनलाइन वेबिनार में भागीदारी

12 जनवरी, 2021 को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट वेबिनार पर नीति संवाद पर ऑनलाइन वेबिनार

15 दिसंबर 2020 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेशन के लिए सुधार पर ऑनलाइन वेबिनार

8 अगस्त, 2020 को (विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई) द्वारा आयोजित भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि पर ऑनलाइन वेबिनार

19 अगस्त, 2020 को शिक्षा नीति विभाग, नीपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियाँ और रास्ते, पर ऑनलाइन वेबिनार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 पर मा.सं.वि. मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार

अन्य शैक्षणिक गतिविधियां

वार्षिक संगोष्ठी, समीक्षा संगोष्ठी, पूर्व प्रस्तुतीकरण संगोष्ठी, सहकर्मी समीक्षा संगोष्ठी आदि जैसे सभी संगोष्ठियों में अध्यक्ष या विशेषज्ञ के रूप में एम.फिल./पी–एच.डी. छात्र–संबंधी गतिविधियों में शामिल होना, तथा एम.फिल./पी–एच.डी. बैच 2020–2021 के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा एवं पर्यवेक्षण भी शामिल है।

नीपा के अन्य विभागीय बैठकों और गतिविधियों में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित, जिसमें विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक एवं मूल्यांकन इकाई, की सलाहकार समिति, नीपा शामिल हैं।

स्कूल नेतृत्व, स्कूल परिसर, संस्थागत योजना और स्कूल नेतृत्व की भूमिका आदि पर व्याख्यान देने के लिए नीपा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

एनवीएस, सीबीएसई, केवीएस आदि जैसे प्रमुख संस्थानों को परामर्श और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं। विभिन्न मुद्दों पर स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को जानकारी प्रदान की, जिनमें एक है 15000 मॉडल स्कूलों की कार्यान्वयन रणनीति भी है।

समितियों में सदस्यता

अध्ययन बोर्ड

अकादमिक परिषद

योजना और निगरानी

परियोजना सलाहकार बोर्ड

सुनीता चुग

प्रकाशन

पाठ्यचर्या और सामग्री विकास

स्कूल नेतृत्वः निष्ठा के माध्यमिक स्तर के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर मॉड्यूल के विकास में योगदान

स्कूल नेतृत्वः प्रारंभिक स्तर के लिए अवधारणाएं और अभ्यास पर निष्ठा मॉड्यूल के ऑनलाइन संस्करण की संकल्पना और विकास किया

3 इकाइयों (सभी 4 चतुर्थांश) वाली अग्रणी साझेदारी पर मध्यस्थ स्तर के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को पूरा किया और जमा किया।

विकास क्षमता

22–27 फरवरी, 2021 तक ''शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम के लिए हस्तपुस्तिा पर आधारित एनवीएस स्कूलों के प्राचार्यों के लिए शैक्षणिक नेतृत्व पर क्षमता विकास कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया। समन्वयकः डॉ. एन मैथिली और डॉ. सुनीता चुघ .

स्कूल नेतृत्वः टीम के सदस्यों के साथ प्रारंभिक शिक्षा के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए संकल्पित और विकसित निष्ठा वीडियो (अंग्रेजी और हिंदी)

स्कूल नेतृत्व पर प्रासंगिक निष्ठा ऑनलाइन मॉड्यूलः प्रारंभिक शिक्षा के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग (हिंदी)

15–18 दिसंबर, 2020 को सरकारी स्कूलों में छात्र अधिगम और शिक्षण के परिणामों में सुधार के लिए नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यशाला डॉ सुबिता जी. वी. मेनन और डॉ सुनीता चुघ

23 स्कूल लीडरशिप अकादमियों के साथ गूगल मीट का पहला दौर– 2020–21 में किए गए कार्यों की समीक्षा और 2021–22 के लिए कार्य योजना

11 जनवरी 2021 से 27 फरवरी, 2021 तक फरक्का बैराज परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यशाला, चारु स्मिता मलिक और सुनीता चुग

अनुसंधान और विकास

23–24 मार्च 2021 को ''विद्यालय नेतृत्व पर दृष्टिकोण और व्यवहार'' पर शोध वेबिनार की कल्पना, योजना और संचालन किया। डॉ. एन. मैथिली के साथ कार्यक्रम के समन्वयक के रूप में 35 पेपर प्रस्तुत किए जिनमें से 19 विश्वविद्यालयों के शोध पत्र थे और शेष 17 केवीएस और एनवीएस से संबद्ध स्कूलों में काम करने वाले प्राचार्यों द्वारा किए गए अभ्यासों पर आधारित थे।

अनुसंधान परियोजना पूर्ण

भारत के शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों की शैक्षिक भागीदारी का समालोचनात्मक मूल्यांकन।

वर्तमान अध्ययन दस चुनिंदा शहरों की मलिन बस्तियों में स्कूली शिक्षा में बच्चों की भागीदारी का आकलन करने के लिए किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं– महानगरीय शहर, महानगर और अन्य छोटे शहरः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लुधियाना, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, कानपुर, रायपुर का चयन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य मुख्य प्रश्न पूछना थाः दस शहरों की मलिन बस्तियों में बच्चों की पहुंच और भागीदारी में परिवर्तनशीलता को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं? इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं थीं– (1) बच्चों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले घरेलू कारकों की जांच करना और (2) चुनिंदा शहरों में बच्चों की भागीदारी पर 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग और दो डेटासेट के बीच तुलना का पता लगाना। जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि बच्चे छह साल की उम्र में विद्यालय जाना शुरू नहीं करते हैं। इसके अलावा, भागीदारी 7 साल की उम्र से बढ़ जाती है और 9 से 11 साल की उम्र में चरम पर पहुंच जाती है। नामांकन में गिरावट 13 साल की उम्र से शुरू होती है।

जनसंख्या आयु समूह के अनुसार वितरण पर परिवारों से एकत्र किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 6–14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल जाने वाली आबादी कोलकाता को छोड़कर सभी शहरों की चयनित मलिन बस्तियों में 28 से 30 प्रतिशत के बीच है। दस शहरों में झुग्गीवासियों के सामाजिक समूहवार वितरण से पता चलता है कि आधे शहरों में ओबीसी श्रेणी की आबादी हावी है, जबकि चार शहरों में अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। बच्चों के स्कूल जाने की स्थिति के क्षेत्र आंकड़े बताते हैं कि लखनऊ को छोड़कर सभी शहरों में भागीदारी दर 80 प्रतिशत से अधिक है। सभी शहरों में 6–17 वर्ष के आयु वर्ग के ड्रॉप आउट बच्चे 6–17 प्रतिशत की सीमा में हैं, जिनमें लखनऊ की मलिन बस्तियों में स्कूल छोड़ने वालों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सबसे अधिक है। चयनित मलिन बस्तियों में बच्चों की स्कूल जाने की स्थिति सामाजिक श्रेणी के संबंध में कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखाती है। भुवनेश्वर, रायपुर, मुंबई, दिल्ली और कानपुर में चयनित मलिन बस्तियों के बच्चों का उच्च प्रतिशत सरकारी स्कूलों में जा रहा था जबकि हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ में निजी स्कूलों में बच्चों का प्रतिशत अधिक था।

झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा और सार्वभौमिक भागीदारी पर समसामयिक पत्रः मुद्दे अंतराल और चुनौतियां, नीपा समसामयिक पत्र 54, नीपा, 2020

यह पत्र लखनऊ शहर की मलिन बस्तियों के स्कूलों में बच्चों की शैक्षिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। अन्य बातों के साथ–साथ स्कूली शिक्षा में बच्चों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले घरेलू और स्कूलर कारकों की जांच करता है। लखनऊ की चुनी हुई मलिन बस्तियों में स्कूली शिक्षा की सुविधा लगभग सार्वभौमिक है। विशेषरूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित बड़ी संख्या में बच्चों को उनकी उम्र की तुलना में निचली कक्षा में नामांकित किया गया था। निष्कर्ष निजी स्कूलों के लिए अभिभावकों की बढ़ती पसंद के रुझान को भी इंगित करते हैं। माता–पिता की शैक्षिक उपलब्धि का स्तर स्कूल में बच्चों की भागीदारी का एक मजबूत निर्धारक है। ये निष्कर्ष आरटीई 2009 अधिनियम (चुनिंदा संकेतकों पर आधारित विश्लेषण) के कार्यान्वयन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं जो मलिन बस्तियों के संदर्भ में बच्चों के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

स्कूल प्रबंधन समितियाँः भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त सरकार की दिशा में बढ़ने का प्रयास पर आईआईईपी प्रायोजित परियोजना रिपोर्टः

यह अध्ययन आईआईईपी, यूनेस्को, पेरिस के नेतृत्व में शिक्षा में मुक्त शासन पर अध्ययन के एक बड़े संघ का हिस्सा है। इस अध्ययन का केंद्र भारत में मुक्त शासन के एक उदाहरण के रूप में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी, सामुदायिक भागीदारी का एक रूप) की पारदर्शिता शुरू करने, नागरिक जुड़ाव और स्कूली शिक्षा में जवाबदेही बनाने में प्रभावशीलता की खोज में निहित है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर (यूडाईस, एनएएस और एनपीएसएसई) पर एकत्रित स्कूल संबंधी जानकारी

और स्कूल प्रबंधन समितियों के कामकाज पर अखिल भारतीय और सूक्ष्म दोनों तरह के लगभग 50 अध्ययनों की समीक्षा का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन एक अधिकार आधारित ढ़ांचे में भारत में मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में पहल की सराहना करता है। हालांकि, स्कूल सुधार में स्कूल–आधारित प्रबंधन संरचनाओं की अधिक निरंतर और सार्थक भागीदारी को अभी भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की शैक्षिक नीति और कार्यक्रमों में निर्धारित संचालन के इष्टतम स्तर तक पहुंचना है।

प्रकाशन

एजूकेशन इन द फ्रिंग्रेज ऑफ अर्बन सिटीजः हैदराबाद और लुधियाना में मलिन बस्तियों का एक अध्ययन (2021) पर पुस्तक प्रकाशित

यह पुस्तक उन प्रवासियों के परिवेश के इर्द–गिर्द घूमती है, जो शहरों के बाहरी इलाकों में रहते हैं, और अपने बच्चों के जीवनयापन हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए मौजूदा संसाधनों से जूझते हैं। इस पुस्तक का मुख्य तर्क इस बात के इर्द–गिर्द घूमता है कि कैसे शैक्षिक पहुंच (या इसका अभाव) झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के सामाजिक बहिष्कार में योगदान करती है। इस मुख्य तर्क का पता लगाने के लिए, पुस्तक दो महानगरीय शहरों– हैदराबाद और लुधियाना की चयनित झुग्गियों में घरों के स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, अपने बच्चों की पहुंच, भागीदारी और शिक्षार्थियों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृहद और व्यापक सर्वेक्षण निष्कर्षों को प्रस्तुत करती है। निष्कर्षों से पता चलता है कि हैदराबाद और लुधियाना दोनों में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की शैक्षिक पहुंच के इष्टतम स्तर से कम थी। लैंगिक असमानता, सरकारी और निजी स्कूलों के आधार पर भागीदारी के भेदभाव और अधिगम की उपलब्धि के स्तर के मामले में दोनों मलिन बस्तियों के भीतर हाशिए पर मौजूद थीं। हालाँकि, स्कूली शिक्षा सुविधाओं की कमी, स्कूली शिक्षकों और बच्चों की भाषा के बीच शिक्षा के समान माध्यम की अनुपस्थिति, खराब शिक्षण गुणवत्ता, कभी–कभी नहीं होने की उच्च घटनाओं के कारण लुधियाना में झुग्गी बस्तियों की स्थिति अधिक थी, नामांकित बच्चे, भागीदारी में लैंगिक असमानता, विशेष रूप से हैदराबाद में मलिन बस्तियों की तुलना में भाषा और उपलब्धि के निम्न स्तर, माता–पिता की निम्न शैक्षिक और आर्थिक स्थिति बच्चों की स्कूल जाने की स्थिति को प्रभावित करती है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के अधिगम की उपलब्धि के स्तर के संदर्भ में, यह पाया गया कि दोनों शहर की मलिन बस्तियों में, स्तर निम्न थे; हालांकि, लुधियाना की मलिन बस्तियों में कम, यह दर्शाता है कि खराब शैक्षिक पहुंच (शिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में) ने हैदराबाद की मलिन बस्तियों की तुलना में अधिगम के स्तर के भीतर भी 'हाशिए पर' ला दिया। इस शोध के निष्कर्ष पुस्तक के केंद्रीय तर्क की पुष्टि करते हैं कि शैक्षिक पहुंच मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के सामाजिक बहिष्कार में योगदान करती है।

भारत में माध्यमिक शिक्षाः विकास और असमानताएं तिलक, जंध्याला बी.जी. (संपादित) पुस्तक में (सह–लेखक) – भारत में सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षाः मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं, पर एक लेख स्प्रिंगर, जुलाई 2020

एम.फिल. कार्यक्रम में भागीदारी

एम.फिल. वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–8 शिक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारः योजना पर सत्रों का संचालन एवं मूल्यांकन के सह–संयोजक

एम.फिल. वैकल्पिक पाठ्यक्रम ओसी–9 शिक्षा, लैंगिक और विकास योजना, सत्र का संचालन और मूल्यांकन के सह–संयोजक

वेबिनार में भागीदारी

5 मई 2021 को आरटीई फोरम द्वारा आयोजित 'चुनौतीपूर्ण समय में शिक्षा के अधिकार की पुष्टि' वेबिनार में भागीदारी

14 मई, 2021 को आरटीई फोरम द्वारा 'कोविड 19 एवं बालिका शिक्षा' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

21 मई, 2021 को ''शिक्षा का सार्वभौमीकरण और कोविड–19 संकट से उभरती चुनौतियाँ'' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

अगस्त 8, 2021 को (विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक और मूल्यांकन इकाई) द्वारा 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

19 अगस्त, 2021 को शैक्षिक नीति विभाग, नीपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियाँ और मार्ग, पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

वेबिनार में प्रस्तुति

10 फरवरी 2021 को विद्यालय नेतृत्व अकादमी, एससीईआरटी, तेलंगाना द्वारा सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से आयोजित विद्यालय नेतृत्व पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक में विद्यालय नेतृत्वः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विषय पर वक्ता के रूप में भागीदारी।

एससीईआरटी, आंध्र प्रदेश द्वारा 'विद्यालय नेतृत्वः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, पर सलाहकारी बैठक में भगीदारी

26 सितंबर, 2020 को विद्यालय परिसर/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी शासन, राज्य स्तरीय वेबिनार, उत्तराखंड

5 नवंबर, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित 'एनईपी–2020: अग्रणी विद्यालय परिसर और स्थानीय शासन' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

22 दिसंबर, 2020 को विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम के शुभारंभ पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

21 मई 2020 को, एससीईआरटी, तेलंगाना द्वारा आयोजित, विद्यालय नेतृत्व पर वेबिनार श्रृंखला में विद्यालय नेतृत्वः राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विषय पर एक सत्र आयोजन किया

23–24 मार्च 2021 को एनसीएसएल–नीपा द्वारा आयोजित विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य और प्रथाओं पर वेबिनार में 'बदलते संदर्भ में स्कूल नेतृत्वः एनईपी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दें' विषय पर पैनल चर्चा में अध्यक्ष

अन्य संगठनों में व्याख्यान दिए

30 सितंबर 2020 को समग्र शिक्षा, सिद्दीपेट, तेलंगाना द्वारा आयोजित विद्यालय प्रमुखों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम, में व्याख्यान

विद्यालय नेतृत्वः अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर डीएमएस शिक्षकों के लिए निष्ठा पर व्याख्यान

2 दिसंबर, 2020 को महाराष्ट्र शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन पर पीएसएलएम कार्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने पर मुख्य वक्त

7 जनवरी, 2021 को विद्यालय नेतृत्वः एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर एनसीईआरटी के संकाय के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में सत्र

'शिक्षार्थियों और अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी के लिए मूल्यांकन विशेषज्ञ

एसएलए–एससीईआरटी, टीएस, हैदराबाद – सेव द चिल्ड्रन (एनजीओ) के सहयोग से विद्यालय नेतृत्व पर राष्ट्रीय आभासी सलाहकार बैठक में विशेष आमंत्रिति अतिथि

नीपा शैक्षणिक गतिविधियां

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए नीपा में निम्नलिखित थिंक टैंक समूहों में योगदानः

समानता, गुणवत्ता और समावेशन

विद्यालय–पूर्व शिक्षा और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता को सार्वभौम बनाना

12 मार्च, 2020 को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के बाद मा.सं.वि.मंत्रालय से संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीबी) तैयार किया और एमएचआरडी को प्रस्तुत किया।

हिंदी जर्नल परिपेक्ष्य की संपादकीय समिति के सदस्य

परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में परिणाम की तैयारी और एम.फिल. और पीएच.डी. उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा में भाग लिया।

एम.फिल. पर्यवेक्षक

एम.फिल. छात्र शादाब अनीस के 'शहरी सीमान्तता और शैक्षिक स्थितिः पटना के मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों का अध्ययन' शीर्षक का पर्यवेक्षण।

एम.फिल. छात्रा सुश्री अनुष्का तिवारी के 'दिल्ली में अफगान शरणार्थियों की उच्च शिक्षा' शीर्षक का पर्यवेक्षण

पी–एच.डी. पर्यवेक्षक

पी–एच.डी. प्रतिभागी देपिंदर कौर के 'पंजाब में स्कूल शिक्षक भर्ती का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' शीर्षक का पर्यवेक्षण।

पी–एच.डी. प्रतिभागी मृण्मयी मंडल के 'स्कूल के शिक्षकों और प्रशासकों के बीच लैंगिक न्याय की अवधारणा, समझ और अभ्यासः दिल्ली के सरकारी स्कूल का अध्ययन' शोध का पर्यवेक्षण।

पी–एच.डी. प्रतिभागी शादाब अनीस के 'शहरी हाशिये पर पड़े लोगों का सामाजिक बहिष्करणः स्लम बस्तियों के बच्चों की शिक्षा पर स्थानिक विषमताओं का प्रभाव' विषय का पर्यवेक्षण

पीजीडेपा पर्यवेक्षक

पीजीडेपा प्रतिभागी रोशनी के 'मध्यप्रदेश के देवास और इंदौरा जिले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाले सुविधाओं के आकलन' शीर्षक का पर्यवेक्षण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श एवं अकादमिक सहायता

स्टार प्रोजेक्ट (राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों के मजबूतीकरण) पर शिक्षा मंत्रालय के विचार–विमर्श में भागीदारी

दीक्षा पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वर्गीकरण विकसित करने के लिए कार्य समूह

केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए एनईपी–2020 के तहत प्रमुख विषयों पर (चल रही) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में एक विशेषज्ञ के रूप में अकादमिक समर्थन प्रदान की।

कश्यपी अवस्थी

प्रकाशन

पुस्तकें/अनुसंधान आलेख/रिपोर्ट/दिशानिर्देश

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य समिति के सदस्य के रूप में विद्यालयों को सुरक्षित और भय मुक्त बनानाः कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विकसित किया और विद्यालयों में सुरक्षा और इसके दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर दो अध्याय जिनमें एक नई शिक्षा नीति के आलोक में और दूसरा स्कूलों के हितधारक मूल्यांकन के लिए उपकरणों पर जोड़े गये हैं।

वर्ष के दौरान वेबिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

21 और 22 जनवरी, 2021 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित सिक्किम में 5वें शिक्षक शिक्षक सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित और सिक्किम राज्य के लिए विद्यालयों परिसरों के विकासः नीतिगत निहितार्थ और संभावनाएं पर एक पत्र प्रस्तुत किया। .

नीचे निर्धारित सभी वेबिनारों में प्रस्तुतकर्ता और संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित

28 मई 2020 को (दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे) तक डॉ. एच.आर. गजवानी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गुजरात द्वारा चिंतनशील प्रयोगकर्ता होने के नाते अकादमिक नेतृत्व की कला पर आयोजित वेबिनार

10 जून 2020 को (शाम 4:30 से शाम 6:30 बजे) तक उत्तर प्रदेश में स्कूल प्रमुखों व्यावसायिक संघ द्वारा आयोजित मिशन शिक्षण संवाद आईसीटी कार्यशाला–2020

15 जून, 2020 (03:00 अपराह्न से 05:00 बजे) तक राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा चिंतनशील प्रमुख के रूप में स्वयं का विकास करना पर आयोजित वेबिनार

24 जून, 2020 को (दोपहर 03:00 बजे से शाम 5:00 बजे) तक दूरस्थ अधिगम और डिजिटल डिवाइडः समानता के मुद्दों पर निर्देश पर अभिभाषण डाइट, पीतमपुरा, दिल्ली

9 अगस्त, 2020 को (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे) तक समष्टि एकीकृत शिक्षण संस्थान, गुजरात द्वारा आयोजित वेबिनार 'नई शिक्षा नीतिः शिक्षक शिक्षा पर विचार' में भागीदारी

4 सितंबर, 2020 को (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे) तक जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित विद्यालय परिसरों की स्थापना के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी अभिशासन पर वेबिनार में भागीदारी

11 सितंबर, 2020 को (दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे) तक टाटा ट्रस्ट्स द्वारा आयोजित 'स्कूल परिसरों की स्थापना के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी अभिशासन' पर वेबिनार में भागीदारी

4 से 14 सितंबर, 2020 सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और दोपहर 2:00 से 4:00 बजे) तक समानता और उत्कृष्टता के लिए नेतृत्वः ईएमआरएस में स्कूल के प्रधानाध्यापकों की क्षमता निर्माण', पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ आयोजित दस दिवसीय कार्यशाला में भागीदारी

19 सितंबर, 2020 को (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे) तक रवींद्र ठाकुर महाविद्यालय, त्रिपुरा द्वारा 'नई शिक्षा नीतिः स्कूल शिक्षा में सुधार' पर आयोजित वेबिनार

16 अक्टूबर, 2020 को (शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे) तक शिक्षा आज, समाज कल – परिवर्तन की पहल, भारत द्वारा अयोजित विद्यालयों का पुनर्निमाण, दुनिया का पुनर्निमाण (वेब सीरीज) में भागीदारी

09 नवंबर, 2020 को (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे) तक एससीईआरटी, त्रिपुरा द्वारा नई शिक्षा नीतिः स्कूल शिक्षा में सुधार और स्कूल प्रमुखों की बदलती भूमिका पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

22 फरवरी, 2021 को (शाम 6:30 से 8:30 बजे) तक सरस्वती विद्यापीठम, तेलंगाना द्वारा नई शिक्षा नीति 2020ः अधिगम और आकलन पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

27 फरवरी, 2021 को (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे) तक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित मानसिक मॉडल और शैक्षणिक नेतृत्व संकाय विकास कार्यशाला में भागीदारी

27 फरवरी, 2021 को (अपराह्न 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे) तक एएससी, जाधवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित अकादमिक नेतृत्व संकाय विकास कार्यक्रम में भागीदारी

12 मार्च, 2021 को (2:30 से शाम 4:00 बजे) तक सीआईईटी, एनसीईआरटी द्वारा मनोदर्पण पहल परीक्षा तनाव और चिंता से निपटना पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

26 मार्च, 2021 (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे) तक एसएलए, सीमैट राजस्थान द्वारा प्रभावी स्कूल परिसरों का विकासः नीति और अभ्यास पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

31 मार्च, 2021 (शाम 6:00 बजे से रात 8:00 बजे) तक निजी स्कूल प्राचार्य संघ, हैदराबाद द्वारा नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी विद्यालय नेतृत्व पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

07 अप्रैल, 2021 को (02:30 अपराह्न से 04:00 बजे) तक मनोदर्पण पहल, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा स्कूल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याणः उभरती आवश्यकताएं, समाधान और अच्छे व्यवहारकर्ता पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और छात्रों की चिंताओं की निगरानी और कोविड के बाद मानसिक स्वास्थ्य और विकास के मनोसामाजिक पहलुओं का समर्थन, मनोदर्पण (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल) कार्य समूह के सदस्य

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रणाली स्तर के अधिकारियों, स्कूल प्राचार्यों, उप–प्राचार्यों और शिक्षकों के चयन के लिए पाठ्यक्रम और दिशा–निर्देशों में संशोधन के लिए समिति के सदस्य

नीपा और एससीईआरटी, सिक्किम द्वारा संयुक्त रूप से विशेषकर विद्यालय परिसरों के विकास हेतु सिक्किम राज्य में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्य समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत

दीक्षा (डिजिटल ज्ञान साझा करने और उन्नति के लिए पहल) और विद्यालय नेतृत्व के लिए वर्गीकरण के विकास कार्य हेतु संचालन समिति के सदस्य

दीक्षा के लिए 'ई–सामग्री विकास हेतु दिशानिर्देशों' के विकास के लिए संचालन समिति के सदस्य और एनसीईआरटी पोर्टल पर प्रकाशित दिशानिर्देशों के विकास के लिए सीआईईटी, एनसीईआरटी के सहयोग से काम किया।

सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित स्कूल सुरक्षा एवं सिक्योरिटी पर दिशानिर्देशों के विकास हेतु समिति के सदस्य।

आईयूसीटीई के सलाहकार समूह के सदस्य, शिक्षा विभाग, एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, गुजरात।

शिक्षक शिक्षा निदेशालय, एससीईआरटी, ओडिशा द्वारा गठित शिक्षक शिक्षा पर थिंक टैंक के सदस्य।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित

सुरक्षित और भयमुक्त स्कूल पर मौजूदा दिशानिर्देशों में नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप एक नया अध्याय जोड़ा, जिसे स्कूल सुरक्षा और सिक्योरिटी समिति के एक भाग के रूप में तैयार किया गया।

स्कूलों में सुरक्षा और भयमुक्त माहौल के आकलन के लिए हितधारक मानचित्रण उपकरण विकसित किये।

मनोदर्पण (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल) के कार्यकारी समूह के सदस्य के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और छात्रों की चिंताओं की निगरानी और कोविड के बाद छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए सलाहकारी दिशा–निर्देश विकसित किए

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए 'समानता और उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व' पर मसौदा प्रशिक्षण सामग्री विकसित की

केंद्रीय विद्यालयों में चयन परीक्षा के पाठ्यक्रम और प्रणाली स्तर के अधिकारियों, स्कूल के प्राचार्यों, उप–प्राचार्यों और शिक्षकों के चयन के लिए दिशा–निर्देशों को संशोधित किया।

अन्य अकादमिक और व्यावसायिक योगदान

28 दिसंबर, 2020 को डाइट ऊना में हिमाचल प्रदेश के स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए ऑनलाइन समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला आयोजित की गई

24–25 मार्च, 2021 को राजस्थान में राज्य संसाधन समूह के सदस्यों के साथ स्कूल नेतृत्व विकास पर मॉड्यूल के विकास हेतु विद्यालय नेतृत्व अकादमी, सीमैट, राजस्थान के साथ दो दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया

21 सितंबर, 2020 से 1 अक्टूबर, 2020 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के स्कूल प्रधानाचार्यों का दस दिवसीय ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन

5 और 6 अप्रैल, 2021 को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए ऑनलाइन समीक्षा और प्रतिक्रिया कार्यशाला का आयोजन

शिक्षण

प्रो. रश्मि दिवान के साथ स्कूल नेतृत्व पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम को साझा किया और 9 सत्रों में शिक्षण।

एम.फिल. कार्यक्रम

सुश्री पल्लवी कुमारी को ''शिक्षक शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का एकीकरणः नीति और व्यवहार का अध्ययन'' विषय पर मार्गदर्शन।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा (पीजीडेपा)

पीजीडेपा प्रतिभागी सुश्री पूर्णिमा चौधरी को ''आसाम के गोलपारा जिले में दूधनोई ब्लॉक के विद्यालयों में शैक्षणिक पर्यवेक्षण प्रतिक्रिया की प्रक्रिया और अभ्यास का अध्ययन'' विषय पर शोध मार्गदर्शन।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आइडेपा)

आईडेपा प्रतिभागी श्री द्वा गेलसेन को ''सरपंग डोंगकोंग में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अग्रणी शिक्षकों की कमी के कारकों का अध्ययन'' विषय पर मार्गदर्शन।

आइडेपा प्रतिभागी श्री मुटिंटा चोंय्या को ''जाम्बिया के काबवे जिले के स्कूलों में महिला प्रधान शिक्षकों की चुनौतियों का आकलन'' का अध्ययन विषय पर मार्गदर्शन।

सुभीथा जी.वी.

सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं में भागीदारी

7 अगस्त, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सम्मेलन में भागीदारी

8 अगस्त, 2020 को विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, स्कूल मानक और मूल्यांकन इकाई, नीपा, नई दिल्ली द्वारा 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं:

शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी

19 अगस्त, 2020 को शैक्षिक नीति विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: संभावनाएं, चुनौतियां और मार्ग पर आयोजित सम्मेलन में भागीदारी

21 मई, 2020 को, एससीईआरटी, तेलंगाना द्वारा आयोजित, स्कूल नेतृत्व पर वेबिनार श्रृंखला में 'स्कूल नेतृत्व और शिक्षक व्यावसायिक विकास' विषय पर एक सत्र आयोजित किया

26 अगस्त 2020 को समग्र शिक्षा, तेलंगाना द्वारा आयोजित केजीबीवी के विशेष अधिकारियों के लिए नेतृत्व कार्यक्रम में 'चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक' विषय पर एक सत्र आयोजित किया

19 सितंबर 2020 को समग्र शिक्षा, वारंगल, शहरी, तेलंगाना द्वारा आयोजित स्कूल प्रमुखों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम में 'शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बदलने के लिए नेतृत्व' विषय पर एक सत्र आयोजित किया

30 सितंबर, 2020 को समग्र शिक्षा, सिद्दीपेट, तेलंगाना द्वारा आयोजित स्कूल प्रमुखों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम ने 'शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को बदलने के लिए नेतृत्व' विषय पर एक सत्र आयोजित किया

10 फरवरी, 2021 को सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग से स्कूल नेतृत्व अकादमी, एससीईआरटी, तेलंगाना द्वारा आयोजित स्कूल नेतृत्व पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक में 'विद्यालय नेतृत्व अकादमी और इसकी यात्रा' विषय पर वक्ता के रूप में भागीदारी

8–12 मार्च, को विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा, चुनौतियाँ और अवसर में लैंगिक समानता पर वार्षिक कार्यशाला में 'एनईपी–2020 के आलोक में हाशिए की आबादी से लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों में सुधार का दायरा' पर सत्र की अध्यक्षता की

23–24 मार्च, 2021 को एनसीएसएल–नीपा द्वारा विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य और प्रथाओं पर आयोजित वेबिनार में 'बदलते संदर्भ में स्कूल नेतृत्व: एनईपी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान' विषय पर पैनल चर्चा में वक्ता के रूप में भागीदारी।

वर्ष 2020–21 के लिए कार्य योजना पर उन्मुख करने के लिए असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में गठित स्कूल नेतृत्व अकादमियों के साथ अभिविन्यास कार्यशालाओं में भागीदारी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित

15–18 दिसंबर 2020 को सरकारी स्कूलों में छात्रों के अधिगम और शिक्षण के परिणामों में सुधार के लिए नेतृत्व विकास पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया

एनसीएसएल–राष्ट्रीय सलाहकार समूह की बैठक का आयोजन (2020–21)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

विद्यालय नेतृत्व और विकास में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बदलाव' विषय पर मध्यावधि पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की

विद्यालय नेतृत्व और विकास पर उन्नत स्तर के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए 'चिंतनशील अभ्यासकर्ता के रूप में शिक्षक' विषय पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

संसाधन व्यक्ति के रूप में केन्द्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए एनईपी–2020 के तहत प्रमुख विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में अकादमिक सहायता प्रदान की।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए नीति सहायता प्रदान करने हेतु नीपा द्वारा गठित निम्नलिखित थिंक टैंक समूहों में योगदान:

प्रभावी संसाधन साझाकरण और स्थानीय स्तर के शासन हेतु स्कूल परिसरों का निर्माण

शिक्षक विकास और प्रबंधन

एन. मैथिली

पाठ्यचर्या एवं सामग्री विकास

शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका (लेखक एन. मैथिली, नवंबर 2020)

शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका का दूसरा संस्करण बनाया (लेखकः एन. मैथिली, मार्च 2021)

विद्यालय नेतृत्व पर निष्ठा कार्यक्रम के माध्यमिक स्तर के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर मॉड्यूल के विकास में योगदान

प्राथमिक स्तर के लिए स्कूल नेतृत्व और अवधारणाओं पर निष्ठा मॉड्यूल के ऑनलाइन संस्करण का पहला मसौदा तैयार करने में सहयोग

'विद्यालय प्रमुखः नवाचारों के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति' पर 4 इकाइयों (सभी 4 चतुर्थांश) वाले अग्रणी नवाचारों पर मध्यस्थ स्तर के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को पूरा किया और प्रस्तुत किया

क्षमता विकास

22–27 फरवरी 2021 तक 'शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका' के आधार पर एनवीएस स्कूलों के प्राचार्यों के लिए शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व पर क्षमता विकास कार्यक्रम के पहले बैच का आयोजन किया तथा डा. सुनीता चुघ के साथ समन्वय किया।

एनसीईआरटी द्वारा आयोजित विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा कार्यक्रम ''अकादमिक नेतृत्व'' विषय पर एनसीईआरटी के प्रदर्शन के लिए संसाधन व्यक्ति

''स्कूल नेतृत्वः अवधारणाएं और अनुप्रयोग'' मॉड्यूल पर आंध्र प्रदेश के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा कार्यक्रम (ऑनलाइन) के लिए संसाधन व्यक्ति
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QrGy5iAfEwQ&t=900s

अन्य निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

स्कूल नेतृत्व अकादमियों को छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, सिक्किम, केरल, गोवा, मेघालय, मणिपुर) में स्कूल नेतृत्व विकसित करने पर सौंपे गए कार्यों के संबंध में मार्गदर्शन एवं समन्वयन किया

शैक्षणिक नेतृत्व ढांचे को विकसित करने के लिए सीबीएसई के साथ सहयोग किया

शैक्षणिक नेतृत्व पर प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन परीक्षण तैयार करने के लिए एनवीएस के साथ सहयोग किया

शैक्षणिक नेतृत्व पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के क्षमता विकास के संचालन के लिए एनवीएस के साथ सहयोग किया

अनुसंधान और विकास

अनुसंधान परियोजना पूर्ण

क) परियोजना का शीर्षकः भारत में सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के लिए शैक्षणिक नेतृत्व।

एजेंसीः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली

अवधिः दिसंबर 2019 से नवंबर 2020

परियोजना आउटपुटः ''भारत में सीबीएसई विद्यालयों में काम कर रहे प्रधानाध्यापकों के लिए शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व पर हस्तपुस्तिका''।

ख) परियोजना का शीर्षकः ''शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका'' पुस्तक के आधार पर प्राचार्यों के क्षमता विकास के लिए पूर्व और पश्चात के परीक्षण आयोजित करने हेतू मूल्यांकन ढांचा विकसित करना। एनवीएस के प्राचार्यों के लिए प्रशासित मूल्यांकन परीक्षण शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व हस्तपुस्तिका के आधार पर विकसित किए तथा इसके बाद 55 प्राचार्यों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया।

एजेंसीः नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा

अवधिः जनवरी से अप्रैल 2021

परियोजना आउटपुटः शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व हस्तपुस्तिका पर आधारित 55 प्राचार्यों के पूर्व और पश्चात मूल्यांकन विषय और प्रशिक्षण। प्रतिभागियों ने अपने संबंधित स्कूलों के लिए एक नमूना वार्षिक शैक्षणिक योजना विकसित की और प्रस्तुत किये।

ग) 23–24 मार्च 2021 को सुनीता चुग के साथ कार्यक्रम की समन्वयक के रूप में ''विद्यालय नेतृत्व पर दृष्टिकोण और व्यवहार'' पर शोध वेबिनार का आयोजन और संचालन तथा 35 पत्र प्रस्तुत किए गए जिनमें से 19 विश्वविद्यालयों के शोध पत्र और शेष 17 केवीएस और एनवीएस से संबद्ध स्कूलों में काम करने वाले प्राचार्यों द्वारा किए गए अभ्यासों पर आधारित थे।

संगोष्ठी/सम्मेलन में प्रस्तुत शोधपत्र

23–24 मार्च, 2021 को एनसीएसएल, नीपा, नई दिल्ली द्वारा ''विद्यालय नेतृत्व के संचालकों की खोजः क्रियाएँ या मूल्य?'' पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में ''विद्यालय नेतृत्व पर दृष्टिकोण और व्यवहार'' पर पत्र प्रस्तुत।

प्रकाशन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित ''शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका'' (पहला संस्करण, नवंबर 2020)।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित ''शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका'' (दूसरा संस्करण, मार्च 2021)।

''क्षेत्रीय विविधता, स्कूल नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण शिक्षाः भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन'' (''माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण'' पर संपादित वाल्यूम में अध्याय। जेबीजी तिलक द्वारा संपादित, नई दिल्ली, भारतः स्प्रिंगर, 2020)।

व्याख्यान दिये

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा पीएमएमएमएनएनटीटी, भारत सरकार के तहत आयोजित शिक्षण और अधिगम पर 10 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में ''अधिगम के लिए नेतृत्व'' पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित।

जनवरी 2020 में (पीएमएमएमएनएनटीटी, भारत सरकार) मानव संसाधन विकास केन्द्र, जेएनयू, नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित ''विद्यालय नेतृत्वः अवधारणाएं और अनुप्रयोग'' शिक्षक विशरदों के लिए उन्मुखीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में 2018 से कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य और 4 साल से स्कूल नेतृत्व पर विभिन्न सत्रों में वार्ताएं।

8 मार्च 2021 को सामाजिक विकास परिषद, लोधी रोड, नई दिल्ली द्वारा महिला नेतृत्वः परिप्रेक्ष्य और समस्याएं पर वार्ता के लिए पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित

9 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीपा नई दिल्ली द्वारा आयोजित लैंगिक समानता पर कार्यशाला में ''स्कूल नेतृत्व में महिलाएं'' पर एक व्याख्यान दिया

6 मार्च 2021 को इंडियन फोरम ऑफ एजुकेटर्स मुंबई में शिक्षाशाास्त्रीय नेतृत्व पर व्याख्यान दिया

मान्यता प्राप्त

''शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्वः विद्यालयों में अधिगम नेतृत्व के लिए हस्तपुस्तिका'' को इसकी गुणवत्ता और स्कूलों के लिए प्रयोज्यता के लिए व्यापक मान्यता मिली एवं सुश्री अनीता करवाल, सचिव स्कूल शिक्षा और साक्षरता, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ''उत्कृष्ट'' के रूप में उच्च सराहना की गई।

दीक्षा पोर्टल में शामिल करने हेतु मंत्रालय द्वारा शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व पर हस्तपुस्तिका का सुझाव दिया

गया। इसके आधार पर, नीपा को दीक्षा पोर्टल पर पट्टेदारी भी दी गई ताकि शिक्षाशास्त्रीय नेतृत्व पर हस्तपुस्तिका के अलावा नीपा के कई अन्य कई कार्य भी दीक्षा पोर्टल में जा सकें।

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एनवीएस प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की गई, क्योंकि यह शत–प्रतिशत सफल रहा।

चारु स्मिता मलिक

कार्यशालाएँ/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

11 जनवरी 2021 से 27 फरवरी 2021 तक फरक्का बैराज परियोजना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, मुर्शिदाबाद, के लिए नेतृत्व विकास कार्यशाला (प्रो. सुनीता चुग के साथ सह–आयोजित)

2 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा ''पीएसएलएम– विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन पर कार्यक्रम'' पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने में भागीदारी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/संचालित

स्कूल नेतृत्वः निष्ठा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्राथमिक स्कूल प्रमुखों के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर विकसित ऑनलाइन मॉड्यूल

स्कूल नेतृत्वः निष्ठा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में प्राथमिक स्कूल प्रमुखों के लिए अवधारणाएं और अनुप्रयोग पर ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए 12 वीडियो दस्तावेज विकसित किए

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र

निधि एस. सभरवाल

प्रकाशन

पुस्तक में लेख और अध्याय

सभरवाल, एन.एस., जोसेफ आर.एस., बांकर ए., और तलमाले ए. (2021). एक्सैसिंग साइलेंस वॉइस? डायरी मैथड एज अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर अंडरस्टेंडिंग हायर एजूकेशन एक्सपीरियंए ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोसियली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स. ज्यूमेंग काओ और एमिली एफ. हेंडरसन (सं.) एक्सप्लोरिंग डायरी मैथड्स इन हायर एजूकेशन रिसर्चः ऑपरच्युनिटीज, च्वॉइसेज एंड चैलेंजेज. लंडन, रूटलेज, पीपी 131–144।

सभरवाल, एन.एस. (2020). मेंनेजिंग स्टूडेंट डायवरसिटी इन इंडियन हायर एजूकेशन इंस्टीट्यूशंसः अचीविंग एकेडमिक इंटेग्रेशन एंड सोशियल इन्क्लूजन. एन.वी. वर्गीज और गरिमा मलिक (सं.), गवर्नेंस एंड मेंनेजमेंट ऑफ हायर एजूकेशन इन इंडिया. नई दिल्ली, सेज, पीपी. 315–344।

सभरवाल, एन.एस. (2020). कास्ट रिलेशंस इन स्टूडेंट डायवरसिटीः थिंकिंग थ्रू डा. अम्बेडकर पर्सपैक्टिव टूवार्डस ए सिविक लर्निंग एप्रोच इन हायर एजूकेशन। द इंटरनेशनल एजुकेशन जर्नलः कम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव, 19(1), पीपी. 31–43.

सभरवाल, एन.एस. और टियरनी, डब्ल्यू.जी. (2020). ''अनालाइजिंग द कल्चर ऑफ क्रप्शन. ऐलेना डेनिसोवा–स्मिथ (सं.), क्रप्शन इन हायर एजूकेशनः

ग्लोबल चैलेंजेज एंड रिसपांसेज (पीपी. 111–116)। ब्रिल सेंस।

सभरवाल, एन.एस., हेंडरसन, ई.एफ., और जोसेफ, आर. एस. (2020).हिडन सोशल एक्सक्लूजन इन इंडियन एकेडेमियाः जेंडर, कास्ट एंड कांफ्रेंस पार्टिसिपेशन। जेंडर एंड एजूकेशन, 32(1), 27–42.

हेंडरसन, ई.एफ. और सभरवाल, एन.एस. (2020). फेमिनिस्ट अनालिसिस. मिरियम ई. डेविड और मर्लिन जे. अमे (सं.) में, द सेज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ हायर एजुकेशन, सेज।

सभरवाल, एन.एस. (2020). स्टूडेंट डायवरसिटी एंड डिस्क्रीमिनेसन इन इंडियन हायर एजूकेशनः करिकुला ट्रांसफारमेशन फॉर सिविक लर्निंग. आंद्रे माज़ावी और मिशेल स्टैक (सं.) बॉडीज ऑफ नौलेज एंड दियर डिसकन्टेंट्सः क्रिटिकल इंटरनेशनल पर्सपैक्टिव्ज ऑन कोर्स सिलेबी इन फैकल्टीज ऑफ एजूकेशन. ब्लूम्सबरी।

वर्गीज, एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (आगामी)। इक्विटी इन हायर एजूकेशन फॉर इन्क्लूसिव ग्रॉथः एविडेंस फ्रॉम इंडिया. सौमेन चट्टोपाध्याय, साइमन मार्जिन्सन और एन.वी. वर्गीज (सं.). चेजिंग हायर एजूकेशन इन इंडिया. लंदनः ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग.

सभरवाल एन.एस. (आगामी): द नेचर ऑफ एक्सेस टू हायर एजूकेशन इन इंडियाः इमरजिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल एंड स्पेटिअल इनएक्वालिटीज इन एजूकेशनल ऑपरच्यूनिटीज. महाबीर एस. जगलान और राजेश्वरी (सं.) रिफ्लैक्शंस ऑन 21 सेंचुरी ह्यूमन हैविट्स इन इंडिया. स्प्रिंगर नचर, सिंगापुर।

सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (आगामी). मिक्स मैथड्स अप्रोज एंड क्वालिटेटिव मैथडोलॉजी फॉर हायर एजूकेशन पॉलिसी रिसर्च. जॉर्ज डब्ल्यू. नोब्लिट (सं.). ऑक्सफोर्ड रिसर्च इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्वालीटेटिव रिसर्च मैथड्स इन एजूकेशन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट

प्रोफेसर ओडिले हेनरी, डा. जिणुशा पाणिग्रही और डॉ. निधि एस. सभरवाल द्वारा ईएसपीआई इंडिया रिपोर्टः हायर एजूकेशन इन इंडिया एंड सोशल इनैक्वालिटीज, ईएसपीआई, पेरिस/सीपीआरएचई–नीपा, नई दिल्ली, 2020

वेबिनार/प्रस्तुत पत्र/पैनल वक्ता में भागीदारी

24 फरवरी, 2021 को डरहम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एजुकेशन सेमिनार सीरीज द्वारा आयोजित हरियाणा, भारत में उच्चतर शिक्षा विकल्प के लिए जेंडर कैचमेंट क्षेत्रों पर प्रस्तुति, डरहम विश्वविद्यालय,

9 फरवरी, 2021 को डिबेटिंग सोसाइटी सेंट स्टीफन कॉलेज द्वारा आयोजित ''भारतीय उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन – एनईपी 2020 के प्रभाव पर मुखर्जी स्मारक वार्ता पैनल चर्चा में एनईपी 2020 और भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए निहितार्थ'' पर पैनल वक्ता।

23 जनवरी, 2021 को रीथिंकिंग इकोनॉमिक्स इंडिया नेटवर्क (आरईआईएन), ''अर्थशास्त्रः विविधता और समावेशन' पर कार्यक्रम में उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव पर पूर्ण सत्र में पैनल वक्ता।

15 दिसंबर 2020 को (15:00 – 17:30 बजे) तक सीपीएचआरई/नीपा द्वारा आयोजित 'भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेशन के लिए सुधार' शीर्षक से, नीति संवाद वेबिनार में भारत में उच्च शिक्षा में अकादमिक एकीकरण और समावेशन की चुनौतियों पर प्रस्तुति

5 दिसंबर, 2020 को सावित्री बाई फुले महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर, राजस्थान, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावती विश्वविद्यालय, सीकर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर और भूगोल विभाग, राजकीय लोहिया कॉलेज, चुरू, राजस्थान, सहयोगात्मक ज्ञान भागीदारों के रूप में उच्च शिक्षा में मिश्रण अनुसंधानः मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों को एकीकृत करने पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान कैसे करें पर विश्लेषण संकल्पना और पद्धतिगत हस्तक्षेप पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान

11 नवंबर, 2020 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल कार्यान्वयन, अवसर, चुनौतियां

और संभावित रोडमैप, पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में पैनल वक्ता।

28 अक्टूबर, 2020 को राजकीय कला महाविद्यालय सीकर (राजस्थान) द्वारा नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षाः संभावनाएं और चुनौतियां, पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में पैनल वक्ता

20 अगस्त, 2020 को 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर नीपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

19 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक) नीपा द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियाँ और मार्ग' पर राष्ट्रीय वेबिनार में भागीदारी

8 अगस्त, 2020 को (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे) तक विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग और स्कूल मानक और मूल्यांकन इकाई, नीपा द्वारा 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

24 जुलाई, 2020 को नीपा द्वारा आयोजित 'कोविड महामारी के दौरान उच्चतर शिक्षा' पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

6 जुलाई 2020 को ब्रिटिश काउंसिल की यूकेआईईआरआई स्पार्क वेबिनार श्रृंखलाः 'मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लैंगिक अध्ययन' द्वारा आयोजित हरियाणा में शैक्षिक सफलता के लिए लैंगिक मार्ग पर वेबिनार में पैनल वक्ता

18 मई 2020 को स्कूल ऑफ लॉ और वारविक एजूकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट, वारविक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों तक पहुंच में असमानताओं की गतिशीलता, पर वेबिनार में पैनल वक्ता

संगोष्ठी / कार्यशालाओं / क्षेत्रीय कार्य का आयोजन

15 जुलाई, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण' पर प्रोफेसर एन.वी. वर्गीज, कुलपति, नीपा, की अध्यक्षता में सीपीएचआरई / नीपा के पहले वेबिनार का आयोजन किया। जिसमें सुविख्यात चर्चाकारों में प्रोफेसर एन. स्टीवर्ट, कानून एवं लैंगिक न्याय के प्रोफेसर, वारविक विश्वविद्यालय, यूके; प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अनौपचारिक क्षेत्र एवं श्रम अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, यूजीसी; प्रोफेसर मीनाक्षी गोपीनाथ, निदेशक, शांति एवं महिला सुरक्षा संघर्ष प्रबंधन, नई दिल्ली शामिल थे।

10 दिसंबर, 2020 को उच्चतर शिक्षा अनुसंधान सोसाइटी (एसआरएचई) में ऑनलाइन सम्मेलन – उन्माद और / या थकान? शीर्षक से एक ऑनलाइन सत्र का आयोजन और सह–मेजबानी की।

12 मार्च, 2021 को सीपीआरएचई–ईसी बैठक के संगठन का समन्वय किया।

शिक्षण / निरीक्षक / मूल्यांकन

समाजशास्त्र विभाग, वारविक विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्रों के लिए लैंगिक और विकास पर मॉड्यूल एवं 2 मार्च, 2021 को 'भारत में लैंगिक और उच्च शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के निहितार्थ' पर वारविक विश्वविद्यालय के परास्नातक छात्रों के लिए व्याख्यान, वारविक विश्वविद्यालय

17 फरवरी, 2021 को कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, में महत्वपूर्ण अभिनव सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए डायरी विधि अनुसंधान की खोज पर व्याख्यान।

14 जनवरी, 2021 को दोपहर 2 बजे समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम में परिसर में समावेशिता पर व्याख्यान, शिवाजी कॉलेज।

10 दिसंबर, 2020 को वारविक शिक्षा अध्ययन विभाग, वारविक विश्वविद्यालय में वैश्विक शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विकास को समझने पर संगोष्ठी में शैक्षिक असमानताओं और कोविड 19 पर व्याख्यान दिया।

30 नवंबर 2020 को गुरुदक्षता (संकाय प्रेरण कार्यक्रम–2) एचआरडीसी, शिमला में समानता और समावेशनः भारत में उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, छात्र विविधता के लिए पारिस्थितिकी बनाने पर व्याख्यान दिया।

29 जून से 03 जुलाई 2020 तक नीपा द्वारा एम.फिल. छात्रों के लिए लेखन कौशल पर आयोजित कार्यशाला में शोध पत्र लेखन पर 1 जुलाई 2020 को व्याख्यान।

03 जुलाई, 2020 को नीपा–एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आमंत्रण।

3 जुलाई, 2020 को आयोजित ऑनलाइन एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र का मूल्यांकन।

अन्य गतिविधियां

आंतरिक अनुसंधान समीक्षा समिति, नीपा के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए और समिति को प्रस्तुत की गई कई शोध रिपोर्टों पर सहकर्मी प्रतिक्रिया प्रदान की है।

नवंबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए नीपा संकाय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कार्यान्वयन रणनीति दस्तावेज़ विकसित करने योगदान दिया और समानता और समावेशन कार्य समूह पर उप–समूह का समन्वय किया।

डॉक्टरेट पर्यवेक्षण और संपादकीय सदस्यता/नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

उच्च शिक्षा के लिए लैंगिक मार्ग, डॉक्टरेट कार्य पर कोर ग्रुप के सदस्य, वारविक विश्वविद्यालय

भारतीय अर्थशास्त्र पुर्नविचार नेटवर्क (आरईआईएन) के परामर्शदाता के रूप में कार्य

रूटलेज द्वारा प्रकाशित जर्नल, जेंडर एंड एजुकेशन के संपादकीय बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य।

अनुपम पचौरी

प्रकाशन

आलेख और पुस्तक में अध्याय

चौहान, वी.एस., पचौरी, अनुपम. (2021). 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–2020: पाथ्स एंड डेस्टिनेशन, सी. एन. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अहमदाबाद' में 'मोटिवेटेड, एनरजिस्ड एंड कैपेबल फैकल्टी : एनईपी 2020।

पचौरी, ए. (2021). नौवीं कक्षा की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 'द फण्डामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ' एनसीईआरटी, नई दिल्ली, आईएसबीएन 81–7450–492–3 (ई–बुक)।

रिपोर्टः सीपीआरएचई प्रकाशन

सी.एम. मलिश, पचौरी, अनुपम (2020), उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट।

सीएम, मलिश, पचौरी, अनुपम (2020)।

क्या लचीली उच्च शिक्षा प्रवेश–निकास प्रणाली से असमानता बढ़ेगी?, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज, 17 अक्टूबर 2020।

प्रस्तुत पत्र

पचौरी, अनुपम (2020), 11 नवंबर 2020 को यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान द्वारा आयोजित 'उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर वेबिनार में 'एनईपी 2020 में गुणवत्ता और प्रत्यायन' पर पत्र प्रस्तुत

पचौरी, अनुपम (2020), 11 नवंबर 2020 को अखिल भारतीय शिक्षा मंच, नई दिल्ली, द्वारा आयोजित 'एनईपी 2020– गुणवत्ता शिक्षा के लिए संभावनाएं और चुनौतियां' पर वेबिनार में 'एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा और गुणवत्ता' पर पत्र प्रस्तुत

पचौरी, अनुपम (2020), 16 जुलाई 2020 को राइट टू एजुकेशन फोरम, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गैर राज्यीय अभिनेताओं का विनियमन और निजी स्कूलों का संबंध पर वेबिनार में 'सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षकों के कार्य में गैर–राज्यीय अभिनेता' पर पत्र प्रस्तुत।

संगोष्ठी/कार्यशालाओं का आयोजन

मई के हर रविवार यानी 03, 10, 17, 24 और 31 मई 2020 को सीआईआई शिक्षा विभाग पूर्व छात्र संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 'समर शेष है, शेष है साहस और उम्मीद' शीर्षक से 'कोविड 19 महामारी के कार्यबल और चुनौतियां– शिक्षकों की भावनात्मक प्रतिक्रिया' पर वेबिनार की पांच भाग श्रृंखला के संयोजक।

कार्यशाला में भागीदारी

07 जनवरी 2021 को नीपा, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र, नीपा द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में शिक्षा अनुशासन शिक्षकों के लिए संकाय संवर्धन वेबिनार।

26 जनवरी 2020 को ओस्लो विश्वविद्यालय द्वारा बड़े पैमाने पर मूल्यांकन में अन्वेषक पर वेबिनार,

15 दिसंबर 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेशन के लिए सुधार पर नीति संवाद वेबिनार।

09 दिसंबर 2020 को महामारी के बीच वैश्विक नागरिकताः पीआईएसए 2018 वैश्विक क्षमता परिणाम पर विचार, डीकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया।

20 नवंबर, 2020 को 15:30 बजे से 17:30 बजे तक (आईएसटी) तक सीपीआरएचई, नीपा और अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (आईआईईपी) यूनेस्को, पेरिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'लचीले अधिगम के रास्तेः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर' पर वेबिनार।

11 नवंबर 2020 को नीपा–11वां मौलाना आज़ाद स्मृति व्याख्यान (राष्ट्रीय शिक्षा दिवस), नीपा 2020।

26 सितंबर 2020 को उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: परिवर्तनकारी क्षमता पर आयोजित वेबिनार में भागीदारी

05 सितंबर 2020 को नीपा द्वारा एनईपी–2020, के आलोक में ''उच्च शिक्षा में शिक्षकों की क्षमता विकास'' पर वेबिनार में भागीदारी

28 अगस्त 2020 को जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा नेतृत्व के लिए कार्यसूची बनानाः शिक्षा क भविष्य के लिए एनईपी 2020 को लागू करना', विषय पर परिचर्चा में भागीदारी।

21 अगस्त 2020 को नीपा द्वारा ''व्यावसायिक नीति निर्माण'', पर अभिविन्यास कार्यक्रम के लिए कार्य दल की बैठक में भागीदारी

20 अगस्त 2020 को नीपा में 14वें स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर प्रोफेसर ए.के. शिव कुमार विकास अर्थशास्त्री और नीति सलाहकार, द्वारा शिक्षा और सामाजिक अवसरः अंतराल को पाटना पर वेबिनार में भागीदारी।

19 अगस्त 2020 को नीपा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020: संभावनाएं, चुनौतियां और रास्ते पर वेबिनार में भागीदारी।

07 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा आयोजित बैठक में भागीदारी।

24 जुलाई 2020 को नीपा द्वारा आयोजित कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा पर वेबिनार में भागीदारी

14 जुलाई 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा 'शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण' पर वेबिनार में भागीदारी

शिक्षण कार्य/अन्वीक्षण/मूल्यांकन

शिक्षण

01 जुलाई 2020 को एम.फिल./पी–एच.डी. विद्वानों के लिए शैक्षणिक अनुसंधान में साहित्य समीक्षा पर सत्र।

02 जुलाई 2020 को एम.फिल./पी–एच.डी. विद्वानों के लिए अकादमिक लेखन में साहित्य समीक्षा पर सत्र।

अन्वीक्षण

03 जुलाई, 2020 को एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में अन्वीक्षण।

01 जुलाई, 2020 को एम.फिल./पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित/निष्पादित

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

दिसंबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए नीपा संकाय द्वारा विकसित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन दस्तावेज़ के लिए 'उच्च शिक्षा में प्रत्यायन' शीर्षक से लघु लेख में योगदान दिया।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

आजीवन सदस्य, कम्पेरेटिव एजूकेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (सेसी), भारत

सदस्य, ब्रिटिश एसोसिएशन फार इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव एजुकेशन (बीएआइसीई), यूके।

गरिमा मलिक

प्रकाशन

पुस्तकें

वर्गीज़, एन.वी. और मलिक, गरिमा. (2020) (संपा.) भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2019: ''भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन। नई दिल्ली, सेज

आलेख और पुस्तक में अध्याय

वर्गीज़, एन.वी. और मलिक, गरिमा. (2020) ''भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन'', भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2019 में वगीज़, एन.वी. और मलिक, गरिमा द्वारा संपादित, भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासनः एक परिचय, सेज

वर्गीज़, एन.वी. और मलिक, गरिमा. (2020) ''भारत में उच्च शिक्षा का अभिशासन और प्रबंधन'', भारत उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2019 में वगीज़, एन.वी. और मलिक, गरिमा द्वारा संपादित, शासन और स्वायत्तताः केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों का अध्ययन, सेज

संगोष्ठी/कार्यशालाओं/वेबिनार का आयोजन

18–19 मार्च, 2021 को नीपा, नई दिल्ली में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक। (आगामी)

20 नवंबर, 2020 को (यूनेस्को–आईआईईपी के सहयोग से) लचीले अधिगम के रास्तेः भारत में उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां और अवसर पर आयोजित वेबिनार

कार्यशाला में भागीदारी

9 फरवरी, 2021 को सेंट स्टीफंस डिबेटिंग सोसाइटी मुखर्जी मेमोरियल संवाद की एक पैनल चर्चा में ''लचीले अधिगम के रास्ते'' और ''नई और उभरती हुई शासन संरचनाऐं'' पर कार्यशाला में भागीदारी।

19 जून 2020 को यूनेस्को–आईआईईपी पेरिस द्वारा आयोजित ''उच्च शिक्षा में लचीले अधिगम के रास्ते'' पर परियोजना के लिए अनुसंधान पद्धति संगोष्ठी में भागीदारी।

8 सितंबर, 2020 को यूनेस्को–आईआईईपी पेरिस द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में लचीले अधिगम के रास्ते पर ऑनलाइन बैठक में भागीदारी।

22 जनवरी, 2021 को राजस्थान विश्वविद्यालय अनुसंधान पद्धति कार्यशाला (ऑनलाइन) के लिए ''मात्रात्मक अनुसंधान की विधियों पर उपकरण विकास के लिए यंत्र'' पर व्याख्यान दिया।

19 जून, 2020 को यूनेस्को–आईआईईपी पेरिस, द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में लचीले अधिगम के रास्ते पर परियोजना के लिए सहकर्मी समीक्षा संगोष्ठी में ''भारत में उच्च शिक्षा में लचीला शिक्षण मार्ग'' पर प्रस्तुतिकरण (ऑनलाइन)

शिक्षण कार्य/अन्वीक्षण/मूल्यांकन

अक्टूबर 2020 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) में ''उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र'' पर व्याख्यान

दिसंबर, 2020 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) में ''उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्रः द्रव्यमान पर व्याख्यान

जनवरी, 2021 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) में ''उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्रः अभिशासनष'' पर व्याख्यान दिया

फरवरी 2021 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय संकाय प्रेरण कार्यक्रम (एफआईपी) में ''उच्च शिक्षा का पारिस्थितिकी तंत्रः एनईपी 2020'' पर व्याख्यान दिया

22 जनवरी, 2021 को राजस्थान विश्वविद्यालय अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में मात्रात्मक अनुसंधान विधियों पर व्याख्यान दिया।

जनवरी 2021 में सीसी5बीः मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति इकाई–Iः केन्द्रीय सीमा प्रमेय और संभाव्यता वितरण पर एम.फिल. के लिए व्याख्यान

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और अकादमिक सहायता

जनवरी–मार्च, 2021 में राष्ट्रीय ऋण ढांचे के विकास पर शिक्षा मंत्रालय समिति का समर्थन हेतु सचिवालय के सदस्य।

17 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय ऋण ढांचे के लिए समिति की पहली बैठक आयोजन

एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए ''पुनर्गठन शासन और शासन के संघीय ढांचेः मुद्दे और चुनौतियां'' पर कार्य पत्र तैयार करने के लिए कार्य समूह के सदस्य, नीपा

अन्य गतिविधियां

20–21 फरवरी, 2020 को उच्च शिक्षा में अभिशासन और स्वायत्तता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत पत्रों के आधार पर ''उच्च शिक्षा में अभिशासन और स्वायत्तता'' पर संगोष्ठी की वाल्यूम का संपादन।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

इंडिया हैबिटेट सेंटर (आजीवन सदस्य)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (सदस्य)

अंतर्राष्ट्रीय केंद्र–गोवा (आजीवन सदस्य)

जिणुशा पाणिग्रही

प्रकाशन

पुस्तकें

एन.वी. वर्गीज़ के साथ ''उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में नवाचार'' पर संपादित पुस्तक, स्प्रिंगर प्रकाशन, नई दिल्ली, भारत (पांडुलिपि स्वीकृत) (आगामी)

एन.वी. वर्गीज़ के साथ ''इंडिया हायर एजूकेशन (आईएचईआर) 2021 प्राइवेट हायर एजूकेशन'' पर संपादित पुस्तक, रूटलेज, नई दिल्ली, भारत (पांडुलिपि समीक्षाधीन)

आलेख और पुस्तक में अध्याय

'उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचार' पर संपादित वाल्यूम में ''भारत में सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण'' पर अध्याय, एन.वी. वर्गीस और जिनुशा पाणिग्रही (संपा.), स्प्रिंगर प्रकाशन, नई दिल्ली भारत, (प्रकाशन के लिए पांडुलिपि स्वीकृत)।

एन.वी. वर्गीज के साथ, 'उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचार' पर संपादित खंड में ''उच्च शिक्षा के वित्तपोषण में नवाचारः एक अवलोकन'' पर अध्याय एन.वी. वर्गीज और जिनुशा पाणिग्रही (संपा.), स्प्रिंगर प्रकाशन, नई दिल्ली, भारत (पांडुलिपि प्रकाशन के लिए स्वीकृत)।

सीपीआरएचई शोध पत्र 13, में ''निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्कः भारत में विश्वविद्यालयों के लिए एक अध्ययन'' शीर्षक से शोध पत्र, (संपादक वर्गीज एन.वी. एंड सी.एम. मलिश) सितंबर 2020, नीपा, नई दिल्ली

तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की वार्षिक समीक्षा वाइसमैन ए.डब्ल्यू. (संपा.) में थापा, ए और हदर आई.बी के साथ ''शिक्षा का अर्थशास्त्र और वित्तः विकास, रुझान और चुनौतियों की समीक्षा'' पर अध्याय, एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम, जून 2020।

अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट

प्रोफेसर ओडिले हेनरी, डा. जिनुशा पाणिग्रही और डा. निधि एस. सभरवाल, ईएसपीआई, पेरिस / सीपीआरएचई–नीपा द्वारा 'ईएसपीआई इंडिया रिपोर्टः भारत में उच्च शिक्षा और सामाजिक असमानताएं', नई दिल्ली, 2020।

संगोष्ठी/कार्यशालाओं का आयोजन

17 दिसंबर, 2020 को आईएचईआर 2021: भारत में निजी उच्च शिक्षा पर दूसरी सहकर्मी समीक्षा बैठक

21 सितंबर, 2020 को आईएचईआर 2021: भारत में निजी उच्च शिक्षा पर पहली सहकर्मी समीक्षा बैठक

सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

भारत सरकार की 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति की तैयारी हेतु वित्त पोषण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) पर सलाहकार विषयगत समूह के सदस्य।

अन्य गतिविधियां

नीपा डायरेक्ट पी–एच.डी,, पार्ट–टाइम पी–एच.डी. और एम.फिल. कार्यक्रम सीसी3 पाठ्यक्रम शिक्षण कार्य और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

नीपा, नई दिल्ली में वर्ष 2019–20 के लिए नीपा डायरेक्ट पी–एच.डी., अंशकालिक पी–एच.डी. और एम.फिल. कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

2019–2021 अर्थशास्त्र और शिक्षा वित्त विशेष रुचि समूह (ईएफई–एसआईजी), तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एसआइईईएस), यूएसए के सह–अध्यक्ष

विश्व की सबसे बड़ी तुलनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (सीआईईएस), यूएसए के विशिष्ट सदस्य।

मलिश सी.एम.

प्रकाशन

आलेख और पुस्तक में अध्याय

मलिश, सी.एम. (आगामी) उच्च शिक्षा तक पहुंच को मापने का उद्देश्य और संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा।

वर्गीज, एन.वी., सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (आगामी), चेजिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया सौमेन चट्टोपाध्याय, साइमन मार्जिन्सन और एन.वी. वर्गीज (संपा.) में 'समावेशी विकास के लिए उच्च शिक्षा में समानता: भारत से साक्ष्य' लंदन: ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग.

सभरवाल, एन.एस. और मलिश, सी.एम. (आगामी), उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान के लिए मिश्रित पद्धति दृष्टिकोण और गुणात्मक पद्धति, जॉर्ज डब्ल्यू. नोब्लिट (संपा.) में शिक्षा में गुणात्मक अनुसंधान विधियों का ऑक्सफोर्ड अनुसंधान विश्वकोष, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस

मलिश, सी.एम. (2020) उच्च शिक्षा तक पहुंच को मापना: संकेतक और संकेत, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, एल.वी. (40), पीपी. 54–56, https://www.epw.in/journal/2020/40/discussion/measuring-access-higher-education.html

मलिश, सी.एम. (2020). पुस्तक समीक्षा [मृणाल मिरी, 2018 द्वारा हमारे विश्वविद्यालयों में मानविकी का स्थान, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, XXXIII (4), 2, पीपी. 351–362।

मलिश, सीएम (2020), एक प्रवर्तक के रूप में प्रौद्योगिकी, द हिंदू, 21 अगस्त 2020, https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/technology-as-an-enabler/article32407777.ece से एक्सेस किया।

मलिश, सी,एम, (2020) सोशल डिस्टेंस ऑन कैंपस, बट सोशल डिसकनेक्ट ऑनलाइन, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज, 25 जुलाई 2020। https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200725100908 43 से एक्सेस किया।

मलिश, सी.एम. और अनुपम पचौरी (2020), क्या लचीली उच्च शिक्षा में प्रवेश–निकास प्रणाली से असमानता बढ़ेगी? यूनिवर्सिटी वर्ल्ड न्यूज, 17 अक्टूबर 2020, https://www-universityworldnews-com/post.php?story=20201015063206 41 से एक्सेस किया।

वेबिनार में प्रस्तुत शोधपत्र

15 दिसंबर 2020 को सीपीआरएचई, नीपा द्वारा आयोजित ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर नीति संवाद वेबिनार में भारत में सामाजिक रूप से समावेशी परिसरों के विकास पर प्रस्तुति

23 सितंबर 2020 को कुमारगुरु कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर, तमिलनाडु द्वारा आयोजित विशेषज्ञ चर्चा (वेबिनार) में नई शिक्षा नीति और सभी के लिए समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रस्तुति।

15 सितंबर 2020 को मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः आगे की रणनीति पर चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में वक्ता।

सामाजिक कार्य विभाग, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल द्वारा आयोजित वेबिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समावेशी विकास पर प्रस्तुति।

कार्यशाला/वेबिनार में भागीदारी

3 फरवरी 2021 को केरल राज्य योजना बोर्ड द्वारा आयोजित 'केरल आगे दिखता है' उच्च शिक्षा पर ऑनलाइन पैनल चर्चा में भागीदारी।

24 जुलाई 2020 को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा द्वारा आयोजित कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा पर वेबिनार में भागीदारी

14 जुलाई 2020 को सीपीआरएचई–नीपा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ''शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण'' पर वेबिनार में भागीदारी।

संगोष्ठी/कार्यशालाओं/वेबिनार का आयोजन

मंगलवार, 15 दिसंबर 2020 को बजे तक ''भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेश के लिए सुधार'' पर नीति संवाद वेबिनार का आयोजित किया।

शिक्षण कार्य/अन्वीक्षण/मूल्यांकन

01 अक्टूबर 2020 को मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आईआईटी जम्मू द्वारा प्री–पी–एच.डी. व्याख्यान श्रृंखला में उच्च शिक्षा में विविधता और भेदभाव पर व्याख्यान (ऑनलाइन)।

25 सितंबर 2020 को मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, आईआईटी जम्मू द्वारा प्री–पी–एच.डी. व्याख्यान श्रृंखला में शिक्षा अनुसंधान में डेटा संग्रहः मुद्दे और चुनौतियां पर व्याख्यान (ऑनलाइन)।

23 सितंबर 2020 को श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, पय्यन्नूर केंद्र, कासरगोड, केरल द्वारा आयोजित अकादमिक लेखनः एक परिचय पर सत्र।

अन्य गतिविधियां

सीपीआरएचई शोध पत्र श्रृंखला के दो पत्रों के संपादक (शोध पत्र 13 'निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्कः भारत में विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन' जिनुशा पाणिग्रही और रिसर्च पेपर 14 'भारत में स्नातक रोजगार और सतत रोजगार कौशल' मोना खरे) प्रकाशित।

जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (जेपा) के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य।

उच्चतर शिक्षाः उच्चतर शिक्षा शोध की अन्तरराष्ट्रीय पत्रिका के समीक्षक के रूप में कार्य।

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक

प्रणति पंडा

रस्मिता दास स्वैन

ए.एन. रेड्डी

एकक के बारे में संक्षिप्त

शाला सिद्धिः गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन की दिशा में एक अभिनव पहल

शिक्षा के बदलते परिवेश में इसकी प्रभावशीलता और सुधारात्मक संदर्भ में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिगम हेतु एक संस्थागत स्थान के रूप में स्कूल

को अब अधिगम के परिणामों में सुधार करने और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं को बदलने में खुद को संलग्न करने के लिए स्कूलों में धीरे–धीरे बदलाव हो रहा है। भारत में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांगों को पूरा करने के साथ–साथ स्कूल सुधारात्मक पहल के रूप में व्यापक और समग्र स्कूल मूल्यांकन प्रणाली पर जोर दिया जा रहा है। स्कूल मूल्यांकन के उद्देश्य को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के व्यापक लक्ष्य में इसकी भूमिका और योगदान के संदर्भ में समझने की जरूरत है।

इस संदर्भ में, व्यापक स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए 2015 से राष्ट्रीय पहल के रूप में स्कूल मानक और मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संस्थागत रूप दिया गया है। शाला सिद्धि कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य मानकों और प्रक्रियाओं के एक सहमत सेट स्थापित करना और संदर्भित करना है जिसे सभी स्कूलों को स्थायी तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करना है। यह 'विद्यालय मूल्यांकन' को साधन और 'विद्यालय सुधार' को लक्ष्य के रूप में देखना और जवाबदेही के साथ स्कूल सुधार की दिशा में स्व और बाहरी मूल्यांकन के लिए प्रत्येक स्कूल को स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। इसलिए विद्यालय मूल्यांकन का तात्पर्य किसी एक विद्यालय के समग्र रूप से उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन से है। यह स्कूलों को उनके अधिकार, सुधार के अवसरों, कार्यों को प्राथमिकता देने, निर्णय लेने, जिम्मेदारी सौंपने, समय सीमा निर्धारित करने और उनके सुधार के लिए साक्ष्य–आधारित समर्थन बनाने की सुविधा प्रदान करता है। शाला सिद्धि कार्यक्रम के विकास की प्रक्रिया ने बहुत व्यवस्थित दृष्टिकोण का अनुसरण किया। यह साक्ष्य–आधारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधों द्वारा दृढ़ता से समर्थित है। कार्यक्रम 'सभी बच्चे सीख सकते हैं' और 'सभी स्कूल उन्नति कर सकते हैं' की धारणा पर आधारित है। कार्यक्रम ने आगे '1.53 मिलियन अनेक भारतीय स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उन्हें सुधार के लिए कार्रवाई करने की सुविधा कैसे दें के लिए कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया?

शाला सिद्धि कार्यक्रम के तहत मानक निर्धारण

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्कूल प्रदर्शन का मूल्यांकन और मान्यता के लिए मानक निर्धारण को अब तेजी से परिवर्तन के संभावित उत्तोलक के रूप में माना जा रहा है। मानक निर्धारण स्कूली शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्कूल के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्रों के व्यापक ढांचे के भीतर मापने योग्य अपेक्षाओं के मानदंड की पहचान करते हैं, गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करते हैं, और स्कूल के प्रदर्शन के मूल्यांकन, और मान्यता के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार, मानकों का उपयोग एक मापदंड के रूप में या एक माप बिंदु के रूप में किया जा सकता है। सभी स्कूलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानकों के राष्ट्रीय सेट होने का मूल्य इस तर्क पर आधारित है कि राष्ट्रीय मानक होंगेः

कक्षा, स्कूल या शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों के लिए अपेक्षाओं का स्तर बढ़ाएं

आश्वस्त करें कि सभी छात्र राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि को पूरा करते हैं

बेहतर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया और स्कूली शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करें

शाला सिद्धि कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य मानकों और प्रक्रियाओं के एक सहमत सेट को स्थापित और संदर्भित करना है जिसे सभी स्कूलों को एक स्थायी तरीके से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में, राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ पारस्परिक रूप से सहमत और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मानकों का एक सेट विकसित किया गया है। तदनुसार, स्कूल के मूल्यांकन और मान्यता के लिए रणनीतिक रूप में स्कूल मानक और मूल्यांकन ढांचा (एसएसईएफ) विकसित किया गया है। फ्रेमवर्क 7 डोमेन को 'प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्रों' के रूप में और '46 कोर मानकों' को मूल्यांकन और सुधार के लिए कार्रवाई के संदर्भित बिंदुओं के रूप में पहचाना है।

शाला सिद्धि को एनईपी 2020 के साथ संरेखित करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल विनियमन, मान्यता और अभिशासन के लिए मानक निर्धारण और नियामक रूपरेखा की सिफारिश करती है। स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना बुनियादी मानकों (अर्थात सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, विषयों और ग्रेडों में शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी और शासन की ध्वनि प्रक्रियाओं) के आधार पर मानकों का एक न्यूनतम सेट स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। इसने शिक्षा के सभी चरणों के लिए मान्यतागत प्रणाली के संस्थागतकरण और स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) के विकास पर भी जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्कूल कुछ न्यूनतम व्यावसायिक और गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं।

कार्यक्रम के संस्थागतकरण के बाद के प्रमुख चरण हैं: तैयारी; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल मूल्यांकन का कार्यान्वयन; कार्यप्रणाली और दृष्टिकोण; गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रभावशीलता और उपयोगिता।

सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकनः शाला सिद्धि कार्यक्रम की तैयारी

स्कूल मूल्यांकन और सुधार के लिए व्यापक पैकेज का विकास

शाला सिद्धि–स्कूल मानक और मूल्यांकन ढांचा (एसएसईएफ)– स्कूल मानक और मूल्यांकन ढांचा स्कूल मूल्यांकन के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है। यह स्कूलों को एक केंद्रित और रणनीतिक तरीके से परिभाषित मानदंडों के प्रतिकूल अपने महत्वपूर्ण प्रदर्शन क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। फ्रेमवर्क 7 डोमेन को 'मुख्य प्रदर्शन क्षेत्रों' के रूप में और '46 कोर मानकों' को मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाई के संदर्भ बिंदुओं के रूप में पहचान करता है।

स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड – स्कूल में सुधार के लिए कार्रवाई के साथ–साथ स्कूल की व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट।।

स्कूल स्व–मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश– दिशानिर्देश का उद्देश्य क्रमिक और निर्देशित तरीके से स्कूल स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। सटीक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए स्कूलों को दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

स्कूल बाह्य–मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश– दिशानिर्देश क्रमिक और निर्देशित तरीके से प्रभावी बाह्य मूल्यांकन के संचालन हेतू स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं।

साक्ष्य आधारित स्कूल सुधार के लिए दिशानिर्देश– साक्ष्य आधारित स्कूल मूल्यांकन स्कूल में सुधारात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए स्कूलों का सहयोग करते हैं। यह स्कूलों को प्रगतिशील और प्राथमिकता के माध्यम से प्रमुख डोमेन में कार्रवाई उन्मुख गतिविधियों को शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है।

इन दस्तावेजों का 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम सभी स्कूलों में वितरित किया गया है। शाला सिद्धि के वेब पोर्टल में सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध हैं।

शाला सिद्धि कार्यक्रम के लिए आईटी समर्थित समर्थन (www.shaalasiddhi.niepa.ac.in)

शाला सिद्धि परस्पर संवादात्मक वेब पोर्टल द्वारा समर्थित है। वेब पोर्टल में कार्यक्रम संबंधी सभी दस्तावेजों को उपयोगकर्ता डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पोर्टल में एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रत्येक स्कूल अपनी स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकता है। बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए उसी वेब पोर्टल का उपयोग करने की आवश्यकता है। समेकित स्कूल मूल्यांकन रिपोर्ट (स्व और बाह्य दोनों) ऑनलाइन तैयार की जाती है जिससे व्यवसायी, नीति निर्माता, अन्य सभी हितधारक जानकारी तक पहुँच सकते हैं, इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

स्कूल मूल्यांकन के लिए कार्यान्वयन रणनीतियाँ

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

शाला सिद्धि कार्यक्रमों को सही मायने में लागू करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की

जाती है। जिसमें लगभग 10 लाख शिक्षक–प्रशिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और शिक्षकों को शाला सिद्धि कार्यक्रम की तैयारी, रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया है।

संस्थागत और संरचनात्मक व्यवस्था

शाला सिद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी स्कूलों तक पहुंचना और उन्हें स्कूल स्व–मूल्यांकन प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तैयार करना और स्कूल सुधार के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग करना है। कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्यरूप बनाया है:

मानव श्रृंखला दृष्टिकोण: सभी स्तरों पर नामित 'नोडल अधिकारियों' के साथ 'मानव श्रृंखला' दृष्टिकोण का पालन करते हुए राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तरों पर 'मुख्य समूह' बनाना;

ब्लॉक श्रृंखला दृष्टिकोण: व्हाट्सएप ग्रुप, स्थानीय भाषाओं में वीडियो बनाकर और अन्य सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी का उपयोग करके स्कूलों के साथ इंटरकनेक्टिविटी बनाई गई।

स्कूल मूल्यांकन की पद्धति और दृष्टिकोण

शाला सिद्धि में स्व और बाह्य मूल्यांकन शामिल है। स्व और बाह्य–मूल्यांकन एक रणनीतिक साधन के रूप में स्कूल मानक और मूल्यांकन फ्रेमवर्क (एसएसईएफ) का उपयोग करता है।

वार्षिक विशेषता के रूप में स्कूल स्व–मूल्यांकन– स्व–मूल्यांकन को स्कूल मूल्यांकन प्रक्रिया के केंद्र के रूप में माना जाता है। इसका उद्देश्य स्कूल कर्मियों को स्कूल के समग्र प्रदर्शन की एक सामान्य समझ प्रदान करना और सुधार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है। स्व–मूल्यांकन स्कूल के सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। स्कूल स्व–मूल्यांकन एक वार्षिक सुविधा के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रमशः वर्ष 2016–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए लागू किया गया है। स्कूल स्व–मूल्यांकन और बाह्य–मूल्यांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के लिए राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2016–18 को 'अधिगम वर्ष' के रूप में माना जाता है क्योंकि प्रणाली और स्कूल अधिक समझ, दक्षता एवं कौशल के साथ नए तरह के जुड़ाव के लिए तैयार हो रहे थे।

विद्यालय बाह्य–मूल्यांकन– विद्यालयों का बाह्य–मूल्यांकन को स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया का पूरक माना जाता है। यह स्व–मूल्यांकन के परिणाम के रूप में अनुसरण करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों दृष्टिकोण तालमेल से कार्य करते हैं। एक सहयोगी बाह्य–मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता, सटीकता लाना और समग्र विद्यालय सुधार प्रक्रिया की बेहतर समझ का निर्माण करना है। प्रत्येक विद्यालय के लिए तीन वर्ष में एक बार बाह्य–मूल्यांकन किया जाता है (लगभग प्रत्येक वर्ष 33 प्रतिशत)। वर्ष 2019–20 में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूलों का बाह्य मूल्यांकन शुरू किया है।

प्रगति और उपलब्धि

स्कूल मानक एवं मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (शाला सिद्धि) भारत में व्यापक स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को संस्थागत बनाने के लिए एक अभिनव पहल है। वर्ष 2019–20 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वार्षिक सुविधा के रूप में स्कूल स्व–मूल्यांकन लागू किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर स्व–मूल्यांकन (2019–20) और बाह्य–मूल्यांकन (2019–20) के संचालन और अपलोड करने की समयसीमा को 2021 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 4655846 लाख स्कूलों ने स्कूल स्व–मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है। स्व–मूल्यांकन डैशबोर्ड (2020–21) और बाहरी–मूल्यांकन डैशबोर्ड (2019–20) अपलोड करने के लिए पोर्टल 1 मार्च, 2021 से खोला गया था।

कोविड–19 के कारण अप्रत्याशित अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, राष्ट्रीय और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयास शाला सिद्धि कार्यक्रम को न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन का एक सफल मॉडल बना रहे हैं।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

शाला सिद्धि कार्यक्रम को सही मायने में तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। पिछले 4 वर्षों में शाला सिद्धि कार्यक्रम की तैयारी, रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन के लिए लगभग 11 लाख शिक्षक–प्रशिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, प्रचार्यों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2019–20 में विद्यालय मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों का आयोजन

11–12 फरवरी, 2021 को सुधार के लिए मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक (शाला सिद्धि), पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम।

17–18, दिसंबर 2020 को स्कूल बाह्य–मूल्यांकन पर क्षेत्रीय कार्यशाला: भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए शाला सिद्धि पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम।

स्कूल स्व–मूल्यांकन (शाला सिद्धि) पर राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण कार्यक्रम:

08 अगस्त, 2020 को नीपा, नई दिल्ली में 'भारत में स्कूल कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? शाला सिद्धि से अंतर्दृष्टि' पर राष्ट्रीय वेबिनार

21 सितंबर, 2020 को जम्मू और कश्मीर में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

9–10 अक्टूबर, 2020 को असम में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम,

12–13 अक्टूबर, 2020 को तेलंगाना में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

25 नवंबर, 2020 को उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

26–27 नवंबर, 2020 को मेघालय में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

2 दिसंबर, 2020 को राजस्थान में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

8–9 दिसंबर, 2020 को हरियाणा में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

12–13 जनवरी, 2021 को बिहार में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

21–22 जनवरी, 2021 को झारखंड में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

9 फरवरी, 2021 को जम्मू और कश्मीर में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

25 मार्च, 2021 को महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम,

25 मार्च, 2021 को समग्र शिक्षा दिल्ली के लिए स्कूल बाह्य–मूल्यांकन और साक्ष्य–आधारित स्कूल सुधार पर तकनीकी सहायता पर ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम

'गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन' पर स्व–शिक्षण मॉड्यूल का विकास

व्यवस्थित संचालन प्रक्रिया में राज्य के अधिकारियों की तैयारी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता विकास शामिल है। नीपा, शाला सिद्धि इस प्रयास के तहत, मानक निर्धारण, स्कूल मूल्यांकन और मान्यता पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित कर रहा है। इस प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग उन महत्वपूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा जो गुणवत्ता सुधार और स्कूल मूल्यांकन के लिए समर्थन देने हेतु जवाबदेह और जिम्मेदार हैं।

प्रशिक्षण पैकेज में प्रक्रियाधीन निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं:

मॉड्यूल 1: स्कूल गुणवत्ता और सुधार

मॉड्यूल 2: स्कूल निष्पादन प्रबंधन और मूल्यांकन

मॉड्यूल 3: स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण

मॉड्यूल 4: शाला सिद्धिः सुधार के लिए मूल्यांकन

मॉड्यूल 5: स्कूल मानक और मूल्यांकन ढांचा

मॉड्यूल 6: स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन डैशबोर्ड/रिपोर्ट

मॉड्यूल 7: स्कूल प्रदर्शन मूल्यांकन विश्लेषिकी

मॉड्यूल 8: साक्ष्य आधारित स्कूल सुधार

मॉड्यूल 9: सुधार हेतु स्कूल प्रशासन

विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और परिणाम

अनुसंधान और विकास एक महत्वपूर्ण घटक है जो स्कूल विकास प्रक्रिया में सुधार के लिए नई जानकारियां उत्पन्न करता है। यह गुणवत्ता सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन के संग्रह, प्रलेखन और प्रसार पर केंद्रित है। शाला सिद्धि कार्यक्रम को बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विश्लेषणात्मक रिपोर्ट; राज्य विशिष्ट प्रगति और स्थिति रिपोर्ट; राज्य विशिष्ट स्कूल स्व–मूल्यांकन ग्रेडिंग रिपोर्ट; शाला सिद्धिः राज्य विशिष्ट अभिनव रणनीतियाँ आदि रिपोर्टें भी तैयार की जाती हैं। शाला सिद्धि कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालय निष्पादन मूल्यांकन प्रवृत्तियों का वर्षवार विश्लेषण, विद्यालय सुधार के लिए उचित कार्रवाई हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करने वाला भावीसूचक विश्लेषण किया जाता है।

स्कूल प्रदर्शन विश्लेषण स्कूल स्व–मूल्यांकन डैशबोर्ड के आधार पर तैयार किए जाते हैं

राष्ट्रीय विद्यालय प्रदर्शन विश्लेषिकी, 2018–19।

राष्ट्रीय विद्यालय प्रदर्शन विश्लेषिकी, 2019–20।

स्व–मूल्यांकन डैशबोर्ड पर आधारित स्कूल प्रदर्शन का डेटा विश्लेषण (2016–18)

स्व–मूल्यांकन डैशबोर्ड पर आधारित स्कूल प्रदर्शन का डेटा विश्लेषण (2019–21)

राज्यवार प्रदर्शन विश्लेषिण्की 2016–18 (36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

राज्यवार प्रदर्शन विश्लेषण 2018–19 (36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)

राज्यवार प्रदर्शन विश्लेषण 2019–21 (प्रगति में)।

अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग एकक

शेरिंग चोंजोम भूटिया

समीक्षाधीनअवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

शिक्षा पर मसौदा प्रस्ताव की ''समीक्षा और जाँच'' करने हेतु, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के तहत ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त अनुरोध के आधार पर वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार सेवाओं के लिए टिप्पणियां/जानकारी भी प्रदान की और विस्तृत जानकारी 29 अप्रैल 2020 को शिक्षा मंत्रालय को सौंपी।

''ऑस्ट्रेलियाई पक्ष'' से प्राप्त पारस्परिक मान्यता पर मसौदा समझौता ज्ञापन पर ट्रैक परिवर्तन मोड को ध्यान में रखते हुए कि दोनों देशों के भीतर संतुलित गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए इसे कैसे संशोधित किया जा सकता है पर जानकारी प्रदान की और 6 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

9 जुलाई 2020 को आभासी प्रणाली के माध्यम से ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के निर्णय के संबंध में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के लिए एक पृष्ठभूमि नोट तैयार किया। 13 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय को जानकारी जमा किए गए।

17 जून 2020 को भारत में उच्चतर शिक्षा में एफडीआई पर नीति टिप्पणी प्रस्तुत की।

19–20 नवंबर 2020, को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और शिक्षा कौशल और रोजगार विभाग, ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ''नियामक और ऑनलाइन शिक्षण अधिगम गुणवत्ता आश्वासन'' पर आयोजित दो दिवसीय वेबिनार में भागीदारी

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग से प्राप्त ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिसर्चर्स हब के लिए मसौदा प्रस्ताव में ट्रैक परिवर्तन मोड में जानकारी तैयार जानकारी की और 8 फरवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

आगामी ब्रिक्स इंडिया चेयरशिप 2021 के संबंध में कई जानकारी प्रदान किए

ईमेल का तैयार मसौदा ब्रिक्स एनसीसी सदस्यों को भेजा और 8 जनवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

ब्रिक्स एनयू समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति का पहला मसौदा तैयार किया और 1 फरवरी 2021 को आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वर्तमान में आंतरिक जानकारी के अनुसार टिप्पणी को संशोधित किया जा रहा है।

22 जनवरी 2021 को शास्त्री भवन, शिक्षा मंत्रालय में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 पर चर्चा के लिए प्रारंभिक बैठक में भागीदारी और उसी दिन शिक्षा मंत्रालय को बैठक की विस्तृत परिणाम प्रस्तुत किए।

आर्थिक और व्यापार सहयोग, 2021–2025 पर ब्रिक्स कार्य योजना/एजेंडा के संबंध में जानकारी की और 2 फरवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

जेएस (आईसीसी) की अध्यक्षता में ब्रिक्स की तैयारी बैठक में भागीदारी और 27 जनवरी 2021 को कुलपति, नीपा, आईआईटीबी और प्रोफेसर रामचंद्रन ने भाग लिया और 29 जनवरी 2021 को बैठक की सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की।

ब्रिक्स शिक्षा 2021 के लिए चुने गए दो विषयों– ब्रिक्स देशों में समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना; और ब्रिक्स देशों में सतत शिक्षा हेतु अधिगम के परिणामों को प्राथमिकता देना शीर्षक के लिए सुझाव तैयार किए– पहले विषय पर एक संक्षिप्त नोट भी तैयार किया और 7 फरवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

''ब्रिक्स इंडिया चेयरशिप, 2021 के लिए गतिविधि योजना'' शीर्षक से विस्तृत जानकारियां तैयार की, जिसमें ब्रिक्स शिक्षा से संबंधित दो कार्यक्षेत्र – ब्रिक्स शिक्षा नीति एवं ब्रिक्स एनयू – और भारत की अध्यक्षता के दौरान 2021 के लिए नियोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियां शामिल थी। साथ ही पूरे साल के लिए विस्तृत निधि की आवश्यकता तैयार की और 10 फरवरी 2021 को शिक्षा मंत्रालय को सभी दस्तावेज जमा किए।

अप्रैल 2021 के मध्य में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों को आमंत्रण पत्र का मसौदा तैयार किया।

दूसरी भारत–जापान उच्च स्तरीय वार्ता/जेडब्ल्यूजी बैठक के लिए एजेंडा और चर्चा बिंदुओं का मसौदा तैयार किया और इसे 18 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

नेगारा ब्रुनेई दारुसलम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया और 22 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

फिजी गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार किया और 9 अप्रैल 2021 को शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

206 देशों और प्रदेशों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। मार्च 2020 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित 33 देशों और 2 क्षेत्रों के अद्यतन किए गए तथ्य पत्रक 23 मार्च 2020 को आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए और 28 अप्रैल 2020 को संशोधित तथ्य पत्रक आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए।

मार्च 2020 में शुरू की गई ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया और मई 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए पहला मसौदा पूरा किया।

भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया और पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत – चीन, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया के तीन संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर एक विस्तृत नोट तैयार किया। जून के अंत में आंतरिक समीक्षा के लिए पहला मसौदा प्रस्तुत किया।

ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और म्यांमार – कुल संख्या को पांच तक लाते हुए तीन देशों को जोड़कर संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों का

दूसरा मसौदा तैयार किया और जुलाई 2020 के मध्य में आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया

206 देशों और प्रदेशों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 35 देशों/क्षेत्रों में से छह (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया) के 22 सितंबर 2020 को आंतरिक समीक्षा के लिए प्रोफाइल कार्य पूरा किया और प्रस्तुत किया।

''विश्वविद्यालय नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाएं'' बहुपक्षीय संगठनों में अवधारणाएं पर आयोजित यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। ब्रिक्स एनयू पर टिप्पणी तैयार की और 26 सितंबर 2020 को आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। इसके अलावा, एनयू कार्यभार पर एक टेबल नोट तैयार किया और 29 सितंबर 2020 को आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया।

एनईपी 2020 कार्यान्वयन रणनीतियों पर नीपा परियोजना में योगदान दिया। ''भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों का संचालन'' विषय पर कार्य समूह के समन्वयक के रूप में नियुक्त।

30 सितंबर 2020 को आन्तरिक समिति को सौंपे गए कार्य पत्र की रूपरेखा में योगदान दिया।

अक्टूबर 2020 के मध्य में प्रस्तुत नॉटिंघम विश्वविद्यालय मलेशिया पर केस अध्ययन का एसडब्ल्यूओटी का विश्लेषण।

31 अक्टूबर 2020 को आन्तरिक समिति को सौंपे गए अंतिम कार्य पत्र के मसौदा में योगदान दिया।

दुबई, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और कतर में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी) के केस अध्ययनः भारत के लिए सबक पर यूआईसी परियोजना में प्रधान योगदानकर्ता

पत्र के लिए विस्तृत ढांचा/रूपरेखा तैयार की।

सामान्य वर्गों का पहला मसौदा तैयार किया और साझा किया।

नॉटिंघम विश्वविद्यालय मलेशिया पर केस अध्ययन का पहला मसौदा पूरा हो गया है।

फरवरी 2021 तक अद्यतन किए गए 206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

सह संपादक, इंडिया क्वार्टरली, सेज प्रकाशन।

एल्डो मैथ्यूज

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

''लेवरेजिंग इंटरनेशनल इन्फ्लूएंस थ्रू हायर एजूकेशनः एन ऑपरच्युनिटी इन डिसरपशन फॉर इंडिया'', इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। वॉल्यूम 56, सं. 1, 02 जनवरी, 2021। पीपी 26–28

इंडियाज हायर एजूकेशन एंड कोविड–19: रिसपांसेज एंड चैलेंजेज'', इंटरनेशनल हायर एजूकेशन, सं. 102, विशेष अंक, 2020 पीपी. 22–24

''''म्युच्अल रिकॉगनिशन ऑफ एकेडिमिक क्वालिफिकेशंसः पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, ट्रेड–ऑफ एंड द वे फॉरवर्ड, कम्पेरेटिव एंड ग्लोबल एजूकेशन, वर्किंग पेपर सीरीज'', ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, खंड 3, सं. 1, पीपी. 15–19

''लैसन फ्रॉम मोनॉश, द हिंदू, 22 दिसंबर 2020

''कीप द फोकस ऑन हिन्दू'', द हिंदू, 1 अगस्त 2020

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

फरवरी 2021 में ''यूनेस्को के वैश्विक सम्मेलन और उच्च शिक्षा में योग्यता की मान्यता पर एशिया–प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलनः भारत के लिए निहितार्थ और जिम्मेदारियां'' पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत किया।

मार्च 2021 में शिक्षा के क्षेत्र में भारत और मोरक्को के बीच व्यापक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए जानाकरी प्रस्तुत की।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। मार्च 2020 तक अद्यतन की गई अफ्रीका की तथ्य पत्रक 23 मार्च 2020 को आंतरिक समीक्षा हेतु प्रस्तुत की तथा संशोधित तथ्य पत्रक को अप्रैल 2020 में प्रस्तुत किया।

भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। तथा अफ्रीका के चार संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देश मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और नाइजीरिया में भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर एक नोट तैयार किया।

मार्च 2020 में शुरू की गई ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। जून 2020 में ''अवसर के रूप में व्यवधानः आगे बढ़ने के लिए प्रस्ताव'' पर विषय–सूची और पत्र पूरे किए।

''भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों का संचालन'' विषय पर कार्य समूह के समन्वयक के रूप में नियुक्ति और एनईपी 2020 कार्यान्वयन रणनीतियों पर नीपा परियोजना में योगदान दिया।

अवधारणा नोट और कार्य पत्रक की रूपरेखा तैयार की, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण का प्रारूप बनाया, साक्षात्कार विशेषज्ञों के लिए जानकारियां प्रदान की, और एनईपी कोर कमेटी को प्रस्तुत 'अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों' पर अध्याय का मसौदा तैयार किया।

दुबई, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और कतर में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी) के केस अध्ययन भारत के लिए सीख पर यूआईसी परियोजना में योगदानकर्ता तथा अगस्त 2020 में 'अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसारः मोनॉश विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका के परिवर्तन की जाँच पर शोध अध्ययन पूरा हुआ।

भारत में शाखा परिसरों की स्थापना पर दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए मसौदा मार्च 2021 में प्रस्तुत किया।

फरवरी 2021 तक अद्यतन किए गए 206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया।

अनामिका

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

अनामिका, ''*अफ्टर द ऑफर लेटर*'' द इंडियन एक्सप्रेस, 22 जनवरी 2021, पृ. 8. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-education-policy-colleges-iit-iim-placements-collaboration-iit-iim-7156431/

न्यग्रेन, टी., क्रोनलिड, डी.ओ., लार्सन, ई., नोवक, जे., बेंट्रोवेटो, डी., वाशरमैन, जे., वेपली, ओ., गुथ, एम., अनामिका (2020). ग्लोबल सिटीजनशिप एजूकेशन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप? मानव अधिकारों, शांति और सतत विकास के बारे में इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन के माध्यम से सीख के बारे में छात्रों के विचार। *जर्नल ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन,* वॉल्यूम 19(4), 63–97।

अनामिका, ''*ओपन कैंपस चौलेंजः भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने हेतु एनईपी के दृष्टिकोण को संशोधित करने की आवश्यकता है*'' द इंडियन एक्सप्रेस, 4 सितंबर 2020, पृ. 8. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-education-policy-open-campus-6582118/

टिबिट्स, एफ., न्यग्रेन, टी., नोवक, जे., बेंट्रोवेटो, डी., वाशरमैन, पी. और अनामिका (2020). ''भारत, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में मानवाधिकार शिक्षा पर छात्रों से अंतर्दृष्टि'' जे. ज़जदा (संपादक), *ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ग्लोबली, ग्लोबलाइज़ेशन, कम्पेरेटिव एजुकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च* 22. नीदरलैंड्सः स्प्रिंगर में आलेख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायताः

21 अप्रैल, 2020 को एएसईएम शिक्षा सचिवालय, ब्रूसेल्स, बेल्जियम द्वारा (ऑनलाइन) आयोजित एएसईएम शिक्षा विजन और रणनीति 2030 मसौदा समिति की बैठक में भागीदारी

18 मई, 2020 को एएसईएम सचिवालय, ब्रूसेल्स, बेल्जियम द्वारा (ऑनलाइन) आयोजित एएसईएम शिक्षा विजन और रणनीति 2030 दूसरी मसौदा समिति की बैठक में भागीदारी

28 मई, 2020 को एएसईएम शिक्षा सचिवालय, ब्रूसेल्स, बेल्जियम द्वारा आयोजित शिक्षा विजन और रणनीति–2030 पर वेबिनार में भागीदारी

डीएएडी जर्मनी द्वारा आयोजित डिजिटलाइजेशन पर एएसईएम स्थायी कार्य समूह में भागीदारी

9 फरवरी, 2021 को एएसईएम सचिवालय, ब्रूसेल्स, बेल्जियम द्वारा आयोजित तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (टीवीईटी) सहित आजीवन अधिगम (एलएलएल) कार्य योजना 2030 पर एक संवादात्मक विचार मंथन सत्र का संचालन किया।

31 मार्च, 2021 को एएसईएम शिक्षा सचिवालय, ब्रूसेल्स, बेल्जियम द्वारा आयोजित एएमईएम शिक्षा विजन और रणनीति कार्य योजना 2030 पर (ऑनलाइन) वेबिनार में भागीदारी

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

29 जून 2020 को ''बहुपक्षीय संगठनों में नेटवर्क यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ाएं'' पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया और इंडियन ओसियन रिम यूनिवर्सिटी नेटवर्क (आईओआरयूएन) पर पहला ड्राफ्ट आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया

अप्रैल 2020 में शुरू किए ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर आलेख में तीन खंडों में योगदान दिया और 8 मई 2020 को प्रस्तुत किया

एनईपी 2020 कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्य समूह में ''भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों का संचालन'' पर नीपा परियोजना में योगदान दिया

सितंबर 2020 में आयोजित साक्षात्कारों के लिए साक्षात्कार प्रश्नावली तैयार किए और साक्षात्कार से अंतर्दृष्टि 22 अक्टूबर 2020 को पूरी हुई

10 अक्टूबर 2020 को बिट्स पिलानी के इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस पर केस अध्ययन का मसौदा पूरा किया

''राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के संचालन'' पर कार्य समूह में तीन वर्गों में योगदान दिया। 24 अक्टूबर 2020 को पूर्ण और प्रस्तुत किया गया।

यूआईसी परियोजना, दुबई, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और कतर में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर (आईबीसी): भारत के लिए सबक पर शोध अध्ययन में योगदानकर्ता के रूप में भागीदारी

बिट्स पिलानी–दुबई परिसर पर शोध अध्ययन प्रस्तुत किया

नीपा एनईपी परियोजना के लिए आयोजित साक्षात्कारों से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीयकरण और सीख पर सामान्य खंड तैयार किया

पल्स सर्वेक्षणः भारत में शाखा परिसरों की स्थापना के लिए संभावनाएंः 'सर्वोच्च 200' विश्वविद्यालयों की प्राथमिकताओं को समझने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पल्स सर्वेक्षण पर परियोजना में योगदान दिया और सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए जनवरी 2021 में 'सर्वोच्च 200' विश्वविद्यालयों के 168 प्रशासकों को ईमेल अनुरोध भेजा।

फरवरी 2021 तक अद्यतन किए गए 206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया।

नीपा के बाहर प्रख्यात निकायों की सदस्यता

मानवाधिकार शिक्षा समीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय संपादकीय बोर्ड के सदस्य

आलोक रंजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की सामान्य स्थिति; प्राथमिकता वाले क्षेत्र, समस्याएं तथा एससीओ सदस्य देशों के साथ सहयोग के आशाजनक क्षेत्र पर तैयार स्थिति रिपोर्ट को मार्च 2020 में आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया।

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की सामान्य स्थिति; प्राथमिकता वाले क्षेत्र, समस्याएं तथा एससीओ सदस्य देशों के साथ सहयोग के आशाजनक क्षेत्र पर तैयार स्थिति रिपोर्ट को अप्रैल 2020 में समीक्षा के लिए वरिष्ठ सलाहकार को प्रस्तुत किया।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। मार्च 2020 तक दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया और काकेशस क्षेत्र के सभी देशों के अद्यतन तथ्य पत्रकों को 23 मार्च 2020 में आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया और संशोधित किए गए तथ्य पत्रकों को 28 अप्रैल 2020 को फिर आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए।

मार्च 2020 में शुरू की गई ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। मई 2020 में दक्षिण एशिया प्रान्त के लिए पहला मसौदा पूरा किया।

भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया तथा काकेशस क्षेत्र में भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर एक विस्तृत नोट तैयार किया। जुलाई 2020 के मध्य में आंतरिक समीक्षा के लिए दूसरा मसौदा प्रस्तुत किया।

206 देशों और क्षेत्रों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदानकर्ता के रूप में कार्य तथा दक्षिण एशिया (6 देश), पश्चिम एशिया (10 देशों में से 7) और मध्य एशिया (5 देश) से 18 देशों के प्रोफाइल 12 अगस्त 2020 को पूर्ण करके आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए।

बहुपक्षीय संगठनों में ''हाउ टू टेक फॉरवर्ड नेटवर्क यूनिवर्सिटी'' अवधारणाओं पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। एससीओ नेटवर्क यूनिवर्सिटी पर एक नोट तैयार किया और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया।

''भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के शाखा परिसरों के संचालन'' पर कार्य समूह में एनईपी 2020 कार्यान्वयन रणनीतियों पर नीपा परियोजना में योगदान दिया।

सितंबर 2020 में ग्रामीण कैलेडोनियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बांग्लादेश पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(ग्रामीण कैलेडोनियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बांग्लादेश) पर शोध अध्ययन का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण अक्टूबर 2020 के मध्य में प्रस्तुत किया।

फरवरी 2021 तक अद्यतन किए गए 206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया तथा काकेशस क्षेत्र के सभी देशों के तथ्य पत्रक पूरे किये।

बिनय प्रसाद

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सार्वजनिक निकायों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता

मई 2020 में 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व के वाणिज्यिक, आर्थिक और निवेश के क्षेत्रों में रूस–भारत सहयोग के विकास हेतु कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान की।

जून 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर जानकारी प्रदान की।

जून 2020 में भारत–डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर संकल्पना पत्र हेतु जानकारी प्रदान की।

फरवरी 2021 में पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत डाटा प्रोसेसिंग क्लॉज पर राय साझा की।

फरवरी 2021 में भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी दस्तावेज़ पर यूरोपीय संघ द्वारा साझा किए गए काउंटर ड्राफ्ट पर टिप्पणियां प्रदान की।

फरवरी 2021 में भारत और फिनलैंड के बीच उच्च स्तरीय बैठक पर कार्यसूची के लिए जानकारी प्रस्तुत की।

अन्य शैक्षणिक और व्यावसायिक योगदान

206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। यूरोप के सभी देशों के तथ्य पत्रक मार्च 2020 तक अद्यतन किए गए। अप्रैल 2020 में आंतरिक समीक्षा के लिए संशोधित तथ्य पत्रक प्रस्तुत की गईं।

मार्च 2020 में शुरू की गई ''कोविड–19 और उच्च शिक्षाः भारत के लिए चुनौतियां और अवसर'' पर एनईपी परियोजना में योगदान दिया। मई 2020 में यूरोप के लिए पहला मसौदा पूरा किया।

भारत की उच्च शिक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए संभावित उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। यूरोप में भारत की उच्च शिक्षा भागीदारी को बढ़ाने हेतू उच्च प्राथमिकता वाले देशों पर एक विस्तृत नोट तैयार किया और जुलाई 2020 में आंतरिक समीक्षा के लिए दूसरा मसौदा प्रस्तुत किया।

206 देशों और क्षेत्रों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदानकर्ता। यूरोप के देशों की प्रोफाइल पर 10 समझौता ज्ञापन अगस्त 2020 में पूरी हुई।

बहुपक्षीय संगठनों में ''हाउ टू टेक फॉरवर्ड नेटवर्क यूनिवर्सिटी'' अवधारणाओं पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया। रूसी भारतीय विश्वविद्यालयों के नेटवर्क (आरआईएन) पर एक नोट तैयार किया और आंतरिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया।

फरवरी 2021 तक अद्यतन किए गए 206 देशों और क्षेत्रों की तथ्य पत्रक तैयार करने पर यूआईसी परियोजना में योगदान दिया और यूरोप के सभी देशों के तथ्य पत्रकों को पूरा किया।

गौरव कुमार झा

प्रकाशन

समीक्षाधीन वर्ष में प्रकाशित शोध पत्र/आलेख

द प्रिंट न्यूज पोर्टल के लिए 'एक साल भारत में कोई नया डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है – नीट/जेईई में देरी करने से क्या होगा'। 28 अगस्त, 2020 को प्रकाशित, https://theprint-in/opinion/year-with-no-doctors-engineers-what-delaying-neet-jee-will-do/490882/

संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी

26 सितंबर, 2020 को इंडिक–बेल्ट सोसाइटी और सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, जेएनयू द्वारा आयोजित 'अंडरस्टैंडिंग इन्डोनेशियाई इस्लाम' शीर्षक से श्री एम.जे. अकबर, पूर्व विदेश राज्य मंत्री के साथ इस्लाम पर पहली अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को संबोधित किया।

8 अप्रैल, 2020 को 'महामारी के समय में निरस्त्रीकरण के बहुपक्षीय प्रयासः सीटीबीटीओ के सबक और सर्वोत्तम अभ्यास' विषय पर संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सीटीबीटीओ युवा समूह, वियना को संबोधन।

सार्वजनिक निकायों को परामर्शी और शैक्षणिक सहायता

5 जुलाई, 2020 को जी20 ईडीडब्ल्यूजी के लिए ओईसीडी प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ तैयार और प्रस्तुति।

10–11 मार्च, 2020 को निर्धारित दूसरी जी20 शेरपा बैठक के लिए जानकारी/कार्यवृत्त तैयार और प्रस्तुति।

30 जून को वर्ष 2020 के दौरान जी20 शिक्षा कार्य समूह में अब तक के महत्वपूर्ण विकासों को दर्शाने वाला टिप्पणी तैयार और प्रस्तुति।

आईसीटी अनुप्रयोग

के. श्रीनिवास

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों में भागीदारी

13 जून, 2020 को एस.एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद द्वारा आयोजित वर्तमान परिदृश्य में डिजिटल शिक्षण और अधिगम की चुनौतियां और संभावनाएं पर राष्ट्रीय वेबिनार आमंत्रिति अध्यक्ष।

15–16 जून, 2020 को स्कूल ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा आयोजित शिक्षक शिक्षा में वैकल्पिक आकलन और मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित।

20 जुलाई 2020 को डीडीआर कॉलेज, चबुआ, असम द्वारा आयोजित महामारी के माध्यम से शिक्षणः चुनौतियां और अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के ऑनलाइन सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित।

25 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी, वारंगल द्वारा ऑनलाइन शिक्षा – अवसर और चुनौतियां, पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में आमंत्रिति अध्यक्ष।

26 अगस्त, 2020 को मैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉमर्स टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मश्विास और प्रौद्योगिकी अनुकूल शिक्षक – पार्ट III पर राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के आमंत्रिति अध्यक्ष

19 सितंबर, 2020 को मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज फॉर विमेन, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति–2020 में प्रतिमान बदलावः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर रूसा प्रायोजित वेबिनार के आमंत्रिति अध्यक्ष।

20 सितंबर 2020 को शिक्षा विभाग, ग्रामीण उच्च अध्ययन संस्थान (आरआईएचएस), भोगराई, उड़ीसा द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी और गेमिंग के माध्यम से शिक्षण और अधिगम को बदलना पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के आमंत्रिति अध्यक्ष।

27 अक्टूबर 2020 को एसोचौम, दिल्ली द्वारा आयोजित ''नई शिक्षा नीति 2020 ज्ञान श्रृंखला – उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी–कार्यान्वयन की चुनौतियां'' पर वेबिनार के प्रख्यात आमंत्रिति अध्यक्ष।

11 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर स्कूल ऑफ एजुकेशन, इग्नू द्वारा आयोजित ''ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षाः शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का समान उपयोग सुनिश्चित करना'' पर पैनल चर्चा में एक संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

29–30 दिसंबर, 2020 को पालीवाल पीजी कॉलेज, फिरोजाबाद द्वारा आयोजित 'बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन' पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के आमंत्रिति मुख्य वक्ता

16 जनवरी 2021 को बैरकपुर राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज द्वारा आयोजित ई–लर्निंग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए आमंत्रिति मुख्य वक्ता।

महत्वपूर्ण परामर्श और सलाहकारी सेवाएं

स्कूली शिक्षा और साक्षरता हेतु राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के लिए तकनीकी वास्तुकला एवं मानकों पर कार्य समूह के सदस्य (एनडीईएआर–एसई एंड एल)।

अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता सुधार परियोजना के सदस्य, ''वैश्विक ज्ञान पुंज के उचित उपयोग और अपनाने के लिए अनुकूलन योग्य एलएमएसः ई–अधिगम के आकस्मिक सिद्धांत का अनुकूलन'' रूसा 2.0 के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान को सम्मानित किया गया।

शिक्षण के मिश्रित तरीके पर एक अवधारणा नोट तैयार करने के लिए यूजीसी विशेषज्ञ समिति के सदस्य।

पारुल विश्वविद्यालय, गुजरात द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा में अधिगम प्रबंधन प्रणाली में प्रमाणपत्र कार्यक्रम पर सलाहकार समिति के सदस्य।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सोनीपत के सीनेट सदस्य

सार्वजनिक निकायों को शैक्षणिक सहायता

20 मई, 2020 को एसआरएम विश्वविद्यालय, सोनीपत के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस), की बैठक में भाग लिया।

नीपा के बाहर दिये व्याख्यान

3 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले एनआईटी वारंगल के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा, विकास और वितरण पर एक महीने के लिए (3 घंटे/प्रतिदिन, ऑनलाइन क्रियाशील संकाय उन्मुखीकरण कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति/परामर्शदाता के रूप में आमंत्रित

4–5 अप्रैल, 2020 को पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू, संकाय के लिए दो दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

10–11 अप्रैल, 2020 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू), संकाय के लिए दो दिवसीय मूक कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

27–28 अप्रैल, 2020 को विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय, नेल्लोर (वीएसयू), संकाय के लिए दो दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

29 अप्रैल 2020 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश संकाय के लिए एक दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

30 अप्रैल, 1 मई 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), संकाय के लिए दो दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

2–3 मई, 2020 मई को आईआईआईटीडीएम कुरनूल और आईआईआईटी, तिरुचिनापल्ली द्वारा आयोजित मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर दो दिवसीय आभासी कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

6–8 मई, 2020 को यूजीसी–मा.सं.वि. केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला बैच–1, के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

9–11 मई, 2020 को यूजीसी–मा.सं.वि. केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला बैच–2, के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

12–14 मई, 2020 को यूजीसी–मा.सं.वि. केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक कार्यशाला बैच–3, के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

15–16 मई, 2020 को कोयंबटूर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोयमबटूर द्वारा आयोजित तमिलनाडु राज्य उच्च शिक्षा परिषद (टीएएनएससीएचई) द्वारा प्रायोजित मूडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा, विकास और वितरण पर दो दिवसीय आभासी कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

13–14 जुलाई, 2020 को एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडिया (ईपीएसआई), नई दिल्ली द्वारा ऑनलाइन शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पर दो दिवसीय आभासी संकाय विकास कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

23–24 मई, 2020 को यूजीसी–एचआरडीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक्स कार्यशाला (बैच–1), के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

25–26 मई, 2020 मई को यूजीसी–एचआरडीसी, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक्स कार्यशाला (बैच–2), के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

29–31 मई, 2020 मई को यूजीसी–एचआरडीसी, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास, वितरण और मूल्यांकन पर तीन दिवसीय आभासी मूक्स कार्यशाला (बैच–4), के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित

04–17 जून, 2020 को श्री वेंकटसामी नायडू कॉलेज, तमिलनाडु द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल पहल पर दो सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

9–10 जून, 2020 को भवंस विवेकानंद कॉलेज, हैदराबाद द्वारा आयोजित मूडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा, विकास और वितरण पर दो दिवसीय आभासी कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

11–12 जून, 2020 को महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद द्वारा मूडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के डिजाइन, विकास और वितरण पर दो दिवसीय आभासी कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

17 जून 2020 को शिक्षा विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय आभासी मूक्स कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

22–23 जुलाई, 2020 को तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन पर दो दिवसीय आभासी संकाय विकास कार्यशाला के लिए एक संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

13–17 अगस्त, 2020 से श्रीश्री रविशंकर विश्वविद्यालय, कटक के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की रूपरेखा, विकास और वितरित करने पर पांच दिवसीय (3 घंटे/प्रतिदिन) ऑनलाइन क्रियाशील संकाय उन्मुखीकरण कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति/परामर्शदाता के रूप में आमंत्रित।

आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एपीएससीएचई), और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरनूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा, विकास और वितरण पर पांच दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में आमंत्रित।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/आयोजित/संचालित

स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूक पाठ्यक्रम की रूपरेखा, विकास और वितरण पर संकाय विकास कार्यक्रम (समय अवधि 6 दिन), नीपा, नई दिल्ली।

स्वयं मंच के माध्यम से मूक पाठ्यक्रमों के डिजाइन, विकास और वितरण पर संकाय विकास कार्यक्रम (समय अवधि 6 दिन), नीपा, नई दिल्ली।

शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालयों में मूक और आईसीटी के अनुप्रयोग पर संकाय विकास कार्यक्रम (समय अवधि 6 दिन), नीपा, नई दिल्ली।

प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम विकसित और निष्पादित

चार वृत्तखंडीय दृष्टिकोण में प्रशिक्षण सामग्री तैयार की और प्रोफेसर श्रीनिवास लर्निंग पोर्टल [http://profksrinivas.in] में अपलोड की।

मिश्रित/व्यवस्थित वातावरण में सभी कार्यशालाओं का संचालन किया।

मूडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग सामग्री विकसित की।

पी–एच.डी. मौखिक परीक्षा के परीक्षक

सुश्री बिचित्रा चौधरी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा ''शिक्षण–अधिगम के बीच माध्यमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों पर स्मार्ट कक्षाओं का प्रभाव'' शीर्षक के लिए जून 2019 को पीएच.डी. मौखिक परीक्षा के परीक्षक।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

प्रबंधन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

अध्यक्ष

1. प्रो. एन.वी.वर्गीज, — अध्यक्ष
   कुलपति, नीपा, नई दिल्ली।

डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)

2. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   अध्यक्ष, उच्चतर एवं व्यावसायिक
   शिक्षा विभाग, नीपा, नई दिल्ली।

3–5 प्रख्यात शिक्षाविद् कुलाधिपति द्वारा नामित

3. प्रो. कपिल कपूर — सदस्य
   भूतपूर्व सम–कुलपति, जेएनयू,
   बी–2/332, एकता गार्डन,
   9–आई.पी. एक्स्टेंशन,
   मदर डेरी मार्ग, दिल्ली– 110092

4. प्रो. डी.एस. चौहान — सदस्य
   कुलपति,
   जी.एल.ए. विश्वविद्यालय,
   17के.एम. स्टोन, एनएच–2,
   मथुरा–दिल्ली रोड, पी.ओ.– चुमुहन,
   मथुरा– 281406 (यू.पी.)

5. प्रो. पी. दुराईस्वामी — सदस्य
   भूतपूर्व कुलपति
   मद्रास विश्वविद्यालय,
   नया नं. 3, पुराना नं. 2/1,
   थर्ड स्ट्रीट, नेहरु नगर, अदयार,
   चेन्नई– 600020

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

6. सुश्री नीता प्रसाद — सदस्य
   संयुक्त सचिव (आई.सी.सी./पी)
   उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

7–8 संस्थान के दो संकाय सदस्यः एक प्रोफेसर तथा एक सह–प्रोफेसर

7. प्रो. ए.के. सिंह — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक नीति विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

8. डॉ. संगीता अंगोम — सदस्य
   सह–प्रोफेसर
   उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा,
   नीपा, नई दिल्ली

9–11 शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित तीन विख्यात शिक्षाविद्

9. प्रो. बद्री नारायण तिवारी — सदस्य
अध्यक्ष तथा निदेशक
जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान,
झुसी, प्रयागराज– 211019 (उत्तर प्रदेश)

10. प्रो. पी.एस. राणा — सदस्य
प्रो. (अध्यक्ष) अर्थशास्त्र
हेमवती नंदन बहुगुणा,
गढ़वाल विश्वविद्यालय,
गढ़वाल, श्रीनगर– 246147
(उत्तराखण्ड)

11. प्रो. शैलेन्द्र कुमार पोखरियाल — सदस्य
परामर्शदाता,
ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिस्टम इंडिया प्रा.लि.,
गुरुग्राम (हरियाणा)
भूतपूर्व प्रोफेसर, पेट्रोलियम
एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून

कुलसचिव, नीपा

12. डॉ. संदीप चटर्जी — पदेन–सचिव
कुलसचिव
नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट–II

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी. वर्गीज — अध्यक्ष
   कुलपति
   नीपा, नई दिल्ली

डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)

2. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   अध्यक्ष, उच्चतर एवं व्यावसायिक
   शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

3. सुश्री दर्शना मोमाया डबराल — सदस्य
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
   उच्चतर शिक्षा विभाग
   शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली

4–5 प्रबंधन बोर्ड के नामित दो सदस्य

4. प्रो. बद्री नारायण तिवारी — सदस्य
   अध्यक्ष तथा निदेशक
   जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान,
   झुसी, प्रयागराज–211019 (उत्तर प्रदेश)

5. प्रो. पी.एस. राणा — सदस्य
   प्रो. (अध्यक्ष) अर्थशास्त्र
   हेमवती नंदन बहुगुणा,गढ़वाल विश्वविद्यालय,
   गढ़वाल, श्रीनगर–246147 (उत्तराखण्ड)

6. वित्त अधिकारी (प्रभारी) — पदेन–सचिव
   नीपा, नई दिल्ली–110016

परिशिष्ट-III

अकादमिक परिषद के सदस्य

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी. वर्गीज — अध्यक्ष
   कुलपति,
   नीपा, नई दिल्ली

डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)

2. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

03–12 सभी विभागाध्यक्ष

3. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

4. प्रो. ए.के. सिंह — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक नीति विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

5. प्रो. प्रणति पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
   स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक,
   नीपा, नई दिल्ली

6. प्रो. मोना खरे — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

7. प्रो. कुमार सुरेश — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशासन विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

8. प्रो. बी.के. पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं
   क्षमता विकास विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

9. प्रो. के. बिस्बाल — सदस्य
   प्रोफेसर और अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली

10. प्रो. वीरा गुप्ता — सदस्य
    प्रोफेसर और कार्यवाहक अध्यक्ष
    शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
    नीपा, नई दिल्ली

11. प्रो. रश्मि दीवान — सदस्य
प्रोफेसर और अध्यक्ष
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र,
नीपा, नई दिल्ली

12. प्रो. के. श्रीनिवास — सदस्य
प्रोफेसर
आई.सी.टी. तथा अध्यक्ष, पी.एम.यू.,
नीपा, नई दिल्ली

13–20 सभी प्रोफेसर

13. प्रो. पी. गीता रानी — सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक योजना विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

14. प्रो. विनिता सिरोही — सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक प्रशासन विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

15. प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय — सदस्य
प्रोफेसर
विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

16. प्रो. आरती श्रीवास्तव — सदस्य
प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
नीपा, नई दिल्ली

17. प्रो. रस्मिता दास स्वैन — सदस्य
प्रोफेसर
स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक,
नीपा, नई दिल्ली

18. प्रो. मनीषा प्रियम — सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक नीति विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

19. प्रो. नीरु स्नेही — सदस्य
प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

20. प्रो. सुनीता चुग — सदस्य
प्रोफेसर
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र
नीपा, नई दिल्ली

21–23 संस्थान के बाहर के तीन प्रख्यात शिक्षविद्

21. प्रो. एच. रामचंद्रन — सदस्य
राष्ट्रीय अध्येता, आई.सी.एस.एस.आर

22. प्रो. पूनम बत्रा — सदस्य
केंद्रीय शिक्षा संस्थान,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

23. प्रो. एस. माधेश्वरम — सदस्य
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
आर्थिक एवं नीति अध्ययन केंद्र,
सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान,
बंगलुरू

कुलपति द्वारा नामित दो सह–प्रोफेसर

24. डॉ. संगीता अंगोम — सदस्य
सह–प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

25–26 कुलपति द्वारा नामित दो सहायक प्रोफेसर

25. डॉ. कश्यपी अवस्थी — सदस्य
सहायक प्रोफेसर
विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

26. डॉ. वी सुचरिता — सदस्य
सहायक प्रोफेसर
शैक्षिक प्रशासन विभाग,
नीपा, नई दिल्ली

27–29 अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण समेकित तीन व्यक्ति

27. प्रो. सुदर्शन अयंगर — सदस्य
    प्लॉट नं. 3, ए.आर.सी.एच कैम्पस,
    नगरिया, ओज़ारपाडा रोड,
    धर्मपुर– 396050
    जिला– वलसाड– गुजरात

28. प्रो. अतुल शर्मा — सदस्य
    अध्यक्ष, ओ.के.डी.आई.एस.सी.डी. गुवाहाटी,
    264, रामा अपार्टमेन्टस, सेक्टर–11,
    पॉकेट–2, द्वारका, नई दिल्ली–110075

29. प्रो. गीता बी. नामबिसन — सदस्य
    ज़ाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केंद्र,
    सामाजिक विज्ञान विभाग,
    जे.एन.यू., नई दिल्ली

परीक्षा नियंत्रक

30. प्रो. ए.के. सिंह — स्थायी आमंत्रिति
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    शैक्षिक नीति विभाग,
    नीपा, नई दिल्ली

31. डॉ. संदीप चटर्जी — पदेन–सदस्य
    कुलसचिव, नीपा

परिशिष्ट-IV

अध्ययन बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी.वर्गीज — अध्यक्ष
   कुलपति
   नीपा, नई दिल्ली।

डीन (अकादमिक एवं अनुसंधान)

2. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

3–15 विभागाध्यक्ष और संकाय/विभाग के सभी प्रोफेसर

3. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

4. प्रो. ए.के. सिंह — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक नीति विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

5. प्रो. प्रणति पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
   स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक,
   नीपा, नई दिल्ली।

6. प्रो. मोना खरे — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

7. प्रो. कुमार सुरेश — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशासन विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

8. प्रो. बी. के. पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

9. प्रो. के. बिस्वाल — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

10. प्रो. रश्मि दीवान — सदस्य
    प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
    राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र,
    नीपा, नई दिल्ली।

11. प्रो. के. श्रीनिवास सदस्य
प्रोफेसर
आई.सी.टी. तथा अध्यक्ष, पी.एम.यू.,
नीपा, नई दिल्ली।

12. प्रो. वीरा गुप्ता सदस्य
प्रोफेसर एवं कार्यवाहक अध्यक्ष
शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

13. प्रो. पी. गीता रानी सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक योजना विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

14. प्रो. विनिता सिरोही सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक प्रशासन विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

15. प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय सदस्य
प्रोफेसर
विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

16. प्रो. आरती श्रीवास्तव सदस्य
प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
नीपा, नई दिल्ली।

17. प्रो. रस्मिता दास स्वैन सदस्य
प्रोफेसर
स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक,
नीपा, नई दिल्ली।

18. प्रो. मनीषा प्रियम सदस्य
प्रोफेसर
शैक्षिक नीति विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

19. प्रो. नीरू स्नेही सदस्य
प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

20. प्रो. सुनीता चुग सदस्य
प्रोफेसर
राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र
नीपा, नई दिल्ली।

कुलपति द्वारा नामित दो सह–प्रोफेसर

21. डॉ. संगीता अंगोम सदस्य
सह–प्रोफेसर
उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

कुलपति द्वारा नामित दो सहायक प्रोफेसर

22. डॉ. कश्यपी अवस्थी सदस्य
सहायक प्रोफेसर
विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

23. डॉ. वी. सुचरिता सदस्य
सहायक प्रोफेसर
शैक्षिक प्रशासन विभाग,
नीपा, नई दिल्ली।

24–25 अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण समेकित दो व्यक्ति

24. प्रो. संतोष पांडा सदस्य
स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली–110068
ई–मेलः spanda.ignou@gmail.com

25. प्रो. जानकी राजन सदस्य
अध्यापक प्रशिक्षण एवं
अनौपचारिक शिक्षा विभाग
जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर, नई दिल्ली– 110025
ई–मेलः janakirajan1@rediffmail.com

परीक्षा नियंत्रक

26. प्रो. ए.के. सिंह स्थायी आमंत्रिति
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
शैक्षिक नीति विभाग
नीपा, नई दिल्ली।

परिशिष्ट-V

योजना और निरीक्षण बोर्ड के सदस्य

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1. प्रो. एन.वी. वर्गीज — अध्यक्ष
   कुलपति
   नीपा, नई दिल्ली।

2 से 9 सभी विभागाध्यक्ष

2. प्रो. सुधांशु भूषण — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   उच्चतर एवं व्यासायिक शिक्षा विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

3. प्रो. ए.के. सिंह — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक नीति विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

4. प्रो. प्रणती पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग,
   स्कूल मानक एवं मूल्यांकन एकक
   नीपा, नई दिल्ली।

5. प्रो. मोना खरे — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक वित्त विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

6. प्रो. कुमार सुरेश — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशासन विभाग
   नीपा, नई दिल्ली।

7. प्रो. बी.के. पांडा — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

8. प्रो. के. बिस्वाल — सदस्य
   प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
   शैक्षिक योजना विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

9. प्रो. वीरा गुप्ता — सदस्य
   प्रोफेसर एवं कार्यवाहक अध्यक्ष
   शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग,
   नीपा, नई दिल्ली।

10–12 संस्थान के बाहर के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ

10. प्रो. जी.डी. शर्मा — सदस्य
अध्यक्ष
समाज के लिये शिक्षा और
आर्थिक विकास समिति,
नई दिल्ली।
ईमेलः ganeshdatts@gmail.com

11. प्रो. मोहम्मद अख्तर सिद्दकी — सदस्य
प्रोफेसर
उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान,
शिक्षा संकाय
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली
ईमेलः mohdakhtar.siddiqui@gmail.com

12. प्रो. नमिता रंगनाथन — सदस्य
प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, सी.आई.ई.
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
ईमेलः namita.ranganathan@gmail.com

13. डॉ. संदीप चटर्जी — सचिव
कुलसचिव,
नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट-VI

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

कुलपति
प्रो. एन.वी. वर्गीज

शैक्षिक योजना विभाग
के. बिस्वाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
पी. गीता रानी, प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर)
एन.के. मोहंती, सहायक प्रोफेसर
सुमन नेगी, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक प्रशासन विभाग
कुमार सुरेश, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
विनीता सिरोही, प्रोफेसर
वी. सुचरिता, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक वित्त विभाग
मोना खरे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वेटुकुरी पी.एस. राजू, सहायक प्रोफेसर

शैक्षिक नीति विभाग
अविनाश के. सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
मनीषा प्रियम, प्रोफेसर
एस.के. मलिक, सहायक प्रोफेसर
नरेश कुमार, सहायक प्रोफेसर

विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग
प्रणति पांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
रश्मि दिवान, प्रोफेसर
मधुमिता बंद्योपाध्याय, प्रोफेसर
सुनीता चुग, प्रोफेसर
कश्यपी अवस्थी, सहायक प्रोफेसर

उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग
सुधांशु भूषण, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र (एनआरसीई)
आरती श्रीवास्तव, प्रोफेसर
और समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केंद्र (एनआरसीई)
नीरू स्नेही, प्रोफेसर
संगीता अंगोम, सह–प्रोफेसर

शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग

शैक्षिक प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास विभाग
बी.के. पांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
वीरा गुप्ता, प्रोफेसर
सविता कौशल, सहायक प्रोफेसर (प्रतिनियुक्ति पर)
मोना सेदवाल, सहायक प्रोफेसर

कंप्यूटर केंद्र
के. श्रीनिवास, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

राष्ट्रीय विद्यालय नेतृत्व केंद्र
रश्मि दीवान, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
सुनीता चुग, प्रोफेसर
एन. मैथिली, सहायक प्रोफेसर
सुभिथा जी.वी. सहायक प्रोफेसर

उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केंद्र
मोना खरे, प्रोफेसर
निधि सदाना सभरवाल, सह–प्रोफेसर
अनुपम पचौरी, सहायक प्रोफेसर
गरिमा मलिक, सहायक प्रोफेसर
जिणुशा पाणिग्रही, सहायक प्रोफेसर
मलिश सी.एम., सहायक प्रोफेसर

स्कूल मानक एवं मूल्याकन एकक
प्रणति पांडा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
रश्मिता दास स्वैन, प्रोफेसर
ए. एन. रेड्डी, सहायक प्रोफेसर

परियोजना प्रबंधन एकक
के. श्रीनिवास, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

प्रशासनिक और अकादमिक सहयोग

कुलपति (प्रभारी)
कुमार सुरेश (प्रभारी) 30.06.2018 (अपराह्न) से 23.09.2020
संदीप चटर्जी

सामान्य और कार्मिक प्रशासन
जी. वीराबाहू, प्रशासनिक अधिकारी (लियन पर)
नरेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) 15.03.2021 तक
डी.एस. ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी 16.03.2021 से
चंद्र प्रकाश, अनुभाग अधिकारी (सा.प्र.)
सोनम आनंद सागर, अनुभाग अधिकारी (कार्मिक) (तदर्थ)

अकादमिक प्रशासन
पी.पी. सक्सेना, अनुभाग अधिकारी

वित्त और लेखा
पूजा सिंह, वित्त अधिकारी (प्रभारी)

प्रशिक्षण कक्ष
जय प्रकाश धामी, अनुभाग अधिकारी

प्रकाशन एकक
प्रमोद रावत, उप प्रकाशन अधिकारी

हिंदी कक्ष
मनोज गौड़, क. अनुवाद अधिकारी

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र
पूजा सिंह, पुस्तकालयाध्यक्षा
डी.एस. ठाकुर, प्रलेखन अधिकारी

कंप्यूटर केंद्र
के. श्रीनिवास, अध्यक्ष
चन्द्रा कुमार एम. जे, सिस्टम एनालिस्ट

हॉस्टल
वी.पी.एस. राजू, हॉस्टल वार्डन
कश्यपी अवस्थी, सहायक हॉस्टल वार्डन

VII

वार्षिक लेखा
2020-21

तुलन पत्र

31 मार्च 2021 तक

(राशि ₹ में)

निधि के स्रोत / देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पूंजीकृत निधि	1	(15,90,92,631)	(15,37,32,539)
मौजूदा देनदारियां एवं प्रावधान	2	65,66,37,962	62,24,60,551
योग		**49,75,45,331**	**46,87,28,012**
स्थायी परिसंपत्तियां	3	20,07,83,918	19,44,72,690
अचल संपत्तियां – योजनेतर		-	-
अचल संपत्तियां – गैर योजनेतर		-	-
अचल संपत्तियां – अमूर्त आस्तियाँ		-	-
अचल संपत्तियां – पेटेंट और कॉपीराइट्स		-	-
अचल संपत्तियां – अन्य (प्रायोजित परियोजनाएं)		-	-
चालू परिसंपत्तियां	4	22,12,39,072	18,86,41,543
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशियां	5	7,55,22,341	8,56,13,779
योग		**49,75,45,331**	**46,87,28,012**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	15		
आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियां	16		

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

आय और व्यय लेखा

31 मार्च 2021 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अ. आय			
शैक्षणिक प्राप्तियां	6	3,78,150	8,25,760
अनुदान/सब्सिडी	7	31,31,72,934	38,93,83,450
अर्जित ब्याज	8	13,46,370	18,30,212
अन्य आय	9	61,22,783	36,59,277
योग (अ)		32,10,20,237	39,56,98,699
ब. व्यय			
कर्मचारियों को भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	10	23,05,38,555	27,81,22,709
अकादमिक व्यय	11	6,25,21,636	7,71,04,082
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	12	3,21,59,894	3,79,48,173
परिवहन व्यय	13	4,90,326	9,36,637
मरम्मत एवं रखरखाव	14	99,37,048	1,66,68,157
मूल्यह्रास	3	1,53,17,372	1,40,81,559
योग (ब)		**35,09,64,830**	**42,48,61,317**
पूंजी निधि में हो रहे अधिशेष/(घाटा)		**(2,99,44,593)**	**(2,91,62,618)**

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

अनुसूची 1 से 5
तुलन पत्र के भाग के रूप में

31 मार्च 2021 तक

अनुसूची 1
कोष/पूंजी निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(15,37,32,539)	(13,93,71,066)
जोड़कर: काय/पूंजीगत निधि में योगदान	2,12,32,693	1,47,78,209
जोड़कर: उपहार/दान में प्राप्त आस्तियां	7,128	22,936
जोड़कर: असमायोजित शेष आगे बढ़ाया गया	29,48,773	-
जोड़कर: प्रयोजित परियोजना निधि से खरीदी गई आस्तियां	3,95,907	-
जोड़कर: आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय से अधिक आय	-	-
योग	**(12,91,48,039)**	**(12,45,69,921)**
घटाकर: आय और व्यय खाते से स्थानांतरित घाटा	2,99,44,593	2,91,62,618
वर्ष के अंत में शेष	**(15,90,92,631)**	**(15,37,32,539)**

अनुसूची 2

मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
अ. वर्तमान देनदारियां		
प्रतिभूति सुरक्षा राशि	10,78,873	10,12,413
पत्रिकाओं की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	1,06,740	1,39,020
बकाया देयता	24,392	29,48,773
वेतन देय	1,35,66,263	1,34,01,775
मा.सं.वि.मं. को देय ब्याज	-	-
प्रायोजित परियोजना की प्राप्तियां (कुल व्यय)	11,99,28,311	13,98,94,084
अग्रिम में प्राप्त आय (वर्ष 2020–21 की अप्रयुक्त अनुदान)	4,99,68,375	1,55,74,002
योग (अ)	**18,46,72,954**	**17,29,70,067**
ब. प्रावधान		
पेंशन	40,76,61,203	38,82,48,765
उपदान	4,16,22,749	3,96,40,713
अवकाश नकदीकरण	2,26,81,056	2,16,01,006
योग (ब)	**47,19,65,008**	**44,94,90,484**
योग (अ+ब)	**65,66,37,962**	**62,24,60,551**

अनुसूची 2(अ)

प्रायोजित परियोजनाएं

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान अनुदान प्राप्ति	वर्ष के दौरान प्राप्तियां / वसूली	कुल	जमा शेष		
		निकासी	जमा				वर्ष के दौरान व्यय	निक. ासी	जमा
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडेपा)	-	94,93,874	39,33,042	2,70,653	1,36,97,569	45,42,603	-	91,54,966
2	डाईस की स्थापना और संचालन (यूनीसेफ़) डा. के. बिस्वाल	-	6,98,946	-		6,98,946	-	-	6,98,946
3	14 राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में ग्रा.शि.स. / डी.टी.ए. / एस. एम.डी.सी. / नगरीय निकायों की भूमिका का अध्ययन, एडसिल (प्रो. ए.के. सिंह)	-	5,63,371	-		5,63,371	-	-	5,63,371
4	बुरूण्डी, (दक्षिण अफ्रीका) में भारत अफ्रीका शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	-	23,51,152	-	2,92,866	26,44,018	26,44,018	-	-
5	सर्व शिक्षा अभियान पर परियोजना (मा.सं.वि. मंत्रालय)	-	1,07,294	-		1,07,294	-	-	1,07,294
6	माध्यमिक सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली (सेमिस) मा. सं.वि.मं. (प्रो. ए.सी. मेहता)	-	5,03,573	-		5,03,573	-	-	5,03,573
7	प्रशासनिक उपरिव्यय प्रभार / बचत खाता पर ब्याज	-	3,20,29,638		33,34,970	3,53,64,608	26,20,935	-	3,27,43,673
8	आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा (डॉ. के. सुजाता)	(13,63,560)	-	13,63,560	-	-	-	-	-
9	समग्र शिक्षा	(45,42,486)	1,88,46,986	1,04,50,000	1,16,53,404	3,64,07,904	2,65,82,815	-	98,25,089
10	महात्मा गाँधी शान्ति शिक्षा संस्थान (एम.जी.आई.ई.पी.)		21,00,000	-	-	21,00,000	21,00,000	-	-
11	राजीव गांधी शिक्षक स्थापना पीठ	-	-	-		-	-	-	-
12	उच्च शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र (यूजीसी) (प्रो. एन. वी. वर्गीज)	(12,84,354)	-	12,84,354	-	-0.19	-	-	(0.19)
13	राष्ट्रीय अध्येता (आइसीएसएसआर)	-	-	-		-	-	-	-

14	विविधता भेदभाव और असमानता निपटना (डा. निधि सदाना – सीपीआरएचई) केन्द्रीय योजना कार्यक्रम	-	20,05,865	-		20,05,865	-	-	20,05,865
15	श्रीलंका कार्यक्रम (एसएमआईए जैदी)	-	7,79,234	-		7,79,234	-	-	7,79,234
16	एनईपी मसौदा समीति (भारत भूषण)	-	-	-		-	-	-	-
17	आरएमएसए के अन्तर्गत विद्यालय मानक	-	4,46,564	-		4,46,564	-	-	4,46,564
18	वरिष्ठ अध्येता – डॉ. ए. मैथ्यू (आईसीएसएसआर)	-	47,333	-		47,333	-	-	47,333
19	राज्य का राजनीतिक अध्ययन – डॉ. ए. मैथ्यू (आईसीएसएसआर)	(68,746)	-	-		-68,746	3,50,000	-	(4,18,746)
20	पंडित मदन मोहन मालवीय	-	2,35,94,755	-		2,35,94,755	-	-	2,35,94,755
21	शिक्षण और अनुसंधान आस्ट्रेलिया (वीरा गुप्ता)	-	-	-		-	-	-	
22	आईईपीए (विदेश मंत्रालय)	-	4,01,555	3,20,719	-	7,22,274	-	-	7,22,274
23	आईआईईपी – यूनेस्को (के. सुजाता)	-	41,56,240	-		41,56,240	2,187	-	41,54,053
24	शिक्षक विशारद – ब्रिटिश काउंसिल	-	-	-		-	-	-	-
25	राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र (पीएमएमएमटी)	-	2,82,32,703	3,600	67,348	2,83,03,651	54,32,669	-	2,28,70,982
26	आईपीईए – म्यांमार	(22,87,350)	-	33,88,628	-	11,01,278	1,55,002	-	9,46,276
27	स्वयम् योजना शिक्षकों की भागीदारी (विनीता सिरोही)	-	10,55,971	-		10,55,971	10,55,971	-	-
28	लीप प्रोग्राम	-	33,18,177	-	1,90,067	35,08,244	25,94,557	-	9,13,687
29	नीति और व्यवहार – गुजरात और राजस्थान	-	3,26,652	-	1,00,000	4,26,652	2,43,470	-	1,83,182
30	लचीली अधिगम की योजना – गरिमा मलिक	(58,676)	-	6,59,031	-	6,00,355	2,02,042	-	3,98,313
31	शिक्षा प्रशिक्षण में मुक्त सरकार – सुनीता चुघ	-	7,965	5,06,340	-	5,14,305	1,47,661	-	3,66,644
32	उच्च शिक्षा में ईएसपीआई असमानता– जिणुशा पाणिग्रही	-	1,62,932	-		1,62,932	-	-	1,62,932
33	स्कूल मानक शिक्षा ईएफसी (प्रो. प्रणति पांडा)	-	86,63,305	-		86,63,305	-	-	86,63,305
34	शिक्षाशास्त्रीय एन.वी.एस. (एन. मैथिली)	-	-	1,26,000		1,26,000	50,000	-	76,000
	योग	**(96,05,172)**	**13,98,94,085**	**2,20,35,274**	**1,59,09,308**	**16,82,33,495**	**4,87,23,930**		**11,95,09,565**

अनुसूची 2 (ख)

शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुप्रयुक्त अनुदान

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
अ. योजना अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
शेष राशि अग्रानीत	1,55,74,002	-3,62,10,839
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	36,88,00,000	45,59,46,500
योग (अ)	**38,43,74,002**	**41,97,35,661**
घटाकर: राजस्व व्यय के लिए उपयोग	31,31,72,934	38,93,83,450
घटाकर: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	2,12,32,693	1,47,78,209
योग (ब)	**33,44,05,627**	**40,41,61,659**
अनप्रयुक्त अग्रानीत (अ–ब)	**4,99,68,375**	**1,55,74,002**
ब. अनुदान योजनेतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
शेष राशि अग्रानीत	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तियां (अनुदान)	-	-
योग (स)	-	-
घटाकर: राजस्व व्यय के लिए उपयोग	-	-
घटाकर: पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग	-	
योग (द)	-	-
अनप्रयुक्त अग्रानीत (स–द)	-	-
महायोग (अ+ब)	**4,99,68,375**	**1,55,74,002**

अनुसूची 3

अचल संपत्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आस्तियां शीर्ष	सकल ब्लॉक						वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष 2020–21 के लिए मूल्यह्रास			निवल ब्लॉक
		मूल्यह्रास की दर	अथ शेष	परिवर्धन (180 दिनों से अधिक)	परिवर्धन (180 दिनों से कम)	कटौती	जमा शेष	मूल्यह्रास अथ शेष	परिवर्धन पर वर्ष के दौ. रान मूल्यह्रास	कटौती/ समायोजन	कुल मूल्यह्रास	31.03.21
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1	भूमि	0%	23,07,892	-		-	23,07,892	-	-	-	-	23,07,892
2	भवन	2%	11,67,96,393	-		-	11,67,96,393	23,35,928	-	-	23,35,928	11,44,60,465
3	कार्यालय उपकरण	8%	96,45,033	20,48,152		-	1,16,93,185	7,71,603	1,63,852	-	9,35,455	1,07,57,730
4	कम्प्यूटर और उपकरण	20%	41,21,658	55,00,486	81,01,136	-	1,77,23,280	8,24,332	19,10,211	-	27,34,542	1,49,88,738
5	फर्नीचर और फिक्सचर	8%	58,84,300	-	49,300	-	59,33,600	4,70,744	1,972	-	4,72,716	54,60,884
6	वाहन	10%	13,97,374	-		-	13,97,374	1,39,737	-	-	1,39,737	12,57,637
7	पुस्तकालय पुस्तकें	10%	79,95,680		18,489	-	80,14,169	7,99,568	924	-	8,00,492	72,13,676
8	पत्रिकायें	10%	4,00,90,002	17,47,541	33,730	-	4,18,71,273	40,09,000	1,76,441	-	41,85,441	3,76,85,832
	योग (क)		**18,82,38,332**	**92,96,179**	**82,02,655**	**-**	**20,57,37,166**	**93,50,912**	**22,53,400**	**-**	**1,16,04,312**	**19,41,32,854**
9	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	8,58,406	9,97,395	9,20,240	-	27,76,041	3,43,362	5,83,006	-	9,26,368	18,49,673
10	ई–जर्नल	40%	49,07,703	18,16,224	-	-	67,23,927	19,63,081	7,26,490	-	26,89,571	40,34,356
	योग (ख)		**57,66,109**	**28,13,619**	**9,20,240**	**-**	**94,99,968**	**23,06,444**	**13,09,496**	**-**	**36,15,939**	**58,84,029**
11	कंप्यूटर तथा उपक. रण	20%	1,67,256	0	3,95,907	-	5,63,163	33,451	39,591	-	73,042	4,90,121
12	फर्नीचर और फिक्सर	8%	3,00,993	0	-	-	3,00,993	24,079	-	-	24,079	2,76,914
	योग (ग)		**4,68,249**	**-**	**3,95,907**	**-**	**8,64,156**	**57,531**	**39,591**	**-**	**97,121**	**7,67,035**
	महायोग (क+ख+ग)											

अनुसूची 4

चालू परिसम्पत्तियाँ

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
	1. स्टॉक		
1.	हस्तगत प्रकाशन	6,12,082	4,36,633
2.	वस्तुसूची	8,65,438	7,81,272
	2. नकदी एवं बैंक बचत		
1.	भारतीय स्टेट बैंक (34778757702) (चालू खाता)	31,910	32,559
2.	बैंक बचत (बचत खाता)	21,96,69,230	18,73,69,243
3.	हस्तगत डाक टिकट	60,412	21,836
	योग	**22,12,39,072**	**18,86,41,543**

अनुसूची 5

ऋण, अग्रिम और जमा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
	1. कर्मचारियों को अग्रिम (गैर–ब्याज)		
1.	त्यौहार अग्रिम	-	-
	2. कर्मचारियों को दीर्घावधि के लिए अग्रिम (ब्याज)		
1	मोटर कार	-	-
2	कम्प्यूटर अग्रिम	-	-
3	स्कूटर अग्रिम	-	-
	3. अग्रिम और नकद मूल्य या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य राशियां		
1	पूंजीगत खाता पर	7,43,71,491	7,29,42,930
2	संकाय/स्टाफ के लिए विविध अग्रिम	5,000	11,43,000
3	चिकित्सा अग्रिम	5,74,500	5,25,640
4	एलटीसी अग्रिम	-	7,10,421
5	संकाय को यात्रा भत्ता अग्रिम	-	5,85,421
	4. पूर्व भुगतान व्यय		
1.	बीमा	54,306	2,897
2.	अन्य व्यय	-	-
	5. जमा		
1.	एल.पी. गैस	77,348	77,348
2.	जल मीटर	1,650	1,650
3.	विद्युत	17,500	17,500
4.	अन्य	1,800	1,800
	6. प्रोद्भूत आय		
1.	ऋण एवं अग्रिम	-	-
	7. अन्य – यूजीसी/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
1.	प्रायोजित परियोजनाओं में शेष ऋण	4,18,746	96,05,172
	योग	**7,55,22,341**	**8,56,13,779**

अनुसूची 6

शैक्षणिक प्राप्तियां

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
	छात्रों से शुल्क		
	शैक्षणिक		
1.	छात्र शुल्क	2,88,510	6,17,914
	योग (अ)	2,88,510	6,17,914
	बिक्री		
1.	प्रकाशन बिक्री	53,040	1,85,446
2.	प्रास्पेक्टस की बिक्री	36,600	22,400
	योग (ब)		**2,07,846**
	महायोग (अ+ब)	**3,78,150**	**8,25,760**

अनुसूची 7

अनुदान/सब्सिडी (प्राप्त अशोध्य अनुदान)

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष (2020-21)	विगत वर्ष (2019-20)
शेष अग्रानीत	1,55,74,002	-3,62,10,839
जोड़करः वर्ष के दौरान प्राप्तियां	36,88,00,000	45,59,46,500
जोड़करः वर्ष के दौरान अन्य प्राप्तियां	-	-
योग	**38,43,74,002**	**41,97,35,661**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर व्यय (अ)	2,12,32,693	1,47,78,209
शेष	**36,31,41,309**	**40,49,57,452**
घटाकरः परिसंपत्तियों के प्रयोग पर मुद्रा व्यय (ब)	31,31,72,934	38,93,83,450
शेष सी/एफ (स)	**4,99,68,375**	**1,55,74,002**

अनुसूची 8

अर्जित ब्याज

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
1.	**अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खातों पर**		
	अ) योजनेतर	161	14,61,366
	ब) अतिरिक्त प्रशासनिक निधि खाता	13,21,155	2,14,358
	स) छात्रावास खाता	9,887	26,131
	द) केनरा बैंक	3,279	1,02,655
	य) एनआर खाता	14,888	19,214
2.	**ऋणों पर**		
	अ. कर्मचारी / स्टाफ (अग्रिमों पर ब्याज)	(3,000)	6,488
	योग	**13,46,370**	**18,30,212**

अनुसूची 9

अन्य आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019–20)
	अ. भूमि एवं भवनों से आय		
1.	छात्रावास किराया	22,95,250	17,77,550
2.	लाईसेंस शुल्क	5,10,796	5,91,707
3.	जल प्रभार की वसूली	34,343	37,004
	योग (अ)	**28,40,389**	**24,06,261**
	ब. अन्य		
1	रॉयल्टी से आय	58,272	67,786
2	विविध प्राप्तियां	1,00,216	91,246
3	स्टाफ कार प्रयोग	-	-
4	विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त संस्थागत प्रभार	22,32,317	1,50,000
5	बेकार पड़ी वस्तुओं की बिक्री	-	30,170
6	निविदा फार्म की बिक्री	-	9,000
7	पेंशनरों के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रवेश शुल्क	4,06,100	3,55,800
8	किराया दरें और कर	-	90,864
9	चिकित्सा योजना के लिए योगदान	2,99,563	3,13,677
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	1,85,926	1,44,473
	योग (ब)	**32,82,394**	**12,53,016**
	महायोग (अ+ब)	**61,22,783**	**36,59,277**

अनुसूची 10

कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ (स्थापना व्यय)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020-21)		विगत वर्ष (2019-20)	
		आवर्ती	राशि	आवर्ती	राशि
1	वेतन और मजदूरी	9,17,03,960	9,17,03,960	8,95,69,110	8,95,69,110
2	बोनस और भत्ते तथा समयोपरि भत्ता	2,96,72,225	2,96,72,225	4,47,06,692	4,47,06,692
3	नई पेंशन योजना में योगदान	37,83,822	37,83,822	45,13,935	45,13,935
4	कर्मचारी कल्याण व्यय (वर्दी)	1,21,656	1,21,656	-	-
5	अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	8,51,223	8,51,223	15,64,428	15,64,428
6	चिकित्सा भत्ता प्रतिपूर्ति	86,21,922	86,21,922	1,01,96,717	1,01,96,717
7	बाल शिक्षा भत्ता	10,60,500	10,60,500	4,84,650	4,84,650
8	यात्रा भत्ता	-	-	68,553	68,553
9	अन्य (सरकारी अंशदान–सीपीएफ + भुगतान किया गया ब्याज)	2,11,320	2,11,320	42,33,892	42,33,892
10	सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ				
a)	पेंशन	7,88,64,631	7,88,64,631	10,69,86,864	10,69,86,864
b)	ग्रेच्युटी	1,00,35,602	1,00,35,602	90,41,927	90,41,927
c)	अवकाश नकदीकरण	56,11,694	56,11,694	67,55,941	67,55,941
	योग	**23,05,38,555**	**23,05,38,555**	**27,81,22,709**	**27,81,22,709**

अनुसूची 10 अ

कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	अवकाश नकदीकरण	योग
1	01–04–2020 को अथ शेष राशि (अ)	38,82,48,765.00	3,96,40,713.00	2,16,01,006.00	44,94,90,484.00
2	**घटाकर:** वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ब)	5,94,52,193.00	80,53,566.00	45,31,644.00	7,20,37,403.00
3	31–03–2021 को उपलब्ध बचत राशि स (अ–ब)	32,87,96,572.00	3,15,87,147.00	1,70,69,362.00	37,74,53,081.00
4	वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31–03–2021 को आवश्यक प्रावधान (द)	40,76,61,203.00	4,16,22,749.00	2,26,81,056.00	47,19,65,008.00
अ.	**चालू वर्ष में किये जाने वाले प्रावधान (द–स)**	**7,88,64,631.00**	**1,00,35,602.00**	**56,11,694.00**	**9,45,11,927.00**

अनुसूची 11

शैक्षणिक व्यय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020-21)		विगत वर्ष (2019-20)	
		आवर्ती	राशि	आवर्ती	राशि
1	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (संकाय के लिए यात्रा भत्ता)	4,61,916	4,61,916	12,02,938	12,02,938
2	क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी (भागीदार के लिए यात्रा भत्ता)	4,01,632	4,01,632	63,36,265	63,36,265
3	संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय (शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यय)	8,17,333	8,17,333	31,37,917	31,37,917
4	संकाय के भ्रमण के लिए भुगतान (संसाधन/व्यक्ति को मानदेय)	5,84,356	5,84,356	9,44,267	9,44,267
5	संस्थान के अनुसंधान अध्ययन	3,30,44,849	3,30,44,849	3,78,58,549	3,78,58,549
6	छात्रों को अध्येतावृत्ति (एम.फिल. और पी–एच.डी.)	2,30,31,935	2,30,31,935	1,79,06,687	1,79,06,687
7	छात्रवृत्ति/पुस्तकें व परियोजना अनुदान	-	-	7,32,247	7,32,247
8	प्रकाशन व्यय (मुद्रण से प्राप्त)	16,65,535	16,65,535	13,23,493	13,23,493
अ)	(1) जोड़करः पिछले वर्ष का स्टाक	4,36,633	4,36,633	3,81,199	3,81,199
ब)	(2) घटाकरः हस्तगत पुस्तकों का भण्डार	-6,12,082	-6,12,082	-4,36,633	-4,36,633
9	सदस्यता के लिए अंशदान	2,53,234	2,53,234	34,340	34,340
10	अन्य (फोटोकॉपी प्रभार)	3,27,135	3,27,135	6,60,311	6,60,311
11	गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान	7,45,600	7,45,600	40,64,398	40,64,398
12	एनईआर (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित)	-	-	29,58,104	29,58,104
13	ऊपरी प्रशासन कोष 1108	13,63,560	13,63,560	-	-
	योग	**6,25,21,636**	**6,25,21,636**	**7,71,04,082**	**7,71,04,082**

अनुसूची 12

प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020-21)		विगत वर्ष (2019-20)	
		आवर्ती	राशि	आवर्ती	राशि
अ	**आधार संरचना**				
1	विद्युत प्रभार	60,70,855	60,70,855	95,45,650	95,45,650
2	जल प्रभार	1,00,45,279	1,00,45,279	82,87,797	82,87,797
3	किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित)	2,41,851	2,41,851	-	-
4	सुरक्षा प्रभार	78,51,329	78,51,329	86,47,504	86,47,504
ब	**संचार**		-		
1	डाक तथा तार	1,87,040	1,87,040	6,86,332	6,86,332
2	टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट प्रभार	6,22,227	6,22,227	6,68,364	6,68,364
स	**अन्य**		-		
1	स्टेशनरी	13,32,380	13,32,380	21,98,068	21,98,068
2	पोषाहार व्यय	5,90,964	5,90,964	29,96,974	29,96,974
3	लेखा परीक्षा शुल्क	1,32,444	1,32,444	2,46,400	2,46,400
4	मजदूरी प्रभार	3,19,437	3,19,437	1,08,336	1,08,336
5	सलाहकारी शुल्क	21,09,000	21,09,000	31,46,500	31,46,500
6	कानूनी प्रभार	1,47,440	1,47,440	39,400	39,400
7	विज्ञापन प्रभार	10,82,857	10,82,857	8,38,155	8,38,155
8	अखबार प्रभार	3,22,485	3,22,485	3,19,602	3,19,602
9	अन्य (पाठ्यक्रम शुल्क / प्रशिक्षण)	10,445	10,445	10,400	10,400
10	विविध व्यय	10,93,861	10,93,861	2,02,350	2,02,350
12	प्रभार (अन्य खाते)		-	6,341	6,341
	योग	**3,21,59,894**	**3,21,59,894**	**3,79,48,173**	**3,79,48,173**

अनुसूची 13

परिवहन व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020-21)		विगत वर्ष (2019-20)	
		आवर्ती	राशि	आवर्ती	राशि
1	**स्टाफ कार**				
	क) स्टाफ कार का रखरखाव	1,16,886	1,16,886	1,25,524	1,25,524
	ख) बीमा	27,698	27,698	67,307	67,307
	ग) पेट्रोल तेल एवं स्नेहक	3,17,069	3,17,069	2,33,311	2,33,311
2	वाहन टैक्सी के किराए का खर्च	28,673	28,673	5,10,495	5,10,495
	योग	**4,90,326**	**4,90,326**	**9,36,637**	**9,36,637**

अनुसूची 14

मरम्मत एवं रखरखाव

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष (2020-21)		विगत वर्ष (2019-20)	
		आवर्ती	राशि	आवर्ती	राशि
1	भवन का रख–रखाव	3,55,663	3,55,663	8,78,229	8,78,229
2	संपदा रख–रखाव इलेक्ट्रिकल (एआरएमओ)	-	-	21,10,110	21,10,110
3	फर्नीचर तथा फिक्सर का रख–रखाव	7,965	7,965	88,718	88,718
4	कार्यालय उपकरणों का रख–रखाव	14,57,350	14,57,350	44,37,227	44,37,227
5	गृह व्यवस्था सेवाएं	81,16,070	81,16,070	91,53,873	91,53,873
	योग	**99,37,048**	**99,37,048**	**1,66,68,157**	**1,66,68,157**

अनुसूची 15

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा निर्माण के आधार

1.1 जब तक कि विधि का उल्लेख न किया जाए और सामान्यतया आमतौर पर कहा गया है कि लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत लेखांकन के प्रोदभूत विधि पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व मान्यता

2.1 विद्यार्थियों से शुल्क, निविदा प्रपत्रों की बिक्री, प्रवेश फार्म की बिक्री, बचत बैंक खाते पर रॉयल्टी और ब्याज नकद आधार पर लेखांकन किए जाते हैं।

2.2 छात्रावास किराया से आय नकदी आधार पर लेखांकन किया जाता है।

2.3 हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन की पूरी अदायगी के बाद शुरू होती है, गृह निर्माण पेशगी, वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याज सहित अग्रिम की वसूली प्रोद्भूत आधार पर की जाती है।

3. अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास

3.1 अचल संपत्ति भाड़ा, शुल्कों और करों और अधिग्रहण स्थापना और परिचालन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च आवक सहित अधिग्रहण की लागत से निर्धारित किया जाता है।

3.2 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों पर मुद्रित बिक्री मूल्य को मूल्यवान माना जाता है। उपहार में प्राप्त जिन पुस्तकों में मूल्य मुद्रित नहीं होते, उनका मूल्यांकन के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। उन्हें पूंजी कोष में जमा करके संस्था की अचल संपत्ति के साथ विलय कर लिया जाता है। मूल्यह्रास संबंधित परिसंपत्तियों की लागू दरों पर निर्धारित किया जाता है।

3.3 अचल परिसंपत्ति का मूल्यांकन मूल्यह्रास में घटाकर निकाला जाता है। अचल परिसंपत्तियों का अवमूल्यन निम्नलिखित दरों के अनुसार सीधे तौर पर किया जाता है।

1	भवन	2%
2	कार्यालय उपकरण	7.5%
3	कंप्यूटर और अन्य सहायक सामग्री	20%
4	फर्नीचर फिक्चर और फिटिंग्स	7.5%
5	वाहन	10%
6	पुस्तकालय में पुस्तकें	10%
7	जर्नल्स	10%
8	ई–जर्नल	40%
9	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%

3.4 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के अन्तर्गत वर्ष के लिये जमा पर मूल्यह्रास स्वायत संगठनों के लिये पसंदीदा वृद्धि है। इसके अतिरिक्त संपत्तियों का संग्रह पूरे वर्ष के लिए रहा, इससे मूल्यह्रास बराबर रहा।

3.5 जहां एक परिसंपत्ति जिसका पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका हो इसे तुलन पत्र में रु. 1 की एक अवशिष्ट मूल्य पर अंकन किया जाएगा और आगे उसका पुनः मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, मूल्यह्रास के परिवर्धन पर लागू मूल्यह्रास की दर से गणना की गई।

3.6 **इलेक्ट्रानिक पत्रिकाओं** (ई–जर्नल्स) पर व्यय की अधिकता को देखते हुए लाइब्रेरी में इसे पुस्तकों से अलग किया गया है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध कराए गए 10 प्रतिशत के अवमूल्यन के सापेक्ष 40 प्रतिशत की एक उच्च दर पर ई–जर्नल्स के संबंध में मूल्यह्रास प्रदान किया गया।

3.7 कंप्यूटर और सहायक सामग्री को अर्जित सॉफ्टवेयर के व्यय से अलग किया गया है क्योंकि यह कोई ठोस वस्तु नहीं होती और इसकी

लुप्तशीलता की दर अपेक्षाकृत उच्च होती है। उच्च स्तर के साफ्टवेयर का अवमूल्यन दर 40 प्रतिशत है जबकि कंप्यूटर और सहायक सामग्री का अवमूल्यन दर 10 प्रतिशत है।

4. स्टॉक

4.1 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के आधार पर स्टॉक की मूल्य सूची के अनुसार स्टेशनरी, प्रकाशन और अन्य स्टॉक की खरीद को राजस्व व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि सामान्य प्रशासन अनुभाग से प्राप्त जानकारी से वस्तु सूची के अनुसार राजस्व व्यय को कम करके शेष स्टॉक का मूल्य अंकन किया जाता है।

5. सेवानिवृत्त लाभ

5.1 सेवानिवृत्त लाभ यानी, पेंशन, ग्रेच्युटी लाभ और अवकाश नकदीकरण पिछले वर्ष (2019–20) के लेखा खातों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसलिए इस वर्ष वर्तमान प्रावधान की गणना पिछले वर्ष के मूल्यांकन का 5 प्रतिशत बढ़ाकर की गई।

5.2 संस्थान के जो कर्मचारी अन्य नियोक्ता संस्थानों से आये हैं और जिन्हें संस्थान में समाहित कर लिया गया है, उनके नियोक्ता संस्थानों से प्राप्त पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ पूंजीकृत मूल्य के रूप में पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट कर रहे हैं। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् नई पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति पर गृह नगर के लिए यात्रा बिल, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति, (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान सह बकाया बिल) प्रोद्भूत रूप में लेखांकित किया गया है।

6. सरकारी और यू.जी.सी. अनुदान

6.1 सरकारी अनुदान और यू.जी.सी. अनुदान प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

6.2 पूंजीगत व्यय की दिशा में प्रयुक्त सरकारी अनुदान पूंजीगत निधि में स्थानांतरित किया जाता है।

6.3 राजस्व व्यय (वास्तविक आधार पर) को पूरा करने के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान को प्रयुक्त मानकर उसे उस वर्ष की आय के रूप में लिया गया है जिसमें वह प्राप्त हुआ है।

6.4 अनुप्रयुक्त अनुदान (इस तरह के अनुदान का भुगतान अग्रिमों सहित) को आगामी वर्ष में लिया गया है और उसे तुलनपत्र में देयताएं के रूप में प्रस्तुत किया गया।

7. पी–एच.डी. और एम.फिल. के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

7.1 पी–एच.डी. और एम.फिल. के छात्रों को छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा प्रदान किए गए योजना अनुदान से भुगतान की जा रही हैं और इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8. चिकित्सा अंशदान

8.1 चिकित्सा अंशदान नीपा की चिकित्सा योजना के अनुसार योजनेतर खाते में जमा किया जाता है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति गैर–योजना खाते से भुगतान किया जाता है।

9. गैर सरकारी संगठनों को अनुदान

9.1 समान उद्देश्य वाले गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता अनुदान योजना के खाते के अंतर्गत व्यय के रूप में लेखांकित की जा रही है।

10. अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री

10.1 सेवा में प्रयुक्त न होने वाली और पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को ''अन्य आय'' में दर्शाया जाता है, क्योंकि बेकार वस्तुओं के मूल्य का पहले ही पूर्ण अवमूल्यन हो जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

11.1 पहले से जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि ''चल रही परियोजनाओं की मौजूदा देनदारियों और प्रावधान–मौजूदा देनदारियों–अन्य देयताएं–प्राप्तियां'' के रूप में जमा किया गया है। और ऐसी परियोजनाओं के भुगतान हेतु व्यय/अग्रिम है, या संबंधित परियोजना खाते के लिए आवंटित अतिरिक्त व्यय/प्रशासनिक शुल्क के साथ डेबिट किया जाता है। जब देनदार खाता से डेबिट किया जाता है।

12. लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार, अनुसूची 13 को वार्षिक खातों में जोड़ा गया है और अचल संपत्तियों में परिवर्तन अनुसूची 4 को अचल संपत्तियों के उप–विभाजन अमूर्त संपत्ति, लाइसेंस और कॉपीराइट, अन्य (प्रायोजित परियोजनाएं) में वर्गीकृत करने के लिए किया गया है।

अनुसूची 16

आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ

1. अचल संपत्तियां

1.1 अचल संपत्तियां केवल योजना अनुदान से खरीदी गई हैं, अनुसूची 3 में वर्ष के दौरान संबंधित अचल संपत्तियों में योजना निधि (₹ 2,12,32,693), और लाइब्रेरी में किताबें और संस्थान को तोहफे के मूल्य (₹ 7,128), की अन्य सपत्तियाँ शामिल की गई हैं। आस्तियां कैपिटल फंड में जमा करके स्थापित की गई हैं।

1.2 अनुसूची 3 (ई) वर्ष में परियोजना अनुदान से सृजित अचल संपत्तियां, (₹ 3,95,907) शामिल हैं।

1.3 31.03.2021 के तुलन–पत्र और पहले के वर्षों के तुलन–पत्र में साफ तौर पर योजना के धन से बनाई गई अचल आस्तियों और योजना निधि तथा अन्य निधि से बनाई गई अचल आस्तियों को अलग–अलग प्रदर्शित नहीं किया गया है। योजना और गैर–योजना निधि से वर्ष 01.04.2020 से 31.03.2021 तक सवंर्धित और उन परिवर्धनों पर संबंधित अवमूल्यन को अलग रूप में प्रदर्शित किया गया है (अनुसूची–3)।

2. मौजूदा देनदारियां और प्रावधान

2.1 व्यय जो 31 मार्च, 2021 को देय थे जिनका भुगतान नहीं किया गया को देयता और वेतन देय के रूप में प्रदान किया गया है।

2.2 आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय न होने की स्थिति में, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

2.3 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों के प्रति देयता संचित अवकाश के नकदीकरण के एवज में एकमुश्त भुगतान के प्रति दायित्व और पिछले साल के अनुमान के आधार पर निर्धारित थे। इस साल, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार वास्तविक मूल्यांकन किया गया था और पहले किए गए प्रावधानों में पिछले सालों को कवर करने के लिए, पूर्व की अवधि 2020–21 के व्यय को भुगतान किया गया था। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2021 पर और मौजूदा खाते में 2020–21 में किए गए भुगतान और शुद्ध प्रावधानों को आगे 2020–21 के प्रावधानों के लिए आय भुगतान और व्यय खाता द्वारा वर्ष 2020–21 के खातों में भुगतान किए गए थे।

3. मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और जमा

3.1 संस्थान की राय में मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम और जमाओं पर आमतौर पर कम से कम तुलन–पत्र में दिखायी गयी कुल राशि के बराबर मूल्य है।

4. भविष्य निधि खाता

4.1 सरकार से संबंधित निर्देश के अनुसार भविष्य निधि खाते के रूप में संस्थान द्वारा उन निधियों को सदस्यों के स्वामित्व में प्रस्तुत किया गया है, संस्थान के खाते से भविष्य निधि खाते को अलग किया जाता है। हालांकि प्राप्ति और भुगतान खाता (उपचय के आधार पर) आय और व्यय खाता और भविष्य निधि खाते का तुलन–पत्र संस्थान के वार्षिक लेखा में संलग्न है।

5. नई पेंशन योजना खाता

5.1 नई पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों को पीआरए सं. प्राप्त है। नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लि. (एनएसडीएल) में सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी

(सीआरए) द्वारा नियमित रूप से स्थानान्तरण कर रहे हैं। उनमें से संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी योगदान की स्थानांतरित होने की कोई राशि बकाया नहीं है।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

6.1 सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। संस्थान कर्मचारियों की पिछले नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के कैपिटल के मूल्य, संबंधित प्रावधान खातों में जमा किया गया है।

7. अनुदान

7.1 पिछले वर्षों में योजना अनुदान को आय के रूप में लिया गया, केवल वे पूंजीगत व्यय के लिये उपयोग किये जाते थे, बैंक शेष के योजना अनुदान खाते और अग्रिम द्वारा जिनका अनुदान कोष और बकाया समायोजन द्वारा भुगतान किया गया। इन्हें वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को तुलन पत्र की परिसंपत्तियों में दर्शाया गया। 31.3.2021 को अनुप्रयुक्त अनुदान को आगे बढ़ाया गया और तुलन पत्र में देयताओं के रूप में दर्शाया गया।

8. बचत बैंक खातों में शेष के विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची 'अ' में संलग्न हैं।

9. पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यकतानुसार फिर से वर्गीकृत किये गए हैं।

10. अंतिम खातों में आंकड़े निकटतम रुपए में अंकित किया गया हैं।

11. अनुसूची 1 से 13 को संलग्न किया गया है और यह 31 मार्च 2021 के तुलन–पत्र और इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग होता है।

प्राप्तियां और भुगतान लेखा

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष (2020-21)	विगत वर्ष (2019-2020)	भुगतान	चालू वर्ष (2020-21)	विगत वर्ष (2019-20)
प्रारंभिक जमा			**व्यय**		
1 बचत बैंक खाता	18,74,01,802	13,19,02,420			
2 हस्तगत डाक	21,836	50,922	अ) स्थापना व्यय	21,43,51,639	25,35,24,462
शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			ब) शैक्षणिक व्यय	3,39,77,048	6,57,32,807
भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) से			स) प्रशासनिक व्यय	3,59,44,206	3,33,92,975
(अ) योजना	36,88,00,000	45,59,46,500	द) मरम्मत और रख–रखाव	21,86,248	1,52,23,571
			य) यात्रा व्यय	3,45,742	
अकादमिक प्राप्तियां	41,21,266	23,40,157	**अध्येयतावृत्ति से संबंद्ध भुगतान**	2,35,26,435	1,79,06,687
प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के संबंध में प्राप्तियां	3,27,39,979	9,28,41,295	**प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं से संबद्ध भुगतान**	4,35,19,327	6,80,43,745
प्राप्त ब्याज			**सीपीडब्ल्यूडी को अचल संपत्ति और अग्रिम पर व्यय**		
(क) बैंक वचत खाता	161	14,61,366	1 अचल संपत्तियां	2,11,93,566	1,47,78,209
(ख) एनआर खाता	14,888	19,214			
(ग) केनरा बैंक	3,279	1,02,655	2 सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम	14,28,561	3,10,66,487
(घ) अतिरिक्त प्रशासनिक निधि	13,21,155	2,14,358	**वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान**		
(ङ) छात्रावास खाता	9,887	26,131	प्रभार (अन्य खाते)	-	6,341
(च) अवकार वेतन पेंशन अंशदान	1,85,926	1,44,473	**जमा और अग्रिम**		
(छ) ब्याज अग्रिमों पर ब्याज	(3,000)	6,488	पूर्वदाता व्यय	54,306	-
अन्य आय	-	18,07,956	अन्य व्यय	7,59,327	-
जमा और अग्रिम	1,94,460	4,38,541	**प्रेषण**		
प्रेषण	9,17,16,030	5,91,73,576	**शेष समापन**	9,17,12,030	13,19,02,420
वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां			बैंक बैलेस	21,97,01,140	18,74,01,802
1 अतिरिक्त प्रशासनिक निधि खाता 1108	22,32,317	1,50,000	हस्तगत डाक	60,412	21,836
योग	**68,87,59,987**	**74,66,26,052**	**योग**	**68,87,59,987**	**74,66,26,052**

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

भविष्य निधि लेखा

तुलन पत्र 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

देयताएं	चालू वर्ष (2020–21)	विगत वर्ष (2019-20)	परिसंपत्तियां	चालू वर्ष (2020-21)	विगत वर्ष (2019-20)
अथशेष		14,94,70,845	**जीपीएफ / सीपीएफ निवेश**	15,51,05,136.00	14,36,01,109
जीपीएफ खाते	13,00,29,187.00				
सीपीएफ खाते	31,42,976.00				
जीपीएफ					
वर्ष में दौरान अंशदान	2,35,63,900.00	2,33,66,600			
ब्याज जमा	94,23,166.00	96,20,345			
घटाया: निकासी	(1,98,50,292.00)	(3,04,98,609.00)	**बैंक में नकदी**		
सीपीएफ			एसबीआई खाता सं. 10137881013	1,07,36,203.00	78,95,557
वर्ष के दौरान अंशदान	2,40,000.00	2,22,760			
ब्याज जमा	97,486.00	83,278			
संस्थान अंशदान (सीपीएफ)					
ब्याज जमा	85,093.00	72,998			
मार्च 2021 के लिए अंशदान	2,11,320.00	2,00,520			
ब्याज रिजर्व					
व्यय पर आय से अधिक	1,88,98,503.00		व्यय पर आय से अधिक	0	10,42,071
	16,58,41,339.00	**15,25,38,737**		**16,58,41,339.00**	**15,25,38,737**

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

भविष्य निधि लेखा

प्राप्ति और भुगतान लेखा 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2020-21	विगत वर्ष 2019-20	भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	विगत वर्ष 2019-20
प्रारंभिक जमा	78,95,557.00	1,09,32,920.00	जीपीएफ अग्रिम/आहरित	1,98,50,292.00	3,04,98,609.00
जीपीएफ अंशदान	2,35,63,900.00	2,33,66,600.00	सीपीएफ अग्रिम/आहरित	-	-
सीपीएफ अंशदान	2,40,000.00	2,22,760.00	वर्ष के दौरान निवेश	10,86,80,872.00	11,41,74,778.00
सीपीएफ संस्थान अंशदान	2,11,320.00	2,00,520.00			
ब्याज नकदीकरण	9,91,74,778.00	10,39,58,912.00			
प्राप्त ब्याज	81,81,812.00	1,38,87,232.00	अंतशेष	1,07,36,203.00	78,95,557.00
	13,92,67,367.00	**15,25,68,944.00**		**13,92,67,367.00**	**15,25,68,944.00**

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

भविष्य निधि खाता

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

व्यय	चालू वर्ष 2020-21	विगत वर्ष 2019-20	आय	चालू वर्ष 2020-21	विगत वर्ष 2019-20
ब्याज जमा:					
जीपीएफ खाते	94,23,166	96,20,345	निवेश/बचत खाते पर अर्जित ब्याज	81,81,812.00	1,38,87,232.00
सीपीएफ खाते	97,486	83,278	जोड़ें: मार्च 2021 को अर्जित ब्याज	49,37,437.00	30,42,833.00
संस्थान के अंशदान पर ब्याज (सीपीएफ)	85,093	72,998	घटाया: मार्च 2020 के लिए उपार्जित ब्याज	(30,42,833.00)	(63,44,151.00)
संस्थान अंशदान (सीपीएफ)	2,11,320	2,00,520	प्राप्त संस्थान अंशदान (सीपीएफ)	2,11,320.00	2,00,520.00
व्यय से अधिक आय की अधिकता	4,70,671	8,09,293			
	1,02,87,736	**1,07,86,434**		**1,02,87,736**	**1,07,86,434**

ह./–
(वेटुकुरी पी.एस. राजू)
वित्त अधिकारी (प्रभारी)

ह./–
(संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

ह./–
(एन.वी. वर्गीज)
कुलपति

बैंक खातों में शेष राशि

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	बैंक खाते	चालू वर्ष 2020-21	विगत वर्ष (2019-20)
1	भारतीय स्टेट बैंक (10137881320) योजनेतर	2,54,250	2,35,362
2	सिंडिकेट बैंक (91392010001112) योजना	7,11,12,078	3,02,89,470
3	सिंडिकेट बैंक (91392010001092) परियोजना	11,93,37,176	13,00,81,763
4	सिंडिकेट बैंक (91392010001108) अतिरिक्त प्रशासनिक निधि	2,84,48,392	2,62,58,480
5	सिंडिकेट बैंक (91392015365) छात्रावास	4,06,203	3,96,316
6	केनरा बैंक खाता 25536	1,11,133	1,07,854
7	भारतीय स्टेट बैंक (34778757702) चालू खाता	31,910	32,559
	योग	**21,97,01,140**	**18,74,01,802**

गैर–सरकारी संगठनों की अनुदान की सूची

वर्ष 2020–21 के लिए

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	एनजीओ के नाम	जारी राशि
1	निराश्रित युग युवा संघ	1,25,000
2	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट	1,85,600
3	सामाजिक विकास परिषद्	1,50,000
4	श्री ब्रह्मलिंगेश्वर स्वामी शैक्षिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक ग्रामीण विकास ट्रस्ट	1,35,000
5	मैसर्स मदर सोसायटी नंदयाल कुरनूल	1,50,000
	योग	**7,45,600**

अनुलग्नक–ग

निवेश का विस्तार

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि
1	पंजाब नेशनल बैंक	84175	12-07-2020	12-10-2021	1,07,60,225
2	केनरा बैंक	316100	29-06-2020	29-06-2021	70,00,000
3	सिंडिकेट बैंक	197821	31-03-2021	31-03-2024	55,16,368
4	सिंडिकेट बैंक	197811	31-03-2021	31-03-2024	44,17,301
5	सिंडिकेट बैंक	197828	31-03-2021	31-03-2024	77,17,025
6	सिंडिकेट बैंक	969781	31-03-2021	31-03-2024	38,54,486
7	पंजाब नेशनल बैंक	4151	25-02-2021	25-02-2022	1,07,54,678
8	सिंडिकेट बैंक	197860	31-03-2021	31-03-2024	98,86,930
9	सिंडिकेट बैंक	197861	13-03-2021	30-03-2021	98,86,930
10	सिंडिकेट बैंक	197862	13-03-2021	30-03-2021	98,86,930
11	केनरा बैंक	316099	23-06-2021	23-06-2021	70,00,000
12	सिंडिकेट बैंक	197895	20-05-2021	20-05-2021	65,00,000
13	केनरा बैंक	316101	29-06-2021	29-06-2021	70,00,000
14	सिंडिकेट बैंक	197964	14-02-2019	14-08-2021	20,00,000
15	सिंडिकेट बैंक	970252	09-03-2019	09-09-2021	75,00,000
16	एसबीआई विशेष जमा	812	27-06-1981	-	14,24,264
17	सिंडिकेट बैंक	868981	08-11-2019	08-11-2021	45,00,000
18	सिंडिकेट बैंक	868982	08-11-2019	08-11-2021	45,00,000
19	सिंडिकेट बैंक	869041	20-02-2020	25-02-2021	50,00,000
20	सिंडिकेट बैंक	869042	20-02-2020	25-02-2021	50,00,000
21	सिंडिकेट बैंक	869043	20-02-2020	25-02-2021	50,00,000
22	सिंडिकेट बैंक	869044	20-02-2020	25-02-2021	50,00,000
23	सिंडिकेट बैंक	869138	07-12-2020	07-12-2023	50,00,000
24	सिंडिकेट बैंक	869139	07-12-2020	07-12-2023	50,00,000
25	सिंडिकेट बैंक	869140	07-12-2020	07-12-2023	50,00,000
					15,51,05,136

नकदीकरण 2020–21

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि
1	केनरा बैंक	510179	29.07-2019	29.07.2020	66,97,171
2	केनरा बैंक	510631	22.06.2019	22.06.2020	74,55,466
3	केनरा बैंक	495247	20.12.2018	27.06.2020	70,00,000
4	केनरा बैंक	495248	20.12.2018	27.06.2020	70,00,000
5	केनरा बैंक	197821	17.09.2019	31.03.2021	54,84,288
6	केनरा बैंक	197811	20.01.2020	31.03.2021	43,87,431
7	केनरा बैंक	197828	07.02.2020	31.03.2021	76,78,004
8	केनरा बैंक	969781	16.02.2020	31.03.2021	38,38,292
9	केनरा बैंक	197860	13.03.2020	30.03.2021	98,69,895
10	केनरा बैंक	197861	13.03.2020	30.03.2021	98,69,895
11	केनरा बैंक	197862	13.03.2020	30.03.2021	98,69,895
12	केनरा बैंक	84175	12.04.2019	12.07.2020	98,96,543
13	पंजाब नेशनल बैंक	4151	25.02.2020	25.02.2021	1,01,27,898
				योग	**9,91,74,778**

वर्ष 2020–21 के दौरान किये गये एफडी (सावधि जमा)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	एफडी सं.	जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	कुल राशि
1	केनरा बैंक	316099	23.06.2020	23.06.2021	70,00,000
2	केनरा बैंक	316100	29.06.2020	29.06.2021	70,00,000
3	केनरा बैंक	316101	29.06.2020	29.06.2021	70,00,000
4	केनरा बैंक	869138	04.12.2020	07.12.2023	50,00,000
5	केनरा बैंक	869139	04.12.2020	07.12.2023	50,00,000
6	केनरा बैंक	869140	04.12.2020	07.12.2023	50,00,000
7	केनरा बैंक	197821	31.03.2021	31.03.2024	55,16,367
8	केनरा बैंक	197811	31.03.2021	31.03.2024	44,17,301
9	केनरा बैंक	197828	31.03.2021	31.03.2024	77,17,025
10	केनरा बैंक	969781	31.03.2021	31.03.2024	38,54,486
11	केनरा बैंक	197860	31.03.2021	31.03.2024	98,86,930
12	केनरा बैंक	197861	31.03.2021	31.03.2024	98,86,930
13	केनरा बैंक	197862	31.03.2021	31.03.2024	98,86,930
14	पंजाब नेशनल बैंक	4151	25.02.2021	25.02.2022	1,07,54,678
15	केनरा बैंक	84175	12.07.2020	12.10.2021	1,07,60,225
				कुल	**10,86,80,872**

वर्ष 2020–21 के निवेश विवरण

(राशि ₹ में)

अथ शेष	14,55,99,042
वर्ष के दौरान किये गये निवेश	**10,86,80,872**
कुल निवेश	25,42,79,914
वर्ष के दौरान किये गये नकदीकरण	**9,91,74,778**
शुद्ध निवेश (अंत शेष)	**15,51,05,136**

शेष परीक्षण

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक

(राशि ₹ में)

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
पूंजीगत लेखा	153732539.00 Dr		3351807.75	150380731.25 Dr
पूंजीगत निधि	153732539.00 Dr		3351807.75	150380731.25 Dr
चालू देयताएं	612855379.29 Cr	457740380.71	466709604.23	621824602.81 Cr
बिलों से कटौती		2698920.00	2717251.00	18331.00 Cr
ठेकेदार से आयकर – परियोजना		478908.00	491684.00	12776.00 Cr
ठेकेदार से आयकर – आवृती		2148470.00	2154025.00	5555.00 Cr
जीएसटी पर टीडीएस		71542.00	71542.00	
वेतन से कटौती		52483673.00	52485494.00	1821.00 Cr
जी.पी.एफ. अंशदान और वसूली		23363900.00	23363900.00	
सामूहिक बीमा योजना		69980.00	69660.00	320.00 Dr
आयकर (वेतन) – परियोजना		345000.00	345000.00	
आयकर (वेतन) – आवृती		23678955.00	23678955.00	
एल.आई.सी.		137413.00	139554.00	2141.00 Cr
पीएम केयर फण्ड – कोविड 19		227912.00	227912.00	
नई पेंशन स्कीम से वसूली		2683813.00	2683813.00	
सोसायटी वसूली		1976700.00	1976700.00	
विशिष्ट परियोजना	130288912.29 Cr	48723929.71	37944582.23	119509564.81 Cr
प्रावधान	449490484.00 Cr		22474524.00	471965008.00 Cr
प्रावधान – ग्रेच्युटी	39640713.00 Cr		1982036.00	41622749.00 Cr
प्रावधान – अवकाश वेतन	21601006.00 Cr		1080050.00	22681056.00 Cr
प्रावधान – पेंशन	388248765.00 Cr		19412438.00	407661203.00 Cr
बकाया देनदारियाँ	2948773.00 Cr	2948773.00		
वेतन देय	13401775.00 Cr	13401775.00	13566263.00	13566263.00 Cr
सुरक्षा जमा समायोजित	1012413.00 Cr	128000.00	194460.00	1078873.00 Cr
पत्रिका की सदस्यता शुल्क (अग्रिम)	139020.00 Cr	32280.00		106740.00 Cr
निधियों के बीच हस्तांतरण – आवर्ती		67805500.00	122805500.00	55000000.00 Cr
निधियों के बीच हस्तांतरण – अनावर्ती		91712030.00	91716030.00	4000.00 Cr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
निधि हस्तांतरण – ओवरहैड एडमिन. निधि खाता		122805500.00	67805500.00	55000000.00 Dr
निधि के मध्य हस्तांतरण–प्रोजेक्ट खाता		55000000.00	55000000.00	
अनुप्रयुक्त अनुदान – योजना	15574002.00 Cr			15574002.00 Cr
अचल संपत्तियां	194472690.00 Dr	21699036.75	70437.00	216101289.75 Dr
कम्प्यूटर और सहायक उपकरण	4121658.00 Dr	13601622.00		17723280.00 Dr
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	858406.00 Dr	1917635.00		2776041.00 Dr
अचल संपत्ति– प्रायोजित	468249.00 Dr	395907.00		864156.00 Dr
फर्नीचर और फिक्सर	5884300.00 Dr	49300.00		5933600.00 Dr
भूमि	2307892.00 Dr			2307892.00 Dr
पुस्तकालय पुस्तकें	7995680.00 Dr	18488.75		8014168.75 Dr
कार्यालय की इमारत	116796393.00 Dr			116796393.00 Dr
अन्य कार्यालयी उपकरण	9645033.00 Dr	2048152.00		11693185.00 Dr
ई–जर्नल्स की खरीद	4907703.00 Dr	1816224.00		6723927.00 Dr
पत्रिकाओं की खरीद	40090002.00 Dr	1851708.00	70437.00	41871273.00 Dr
स्टाफ कार की खरीद	1397374.00 Dr			1397374.00 Dr
चालू परिसंपत्ति	264650150.27 Dr	832476053.62	800783776.83	296342427.06 Dr
सूची	781272.00 Dr	865438.00	781272.00	865438.00 Dr
इन्वेंटरी – स्टेशनरी	781272.00 Dr	865438.00	781272.00	865438.00 Dr
पूर्वभुगतान व्यय	2897.00 Dr	54306.18	2897.00	54306.18 Dr
पूर्वभुगतान बीमा	2897.00 Dr	54306.18	2897.00	54306.18 Dr
कर्मचारियों से वसूली			240.00	240.00 Cr
जीएसएलआईएस			240.00	240.00 Cr
जमा (संपत्ति)	98298.00 Dr			98298.00 Dr
सुरक्षा जमा वसूली योग्य	98298.00 Dr			98298.00 Dr
ऋण और अग्रिम (परिसंपत्ति)	2964482.00 Dr	2677963.00	5062945.00	579500.00 Dr
एल.टी.सी. अग्रिम	710421.00 Dr	167000.00	877421.00	
चिकित्सा अग्रिम	525640.00 Dr	2269463.00	2220603.00	574500.00 Dr
विविध अग्रिम	1143000.00 Dr	241500.00	1379500.00	5000.00 Dr
संकाय/स्टाफ को यात्रा भत्ता अग्रिम	585421.00 Dr		585421.00	
हस्तगत रोकड़		932100.00	932100.00	

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
नकद परियोजना		899600.00	899600.00	
नकद आवर्ती		32500.00	32500.00	
बैंक खाते	187401802.27 Dr	805616908.16	773317570.83	219701139.60 Dr
3000 – सिंडीकेट बैंक – 91–1092 – परियोजना	130081763.29 Dr	86880706.58	97625294.06	119337175.81 Dr
4000 – चालू खाता – 34778757702	32558.50 Dr		649.00	31909.50 Dr
6000 – हॉस्टल खाता	396315.81 Dr	9886.78		406202.59 Dr
8000 – केनरा बैंक	107854.05 Dr	3279.00		111133.05 Dr
9000 – प्रशासन निधि खाता 1108	26258479.52 Dr	71358972.04	69169060.00	28448391.56 Dr
एस.बी.आई. – 10137881320 – आवर्ती	235361.54 Dr	91834889.27	91816001.27	254249.54 Dr
सिंडीकेट बैंक – 91–1112 – अनावर्ती	30289469.56 Dr	555529174.49	514706566.50	71112077.55 Dr
सीपीडब्ल्यूडी में जमा – सिविल / इलैक्ट्रिकल	72942930.00 Dr	21678680.00	20250119.00	74371491.00 Dr
हस्तगत डाक टिकट	21836.00 Dr	38576.00		60412.00 Dr
हस्तगत प्रकाशन	436633.00 Dr	612082.28	436633.00	612082.28 Dr
अप्रत्यक्ष आय		15126119.27	391773422.58	376647303.31 Cr
प्राप्तियां – ओवरहैड एडमिन फण्ड खाता 1108			3553472.04	3553472.04 Cr
9001 – उपरी प्राप्तियां 1108			2232317.00	2232317.00 Cr
बचत पर ब्याज – ओवरहैड एडमिन. खाता 1108			1321155.04	1321155.04 Cr
प्राप्तियां – आवर्ती		15126119.27	19406623.51	4280504.24 Cr
पेंशन भोगी चिकित्सा दाखिला शुल्क			406100.00	406100.00 Cr
स्वास्थ्य योजना अंशदान (सीजीएचएस)			299563.00	299563.00 Cr
छात्रावास किराया			2295250.00	2295250.00 Cr
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज		3000.00		3000.00 Dr
बचत खाता पर ब्याज		103971.27	118859.27	14888.00 Cr
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान		16848.00	202774.00	185926.00 Cr
विविध प्राप्तियां		15000000.00	15100216.40	100216.40 Cr
लाइसेंस शुल्क की वसूली			510796.00	510796.00 Cr
जल प्रभार की वसूली			34343.00	34343.00 Cr
रॉयल्टी			58271.84	58271.84 Cr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
विवरणिका की बिक्री		2300.00	38900.00	36600.00 Cr
प्रकाशन की बिक्री			53040.00	53040.00 Cr
छात्र शुल्क			288510.00	288510.00 Cr
प्राप्तियां – आवर्ती			368800161.25	368800161.25 Cr
मा.सं.वि. मंत्रालय से अनुदान – आवर्ती			368800000.00	368800000.00 Cr
बचत खाता से ब्याज – आवर्ती			161.25	161.25 Cr
प्राप्तियां – छात्रावास खाता			9886.78	9886.78 Cr
छात्रावास खाते पर अर्जित ब्याज			9886.78	9886.78 Cr
बचत खाते पर ब्याज – केनरा बैंक			3279.00	3279.00 Cr
अप्रत्यक्ष व्यय		354078089.32	18430631.28	335647458.04 Dr
व्यय – चालू खाता		649.00		649.00 Dr
4003 – विविध व्यय		649.00		649.00 Dr
प्रशा. पूंजी खाता 1108 में उपरिव्यय		1363560.00		1363560.00 Dr
9002–व्यय–उपरिव्यय प्रशा. निधि खाता 1108		1363560.00		1363560.00 Dr
आवर्ती व्यय		352713880.32	18430631.28	334283249.04 Dr
विश्वविद्यालय अध्ययन/गैर सरकारी संगठन		33210949.00	166100.00	33044849.00 Dr
सीपीआरएचई		10586766.00		10586766.00 Dr
सीपीआरएचई – विविध व्यय		1513420.00		1513420.00 Dr
सीपीआरएचई – संकाय का वेतन		7714488.00		7714488.00 Dr
सीपीआरएचई – कर्मचारियों का वेतन		1132466.00		1132466.00 Dr
सीपीआरएचई – कार्यशाला		226392.00		226392.00 Dr
यूआईसी		8900239.00	116100.00	8784139.00 Dr
यूआईसी – व्यय		21839.00		21839.00 Dr
यूआईसी – वेतन		8350263.00	116100.00	8234163.00 Dr
यूआईसी – कर्मचारियों का यात्रा भत्ता		528137.00		528137.00 Dr
तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण–राज्यों को अग्रिम (आर.एस. त्यागी)		66000.00		66000.00 Dr
तीसरा अखिल भारतीय सर्वेक्षण (आर. एस. त्यागी)		458565.00		458565.00 Dr
भारतीय उच्च शिक्षा की स्वायत्तता		20517.00		20517.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
तुलनात्मक शैक्षिक लाभ मोना खरे		141000.00		141000.00 Dr
बच्चों की शिक्षा का महत्वपूर्ण मूल्यांकन		619290.00		619290.00 Dr
उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग		108581.00		108581.00 Dr
प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विभाग		196323.00		196323.00 Dr
डीईओ में निर्णय लेने की प्रक्रिया संगीता अंगोम		210000.00		210000.00 Dr
एमआईएस शैक्षिक विभाग–ए.एन. रेड्डी		101414.00		101414.00 Dr
डेपा वेतन		388549.00		388549.00 Dr
शैक्षिक डिजिटल अभिलेखागार दस्तावेज डा. मैथ्यू		200161.00		200161.00 Dr
डाईस योजना		997212.00		997212.00 Dr
लड़कियों की शिक्षा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश		1708011.00	50000.00	1658011.00 Dr
शासन, विनियमन और आश्वासन की गुणवत्ता		504995.00		504995.00 Dr
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलः संस्थागत विकास		202742.00		202742.00 Dr
सहायता अनुदान अध्ययन		4762945.00		4762945.00 Dr
भारतीय उच्च शिक्षा में निर्देशात्मक ढांचा		250549.00		250549.00 Dr
शिक्षकों की भागीदारी		350134.00		350134.00 Dr
भारत में स्नातक महाविद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा		228800.00		228800.00 Dr
राष्ट्रीय ऋण ढांचा		38286.00		38286.00 Dr
शैक्षिक प्रशासन में राष्ट्रीय नवाचार		976272.00		976272.00 Dr
उच्च शिक्षा की राजनीति अर्थव्यवस्था – डा. मलिश		105000.00		105000.00 Dr
परियोजना प्रबंधन ईकाई –डा. के. बिस्वाल		1071598.00		1071598.00 Dr
शैक्षिक प्रशासन में महिलाएं		17000.00		17000.00 Dr
स्थापना व्यय आवर्ती		13816.00	13816.00	
बोनस		13816.00	13816.00	
1. ओएच 36 – वेतन		161968277.00	10294353.00	151673924.00 Dr
भत्ते और मानदेय		32417645.00	2753082.00	29664563.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
ग्रेच्युटी		10370569.00	334967.00	10035602.00 Dr
अभिदाताओं को दिए गए पीएफ पर ब्याज		211320.00		211320.00 Dr
अवकाश नकदीकरण		5611694.00		5611694.00 Dr
अवकाश यात्रा रियायत		851223.00		851223.00 Dr
वर्दी		121656.00		121656.00 Dr
पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति		3472371.00	89770.00	3382601.00 Dr
कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति		5241367.00	2046.00	5239321.00 Dr
नई पेंशन योजना		4061110.00	277288.00	3783822.00 Dr
समयोपरि भत्ता		7662.00		7662.00 Dr
स्थापना पर देय		29355522.00	2179300.00	27176222.00 Dr
अधिकारियों का वेतन		69185638.00	4657900.00	64527738.00 Dr
ट्यूशन शुल्क		1060500.00		1060500.00 Dr
3. ओएच 31–सामान्य		157520838.32	7956362.28	149564476.04 Dr
शैक्षणिक कार्यक्रम (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सहित)		817333.00		817333.00 Dr
विज्ञापन		1082857.00		1082857.00 Dr
लेखा शुल्क		159386.00	26942.00	132444.00 Dr
खानपान शुल्क		590964.00		590964.00 Dr
परामर्श भुगतान		2109000.00		2109000.00 Dr
पाठ्यक्रम शुल्क / प्रशिक्षण		10445.00		10445.00 Dr
दैनिक मजदूरी शुल्क		320006.00	569.00	319437.00 Dr
विद्युत शुल्क – आवर्ती		6905779.00	834924.00	6070855.00 Dr
एम.फिल. / पी.एच.डी. छात्रों को छात्रवृति		23526435.00	494500.00	23031935.00 Dr
गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान		745600.00		745600.00 Dr
संसाधन व्यक्तियों को मानदेय (एससी / एसटी सहित)		594756.00	10400.00	584356.00 Dr
हाउस कीपिंग सर्विसेज		8116070.00		8116070.00 Dr
बीमा		27697.82		27697.82 Dr
कानूनी विस्तार		147440.00		147440.00 Dr
स्थानीय वाहन / टैक्सी शुल्क		28673.00		28673.00 Dr

विवरण	अथशेष	हस्तान्तरण		शेष
		निकासी	जमा	
भवन का रखरखाव / छात्रावास		355663.00		355663.00 Dr
उपकरणों का रखरखाव		1457350.00		1457350.00 Dr
फर्नीचर और फिक्स्चर का रखरखाव		7965.00		7965.00 Dr
स्टाफ कारों का रखरखाव		116886.00		116886.00 Dr
सदस्यता एवं अंशदान शुल्क		253234.00		253234.00 Dr
समाचार पत्र शुल्क		322485.00		322485.00 Dr
अन्य विविध प्रशासनिक व्यय		1205539.50	112328.00	1093211.50 Dr
पेंशन		82630907.00	3766276.00	78864631.00 Dr
पेट्रोल, तेल और स्नेहक प्रभार		356386.00	39317.00	317069.00 Dr
फोटोकॉपी शुल्क		327135.00		327135.00 Dr
डाक और टेलीग्राम		225616.00	38576.00	187040.00 Dr
मुद्रण व्यय		2102168.00	612082.28	1490085.72 Dr
दर / किराया और कर		518121.00	276270.00	241851.00 Dr
सुरक्षा शुल्क		7864070.00	12741.00	7851329.00 Dr
स्टेशनरी / स्टोर आइटम		2210483.00	878103.00	1332380.00 Dr
संकाय को दैनिक / यात्रा भत्ते		461916.00		461916.00 Dr
प्रतिभागियों को दैनिक / यात्रा भत्ते (एससी / एसटी सहित)		411489.00	9857.00	401632.00 Dr
टेलीफोन शुल्क		622227.00		622227.00 Dr
आवर्ती जल प्रभार		10888756.00	843477.00	10045279.00 Dr
प्रारंभिक शेष में अंतर	0.02 Dr			0.02 Dr
महायोग		**1681119679.67**	**1681119679.67**	

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के लेखे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा), के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं, प्राप्ति और भुगतान लेखाओं की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तों) के अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अधीन सलंग्न तुलन–पत्र की लेखापरीक्षा कर ली है। हमें वर्ष 2020–21 तक की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी नीपा के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण के व्यवहार्य से एकरूपता, लेखाकरण के मानदंडों और पारदर्शिता के मानकों इत्यादि के संबंध में लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। पृथक निरीक्षण रिपोर्टों/नि.म.ले. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के द्वारा आवश्यकतानुसार विधि, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियामक) के अनुपालन और वित्तीय संचालन और कार्य निष्पादन सहित कार्यदक्षता संबंधी पक्षों इत्यादि पर लेखा परीक्षा की टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती है।

3. हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानदंडों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों के अधिक यथार्थ विवरणों से युक्त होने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना तथा लेखा परीक्षा का निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों की राशि तथा प्रकटीकरण के साक्ष्यों का लेखा परीक्षण होता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण के सिद्धांतों, महत्वपूर्ण आकलनों की समीक्षा के साथ– साथ प्रस्तुत किए गए संपूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर प्रतिवेदन करते हैं कि–

(i) लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ii) तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सही प्रकार से तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) द्वारा समुचित रूप से लेखा पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का

रखरखाव किया है जो कि ऐसी पुस्तिकाओं की जांच से पता चलता है।

(iv) हम पुनः प्रतिवेदन करते हैं कि :

अ. तुलन पत्र

अ.1 देयताएं

अ.1.1 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–2) रु. 65.66 करोड़

उपरोक्त में रु. 5.00 करोड़ का अप्रयुक्त अनुदान शामिल है। जबकि 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त अनुदान सहायता 9.85 करोड़ रू. था इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके और पूंजीगत निधि को रु. 4.85 करोड़ अधिक दिखाया गया है। वर्ष 2019–20 में इसे संज्ञान में लाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

अ.2 संपत्ति

अ.2.1 ऋण, अग्रिम और जमा (अनुसूची 5) रू. 7.55 करोड़

उपरोक्त में आयकर विभाग से वसूली योग्य 195.28 लाख रुपये (वर्ष 2014–15: रु. 0.78 लाख, वर्ष 2018–19: रु. 30.17 लाख, वर्ष 2019–20: रु. 114. 68 लाख और 2020–21 में 49.65 लाख रूपये) का टीडीएस शामिल नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम और पूंजी कोष की जमाराशियां रु. 195.28 लाख कम दिखाया है। इसे वर्ष 2015–16 से संज्ञान में लाया गया परन्तु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ब. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

शिक्षा मंत्रालय और लेखा मानक 15 द्वारा निर्धारित मानकों के प्रारूप के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए जिसका नीपा द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। महत्वपूर्ण लेखा नीति 5.1 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान की गणना वर्ष 2020–21 के दौरान पिछले वर्ष (2019–20) से बीमांकिक मूल्यांकन के 5 प्रतिशत की वृद्धि करके की गई थी। इसके अलावा, खातों पर टिप्पणी सं. 2.3 में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान 31.03.2021 को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए गए हैं जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है।

स. सामान्य

स.1. नीपा ने 2010–11 से 2020–21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को रु. 21.28 करोड़ का भुगतान किया है। सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त व्यय विवरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय रु. 14.84 करोड़ रहा, जबकि खाता बही के अनुसार यह 13.98 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2019–20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा को रु. 0.86 करोड़ के अंतर के बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा, वर्ष 2020–21 के लिए सीपीडब्ल्यूडी का व्यय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर लेखाओं में दर्शाए गए रु. 7.44 करोड़ के पूंजीगत अग्रिमों को लेखापरीक्षा सत्यापित नहीं कर सका।

स.2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 3.3 के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास उसमें निर्दिष्ट दरों पर प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन मूल्यह्रास को पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को अचल संपत्तियों के सकल मूल्य के बजाय शुद्ध मूल्य पर प्रभारित किया गया है। लेखाओं को तैयार करने में प्रकट लेखांकन नीति को नहीं अपनाया गया है।

इसके अलावा, कार्यालय उपकरण और फर्नीचर और फिक्स्चर पर मूल्यह्रास 8% की दर से लगाया गया है जबकि पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, 7.5% की दर का उल्लेख किया गया है।

द. सहायता अनुदान

नीपा को 2020–21 के दौरान 36.88 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, जिसमें से 3.57 करोड़ रुपये मार्च 2021 में प्राप्त हुए। 1 अप्रैल 2020 को इसमें 6.41 करोड़ रुपये का प्रारंभिक

शेष था। 43.29 करोड़ रुपये के कुल कोष में से, इसने 31 मार्च 2021 तक 33.44 करोड़ रुपये (2. 12 करोड़ रुपये की पूंजी और 31.32 करोड़ रुपये का राजस्व) का उपयोग किया, जिसमें 9.85 करोड़ रुपये शेष थे।

नीपा ने वर्ष के दौरान शिक्षा मंत्रालय से विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 2.24 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त किया और इन परियोजनाओं में 8.23 करोड़ रुपये की शुरुआती शेष राशि थी। कुल 10.47 करोड़ रुपये में से 3.78 करोड़ रुपये का व्यय नीपा द्वारा किया गया था और 31 मार्च 2021 को 6.69 करोड़ रुपये शेष थे।

य. प्रबंधन पत्र

लेखा से संबंधित जो कमियां लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई हैं, उनमें सुधार करने हेतु पृथक रूप से प्रबंधन पत्र के द्वारा कुलपति, नीपा के संज्ञान में लाया गया है।

(v) पिछले अनुच्छेदों में टिप्पणी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस लेखा रिपोर्ट में तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा के विवरण लेखा पुस्तिका के अनुसार है।

(vi) हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित वित्तीय विवरण जो लेखाकरण की नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां के अधीन माने गये हैं, उपर्युक्त महत्वपूर्ण विवरणों तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुलग्नक भाग–I में प्रस्तुत अन्य दूसरी सामग्री के संदर्भ में आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं:

(अ) जहाँ तक यह 31 मार्च 2021 को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के तुलन पत्र की स्थिति से संबंधित हैं : तथा

(ब) जहाँ तक यह इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय तथा व्यय लेखे से संबंधित हैं।

भारत के नियंत्रक तथा महानिदेशक, लेखापरीक्षा की ओर से और कृते

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 24.03.2022

24.3.2022

महानिदेशक, लेखापरीक्षा

गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास

नोट : "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

नीपा की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है क्योंकि:

- नीपा में अलग से कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है। न ही आंतरिक लेखा परीक्षण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- नीपा में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली नहीं है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

नीपा की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को निम्नांकित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

- 31 मार्च 2021 तक 2000–01 से 2011–12 की अवधि के दौरान 33 बाह्य लेखा परीक्षा पैरा के उत्तर प्राप्त नहीं हुए।
- विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अलग अचल सम्पत्तियों रजिस्टर का रखरखाव न करना।
- वर्ष 2020–21 के सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीपा के पास उपलब्ध न होना।
- 2013–14 से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं करना।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था

- 31.03.2013 तक अचल संपत्तियों जैसे फर्नीचरों और फिक्सचर तथा कंप्यूटरों का 31.03.2012 तक भौतिक सत्यापन किया गया है। जुलाई 2012 तक पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया था।

4. इन्वेन्टरी के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

- स्टेशनरी, तथा उपभोग वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 2020–21 तक कर लिया गया है।

5. सांविधिक भुगतान में नियमितता

- लेखा के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2021 तक पिछले छः महीने से कोई भी सांविधिक देयता का भुगतान बाकी नहीं था।

प्रबंधन पत्र के सन्दर्भ में अनुलग्नक

भाग–क (लगातार अनियमितता)

1. वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची–2) रु. 65.66 करोड़

उपरोक्त में 5.00 करोड़ रूपये का अप्रयुक्त सहायता अनुदान राशि शामिल है, जबकि 31 मार्च 2021 के दौरान अप्रयुक्त सहायता अनुदान 9.85 करोड़ रूपये था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं एवं प्रावधान को कम बताया गया है और पूंजीगत निधि 4.85 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। जिसे 2019–20 से इंगित किया जा रहा है लेकिन उपचारात्मक कार्रवाई की नहीं गई है।

2. अचल सम्पत्ति (अनुसूची–3) रु. 20.08 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2019–20 में विशिष्ट परियोजना खाते से खरीदे गए 0.80 लाख रुपये के लैपटॉप शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप अचल सम्पत्ति को कम करके और पूंजी निधि को 0.80 लाख रुपये से कम करके दिखाया गया है। इसे विगत वर्ष की रिपोर्ट में भी इंगित किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा को इसका अनुपालन नहीं दर्शाया गया है।

3. ऋण अग्रिम और जमा (अनुसूची–5) रु. 7.55 करोड़

उपरोक्त में आयकर विभाग से वसूली योग्य 195.28 लाख रुपये का टीडीएस शामिल नहीं है (2014–15: रु. 0.78 लाख, 2018–19: रू 30.17 लाख, 2019–20: रु. 114.68 लाख और 2020–21: रु. 49.65 लाख) जिसके परिणामस्वरूप ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों को कम बताया गया और पूंजीगत निधि को रु.195.28 लाख से अधिक बताया गया। 2015–16 से इस ओर ध्यान दिलाया जा रहा है लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

4. नीपा ने 2010–11 से 2020–21 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी को 21.28 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया है। सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त व्यय विवरण के अनुसार, इस अवधि के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय 14.84 करोड़ रुपये था जबकि खाता बही के अनुसार यह 13.98 करोड़ रुपये था।

   वर्ष 2019–20 के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा को 0.86 करोड़ रुपये के अंतर के बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा वर्ष 2020–21 के लिए सीपीडब्ल्यूडी का व्यय विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर लेखाओं में दर्शाए गए रु. 7.44 करोड़ के पूंजीगत अग्रिमों को लेखापरीक्षा सत्यापित नहीं कर सका।

5. राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान की गणना करते समय उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार वर्ष के दौरान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर खातों में सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान को छोड़कर और सेवानिवृत्ति लाभों के वास्तविक व्यय को जोड़कर दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2019–20 के वार्षिक लेखों में नीपा द्वारा लेखों की अनुसूची 8 में दर्शाए गए राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान में बीमांकिक मूल्यांकन पर सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान शामिल हैं। वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के लिए पृथक लेखा परीक्षा में इस मुद्दे पर टिप्पणी उठाई गई थी।

वर्षवार विवरण निम्न है:–

राशि (करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	लेखों के अनुसार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	लेखा परीक्षा के अनुसार राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया अनुदान	अंतर
2016-17	18. 16	17.21	0.95
2017-18	29.21	27.33	1.88
2018-19	36.45	34.41	2.04
कुल अंतर			**4.86**

वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 में ''राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए अनुदान'' शीर्ष के तहत दिखाए गए आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं पाई गई।

हालाँकि, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के खातों में पाई गई विसंगितियों में सुधार बाद के वर्षों (2019–20 और 2020–21) में नहीं किया गया है, साथ ही अनुदान सहायता के शुरुआती शेष के साथ–साथ सहायता अनुदान के अंतिम शेष को रुपये 4.86 करोड़ से कम करके आंका गया है। जिसे वर्ष 2021–22 के खातों में ठीक करने की आवश्यकता है।

भाग–ख (अन्य अनियमितता)

1. वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 2) – रु. 65.66 करोड़

उपरोक्त में 2016–17, 2017–18 और 2020–21 की अवधि में रु. 25.49 लाख के व्यय के लिए देयता शामिल नहीं है, लेकिन वर्ष के दौरान भुगतान भी नहीं किया गया है जिसका नीचे विवरण दिया गया है:

क्रमांक	वाउचर संख्या/ तिथि	अवधि	एजेंसी के नाम	राशि (रु. में)
1.	49/ 27.05.2021	मार्च और अप्रैल 2017	पिंक हाउसकीपिंग	97,659
2.	05/ 07.04.2021	फरवरी और मार्च 2021	गुड हाउसकीपिंग	15,65,196
3.	121/13.07.2021	फरवरी और मार्च 2021	दिलजीत सिंह सिक्योरिटी एजेंसी	8,86,622
कुल				**25,49,477**

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधान को कम करके और पूंजीगत निधि को रुपये 25.49 लाख से अधिक दिखाया गया है।

2. अचल संपत्तियां (अनुसूची 3)–रु. 20.08 करोड़

विशिष्ट परियोजनाओं के लिए कोई अलग अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं रखा गया था इसलिए लेखापरीक्षा विशिष्ट परियोजना खाते (अनुसूची–3 (ई)) में 7.67 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

3. अनुसूची 7 और अनुसूची 2(बी) में सहायता अनुदान के प्रारंभिक शेष और अंत शेष को क्रमशः रु. 1.56 करोड़ और रु. 5.00 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है जबकि प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष के सही आंकड़े रु. 6.41 करोड़ और क्रमशः 9.85 करोड़ रुपये है। खातों की अनुसूची 7 और अनुसूची 2(बी) में सुधार की आवश्यकता है।

4. भविष्य निधि खाता

लेखा के अनुसार वर्षिक जीपीएफ सदस्यता 235.64 लाख रुपये है जबकि खाता बही के अनुसार राशि 233.64 लाख रुपये है। नीपा के अनुसार यह अंतर प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान के कारण है, जिनका अंशदान सीधे जीपीएफ बैंक खाते में लिया जाता है। ऐसे विसंगतियों से बचने के लिए प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के अंशदान को बहीखाता में दर्ज किया जाना चाहिए था।

5. भविष्य निधि का आय और व्यय खाता

वर्ष 2020–21 के दौरान परिपक्व 5 एफडीआर पर प्राप्त ब्याज 17.09 लाख रुपये की राशि को गलत तरीके से प्रोद्भूत ब्याज के रूप में दिखाया गया था जिसका विवरण नीचे है:

क्र. सं.	एफडी नंबर/बैंक	परिपक्वता तारीख	राशि	प्रोद्भूत ब्याज
1.	197861/सिंडिकेट बैंक	31.03.2021	98,86,930	5,70,598
2.	869041/ सिंडिकेट बैंक	25.02.2021	50,00,000	2,84,795
3.	869042/ सिंडिकेट बैंक	25.02.2021	50,00,000	2,84,795
4,	869043/ सिंडिकेट बैंक	25.02.2021	50,00,000	2,84,795
5.	869044/ सिंडिकेट बैंक	25.02.2021	50,00,000	2,84,795
कुल				**17,09,778**

परिणामस्वरूप प्राप्त ब्याज को कम करके और प्रोद्भूत ब्याज को 17.10 लाख रुपये अधिक बताया गया।

6. महत्वपूर्ण लेखा नीति 5.1 के अनुसार, वर्ष 2020–21 के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधानों की गणना पिछले वर्ष (2019–20) से बीमांकिक मूल्यांकन के 5 प्रतिशत की वृद्धि करके की गई है। जबकि लेखा संख्या 2.3 और 6.1 पर टिप्पणियों के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के प्रावधान किए गए हैं जो महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 5.1 के विपरीत है। लेखा संख्या 2.3 और 6.1 में टिप्पणियों को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
17–बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली–110 016 (भारत)
दूरभाष : 91-011-26544800, 26565600
ई. मेल : niepa@niepa.ac.in
वेबसाइट : www.niepa.ac.in